चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

21 अक्टूबर–27 अक्टूबर 2013

नरेन्द्र मोदी बनाम राहुल

देश में इस वक़्त दो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार हैं. राहुल गांधी और नरेन्द्र मोदी. लेकिन न तो राहुल और न ही मोदी ने तरक्की का ऐसा कोई मॉडल पेश किया है, जो समूचे देश के हित में हो. हालांकि, दोनों ही कहते हैं कि देश मज़बूत और विकसित बने, पर दोनों को ही ये नहीं पता कि ऐसा होगा तो आख़िरकार होगा कैसे? मोदी हों या राहुल, दोनों ही बस जुमले उछालते हैं, सवाल उठाते हैं, पर समाधान नहीं बताते.

रूबी अरुण

ऐसे तमाम सवालात हैं जो नरेन्द्र मोदी के भाषणों की बिना पर पैदा होते हैं. इनमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि नरेन्द्र मोदी के विकास का रोड मैप आख़िरकार है क्या? आज देश बेरोज़गारी, भूख, ग़रीबी, भ्रष्टाचार, महंगाई, सीमा पर घुसपैठ और घोटालों जैसी समस्याओं से जूझ रहा है. अगर मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो आख़िरकार ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाएंगे, जिससे सभी मुश्किलें चुटकियों में हल हो जाएंगी? कांग्रेस की नीतियों से अलग, उनकी क्या रणनीति होगी? यह मोदी को अभी ही देश को बताना होगा. लेकिन मोदी ऐसा करते दिखाई नहीं दे रहे. वे सिर्फ़ आलोचनाएं करते हैं. केंद्र सरकार के कामकाज का मखौल उड़ाते हैं. तोहमतें लगाते हैं. पर इन तमाम मर्जों का इलाज क्या है, मोदी ये नहीं बताते.

मोदी ने दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स में जोशीले और कुछ कर गुज़रने का सपना लिए बैठे नौजवान छात्रों के बीच यह कहा कि चुनाव आ गए हैं और अब देश का भविष्य तय होना है. देश थम गया है और इसे गति देनी होगी, तब लगा था कि मोदी वहां मौजूद युवाओं के सामने कोई ऐसा खाका खींचेंगे जो भरोसा जगाएगा कि हां, इसी रास्ते पर चलकर हम अपने भविष्य को बेहतर और उज्ज्वल बना सकते हैं. लेकिन मोदी ने ऐसी कोई राह नहीं सुझाई. उन्होंने बस इतना कहा कि हर देशवासी एक सपना बुने तो उसके सच होने पर हमारा देश एक सौ पच्चीस क़दम आगे बढ़ जाएगा. पर कैसे और किस दिशा में, मोदी ने इसका कोई तरीका नहीं बताया.

बीजेपी कैम्पेन कमेटी के अध्यक्ष बनने के बाद मोदी ने पहली बार दक्षिण भारत में जनसभा को संबोधित किया. जहां वे देश की सीमाओं की रक्षा के मसले पर ख़ूब गरजे-बरसे. मोदी ने कहा कि सरहद पर हमारे सैनिकों को मारा जा रहा है, पर वोट बैंक की राजनीति में उलझी यूपीए सरकार और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए राष्ट्र की सुरक्षा और सैनिकों की ज़िन्दगी कोई मायने नहीं रखती. लेकिन मोदी यह नहीं बताते कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनके पास कश्मीर मसले का क्या हल होगा और भारत-पाक सीमा पर फैले आतंकवाद तथा सीमा पर घुसपैठ की समस्या पर उनकी कार्रवाई क्या होगी.

नरेन्द्र मोदी माओवाद और आतंकवाद की बात करते हैं. उससे होने वाले नुकसान को बताते हैं, पर वे ये नहीं बताते कि जब वे प्रधानमंत्री बनेंगे, तब नक्सली गतिविधियों को समाप्त करने की उनकी क्या रणनीति होगी. वे जल, जंगल और ज़मीन के मुद्दे पर लड़ते और पिसते आदिवासियों के विकास के लिए ऐसा क्या करेंगे कि वे नक्सलवाद की राह छोड़ दें. संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था तो है, पर उस नौकरी के लिए उनके पास जिस शैक्षिक आधार का होना ज़रूरी है, उसके लिए बतौर प्रधानमंत्री मोदी की क्या नीतियां होंगी. नरेन्द्र मोदी कारपोरेट घरानों के सबसे पसंदीदा नेताओं में शुमार किए जाते हैं. यही कारपोरेट घराने वन्य क्षेत्रों में जमीन और खनिज संपदाओं का दोहन करते हैं. इन्हीं घरानों के दम पर मोदी के गुजरात ने विकास पथ पर दौड़ लगाई है. तो क्या मोदी जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब उन औद्योगिक घरानों की नकेल थाम सकेंगे जो आदिवासियों के जीवन और पर्यावरण के लिए घातक हैं? माओवादी आतंक और पूंजीवादी आतंक से दबे-सहमे आदिवासियों को वे विकास की मुख्यधारा में कैसे लेकर आएंगे? नरेन्द्र मोदी के भाषणों और आश्वासनों में इन बातों

नरेन्द्र मोदी के भाषणों में कहीं भी आर्थिक, विदेश, रक्षा, खाद्य, उद्योग आदि उन नीतियों की चर्चा नहीं होती, जिनके बूते वे भारत को विश्व का अग्रणी देश बनाने का जतन करेंगे. देश के लोगों के सामने अपने आपको भावी प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करते समय नरेन्द्र मोदी की भाव-भंगिमा आक्रामक और ऊर्जावान होती है, पर उनकी बातों में भारत के बेहतर भविष्य का कोई स्पष्ट खाका नहीं होता. दूरदृष्टि नहीं होती. देश की समस्याओं की फेहरिश्त तो होती है, पर किसी मसले का समाधान नहीं होता.

का कोई ज़िक्र नहीं होता.

पुणे के फर्ग्युसन कॉलेज में अध्यापकों और छात्रों की भारी भीड़ से नरेन्द्र मोदी केंद्र सरकार पर आक्रामक होते हुए कहते हैं कि दिल्ली की सरकार में बैठे लोग खाद्य सुरक्षा बिल लेकर आए हैं और दावे तो ऐसे कर रहे हैं मानो आपकी थाली में खाना परोस दिया हो. महज़ क़ानून बनाने से आपकी थाली में खाना नहीं आने वाला. पर नरेन्द्र मोदी इस बात पर बिल्कुल रोशनी नहीं डालते कि ग़रीब की थाली में खाना आएगा तो कैसे आएगा. मोदी के ज़ेहन में कौन से ऐसे उपाय हैं, जिसके ज़रिये ग़रीब की थाली और पेट ख़ाली नहीं रहेंगे. मोदी ने यह भी नहीं

(शेष पृष्ठ 2 पर)

मनीष कुमार

नीम हकीम ख़तरा ए जान, यह एक कहावत है. इसका मतलब है कि जिसे आधा ज्ञान हो उससे ख़तरा होता है. राहुल गांधी ने शायद इस कहावत पर ध्यान नहीं दिया. यही वजह है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद वह अपनी साख़ बतौर एक प्रबल राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करने में विफल रहे हैं. इन्हीं सलाहकारों की वजह से बिहार और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उनकी किरकिरी हुई. राहुल गांधी के सलाहकार कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत बन चुके हैं. अतिबुद्धिमान सलाहकारों की वजह से जो हाल पिछली लोकसभा चुनाव में लालकृष्ण आडवाणी का हुआ, वही हश्र राहुल गांधी का 2014 में होता दिखाई दे रहा है.

चुनाव के दौरान विपक्ष के लिए सत्ताधारी पार्टी के कामों की आलोचना करना आसान काम है, क्योंकि उनका काम सबके सामने होता है. इस बार यह विपक्ष के लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि यूपीए ने पिछले दस सालों में ऐसे-ऐसे कारनामे किए हैं, जिसका दर्द पूरा देश झेल रहा है. चाहे घोटाला हो, महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, बदनामी हो, सरकारी तंत्र में घुन लगना हो, कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार हर बुरे काम में अव्वल है. आज़ादी के बाद से इतनी अलोकप्रिय सरकार कोई नहीं हुई. भारत में दो ऐसे मुद्दे हैं, जो चुनाव को सबसे ज़्यादा असर करते हैं. वह महंगाई और भ्रष्टाचार है. वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ये दोनों ही मुद्दे अपनी पराकाष्ठा को छू चुके हैं. यही कांग्रेस के लिए ख़तरे घंटी है. सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी 2014 में कांग्रेस को जीत दिला सकते हैं. क्या उनके नेतृत्व में वो क्षमता है कि केंद्र में वो फिर से कांग्रेस की सरकार को स्थापित कर पाएंगे और प्रधानमंत्री बन सकेंगे.

राहुल गांधी को लेकर मीडिया में काफी हलचल है. देश ने यह मान लिया है कि 2014 का चुनाव मोदी वर्सेस राहुल होगा. एक ओर जहां मोदी बड़ी-बड़ी रैलियां कर रहे हैं. उनके पक्ष में एक अंडरकरेंट चल रहा है. हाल के दिनों में हुए सारे सर्वे एक स्वर में मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए पहली पसंद बता रहे हैं. मोदी फिलहाल लोकप्रियता के पहले पायदान पर हैं, लेकिन हमारे देश में चुनाव की प्रक्रिया ऐसी है, जिसमें इन सर्वे का कोई ज़्यादा असर नहीं होने वाला है. मोदी के बाद अगर कोई नाम प्रधानमंत्री पद के लिए सामने आता है तो वह है राहुल गांधी. कई लोगों को लगता है कि वह हमारे भविष्य के प्रधानमंत्री हैं. यह कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के सशक्त उम्मीदवार इसलिए हैं, क्योंकि वो इंदिरा गांधी के पोते, राजीव-सोनिया गांधी के पुत्र हैं. वह भारतीय राजनीति में परिवारवाद को मिली लेजिटिमेसी की वजह से राजनीति में हैं. हालांकि, उन्होंने अब तक ऐसे प्रमाण नहीं दिए हैं, जिससे यह भरोसा हो सके कि वह आगे चल कर सफल प्रधानमंत्री बन सकेंगे.

कुछ दिन पहले इकोनॉमिस्ट नाम की एक मशहूर पत्रिका ने लिखा कि राहुल गांधी अभी लीड करने को तैयार नहीं हैं. इस पत्रिका ने राहुल गांधी की राजनीतिक समझदारी पर ही सवाल खड़े कर उनकी क़ाबिलियत को ही कठघरे में खड़ा कर दिया. सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी के दिमाग़ में क्या है और वह क्या हैं. वैसे भी हिंदुस्तान के लोगों को यह जानने और समझने के लिए इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत नहीं है. कांग्रेस ने सबसे

कांग्रेस पार्टी इतिहास की सबसे शर्मनाक हार के मुहाने पर खड़ी है. महंगाई और भ्रष्टाचार के साथ-साथ एक असफल सरकार और मनमोहन सिंह के बेअसर नेतृत्व का काला धब्बा भी राहुल गांधी को ही धोना है. अन्ना हजारे और बाबा रामदेव ने आंदोलन के ज़रिये देश को जगाने का काम किया है. राहुल गांधी को इनसे भी निपटना होगा. इसके अलावा नरेंद्र मोदी भी एक अतिरिक्त चुनौती हैं. जनता सिर्फ़ त्रस्त ही नहीं है, कांग्रेस से नाराज़ भी है.

पहले राहुल गांधी को एक युवा नेता के रूप में पेश किया. पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान एक ऐसा माहौल भी बना था, लेकिन उस मुहिम का फ़ायदा न तो बिहार में मिला और न ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा में. जो लोग राहुल से जुड़े, वो कुछ समय के लिए, लेकिन चुनाव आते-आते वे या तो कांग्रेस के विरोध में खड़े हो गए या फिर दूसरे दलों में चले गए. राहुल गांधी जब राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, तब देश का युवा राहुल गांधी के साथ नहीं है. इसकी वजह यह है कि उनके भाषणों से युवाओं में भविष्य के लिए आशा नहीं जगती.

(शेष पृष्ठ 3 पर)

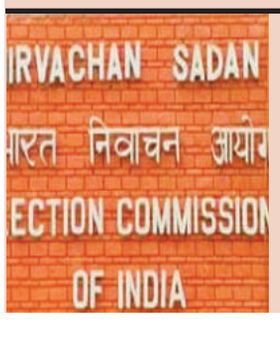

लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल 04

उत्तर प्रदेश में दागियों को संरक्षण दे रही भाजपा 05

कांग्रेस की कलह रमन सिंह की ताकत है 07

साई की महिमा 12

नरेन्द्र मोदी बनाम राहुल

पृष्ठ एक का शेष

बताया कि खाद्य सुरक्षा क़ानून देश के लिए ज़रूरी है या नहीं. अगर ज़रूरी है तो उसे प्रभावशाली तरीक़े से लागू करने और और हर ग़रीब तक उसका लाभ पहुंचाने के लिए उस विधेयक में किन सुधारों की ज़रूरत है.

नरेन्द्र मोदी खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश के ख़िलाफ़ हैं. इससे जुड़े नफ़े–नुकसान की वजह से नहीं बल्कि उन्हें लगा कि भारत में एफडीआई लागू हो जाने से इतालवी व्यापारियों का फ़ायदा होगा. जब केंद्र सरकार ने इस बाबत फैसला लिया तो नरेन्द्र मोदी ने यही सवाल मनमोहन सिंह से किया. जबकि नरेन्द्र मोदी विदेशी निवेश के ख़िलाफ़ कई मज़बूत तर्क दे सकते थे. जो उनकी बुद्धिमता को ही ज़ाहिर करता.

हैदराबाद में मोदी का भाषण सुनने के लिए लोगों ने पांच–पांच रुपये का टिकट ख़रीदा और बेहद उत्साह से उन्हें सुनने को एकत्रित हुए. मोदी ने केंद्र सरकार को भारतीय सीमा में चीनी सेना के घुसपैठ के मसले पर ख़ूब कोसा. मोदी ने कहा कि चीनी सैनिक भारतीय सीमा का अतिक्रमण करते हैं लेकिन भारत सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं, उसे तो बस अपने संबंधों की चिंता है. पर नरेन्द्र मोदी वहां उपस्थित भारी जनसमूह को यह बताना उचित नहीं समझते कि जब वे प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो उनकी सरकार की विदेश नीति इन मुद्दों पर क्या होगी. क्या वे इन समस्याओं को सुलझाने की ख़ातिर युद्ध का रास्ता अख्तियार करेंगे या फिर इन मसलों को वे कुटनीतिक बातचीत के ज़रिये सुलझाने का उपक्रम करेंगे.

महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी अहमदाबाद की एक जनसभा में कहते हैं कि सीता और सावित्री के देश में माताओं और पुत्रियों की सुरक्षा भारतीय समाज में एक बड़ा सवाल है. इस बड़े सामाजिक व आपराधिक मसले पर मोदी और बताने की बजाय उल्टे सभा में उपस्थित पुरुषों की भीड़ से यह सवाल करते हैं कि हमारी मौजूदगी के बाद भी हमारी बहनें शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी पा रही हैं तो हमें मर्द कहलाने का अधिकार है क्या. यहां भी मोदी सवाल करते हैं, कोई हल नहीं सुझाते.

मार्च महीने में नरेन्द्र मोदी ने एक राष्ट्रीय पत्रिका के सालाना कार्यक्रम में कहा कि देश से बेरोज़गारी दूर की जा सकती है. नए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं. प्राकृतिक संपदाओं के बल पर देश समृद्धि की नई मिसाल पेश कर सकता है. जैसा उनके राज्य गुजरात में हुआ. जहां उन्होंने काम के प्रति समर्पित अधिकारियों की फौज तैयार की. उनके निर्देशन में सार्वजानिक कंपनियों के संचालन हेतु एक उच्च स्तरीय पेशेवर कार्य संस्कृति विकसित की है. अगर ऐसी ही कार्य संस्कृति पूरे देश में लागू कर दी जाए तो देश का कायाकल्प हो जाए. लेकिन मोदी ने इस तथाकथित उच्चस्तरीय कार्य संस्कृति की रूप रेखा नहीं बताई. कुछ ही दिनों के बाद गुजरात विधानसभा के पटल पर राज्य के पीएसयू पर आई कैग की रिपोर्ट ने मोदी के दावों को झुठला दिया. कैग की रिपोर्ट में कहा कि राज्य के ज़्यादातर पीएसयू की योजना और वित्तीय प्रबंधन में बड़ा दोष है. जिसकी वजह से वहां कुल 4052 करोड़ का घाटा हुआ है. अगर सरकार ने ध्यान दिया होता तो इस नुकसान से बचा जा सकता था. इसी जलसे में जावेद नाम के एक दर्शक–श्रोता ने नरेन्द्र मोदी से 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित प्रश्न पूछा तो नरेन्द्र मोदी ने जवाब देने से मना कर दिया. दोबारा पूछने पर मोदी ने बड़ी ही रुखाई से कहा कि इस मुद्दे पर मैं पहले जवाब दे चुका हूं, आप इंटरनेट पर देख लीजिए.

इंटरनेट पर राईटर्स के संवाददाता रॉस कॉल्विन द्वारा लिया गया नरेन्द्र मोदी का एक इंटरव्यू है, जिसमें मोदी इस सवाल के जवाब में यह कहते नज़र आते हैं कि लोगों को आलोचना करने का अधिकार है. हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं. प्रत्येक व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है. यदि मैंने कुछ गलत किया हो, तो मैं स्वयं को अपराधी महसूस करूंगा. निराशा तब आती है, जब आपको ये लगता है कि मैं पकड़ा गया. मैं चोरी कर रहा था और मैं पकड़ा गया. मेरे मामले में ऐसा नहीं है. गौर कीजिए. नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है. उन्होंने जवाब के रूप में सिर्फ शाब्दिक जाल बुने हैं.

बहरहाल, नरेन्द्र मोदी ने एसआरसीसी के मंच से कहा कि उन्होंने देश की पचास फीसदी जीडीपी को एक छत के नीचे

लाने में कामयाबी हासिल की है, जिसकी वज़ह से गुजरातियों का जीवन स्तर बेहतर हो गया है. उनकी जीवन शैली, खान–पान, रहन–सहन का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है. पर इसी महीने यानी की अक्टूबर महीने की शुरुआत में ही जब कैग की रिपोर्ट आई तो मोदी के दावे खोखले साबित हो गए.

कैग को गुजरात की महिला एवम शिशु कल्याण मंत्री वसु बेन त्रिवेदी के विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जो आंकड़े हासिल हुए, उसके मुताबिक गुजरात सरकार द्वारा साल 2007 से 2012 के बीच जितने बच्चों को पोषित आहार देने का लक्ष्य रखा गया था, उसे पूरा नहीं किया गया. जिसके फलस्वरूप, इस साल के अगस्त महीने तक गुजरात के 14 जिलों में लगभग सवा छह लाख बच्चे कुपोषित पाए गए. गुजरात की वाणिज्यिक राजधानी अहमदाबाद में कुपोषित बच्चों की संख्या 85 हज़ार से भी अधिक है. जबकि इस सिलसिले में गुजरात के 12 राज्यों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं. इतना ही नहीं, गुजरात में मेहनत–मजदूरी कर अपनी ज़िन्दगी चलाने वालों की स्थिति भी दयनीय है. नरेन्द्र मोदी हर जगह, गुजरात के विकास की गाथा गाते नहीं अघाते, जबकि पर्यावरण, ग्रामीण स्वास्थ्य, पोषण, रोज़गार और शिक्षा जैसे सामाजिक और बुनियादी मानकों पर गुजरात कई राज्यों से पिछड़ा हुआ है. राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात के शहरी इलाकों में दिहाड़ी मजदूरी की दर महज़ 106 रुपये और ग्रामीण इलाकों में दिहाड़ी मजदूरी की दर मनरेगा से इतर सिर्फ़ 83 रुपये है. जो देश में बारहवें स्थान पर है. जबकि केरल में शहरी मजदूरों की दिहाड़ी की दर 218 रुपये और पंजाब में ग्रामीण मजदूरों की दिहाड़ी की दर 152 रुपये है. लेकिन नरेन्द्र मोदी कभी भी अपने भाषणों में इन हकीक़तों का ज़िक्र नहीं करते.

नरेन्द्र मोदी अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो वहां महज़ 11 विश्वविद्यालय हुआ करते थे. मगर आज कुल 42 विश्वविद्यालय हैं. उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात में क्रांतिकारी काम किया है. पर जब हम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट और यूनिसेफ के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि गुजरात सरकार, सरकारी स्कूलों के शिक्षा स्तर को सुधारने की बजाय निजी स्कूलों पर ज़्यादा जोर दे रही है. मोदी के 42 विश्वविद्यालयों में से ज़्यादतर निजी हैं और प्रोफेशनल कोर्सेज़ पर ज़ोर देते हैं. यह पढ़ाई बेहद महंगी है और आम आदमी की पहुंच से बाहर है. यही वज़ह है कि गुजरात में स्कूली छात्रों में ड्राप आउट यानी बच्चों को स्कूल में रोक पाने की दर देश भर में 18वें स्थान पर है.

दिल्ली की रैली में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी हुंकार भरते हैं कि कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने दागी सांसदों के चुनाव लड़ने सम्बन्धी अध्यादेश को फाड़ कर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पगड़ी उछाली है. पर यही मोदी उस वक़्त प्रधानमंत्री पद की गरिमा भूल गए जब उन्होंने नकली लाल किले पर चढ़कर प्रधानमंत्री को ललकारा था.

बहरहाल, नरेन्द्र मोदी रोज़गार को लेकर भी बहुत बड़ी–बड़ी बातें करते हैं. वे कहते हैं कि गुजरात में उन्होंने हर हाथ को काम मुहैया करवाया. मोदी यह भी कहते हैं कि अब वे गुजरात से विश्व भर में शिक्षक निर्यात करेंगे. ताकि भारत को फिर से विश्वगुरु का दर्ज़ा मिल सके. पर मोदी यह काम किस तरीके से अंजाम तक पहुंचाएंगे, इसका कोई जवाब उनके पास नहीं होता. पर अगर हम एनएसएसओ की रिपोर्ट को देखें तो मोदी की चमकीली बातों का अंधेरा पहलू नज़र आता है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात में औद्योगीकरण की अंधी दौड़ ने पिछले दस सालों में गुजरात में बेरोज़गारों की फौज़ खड़ी कर दी है. इस दौरान गुजरात में रोज़गार की दर शून्य के आसपास पहुंच चुकी है. छोटी–छोटी जोत वाले किसानों ने सेज और दूसरी औद्योगिक इकाइयों के लिए अपनी ज़मीनें छोड़ दीं और मोटी रकम लेकर बैठ गए. नतीजतन भूमिहीन और बेरोज़गार लोगों की एक बड़ी जमात गुजरात में इकट्ठा हो गई. नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यह कहता है कि दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है, जबकि गुजरात चौथे नंबर पर है. पर नरेन्द्र मोदी श्रीराम कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स के छात्रों से ये कहते हैं कि गुजरात, सिंगापुर को दूध सप्लाई करता है और भिन्डी की सब्जी यूरोप को. पर हकीक़त यह है कि पूरे देश में भिन्डी का उत्पादन और निर्यात सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश से होता है.

नरेन्द्र मोदी अपने भाषणों में कभी भी इस बात का उल्लेख नहीं करते कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी देश के लिए आर्थिक नीतियां क्या होंगी. विदेशी मामलों पर उनका रुख क्या हो होगा. देश की सुरक्षा और रक्षा सम्बन्धी मसलों पर जो त्रुटियां हैं, उन्हें वे कैसे दूर करेंगे. विश्व के अन्य देशों से भारत के मज़बूत व्यापारिक–आर्थिक संबंधों को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए उनकी दूरदृष्टि क्या होगी. मोदी जिस विकसित और शक्तिशाली भारत का सपना लोगों के सामने परोसते हैं, उसे साकार करने हेतु उनकी क्या योजनाएं हैं. क्या सिर्फ यह कह देने से कि देश भर में गुजरात मॉडल लागू किया जाएगा, क्या उससे भारत विश्व का अग्रणी देश बन जाएगा? क्या गुजरात की तरह ही देश भर में सिर्फ़ अंबानी, अडानी और टाटा जैसे कारपोरेट के बूते नरेन्द्र मोदी देश भर में गुड गवर्नेंस लागू कर लेंगे? नरेन्द्र मोदी को इन सभी सवालों के जवाब देने होंगे. क्योंकि अब समय आ चुका है. नरेन्द्र मोदी ने आज तक सिर्फ़ सवाल उछाले हैं, जवाब नहीं दिया है. प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने अपना राष्ट्रीय एजेंडा घोषित नहीं किया है. उग्र राष्ट्रवाद के हिमायती रहे मोदी ने अभी तक मुज़फ़्फ़रनगर के दंगो पर चुप्पी साध रखी है. जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हो, उसकी निगाह में हर इंसान बराबर होना चाहिए. भले ही वह किसी भी सम्प्रदाय, नस्ल या जाति का हो. इसलिए भी मोदी को बोलना होगा.

नरेन्द्र मोदी अब तक गुजरात में सीमित थे. देश का उनसे ज्यादा साबका नहीं पड़ा था. लेकिन अब मोदी देश के भावी प्रधानमंत्री की तरह पेश आ रहे हैं. इसलिए अब देश के लोगों का नरेन्द्र मोदी को जांचने–परखने का नज़रिया भी अलग होगा. पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. मोदी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी यक़ीनन इन चुनावों और इसके परिणामों पर भी असर डालेगी. इसलिए भी मोदी को हर मसले पर बोलना होगा और ख़ुद के उठाए गए सवालों के जवाब भी देश की समस्याओं के समाधान के तौर पर देने होंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 05 अंक 33
दिल्ली, 21 अक्टूबर–27 अक्टूबर 2013
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना–800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

क्यों बदला मन?

दिलीप चेरियन

गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आजकल देश भर में रैलियों को संबोधित करने में व्यस्त हैं. इस बीच अहमदाबाद में राज्य सरकार को आईएएस अधिकारियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है. स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर है कि सरकार ने हाल ही में चार आईपीएस, दो आईएएस और दो आईएफएस अधिकारियों को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के प्रस्ताव को वापस ले लिया है. जबकि जून में सरकार ने इस प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी थी. प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने वाले आईपीएस अधिकारी डीआईजी दिनेश राय, आईजीपी प्रवीण सिन्हा और एसपी दिव्या मिश्रा हैं. सूत्रों के अनुसार सबसे दिलचस्प बात यह है कि राज्य सरकार दिनेश राय के केंद्र में प्रतिनियुक्त पर भेजे जाने के आवेदन को अनुमति देने के पहले कई महीनों तक दबाए बैठी थी. जबकि अब उसे निरस्त कर दिया गया है. हालांकि, सूत्रों को राज्य सरकार के बयान पर संशय है कि राज्य में अधिकारियों की कमी है. सरकार के इस निर्णय को लेकर अफवाहों का बाज़ार गर्म है कि क्यों मोदी सरकार ने अचानक इन अधिकारियों को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजने का का मन बदल लिया है. ■

पूर्व की ओर निगाहें

जापान के साथ बढ़ते संबंधों को देखते हुए भारत सरकार अधिकारियों को कानून और लोक नीति के क्षेत्र में और प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के प्रशिक्षण प्रभाग ने जापान स्थित क्यूशू विश्वविद्यालय और नेशनल ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्ट्डीज, टोकियो में प्रशिक्षण पाने के इच्छुक अधिकारियों से यंग लीडरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत आवेदन मांगे हैं. डीओपीटी सचिव एस के सरकार के अनुसार इस कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों की आयु आवश्यक रूप से 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, साथ ही वह सेना में कार्यरत नहीं होने चाहिए. अब तक भारत सरकार अधिकारियों को पश्चिमी देशों के हार्वर्ड विश्वविद्यालय और कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में ट्रेनिंग के लिए भेजती रही है. लेकिन सरकार का यह कदम दिखाता है कि सरकार दूसरे देशों के साथ भी संबंधों को प्रगाढ़ करने की इच्छुक है. ■

पी चिदंबरम की टीम

रघुराम राजन की रिजर्व बैंक के गवर्नर बनने के बाद नार्थ ब्लॉक का माहौल में वित्त मंत्रालय का माहौल खुशनुमा हो गया है. स्पष्ट रूप से वह पूर्ववर्ती गवर्नर की तुलना में पी चिदंबरम के ज्यादा घनिष्ट हैं जिसकी वजह से मंत्रालय में एक आशावादी माहौल बना हुआ है .उनके गवर्नर नियुक्त होने के बाद रिक्त हुई मुख्य आर्थिक सलाहकार की जगह अभी भरनी बाकी है. सूत्रों के अनुसार सरकार इस पद को भरने में कोई ज्यादा जल्दबाजी करती नहीं दिख रही है. स्पष्टतया चिदंबरम अपनी मौजूदा टीम से बहुत खुश हैं, जिसमें आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम और अतिरिक्त सचिव के पी कृष्णन भी शामिल हैं. लेकिन नॉर्थ ब्लॉक में ज्यादा अटकलें सचिव (व्यय) आर एस गुजराल के सेवा विस्तार को लेकर लगाई जा रही हैं. वे अगले माह सेवानिवृत्त हो रहे हैं और यूपीए सरकार अधिकांश मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों के जाने के विरुद्ध दिखी है. ■

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

दीक्षित पुलिस एकेडमी प्रमुख बन सकते हैं

1977 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी पी एन दीक्षित को जल्द ही हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है. अकादमी के वर्तमान निदेशक सुभाष गोस्वामी को भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) का अगला निदेशक नियुक्त किया गया है. गोस्वामी 1977 बैच के असम–मेघालय कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं. उनके आईटीबीपी निदेशक का पदभार ग्रहण करने के बाद पुलिस अकादमी में निदेशक का पद रिक्त होगा.

चौधरी विशेष सचिव हो सकते हैं

गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा के विशेष सचिव, एस जयारमन के उत्तराधिकारी को लेकर रहस्य अभी भी बना हुआ है. लेकिन 1978 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी जयंत नारायण चौधरी उनकी जगह ले सकते हैं. चौधरी वर्तमान में असम के पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं.

वर्मा अगले महानिदेशक हो सकते हैं

1978 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी आर. आर. वर्मा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अगले महानिदेशक हो सकते हैं. वह यहां शफी आलम की जगह लेंगे. वर्तमान में वर्मा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के विशेष महानिदेशक हैं.

त्रिपाठी गृहमंत्रालय से जुड़ेंगे

1999 बैच के भारतीय प्रसारण (इंजीनियर्स) सेवा के अधिकारी देबा प्रसाद त्रिपाठी को गृहमंत्रालय के निदेशक (विदेशी) के रूप में नियुक्त किया गया है. वह 1996 बैच के भारतीय लागत लेखा सेवा अधिकारी एनआई चौधरी की जगह लेंगे. चौधरी का कार्यकाल हाल ही में पूरा हुआ है.

सुशिलेश निदेशक बनेंगे

जनजातीय मामलों के मंत्रालय में 1989 बैच के वन सेवा अधिकारी सुशिलेश मोहन सहाय के लिए एक नए पद का सृजन किया गया है. सुशिलेश मोहन सहाय जनजातीय मामलों के मंत्रालय में निदेशक बनेंगे. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

कांग्रेस को यह लगता है कि लोगों के बैंक में जब पैसा जाएगा और फ्री अनाज मिलेगा तो वे यूपीए सरकार की सारी ख़ामियों को भूल जाएंगे. लेकिन समस्या यह है कि यूपीए सरकार ने इन योजनाओं को यूआईडी यानी आधार कार्ड के ज़रिये लागू किया जाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की वैधता पर सवाल खड़ा दिया. देश की जनता चालाक हो चुकी है. कई सालों से धोखे खाती आ रही है. जब तक उसे फायदा नहीं मिलता, तब तक लोगों को कांग्रेस के वादों पर भरोसा नहीं होगा.

राहुल गांधी अभी तैयार नहीं हैं

पृष्ठ 1 का शेष

वैसे भी 43 साल का कोई बच्चा नहीं होता और हम उसे युवा भी नहीं कह सकते. गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट या फिर विवेकानंद हों, इन लोगों ने 30 साल की उम्र में ही अपना लोहा मनवाया, लेकिन 43 साल के राहुल को युवा नेता बताने वाले को इसका जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा कौन सा कारनामा किया है, जिससे हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का सिर गर्व से ऊपर उठ जाए. पार्लियामेंट के अंदर या बाहर उनका एक भाषण या करनामा ऐसा बताएं, जिसे बार-बार सुनने की इच्छा हो. ऐसा भाषण, जिसे सुनकर युवाओं में ऊर्जा भर जाए और जोश से ओत-प्रोत हो जाएं. अगर यह नहीं बता सकते तो यह तो ज़रूर बताना चाहिए कि 43 साल के जीवन में उन्होंने क्या कोई वैचारिक, सैद्धांतिक या अपनी दूरदर्शिता का कोई परिचय दिया है क्या? क्या राहुल गांधी अपनी कोई ऐसी उपलब्धि बता सकते हैं, जिसका समाज या राजनीति पर असर हुआ हो. राहुल गांधी ने यह सब न तो दिखाया है, न उसकी कोई झलक दिख रही है.

हाल में दागी सांसदों व विधायकों के सवाल पर राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री व पूरी कैबिनेट को कठघरे में खड़ा कर दिया, एक संयमी राजनेता से वैसी अपेक्षा नहीं की जा सकती. राहुल गांधी ने अगर यह काम किसी की सलाह पर की, तो वह सलाह ग़लत थी और अगर ख़ुद ही किया तो इसे उनका अहंकार ही कहा जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ अध्यादेश लागू करना एक संवैधानिक विवाद खड़ा कर सकता है. संविधान के मुताबिक, अध्यादेश को लागू तभी किया जा सकता है, जब संसद सत्र में न हो और दूसरा जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, जिस पर तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो. अब ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि अध्यादेश लागू करना आवश्यक हो गया और वो भी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इन सवालों को लेकर देश के तीन कानूनविदों से बातचीत की. विपक्ष ने भी इस अध्यादेश पर सवाल उठाए, जिससे यह लगा कि राष्ट्रपति इस अध्यादेश पर मुहर नहीं लगाएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से इसे नॉनसेंस कह कर कैबिनेट के फ़ैसले को ग़लत बताकर क्रेडिट लेने की कोशिश की, वह एक गैर राजनीतिक व अपरिपक्व फ़ैसला था.

राहुल गांधी कि अपरिपक्वता व लचर नेतृत्व का जीता-जागता उदाहरण यूपी व बिहार के विधानसभा चुनाव परिणाम हैं. कांग्रेस न सिर्फ़ चुनाव हारी, बल्कि पार्टी की साख़ चली गई. बिहार और उत्तर प्रदेश कोई छोटे प्रदेश नहीं हैं. ये दोनों राज्य देश की राजनीति की दिशा-दशा तय करते हैं. यूपी और बिहार चुनाव की कमान सीधे-सीधे राहुल गांधी के हाथ में थी, लेकिन चुनाव आते-आते वे लोग कांग्रेस के विरोधी बन गए, जिन्हें राहुल गांधी ने ज़मीनी नेता व कार्यकर्ता के रूप में तैयार किया था. चुनाव के वक्त सार्वजनिक रूप से यही लोग राहुल गांधी के ख़िलाफ़ आग उगल रहे थे. जिन लोगों को राहुल ने तैयार किया, उसमें से कई लोगों ने कांग्रेस के ख़िलाफ़ चुनाव भी लड़ा और कैंपेन भी किया. इसमें सबसे बड़ी ग़लती राहुल गांधी की ही थी. उन्होंने बीएसपी से निकाले गए, समाजवादी पार्टी से निकाले गए इधर-उधर के नेता को पार्टी में शामिल किया. उन्हें पार्टी की सारी शक्तियां दे दी. चाहे वह टिकट बांटने की हो, कैंपेन से जुड़ी हो, पैसे से जुड़ी हो, चाहे वह संगठन से जुड़ी हो, राहुल ने ये सारे काम बाहर से आए लोगों के हाथ दे दी. ये लोग अपने हिसाब से टिकट बांटने लग गए. कांग्रेस के कार्यकर्ता यह पूछने लग गए कि ये रशीद मसूद कौन हैं, पीएल पुनिया कौन हैं, बेनी बाबू कहां से आ गए और राहुल ने उन्हें सर्वेसर्वा क्यों बना दिया. पुराने कांग्रेसी पानी पी-पीकर कांग्रेस पार्टी को कोसने लगे. उत्तर प्रदेश में सारे नेता-कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह और परवेज हाशमी के साथ चार साल तक काम करते रहे, लेकिन जब चुनाव का वक्त आया, तब राहुल ने इन दोनों को नज़रअंदाज़ कर दिया. लोकसभा चुनाव फिर से नज़दीक हैं. उत्तर प्रदेश और बिहार अत्यंत ही महत्वपूर्ण राज्य हैं, लेकिन इन राज्यों के लिए कोई योजना नहीं है और न ही कोई तैयारी नज़र आ रही है. जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति के मास्टर हैं, उन्हें फिर से नज़रअंदाज़ किया जा रहा है. ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि राहुल अपने कुछ सलाहकारों की राय पर काम करते हैं और उन्हें लगता है कि उनके हमउम्र सलाहकारों की समझ कांग्रेस के परिपक्व नेताओं से ज़्यादा है.

दरअसल, राहुल गांधी को मीडिया मैनेजमेंट के ज़रिये लीडर बनाया जा रहा है. इसे समझना ज़रूरी है. राहुल गांधी को पहले यूथ का नेता घोषित करने का प्रयास किया गया. यह ख़बर फैलाई गई कि राहुल गांधी कांगेस पार्टी को डेमोक्रेटाइज करेंगे. एक प्लानिंग हुई. तैयारी हुई कि उन्हें देश का सबसे बड़ा यूथ लीडर बनाना है. इसके लिए कांग्रेस पार्टी की पूरी कार्यप्रणाली ही बदल दी गई. उनके लिए अलग ऑफिस सेक्रेट्रिएट और अलग स्टाफ सहित सारी व्यवस्था अलग की गई. कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना-देना नहीं है कि राहुल गांधी क्या बोलेंगे, कहां जाएंगे और वहां कौन-कौन सी मीडिया होगी और मीडिया को क्या बोलना है, क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है. ये सब तय करने वाले लोग हैं, जिन्हें राहुल गांधी की इमेज को प्रोजक्ट करना है. उन्होंने समझा दिया कि जो भाषण होना चाहिए, वह दीवार फिल्म के अमिताभ बच्चन की तरह होना चाहिए. यू शुड लुक लाइक ऐंग्री यंग मैन. इसलिए वो कागज फाड़ना, उनके तेवर दिखाने का अंदाज, यह सब उन्हें बताया गया. एजेंसी हायर की गई थी कि कैसे इमेज बनानी है. सबसे मज़ेदार बात तो यह थी कि भाषण लंबे-चौड़े दिए जा रहे हैं. ऐंग्री यंग मैन की इमेज बनाई जा रही थी, लेकिन हक़ीकत यह थी कि राहुल की यूपी यात्रा के दौरान महज़ 1000-3000 लोग ही होते थे. मीडिया न्यूज चैनल्स को जो फीड दिया जा रहा है, उसमें सिर्फ़ क्लोजअप दिखाने को कहा गया था. स्टेज दिखाओ, पब्लिक मत दिखाओ, ऐसा आदेश था, लेकिन विडंबना देखिए, कांग्रेस पार्टी ने चार साल जो मेहनत की, पूरा संगठन तैयार किया, उसके ऊपर ही आपने एसिड डालने का काम किया. राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह जब आजमगढ गए, तो काला झंडा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिखाया. झांसी में राहुल के ऊपर जूता फेंका गया. जूता फेंकने वाला कांग्रेस का कार्यकर्ता था. यही ग़लती बिहार में की थी. अब फिर से यही ग़लती दुहराई जा रही है. अब राहुल गांधी के ऐसे कौन महान सहालकार हैं, जो नवरात्र के दौरान उत्तर प्रदेश में उनकी रैली रखते हैं. 9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और रामपुर में राहुल गांधी की रैलियां हुईं. अलीगढ़ का नुमाइश मैदान काफ़ी बड़ा है, जो राहुल गांधी के भाषण के दौरान ज़्यादातर ख़ाली रहा. कुर्सियां भी ख़ाली थीं. करीब 3000 हज़ार लोग वहां पहुंचे थे. रामपुर की रैली का हाल और भी बुरा था. मतलब यह है कि राहुल एक ही गलती बार-बार करते हैं. अपनी ग़लतियों को पहचानना, स्वीकार करना और उसे न दोहराना भी नेतृत्व का एक गुण होता है.

देश की राजनीति करवट ले रही है. राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है. कांग्रेस पार्टी इतिहास की सबसे शर्मनाक हार के मुहाने पर खड़ी है. महंगाई और भ्रष्टाचार के साथ-साथ एक असफल सरकार और मनमोहन सिंह के बेअसर नेतृत्व का काला धब्बा भी राहुल गांधी को ही धोना है. अन्ना हजारे और बाबा रामदेव ने आंदोलन के ज़रिये देश को जगाने का काम किया है. राहुल गांधी को इनसे भी निपटना होगा. इसके अलावा नरेंद्र मोदी भी एक अतिरिक्त चुनौती हैं. जनता सिर्फ़ त्रस्त ही नहीं है, कांग्रेस से नाराज़ भी है. वह अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रही है. ऐसे वक्त में देश की जनता को ऐसे नेतृत्व की तलाश है, जो उन्हें समाधान दे सके. अगर राहुल गांधी यह कहेंगे कि मैं अभी युवा हूं, मैं भारत को देखना चाहता हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं रियल इंडिया को जानना चाहता हूं तो यह मान लेना चाहिए कि 2014 में देश की जनता राहुल गांधी को सिरे से ख़ारिज कर देगी. ■

manish@chauthiduniya.com

कांग्रेस की मुश्किलें और भी हैं

हिंदुस्तान में चुनाव में जब भी कांग्रेस विरोध की आंधी चली है, उसके पीछे दो ही वजह रही है. महंगाई और भ्रष्टाचार. पिछले 10 सालों में यूपीए सरकार भ्रष्टाचार और महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है. भारत के चुनावी राजनीति में नरेंद्र मोदी जैसे विरोधी का सामना करना आसान है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या सुप्रीम कोर्ट है. सुप्रीम कोर्ट में कोयला घोटला, 2जी घोटाला, यूआईडी सहित कई मामलों की सुनवाई हो रही है. हर घोटाले में सरकार की तरफ से चूक हुई है. एक तरफ कांग्रेस पार्टी फूड सिक्योरिटी बिल, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर आदि कई योजनाओं का हवाला देकर चुनाव जीतना चाहती है. कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि लोगों के बैंक में जब पैसा जाएगा और फ्री अनाज मिलेगा तो वे यूपीए सरकार की सारी ख़ामियों और भ्रष्टाचार को भूल जाएंगे. लोग महंगाई को भूल जाएंगे, लेकिन समस्या यह है कि यूपीए सरकार ने इन योजनाओं को यूआईडी यानी आधार कार्ड के ज़रिये लागू किया जाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की वैधता पर सवाल खड़ा दिया. देश की जनता चालाक हो चुकी है. कई सालों से धोखे खाती आ रही है. जब तक बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, जब तक मुफ्त अनाज नहीं मिलेंगे, तब तक लोगों को कांग्रेस के वादों पर भरोसा नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड पर सवाल खड़ा करके कांग्रेस पार्टी के कैंपेन के आधार

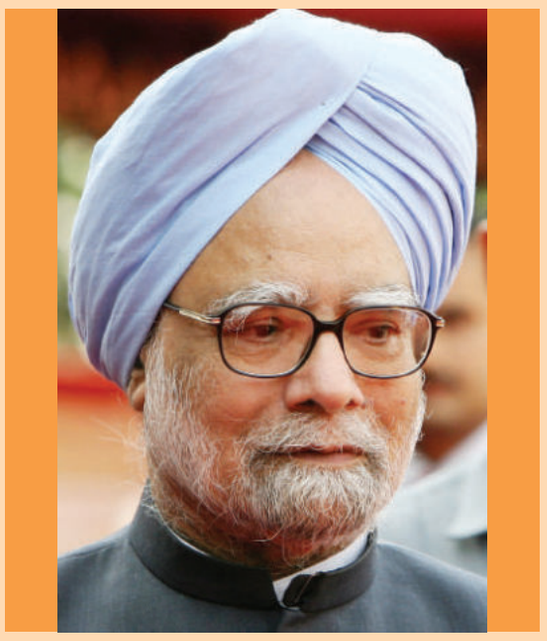

को ही ख़त्म कर दिया है. कांग्रेस की दूसरी परेशानी यह है कि घोटाले के जितने भी मामले कोर्ट में चल रहे हैं, उसकी ख़बरें लगातार आ रही हैं. हाल में ही कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी. घोटाले से जुड़ी फाइलों के ग़ायब होने पर एफआईआर दायर करने तक के आदेश दिए गए थे. इससे कांग्रेस पार्टी की किरकिरी हुई. समस्या यह है कि कोर्ट में चल रही सुनवाई की वजह से घोटाले की ख़बरें आए दिन आती रहेंगी. कांग्रेस पार्टी के नेताओं के घोटाले लोगों के याददाश्त को तरोताज़ा करते रहेंगे. 2जी घोटाले में जेपीसी की रिपोर्ट पर राजनीति शुरू हो गई है. विपक्ष के साथ-साथ अब करुणानिधि की डीएमके भी विरोध में आ चुकी है. इसका मतलब यह है कि 2जी घोटाले पर आने वाले समय में राजनीति होती रहेगी. फैसला क्या होगा, ये तो कोर्ट में निर्धारित होगा, लेकिन इस घोटाले की याद लोगों के ज़ेहन में लगातार बनी रहेगी. साथ ही देश में जो आर्थिक हालात हैं और जिस तरह से सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में पूरी तरह विफल रही है, उससे यही लगता है कि अगले चुनाव तक लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी. मतलब यह कि कांग्रेस पार्टी के लिए चारों तरफ़ से मुसीबत है. कोयला घोटाला को सबसे पहले चौथी दुनिया ने ही उजागर किया था. ख़तरा यह है कि कोयला घोटाले में शक की सूई सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर टिकी है. यह घोटाला उस वक्त हुआ है, जब मनमोहन सिंह कोयला मंत्री थे. इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई बुरी ख़बर आ गई तो कांग्रेस पार्टी का चुनावी कैंपेन धरा का धरा रह जाएगा. ■

> राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली और मिजोरम इन पांचों राज्यों पर गौर किया जाए तो कुछ हद तक मिजोरम को छोड़कर बाकी चारों राज्य ऐसे हैं जो दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता तय करते हैं. राजस्थान का राज इस बार कांग्रेस के हाथ से निकलकर भाजपा के पाले में जाता दिख रहा है तो छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मशहूर जुमला तैर रहा है कि राज्य में कांग्रेस की विरोधी पार्टी कांग्रेस ही है और वही उसको हराएगी. मध्य प्रदेश में शिवराज तीसरी बार कुर्सी हथियाने को जोर लगाएंगे, जिनके विरोध में कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया कमान संभाल रहे हैं.

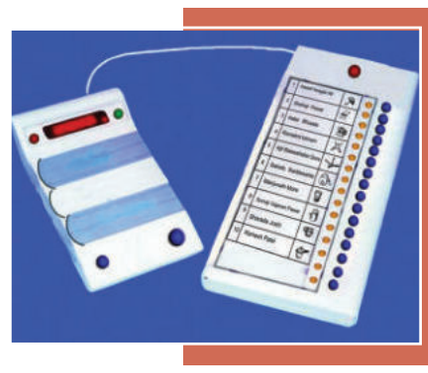

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव

लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल

पांच राज्यों चुनाव की तारीख़ें तय हो गई हैं. भाजपा और कांग्रेस समेत सभी पार्टियां इन राज्यों की सत्ता हथियाने के लिए ज़ोर लगा रही हैं, क्योंकि ये चुनाव लोकसभा चुनाव के ठीक पहले होने जा रहे हैं, जो एक तरह से लोकसभा चुनाव पूर्वपीठिका भी साबित होंगे. पांचों राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ और मध्य प्रदेश में मुकाबला सीधा कांग्रेस और भाजपा के बीच है तो दिल्ली और मिजोरम में अन्य दल भी प्रमुख भूमिका में नजर आ रहे हैं. पांचों राज्यों के चुनावी माहौल की पड़ताल करती एक रिपोर्ट-

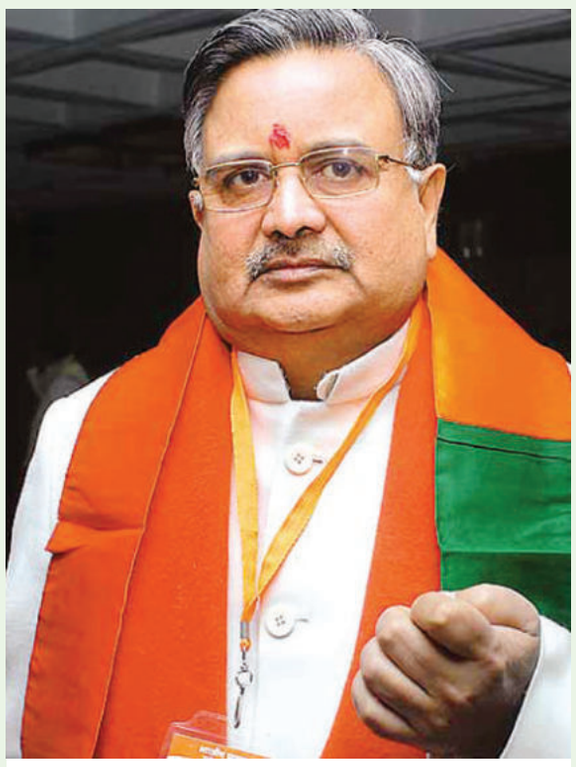

नीरज सिंह

पांच राज्यों में चुनावों की तिथियों की घोषणा हो गई है. चूंकि अगले वर्ष लोकसभा चुनाव भी होने हैं, इसलिए इन चुनावों को सभी राजनीतिक दल सेमीफाइनल के तौर पर ले रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी ने तो घोषणा भी कर दी है कि 2013 में पांच प्रदेश 2014 में पूरा देश. कांग्रेस के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का विषय इसलिए भी है, क्योंकि उन्हें अपने युवराज में ही पार्टी का भविष्य खोजना है, इसलिए ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर हैं. यही वजह है कि यह मौजूं वक्त है कि जब इस बात की पड़ताल की जाए कि किन राज्यों में फिलहाल हवा किसके पक्ष में जाती हुई दिख रही है.

राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली और मिजोरम इन पांचों राज्यों पर गौर किया जाए तो कुछ हद तक मिजोरम को छोड़कर बाकी चारों राज्य ऐसे हैं जो दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता तय करते हैं. इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की. एक आम मतदाता या आम समझ वाले व्यक्ति के नज़रिये से देखें और जैसा कि चुनावी सर्वेक्षण और राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि राजस्थान का राज इस बार कांग्रेस के हाथ से निकलकर भाजपा के पाले में जाता दिख रहा है. लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, इस कयास के विरोध में भी स्वर उठने लगे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस ने हर स्तर पर रूठे हुए मतदाताओं को फिर से अपनी तरफ लाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं. अब स्थिति यह है कि वसुंधरा राजे की राह जितनी आसान बताई जा रही है, वह उतनी भी आसान नहीं है. पिछले एक साल में अशोक गहलोत की अगुआई वाली सरकार ने एक-एक कर कई लोकलुभावन योजनाएं शुरू की हैं, जिन्होंने चुनाव को कांटे की टक्कर में तब्दील कर दिया है. इन योजनाओं के चलते अब राजस्थान में यह बात होने लगी है कि अगर कांग्रेस ने टिकट बंटवारा ठीक से किया और भाजपा ने टिकट बंटवारे में गलतियां कीं तो गहलोत की वापसी हो सकती है. हालांकि, जब तक दोनों दलों की तरफ से चुनावी अखाड़े में उतरने वाले उम्मीदवारों का नाम सामने नहीं आ जाता, तब तक स्पष्ट तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता.

वास्तव में देखा जाए तो यह चुनाव भाजपा से अधिक कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस के सामने यह बात तो स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा दोबारा सत्ता में आ रही है. हो सकता है दिल्ली में कांग्रेस वापसी कर ले. इसलिए दो राज्यों में मानसिक रूप से विन-विन सिचुएशन कांग्रेस अपने लिए ज़रूर बनाना चाहेगी. ऐसा भी नहीं है कि भाजपा एकदम से बैकफुट पर चली जाएगी, लेकिन सत्तारूढ़ गहलोत सरकार ने एक के बाद एक लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा शुरू कर दी है, इससे भाजपा की भी राह आसान नहीं होगी. वैसे भी राजस्थान की राजनीति पर गौर करें तो हमेशा से वहां दो दलीय व्यवस्था रही है, इसलिए ऐसे किसी चमत्कार की उम्मीद करना बेमानी होगा. और देखा जाए तो हर बार चुनाव में ऐसा माहौल बनता है कि प्रदेश में कोई तीसरी ताकत उभरने वाली है, लेकिन अगर आप राजस्थान की राजनीति की पड़ताल करें तो किरोड़ी लाल मीणा एक तीसरी ताक़त के रूप में उभर रहे हैं. मीणा फिलहाल राष्ट्रीय जनता पार्टी में हैं, जिसका गठन कांग्रेस से अलग होने के बाद पीए संगमा ने किया था. किरोड़ी लाल मीणा इसी पार्टी में रहकर राजस्थान में एक ऐसा गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो भाजपा और कांग्रेस दोनों को चुनौती दे. राष्ट्रीय जनता पार्टी फिलहाल प्रदेश की 150 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और जनता दल यूनाइटेड, भाकपा और माकपा जैसी पार्टियों से गठबंधन की बातचीत भी चल रही है. अगर ऐसा माहौल बनता है कि गैरभाजपा और गैरकांग्रेसी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ें तो इस प्रांत की राजनीति में कुछ फेरबदल हो सकता है. हालांकि किसी बड़े फेरबदल की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि मीणा राजस्थान की अगड़ी जनजाति मीणा के नेता हैं, जिनका एक सीमित क्षेत्र में ही प्रभाव है.

राजस्थान के बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ की. छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा मशहूर जुमला तैर रहा है कि राज्य में कांग्रेस की विरोधी पार्टी कांग्रेस ही है और वही उसको हराएगी. आखिर इसकी वजह क्या है अपनी ही पार्टी विपक्षी पार्टी के तौर पर खड़ी हो गई है. पहले इसको समझते हैं. राज्य का गठन होने के बाद ही विधायकों की संख्या बल के आधार पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन गई. आदिवासी बहुल इलाका और आदिवासी राजनीति पर ज़ोर देने के कारण आदिवासी नेता अजीत जोगी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन गए. अजीत जोगी ने तीन साल तक प्रदेश को जस का तस बनाए रखा और जब 2003 में चुनाव हुए तो भाजपा की रमन सरकार सत्ता में आई. रमन सिंह ने प्रांत को विकास की धारा से जोड़ा, हालांकि रमन का सिंह यह विकास भी मोदी के विकास की तरह शहरी इलाकों तक सीमित रहा. यही वजह है कि 2007 के चुनाव में कांग्रेस ने एक बार राज्य में खुद को स्थापित किया, लेकिन बहुमत भाजपा को ही हासिल हुआ.

लगातार दो बार सत्ता से दूर रहने के कारण पार्टी के भीतर असंतोष जन्म लेने लगा और प्रदेश में कांग्रेस दो खेमों में बंट गई. एक खेमे ने अजीत जोगी को अपना नेता माना और एक ने चरणदास महंत को. इस असंतोष ने धीरे-धीरे भितरघात का रूप ले लिया. इस चुनाव की तैयारियों की दौरान कई ऐसे वाक़ये हुए जब दोनों खेमों के लोगों ने एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की. इसी बीच कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी चरणदास महंत को सौंप दी. इससे जोगी खेमा बेहद नाराज़ है और सूत्र तो यहां तक कहते हैं कि जोगी अपनी पार्टी बना सकते हैं. लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस अपनी स्थिति को बेहतर बनाना चाहती है तो अजीत जोगी को मनाना ही होगा. क्योंकि जोगी एक अदिवासी जननेता हैं और अदिवासी बहुल इलाकों में उनकी पकड़ बेहद मज़बूत है. अगर जोगी कोई और राह पकड़ लेते हैं तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा. क्योंकि अदिवासी बहुल इलाकों में आज भी जोगी की तूती बोलती है. अब कांग्रेस आलाकमान एक बार फिर से राज्य में डैमेज कंट्रोल कर रहा है और इसका हथियार बनाया है नई-नई घोषणाओं को. कांग्रेस के घोषणापत्र में किसान, आदिवासी, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग के साथ-साथ सामान्य वर्ग को भी रिझाने की भरपूर कोशिशें होंगी. उधर भाजपा ने जीत की हैट्रिक बनाने के लिए 3-4 माह पहले से ही सरकारी खजाना खोल दिया है. साइकिल, सिलाई मशीन, धान बोनस, लैपटॉप, टैबलेट से लेकर बहुत कुछ बांटे जा रहे हैं.

इसी क्रम में बात करते हैं राजधानी दिल्ली की. दिल्ली में होने वाली राजनीतिक हार या जीत के प्रतीकात्मक तौर पर गहरे अर्थ होते हैं. दिल्ली का राजनीतिक माहौल पूरे देश को प्रभावित करता है, इसलिए देश भर की निगाहें दिल्ली की ओर हैं. दिल्ली का चुनाव इस बार एक मायने में और महत्वूर्ण है, क्योंकि आप पार्टी की राजनीतिक दिशा इसी चुनाव से तय होने वाली है. और जिस तरह के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण आए हैं उनमें तो सबको चौंकाते हुए आप पार्टी को अप्रत्याशित सफलता दी है. हालांकि यह अभी तक अस्पष्ट है कि इस बार तीसरी पार्टी के आने का क्या असर होगा, किसके वोट किसके पास जाएंगे और स्विंग के कारण सीटों पर क्या फ़र्क़ पड़ेगा. हालांकि, कांग्रेस पार्टी के लोग यह कह रहे हैं कि आप पार्टी के लाइम लाइट में आने का फायदा कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के दोषों को आप पार्टी ने दूर कर दिया और वह भाजपा के वोट काटेगी.

मुद्दों के आधार पर देखें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में महंगाई और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा. इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा व दिल्ली के अन्य स्थानीय मुद्दे जैसे बिजली-पानी भी प्रमुख मुद्दा बनेंगे. हालांकि कांग्रेस महंगाई को अपनी नाकामी नहीं वैश्विक स्तर पर बढ़ी महंगाई को इसका ज़िम्मेदार मान रही है. महंगाई को रोकने का कोई स्पष्ट खाका तो भाजपा के पास भी नहीं है, लेकिन वे इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं. भ्रष्टाचार आप पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और वह इसको महंगाई से जोड़कर देख रहे हैं. भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पार्टी कांग्रेस के साथ-साथ भाजपा को भी लपेट रहे हैं. वह भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम में भी भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं.

एक और मसला है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का. लेकिन यह इतना आसान दिखता नहीं और कई बार लगता है कि भाजपा इस मुद्दे को ज़बरदस्ती उछाल रही है क्योंकि किसी भी बड़े मतदाता वर्ग का हित इससे जुड़ा नहीं है. फौरी तौर पर तो सबसे बड़ा मुद्दा बिजली का है जिसकी दरों को कम करने के लिए आप और भाजपा में प्रतिस्पर्धा चल रही है. दिल्ली में निचले तबके की आबादी के लिए पानी एक बड़ा मुद्दा है. फ़िलहाल चुनावी मुद्दे के तौर पर इसे केवल आम आदमी पार्टी ही मुद्दा बना रही है. एक और बड़ा मुद्दा है अनधिकृत कॉलोनियों का. सरकार के दावों के बावजूद सैकड़ों कॉलोनियां नियमित नहीं हो पाई हैं. इन सभी दावों के बीच दिल्ली की तस्वीर अन्य चार राज्यों के मुक़ाबले काफ़ी धुंधली है. इसलिए इस बार अभी तक दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, फिलहाल कह पाना मुश्किल है.

मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर चुनावी विश्लेषक यह तय मान रहे हैं कि राज्य में शिवराज सिंह चौहान तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. हालांकि उनके समक्ष पिछले चुनावों की तरह कोई ताक़तवर विपक्ष तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने शिवराज सिंह के ख़िलाफ़ ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारकर पार्टी के एक उम्मीद ज़रूर पैदा की है. वास्तव में कमोबेश ये सहूलियतें हीं शिवराज की मुश्किल भी हैं.

गुजरात के मुख्यमंत्री के नरेंद्र मोदी को भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन पार्टी के भीतर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अब भी उनके लिए अहम चुनौती माना जा रहा है. शिवराज के नेतृत्व में भाजपा तीसरी बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहती हैं तो नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती और बढ़ेगी, लेकिन वे हारते हैं तो ये न केवल कांग्रेस को एकजुट होने का मौका देगा, बल्कि उमा भारती जैसे उनके धुर विरोधी मध्य प्रदेश की राजनीति में तेजी से वर्चस्वशाली हो जाएंगे.

मध्य प्रदेश में कांग्रेस में आंतरिक बिखराव और गुटबाज़ी के चलते बीजेपी कुछ सालों से फीलगुड में डूबी हुई है. कांग्रेस मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव एक व्यक्ति नहीं, बल्कि टीम के बूते लड़ने के मूड में हैं. इसने चुनाव के पूर्व सीएम के नाम का ऐलान नहीं करने की अपनी परंपरा कायम रखी और वन मैन आर्मी वाली रणनीति अख़्तियार नहीं की. कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को किनारे कर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भरोसा किया है. सिंधिया के आने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कुछ उत्साह ज़रूर बढ़ा है इसीलिए अब यह चुनाव दो पार्टियों के बीच न होकर ब्रांड शिवराज बनाम ब्रांड सिंधिया बन गया है. वास्तव में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह पूरी तरह से नरेंद्र मोदी को ही फॉलो कर रहे हैं. मोदी की ही तरह वे इमेज बिल्डिंग पर ज़ोर दे रहे हैं. यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह लोकायुक्त के सम्मुख इस आशय की शिकायत दर्ज करा चुके हैं कि सीएम शिवराज ने तीन माह में खुद की ब्रांडिंग पर 500 करोड़ रुपये ख़र्च किए हैं. बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी के भीतर का विखराव भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होगा. हां इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भाजपा सरकार ने बीते दस सालों में विकास की जो राह दिखाई है, उसका फायदा भी पार्टी को होता दिख रहा है.

मिजोरम में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है. हालांकि हर राज्यों में मौजूदा सरकार के प्रति एंटी इनकमबैंसी तो होती ही है, लेकिन मिजोरम में कांग्रेस को हराने के लिए सभी राजनीतिक दल एकजुट हो गए हैं. राज्य के क्षेत्रीय दल मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) और मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (एमपीसी) का चुनावी एजेंडा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाना है. एमएनएफ-एमपीसी ने लोगों से आह्वान किया कि एक साफ छवि की सरकार देने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं. अलगाववाद भी एक मुद्दा मिजोरम के चुनावों में उभर कर आ रहा है. यही वजह है कि मिजो नेशनल फ्रंट, मिजो राष्ट्रवाद को ज्यादा तवज्जो दे रहा है. एमएनएफ ग्रेटर मिजोरम के गठन की मांग को चुनावी मुद्दा बना रहा है. दूसरी ओर एमपीसी ने दस चुनावी बिंदुओं को केंद्र में रखा है, जो राज्य के विकास पर केंद्रित है.

भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार पिछले विधानसभा चुनावों में जीत नहीं पाया था. हालांकि ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि भाजपा के लिए राज्य में इस बार के चुनाव बड़ी उम्मीद लेकर आएंगे, लेकिन मोदी के भरोसे राज्य भारतीय जनता पार्टी इकाई किसी चमत्कार की उम्मीद में जरूर है. चुनावी फेरबदल की बात करें तो इस पिछले 10 वर्षों से सत्ता में काबिज कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार खतरा है. 1998 में जिस एमएनएफ-एमपीसी के गठबंधन ने चुनाव जीता था वह अब फिर से सत्ता हथियाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है. दूसरा बड़ा बदलाव है मोदी के रूप में. यह जानकर ताज्जुब होता है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में गांव-देहात तक मोदी का नाम पहुंच चुका है और लोग उन्हें बदलाव के प्रतीक के रूप में देख रहे हैं.

पिछले विधानसभा चुनावों में अधिकांश भारतीय राज्यों के चुनावी एजेंडे में भले ही पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को प्राथमिकता नहीं मिलती है, लेकिन मिजोरम विधानसभा चुनाव के दौरान ये प्रमुख मुद्दे बन कर उभरे थे. बांस में आए फूल राज्य की सबसे बड़ी आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या बने हुए थे, लेकिन इस बार भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है और गैर सत्ताधारी पार्टियां यह मानकर बैठी हैं कि कांग्रेस ही इस भ्रष्टाचार की जड़ है. ■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार

दागी नेताओं वाले अध्यादेश पर राहुल गांधी के एंग्री यंग मैन वाले एप्रोच ने लालू प्रसाद को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है. लालू भले ही सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराज़गी का इज़हार नहीं कर रहे हैं, पर रांची से उनसे मिलकर लौटे नेताओं में से कुछ ने बताया कि लालू प्रसाद को राहुल गांधी और कांग्रेस से इस तरह के रवैये की उम्मीद नहीं थी.

उत्तर प्रदेश

बिहार

लालू और नीतीश में मौक़ा तलाश रही कांग्रेस

सरोज सिंह

सोनिया गांधी और राहुल गांधी के गुणगान में संसद से लेकर सड़क तक शब्दों की सीमा बार-बार लांघने वाले लालू प्रसाद इन दिनों उनसे ख़ासे नाराज़ बताए जा रहे हैं. दागी नेताओं वाले अध्यादेश पर राहुल गांधी के एंग्री यंग मैन वाले एप्रोच ने लालू प्रसाद को अंदर से फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है. लालू भले ही सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराज़गी का इज़हार नहीं कर रहे हैं, पर रांची से उनसे मिलकर लौट रहे नेताओं में से कुछ ने बताया कि लालू प्रसाद को राहुल गांधी और कांग्रेस से इस तरह के रवैये की उम्मीद नहीं थी. लालू के मन में था कि संकट की घड़ी में कांग्रेस एक भरोसे वाले दोस्त की भूमिका निभाएगी और किसी न किसी तरह मदद कर रास्ते को आसान बना देगी, लेकिन राहुल गांधी ने तो लालू की राह में इतने रोड़े बिछा दिए कि इस पर चल कर दोस्ती की कहानी नहीं सुनाई जा सकती. बताया जाता है कि पहले यह तय था कि अगर संसद से बात नहीं बनी तो अध्यादेश के माध्यम से दागी सांसदों की सदस्यता बचाए रखने की कोशिश होगी. कांग्रेस ने आंतरिक विरोध और बाहरी आलोचना झेलने का रिस्क लेकर उसे अमलीजामा पहनाने का प्रयास भी किया, लेकिन इस पूरे प्रकरण में राहुल गांधी की भूमिका ने लालू प्रसाद का बना बनाया खेल बिगाड़ दिया. चारा घोटाले में फैसला आने के पहले लालू प्रसाद ने दिल्ली में जाकर जो होमवर्क किया था, उसमें राहुल के बयान ने पलीता लगा दिया. इसके बाद जो होना था, वही हुआ. लालू प्रसाद को सज़ा हुई. रांची के होटवार जेल में लालू से मिलने सभी दलों के नेता, जो उनके राजनीतिक सहयोगी रहे हैं, मिल रहे हैं, पर एक दो को छोड़ दें तो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उनसे मिलने नहीं गया है. कांग्रेस की यही बेरुख़ी लालू प्रसाद को अखर रही है. राहुल के रुख़ के बावजूद लालू ने अंतिम प्रयास यह बयान देकर किया कि झारखंड की सरकार को राजद का समर्थन जारी रहेगा, पर कांग्रेस के एप्रोच में कोई अंतर नहीं आया. राजद के रणनीतिकारों की यह सोच पुख़्ता हो रही है कि कांग्रेस अब जदयू के नजदीक होती जा रही है. लालू ने अपना दिल ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा किया, पर कांग्रेस को यह पसंद नहीं आया. अब चूंकि लालू जेल में बंद हैं, इसलिए कांग्रेस के लिए और भी दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई है. कांग्रेस में यह सोच मज़बूत हो रही है कि नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ नीतीश कुमार ने अपना 17 साल का गठबंधन तोड़ा और अपनी सरकार को ख़तरे में डाल दिया. इसलिए लड़ाई अगर नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ लड़नी है तो जदयू ही सही साथी रहेगा. इससे मुसलमानों में भी सही संदेश जाएगा कि कांग्रेस सही मायनों में नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ बिहार में लड़ाई लड़ने के लिए संकल्पित है. एक साफ-सुथरी सरकार की बात अगर राहुल गांधी कर रहे हैं तो नीतीश ही स्वाभाविक साथी बनते हैं. यही वजह है कि लालू के नंबर कम हो रहे हैं, लेकिन दिक्कत जदयू के साथ भी है. शरद यादव और उनके समर्थक यह नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ सारी विचारधारा को ताक पर रखकर कोई गठबंधन किया जाए. ज़िंदगी भर कांग्रेस विरोध की राजनीति करने के बाद इस मुकाम पर आकर शरद यादव के लिए यह मुश्किल हो रहा है कि वह कांग्रेस की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाएं. इसलिए नीतीश की इच्छा के बावजूद जदयू व कांग्रेस की दोस्ती परवान नहीं चढ़ रही है. सूत्र बताते हैं कि अगर नीतीश कुमार कांग्रेस की तरफ बढ़ने के लिए अडिग रहे तो पार्टी में विभाजन भी हो सकता है. 22 नवंबर को चारा घोटाले में सीबीआई को नीतीश कुमार को लेकर अपना पक्ष रांची हाईकोर्ट में रखना है. राबड़ी देवी बार-बार कह रही हैं कि सीबीआई की निष्पक्षता 22 नवंबर को ही पता चल जाएगी. मौटे तौर पर पार्टी की कमान संभालने के बाद राबड़ी देवी इस मसले को पूरे बिहार में उठाने जा रही है. राबड़ी देवी चाहती है कि जनता यह जाने की लालू अंदर क्यों हैं और नीतीश बाहर क्यों? पूरी पार्टी राबड़ी देवी को इस मसले पर साथ दे रही है. राबड़ी दशहरे के बाद अपने इस अभियान पर निकल पड़ेंगी. इसका पहला लाभ तो यह होगा कि राजद में जो अभी अटकलों का दौर है, वह ख़त्म हो जाएगा और दूसरा यह कि कार्यकर्ता लालू के नाम पर पूरी तरह सक्रिय हो जाएंगे. राबड़ी चाहती हैं कि अपने अभियान से वह कांग्रेस और जदयू के बीच पक रही खिचड़ी का पर्दाफ़ाश कर दें, लेकिन कांग्रेस की अपनी ही सोच है.

दरअसल, कांग्रेस चुनाव बाद की स्थितियों का आकलन कर अपने कदम बढ़ा रही है. लालू की बिहार में ज़मीनी ताक़त से कांग्रेस को भी इन्कार नहीं है. नीतीश कुमार सत्ता में हैं और फिलहाल उनकी छवि बेहतर है. इसका अहसास भी कांग्रेस को है. इसलिए कांग्रेस लालू और नीतीश दोनों का साथ चाहती है, पर जिस तरह के हालात बन गए हैं, उससे कांग्रेस दुविधा में है. बिहार में यूपी मॉडल लागू करने की बात कही तो जा रही है और सतही स्तर पर यह अपील भी करती है, लेकिन जानकार बताते हैं कि कांग्रेस को यह भय भी सता रहा है कि चुनाव बाद कहीं महामहिम ने चुनाव पूर्व सबसे बड़े गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता दे दिया तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा. इसलिए बीजेपी भी चुनाव से पहले ही अपने सारे नये सहयोगियों को एनडीए में जोड़ने में लगी है. भाजपा की यही पहल कांग्रेस की दुविधा को बढ़ा रही है. इसलिए सोच यह बन रही है कि चुनाव से पहले ही लालू या फिर नीतीश में किसी एक को चुन लिया जाए, पर हालात ऐसे हैं कि गठबंधन की खिचड़ी पक नहीं पा रही है. कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह कहते हैं कि अगामी लोकसभा चुनाव में हम किसके साथ जाएंगे, यह कहना अभी मुश्किल है. अखिल भारतीय कांग्रेस की एंटनी कमेटी के फैसले के बाद ही गठबंधन के बारे में कुछ तय किया जाएगा. उन्होंने कहा कि नवंबर के पहले हफ्ते तक कोई निर्णय लिया जा सकता है. वैसे कांग्रेस को यह मालूम है कि लालू उसके अच्छे सहयोगी रहे हैं. दूसरी ओर राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे कहते हैं कि देश में नमो के खौफ को फैलाया जा रहा है. आरएसएस के इस नाटक से देश पर खतरा है. ऐसे में राजद की हमेशा कोशिश रहेगी कि सेक्युलर ताकतों को लालू के नेतृत्व में एक साथ लाया जाय. यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस के जदयू के साथ जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है, पूर्वे कहते हैं कि कांग्रेस के हम पुराने साथी रहे हैं, उसे यह समझना होगा कि आज भी बिहार की राजनीति के केंद्र में लालू ही हैं. राजद को लालू की राजनीतिक ताकत पर भरोसा है तो जदयू नीतीश कुमार की छवि को आगे कर रही है, लेकिन लगता है कांग्रेस फैसले के लिए कुछ और समय लेना चाहती है. जयराम रमेश जब पटना आए थे तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, जिससे लगे कांग्रेस नीतीश से गठबंधन के लिए बेताब है. उन्होंने यह कहकर और भी दुविधा बढ़ा दी कि बिहार को विशेष दर्जे की नहीं, बल्कि विशेष दर्जी की जरूरत है. सभी जानते हैं कि विशेष राज्य का मसला नीतीश कुमार का चुनावी मुद्दा है और कांग्रेस मंत्री द्वारा उसे हल्का करने वाला बयान देना यह बतलाता है कि कांग्रेस अभी किसी फैसले तक नहीं पहुंच पाई है. लगता है राज्य के बदलते हालात और कांग्रेस की बदलती सोच ही गठबंधन के इस पेंच को सुलझा सकती है. फिलहाल तो कांग्रेस लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच झूल रही है.■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश

दागियों को संरक्षण दे रही है भाजपा

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है. पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए यह अच्छी ख़बर है, पार्टी इस बढ़त को बनाए रख पाएगी, यह उसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा. इसका कारण है कि तमाम सकारात्मक बातें होते हुए भी पार्टी के रणनीतिकार जीत के लिए शॉर्टकट रास्ता अपना रहे हैं. यह विडंबना ही है कि भाजपा को नई दिल्ली में जो दाग ख़राब लगते हैं, उत्तर प्रदेश में वही उसे रास आते हैं. केंद्र में शुचिता की बात करने वाली भाजपा को उत्तर प्रदेश में सिद्धांतों से हटकर जीत सुनिश्चित करने के लिए किसी से भी हाथ मिलाने में परहेज नहीं है. इसका पुख़्ता प्रमाण है प्रदेश में पार्टी द्वारा दागियों के लिए दरवाज़े खोलना. यूपी की राजनीति में आजकल जो कुछ घट रहा है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

राजनीति के जानकारों का कहना है कि कांग्रेस-भाजपा, बसपा-सपा सहित अन्य कई छोटे-छोटे दल उत्तर प्रदेश को राजनीतिक प्रयोगशाला बनाने के लिए नये-नये प्रयोग कर रहे हैं. 2014 के आम चुनाव में जीत का लक्ष्य हासिल करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के रणनीतिकारों ने विकास की बातें ताक पर रख दी हैं और मान-मर्यादा आचार-विचार सभी को तिलांजलि दे दी है. भारतीय जनता पार्टी तो इस मामले में कुछ ज़्यादा ही सुर्ख़ियां बटोर रही है. न वह अतीत से सबक लेना चाहती है, न वर्तमान को समझने की उसमें कूवत दिखाई दे रही है. वह यह भूल गई है कि विधानसभा चुनाव से पूर्व दागी नेता और बसपा के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, बादशाह सिंह को अपने करीब लाने की उसने कितनी बढ़ी सज़ा भुगती थी. जब पूरा देश राजनीति के शुद्धिकरण अभियान की पैरोकारी कर रहा हो, तब भाजपा का दागियों को पनाह देना समझ से परे है. वैसे ही भाजपा में दागी नेताओं की सख्या कम नहीं है, जिसके कारण पार्टी को फजीहत उठानी पड़ती है, उसके बाद भी यूपी में करीब एक दर्जन दागी और दबंग भाजपा से लोकसभा टिकट पाने की जोड़-तोड़ में लगे हैं. कुल मिलाकर विभिन्न दलों के करीब 60-70 नेता भाजपा में आने का मन बनाए हुए हैं. इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं की संख्या भी अच्छी-खासी है. दागी-दबंग चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू, वित्तीय अनियमितता के चलते हटाए गए बसपा के पूर्व मंत्री अशोक दोहरे, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के पुत्र पंकज सिंह, राष्ट्रीय लोकदल की पश्चिमी उत्तर प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष व नगीना व बिजनौर के सांसद रहे मुंशीराम, इटावा के पूर्व चेयरमैन जसवंत वर्मा तथा छत्रपाल सिंह सेंगर व अखिलेश वर्मा आदि कुछ नेताओं को पार्टी में इंट्री मिल भी गई है, कई को जल्द मिलने की उम्मीद है.

आश्चर्यजनक बात यह है कि पार्टी के ही कुछ ऐसे बड़े नेता जिसके ऊपर लोकसभा चुनाव की तैयारियों की जिम्मेदारी है और पार्टी उनसे काफी उम्मीद लगाए हुए है, वही अन्य दलों से आने वाले नेताओं को भाजपा में शामिल करने के लिए नीचे से लेकर ऊपर तक दबाव बना रहे हैं. रोज ही पार्टी में कोई न कोई बाहरी नेता आ रहा है. जिन बड़े नामों के भाजपा के साथ जुड़ने की चर्चा हो रही है, उसमें जौनपुर और गोंडा के निवर्तमान सांसद, अयोध्या के राजा, मथुरा से पूर्व मंत्री चौधरी बाबूलाल, बदांयू से पूर्व मंत्री भगवान सिंह शाक्य, अमरोहा से स्वामी ओमवेश आदि नाम प्रमुख हैं. यह सभी नेता कमल के सहारे संसद का मुंह देखना चाहते हैं. परिर्वतन दल के दबंग नेता डीपी यादव, जदयू के टिकट पर सांसद व विधायक रह चुके बाहुबली धनजंय सिंह, बुरे समय में भाजपा का साथ छोड़कर जाने वाले और भाजपा नेता की हत्या के संदेह के घेरे में आए एक सांसद महोदय भी भाजपा का दरवाजा खटखटा रहे हैं. डीपी यादव का तो आना बिल्कुल तय हो गया था, मगर पार्टी में विरोध के चलते वह नहीं आ पाए. तमाम घोटालों के आरोपी पूर्व आईएएस आर के सिंह और उनकी पत्नी पूर्व मंत्री ओमवती सिंह को पार्टी में जगह देकर भाजपा ने साफ कर दिया है कि उसके लिए कोई अछूत नहीं हैं. बात राजा भैया की करें तो उनकी क्षत्रिय वोट बैंक पर अच्छी-खासी पकड़ है, इसीलिए उनको भाजपा के प्रभारी अमित शाह भी पार्टी के भीतर देखना चाहते हैं. इस बात का पता चलते ही सपा के कान खड़े हो गए. इसी के चलते राजा की नाराजगी को कम करने के लिए ही पिछले दिनों सपा के कद्दावर नेता और मंत्री आजम खान को उनके यहां दस्तक देनी पड़ गई. आजम खान से ही सबसे अधिक राजा भैया नाराज चल रहे थे. जियाउल हक हत्याकांड में आजम ने राजा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे.

बाबू सिंह कुशवाहा

बादशाह सिंह

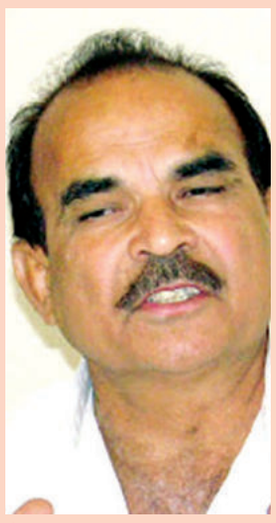

डीपी यादव

स्वामी ओमवेश

बहरहाल, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व समझ ही नहीं पा रहा है कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के लिए कौन-सा फार्मूला चुना जाए. पार्टी कैडर बनाम जिताऊ प्रत्याशी के चयन में उलझी हुई है. इस दुविधा का असर पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कम तो कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है. स्थिति यह है कि हिंदुत्व का केंद्र माने जाने वाली वाराणसी, अयोध्या और मथुरा तक में भाजपा टिकट बंटवारे को लेकर आशंकित है. भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ. रमापति राम त्रिपाठी से जब पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल शब्दों में जबाव देते हुए कहा कि पार्टी उसी नेता को टिकट देगी, जो जनआकांक्षाओं पर खरा उतरेगा. प्रत्याशी चयन की एक लंबी प्रक्रिया से टिकट के दावेदारों को गुज़रना पड़ेगा. उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए कि पार्टी में आने वाले कुछ बड़े नेताओं को टिकट दिया जा सकता है. उनका कहना था भाजपा चरम पर है, इसलिए अन्य दलों के नेता इस मुहिम में भाजपा के सारथी बनना चाहते हैं तो उन्हें कैसे इन्कार किया जा सकता है.

बात भाजपा के मौजूदा दागी नेताओं की बात करें तो लैकफेड घोटाले में एक साल से जेल में बंद बसपा के नेता रहे पूर्व मंत्री बादशाह सिंह को भाजपा ने काफी उम्मीदों के साथ गले लगाया था, लेकिन अब वह अपने इस फैसले पर पछता रही है. पूर्व सांसद हरिसाक्षी महाराज को लेकर भी पार्टी को मलाल हो रहा है. हत्या एवं अन्य संगीन अपराधों में नामजद साक्षी के बारे में अक्सर पार्टी को सफाई देना भारी पड़ जाता है. नोट के बदले सवाल पूछने वाले प्रकरण में सांसदी गंवाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री छत्रपाल सिंह, बसपा काल में कैबिनेट से बर्खास्त हुए अवधेश वर्मा जैसे अनेक विवादित नाम भी भाजपा की छवि धूमिल कर रहे हैं. वैसे भी, इलेक्शन वाच की रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा के लगभग दो दर्जन विधायकों व नगरीय निकाय के तीन दर्जन से अधिक प्रतिनिधियों पर केस दर्ज हैं. लोकसभा चुनाव में दागियों को टिकट न मिले, इस संबंध में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कहना है कि दागियों को टिकट देने का सवाल नहीं उठता. हत्या, बलात्कार व भ्रष्टाचार जैसे आरोपियों को उम्मीदवार बनाना तो दूर संगठन में भी पद नहीं दिया जाएगा.

भाजपा किसे गले लगाएगी और किसे ठुकरा देगी, यह तो वह ही जाने, लेकिन भाजपा इस बात से गदगद जरूर है कि भाजपा की तरफ भाग रहे नेताओं के कारण जनता के बीच यह मैसेज जरूर जा रहा है कि भाजपा अबकी बार सत्ता की प्रबल दावेदार है. खासकर उत्तर प्रदेश में ऐसा दो दशकों में पहली बार हो रहा है, जब अन्य दलों के नेता भाजपा में आने के लिए हाथ-पैर मार रहे हैं, पिछले विधानसभा चुनाव तक भाजपा की स्थिति डांवाडोल थी, उसी कारण उसने अपने विचारों को दरकिनार करके कई दागियों को भी बुला-बुलाकर टिकट थमा दिया था. उसे उम्मीद थी कि दागी नेता के सहारे ही सही, विधानसभा में उसकी कुछ तो ताकत बढ़ेगी, लेकिन इसके उलट जनता ने भाजपा को और बुरी हार का मार्ग प्रशस्त कर दिया था. अबकी से हालात बदले हैं. इसका फायदा भाजपा नहीं उठा पाई तो इसके लिए दिल्ली की मंजिल दूर हो सकती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामालु ने अलग आंध्र की मांग पर आमरण अनशन शुरू कर दिया. 58 दिनों के अनशन के बाद उनकी मौत हो गई और पूरे आंध्र क्षेत्र में दंगे, प्रदर्शन और हिंसा शुरू हो गई, जिसमें कई लोग मारे गए. अंत में सरकार झुक गई और अलग आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को स्वीकार कर लिया. इसके बाद कई भाषाई समूहों की मांगों को देखते हुए 1953 में प्रधानमंत्री नेहरू ने राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया.

बंटवारे की राजनीति का शिकार आंध्र प्रदेश

कृष्णकांत

आंध्र प्रदेश विभाजन की आग में झुलस रहा है. जिस अलग राज्य की मांग के लिए क़रीब पांच दशक से आंदोलन चल रहा था, उसके गठन की घोषणा हो गई है और विभाजन के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं. लंबे समय से उठ रही तेलंगाना की मांग को देखते हुए यूपीए सरकार ने आम चुनाव के ठीक पहले अलग तेलंगाना राज्य की घोषणा कर दी. अब वहां की क्षेत्रिय पार्टियों ने अलग तेलंगाना राज्य का विरोध करना शुरू कर दिया है. आंध्र प्रदेश में अलग राज्य के मसले पर यह संकट आज का नहीं है. आंध्र प्रदेश का गठन ही एक लंबे आंदोलन के बाद हुआ था. अलग राज्य बनने के बाद भी यहां की राजनीति पर अधिकांश समय कांग्रेस का ही कब्ज़ा रहा, लेकिन राज्य के गठन से लेकर अब तक तेलंगाना की मांग कभी कमज़ोर तो कभी मज़बूत तौर पर बरक़रार रही. आंध्र प्रदेश की राजनीति समझने के लिए यहां के राजनीतिक इतिहास पर एक निगाह डालना ज़रूरी है.

17वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश में मुग़ल शासक औरंगज़ेब का राज क़ायम हुआ. उसके बाद निज़ामों का राज रहा. 1772 में आसिफ जाह यहां के निज़ाम-उल-मुल्क़ हुए, जिन्होंने अपने शासित क्षेत्र का नाम हैदराबाद डेक्कन रखा. 1799 में निज़ामों ने ही अंग्रेज़ों के साथ अनुबंध किया और आंध्र प्रदेश अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया. आज़ादी के बाद निज़ामों ने भारत के अधीन राज्य की जगह आंध्र प्रदेश को अलग शाही राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा. यहां तेलुगू भाषी लोग 22 ज़िलों में बंट गए थे, जिसमें से 9 ज़िलों में निज़ामों का वर्चस्व क़ायम रहा. 26 जनवरी, 1950 को आज़ाद भारत की अंतरिम सरकार ने एमके वेल्लोडी को हैदराबाद राज्य का पहला मुख्यमंत्री बनाया. वे मद्रास और बॉम्बे स्टेट से शासन करते रहे. 1952 में जब पहला आम चुनाव हुआ, उसके बाद डॉ. बुर्गुला रामकृष्ण राव आंध्र के पहले मुख्यमंत्री बने. इसी समय अलग तेलंगाना राज्य की मांग शुरू हुई.

आज़ाद भारत के शुरुआती दो दशक में सबसे बड़ा विभाजनकारी मुद्दा भाषा समस्या थी. आज़ादी के बाद भारत में भाषाई आधार पर राज्यों की मांग शुरू हो गई थी. भाषाई राज्यों के उग्र समर्थकों को शांत करने के लिए कांग्रेस ने एक समिति गठित की, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभि सीतारमैया थे. इस समिति ने विचार करने के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विरुद्ध सलाह दी. समिति का तर्क था कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से भारत के एकीकरण की प्रक्रिया बाधित हो सकती है. भाषाई आधार पर विभाजन विखंडनकारी शक्तियों को मज़बूत करेगा, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि वह लोकप्रिय मांगों का विरोध नहीं करती. हालांकि, समिति की रिपोर्ट में आंध्र की मांग को तर्कसंगत कहा गया, क्योंकि मद्रास यानी तमिलनाडु का नेतृत्व भी इस पर सहमत था.

19 अक्टूबर, 1952 को एक स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामालु ने अलग आंध्र की मांग पर आमरण अनशन शुरू कर दिया. 58 दिनों के अनशन के बाद उनकी मौत हो गई और पूरे आंध्र क्षेत्र में दंगे, प्रदर्शन और हिंसा शुरू हो गई, जिसमें कई लोग मारे गए. अंत में सरकार झुक गई और अलग आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को स्वीकार कर लिया. इसके बाद कई भाषाई समूहों की मांगों को देखते हुए 1953 में प्रधानमंत्री नेहरू ने राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया. आयोग ने अक्टूबर 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि प्रशासनिक और आर्थिक पहलुओं को समुचित महत्व देते हुए भाषाई आधार पर पुनर्गठन पर ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए. आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर संसद ने नवंबर, 1956 में पुनर्गठन विधेयक

पास किया. अंतत: पंजाब को छोड़कर भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन हुआ. अब तक भाषा के मुद्दे पर आंदोलन ने हिंदी विरोध का विकराल स्वरूप धारणा कर लिया और देश के हिंदी-अहिंदी राज्यों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई. राज्य पुनर्गठन आयोग आंध्र प्रदेश में तेलंगाना को शामिल करने के पक्ष में नहीं था, लेकिन राजनीतिक दबावों के चलते हैदराबाद के तटीय इलाकों और तेलंगाना क्षेत्र को जोड़कर मद्रास स्टेट से अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया. इस तरह तेलुगू भाषियों को 1 नवंबर, 1956 को आंध्र प्रदेश के रूप में एक अलग राज्य मिल गया.

आंध्र प्रदेश राज्य की मांग पूरी हो गई, लेकिन एक और अलग राज्य की आकांक्षा क्षेत्रवासियों में अभी ज़िंदा रह गई थी. 1969 में अलग तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर *जय तेलंगाना* आंदोलन की शुरुआत हुई. इस आंदोलन के दौरान पुलिस गोलीबारी में 300 लोग मारे गए. तेलंगाना के जवाब में 1972 आंध्र के तटीय इलाकों में *जय आंध्र* आंदोलन की आग भड़की. इस तरह तेलंगाना और आंध्र क्षेत्र के समर्थकों में विद्वेष फैलता गया. आज आंध्र प्रदेश में इतिहास ख़ुद को एक बार फिर दोहरा रहा है. जिस तरीक़े से मद्रास को तोड़कर आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया था, उसी तरीक़े से अब उस राज्य को तोड़कर अलग तेलंगाना राज्य बन गया. अब उस पर भी विरोध प्रदर्शन, हिंसा और अस्थिरता का दौर जारी है.

आंध्र प्रदेश के गठन के बाद से ही कांग्रेस ही वहां की मुख्य पार्टी रही है. 1953 से लेकर 1983 तक कांग्रेस को ही राज्य में बहुमत मिलता रहा. 1956 में राज्य के गठन के बाद से लेकर 1983 तक दस कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने यहां की सत्ता संभाली. हालांकि, तेलंगाना की मांग को लेकर संगठित आंदोलन के लिए तेलंगाना प्रजा समिति का गठन हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में असंतुष्ट कांग्रेसी थे. 1972 में एम श्रीधर रेड्डी के नेतृत्व में तेलंगाना समर्थकों ने चुनाव लड़ा, जिसमें सिर्फ पुरुषोत्तम राव चुनाव जीते थे. 1971 में तेलंगाना क्षेत्र से आने वाले पीवी नरसिंहराव जब मुख्यमंत्री बने, तेलंगाना प्रजा समिति का कांग्रेस में विलय हो गया. विलय के बाद भी बीच-बीच में तेलंगाना की मांग उठती रही. जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी लगातार तेलंगाना की मांग को समर्थन देते रहे.

1983 में तेलुगू फिल्मों के अभिनेता एनटी रामाराव ने तेलुगू देशम पार्टी बनाई. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बार-बार राज्य में मुख्यमंत्री बदल रही थीं, जिससे नाराज लोगों ने *तेलुगू अस्मिता* के नाम पर एनटीआर को समर्थन दिया और वे पहले ग़ैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने. हालांकि, 1984 में एनटीआर अपने हृदय रोग का इलाज कराने अमेरिका गए थे, तभी उनकी पार्टी के एन भास्करा राव ने पार्टी तोड़ दी. वे पार्टी के कुछ लोगों को लेकर अलग हुए और कांग्रेस के सहयोग सरकार बना ली, राव सदन में बहुमत सिद्ध नहीं कर सके. इस तरह एनटीआर सत्ता में बने रहे. 1989 में कांग्रेस फिर सत्ता में लौटी और मैरी चेन्ना रेड्डी मुख्यमंत्री बने. 1994 में एनटीआर की पार्टी ने महिला आंदोलन का समर्थन किया और शराबबंदी के ख़िलाफ़ अभियान चलाया. 1995 में उनकी पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में लौटी. बाद में पार्टी एनटीआर ने अपने दामाद एन चंद्रबाबू नायडू को वित्त मंत्री बनाया. सरकार बनने के कुछ समय बाद सरकार के फ़ैसलों पर एनटीआर की दूसरी पत्नी पार्वती के असर देखा जाने लगा, जिसकी प्रतिक्रिया में ज़्यादातर विधायकों ने चंद्रबाबू नायडू को समर्थन दिया और वे मुख्यमंत्री बन गए. इसके बाद पार्टी दो धड़ों में बंट गई, एक तेलुगू देशम पार्टी और दूसरी तेलुगू देशम पार्टी (एनटीआर). चंद्र बाबू मुख्यमंत्री बने रहे. 1999 के चुनावों में चंद्रबाबू की तेलुगू देशम को बहुमत मिला. इधर तेलंगाना मुद्दा अभी भी जीवित रहा. 1997 में बीजेपी ने तेलंगाना को मुद्दा बनाया और एक *मत, दो राज्य* के नारे को उछाल कर चुनाव लड़ा. 2001 में तेलंगाना आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) की स्थापना की. 2004 में टीआरएस ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और यह गठबंधन सत्ता में आ गया. वाई एस राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री बने.

2008 में अभिनेता चिरंजीवी ने प्रजाराज्यम पार्टी बनाई. इसके पहले लोकसत्ता आंदोलन चलाने वाले आईएएस अधिकारी जयप्रकाश नारायण ने 2006 में लोकसत्ता पार्टी का गठन किया. 2009 के चुनाव में वाईएसआर के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव जीता. इस चुनाव में चिरंजीवी की पार्टी को 16 प्रतिशत वोट मिले. टीआरएस ने वामपंथियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और इस गठबंधन को 7 प्रतिशत वोट मिले. लोकसत्ता पार्टी को भी एक प्रतिशत वोट मिले. इस चुनाव में मात खाए चंद्रशेखर राव ने 2009 में तेलंगाना मुद्दे को फिर से जीवित किया और आमरण अनशन पर बैठ गए, जिसके बाद केंद्र सरकार ने तेलंगाना के गठन के लिए क़दम उठाने की घोषणा की. सितंबर, 2009 में वाईएसआर की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई और उनके बेटे जगनमोहन रेड्डी ने कांग्रेस पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए वाईएसआर कांग्रेस का गठन किया.

इन सभी घटनाक्रमों से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश लगातार अलग राज्य की मांग को लेकर चले आंदोलनों का गवाह रहा है, लेकिन वहां की राजनीति अन्य राज्यों से अलग नहीं रही है. अब जबकि तेलंगाना का गठन हो गया है, उसका विरोध भी जारी है, वाईएसआर के बेटे जगनमोहन आय से अधिक संपत्ति मामले में 16 महीने तक जेल में रहकर बाहर आ गए हैं, ऐसी परिस्थितियों में राज्य का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, कहना मुश्किल है. ■

feedback@chauthiduniya.com

महिलाओं के कुशल नेतृत्व की नज़ीर

1. चंदा कोचर 2. नैना लाल किदवई 3. अर्चना भार्गव 4. शुभालक्ष्मी पनसे 5. शिखा शर्मा 6. विजयालक्ष्मी अय्यर 7. अरुंधति भट्टाचार्य

किसी समुदाय के पिछड़े होने की मुख्य वजह आर्थिक ही होती है. इस लिहाज से कारपोरेट सेक्टर में महिलाओं को बेहतर आर्थिकी के अवसर मुहैया कराता है. आज जब कॉरपोरेट लगातार मज़बूत हो रहा है, वह राजनीति को भी दिशा देने की स्थिति में पहुंच गया है, वहां पर महिलाओं के पहुंचने से निश्चित ही उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा. जिस समाज में सदियों से महिलाएं दोयम दर्जे की हैसियत से जीती आई हों, वहां पर उनके निर्णायक पदों पर पहुंचने और उद्योग-व्यापार नया आयाम देने जैसी भूमिकाएं काफ़ी आश्वस्तकारी हैं.

महिलाओं के बारे में अब अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी... जैसी पंक्तियां लिखने के दिन लद गए. अब यदि किसी तौर-तरीक़े से शौर्यगान की गुंजाइश बची हो, तो उन महिलाओं के कौशल के गीत गाए जाने चाहिए, जो न सिर्फ़ गिने-चुने पदों पर अपनी मेहनत और योग्यता के दम पर पहुंची हैं, बल्कि उद्यमिता के नये कीर्तिमान कायम कर रही हैं. यह देखकर सहज विश्वास नहीं होता कि देश के लगभग सभी बड़े बैंकों में शीर्ष पदों पर महिलाओं का परचम लहरा रहा है. यूं तो देश के निजी क्षेत्र की तमाम कंपनियों में महिलाएं ऊंचे पदों पर पहुंची हैं और कर्मठता की मिसाल पेश कर रही हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर ख़ास तौर से महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है.

हाल ही में यह एक बार फिर से साबित हुआ, जब अरुंधति भट्टाचार्य ने 207 साल पुरानी देश की सबसे बड़ी बैंकिंग सेवा भारतीय स्टेट बैंक की पहली महिला चेयरपर्सन बनीं. नवरात्र के माह में जब अरुंधति ने यह पद संभाला तो एक बार फिर से यह चर्चा छिड़ गई कि विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व की कमान महिलाओं को दी जानी चाहिए. अरुंधति भट्टाचार्य की एसबीआई प्रमुख के रूप में नियुक्ति महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण अध्याय है. यह पद संभालने के साथ ही उनके नाम के साथ कई रिकॉर्ड जुड़ गए. वे आगामी तीन वर्षों तक इस पद पर बने रहने का कीर्तिमान कायम करेंगी. साथ ही अरुंधति स्टेट बैंक की अब तक की सबसे कम उम्र की चेयरपर्सन भी हैं. अरुंधति से पहले प्रतीप चौधरी एसबीआई के चेयरपर्सन थे. उनके सेवानिवृत्त होने के बाद अरुंधति को यह जिम्मेदारी दी गई है. भारतीय स्टेट बैंक की चेयरपर्सन की कुर्सी संभालने वाली अरुंधति भट्टाचार्य इसी बैंक में 36 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही थीं. चेयरपर्सन बनने से पहले उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर और सीएफओ की ज़िम्मेदारियां संभालीं. 1977 में उन्होंने प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में एसबीआई में करियर शुरू किया था और इस दौरान वे धड़ल्ले से सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गईं. अरुंधति एसबीआई की सहयोगी कंपनी एसबीआई कैपिटल मार्केट्स की भी प्रमुख रह चुकी हैं. इसके अलावा वे एसबीआई की न्यूयॉर्क शाखा की भी कमान संभाल चुकी हैं.

इसी तरह हाल के वर्षों में कई निजी व सरकारी बैंकों में शीर्ष पद महिलाएं नियुक्त हुई हैं. निजी क्षेत्र के बैंक एचएसबीसी में नैना लाल किदवई, आईसीआईसीआई में चंदा कोचर और एक्सिस बैंक में शिखा शर्मा सर्वोच्च पद संभाल रही हैं. सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर ग़ौर करें तो शुभालक्ष्मी पनसे इलाहाबाद बैंक में चेयरपर्सन का पद संभाल रही हैं, जबकि विजयालक्ष्मी अय्यर बैंक ऑफ इंडिया की प्रमुख हैं. चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक में 1984 में एक ट्रेनी कर्मचारी के रूप में नौकरी शुरू की थी. महज दस सालों में ही वे कंपनी के एजीएम पद पर पहुंच गईं. फ़िलहाल वे 2009 से बैंक की सीईओ और एमडी का पद संभाल रही हैं. एचएसबीसी इंडिया की प्रमुख नैना लाल किदवई पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. वे फिलहाल फिक्की (भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ) की अध्यक्ष भी हैं. किदवई पहली भारतीय महिला हैं, जिन्होंने देश में किसी विदेशी बैंक का संचालन किया. 1982 में करियर की शुरुआत करने वाली नैना लाल किदवई कई बैंकों में अहम पदों की ज़िम्मेदारियां संभाल चुकी हैं. देश की तीसरे सबसे बड़ी बैंकिंग सेवा-एक्सिस बैंक को करिश्माई तरक्की के मुहाने पर पहुंचाने वाली शिखा शर्मा ने अपना करियर 1980 में आईसीआईसीआई बैंक से शुरू किया था. वे 26 सालों तक इसी बैंक में विभिन्न पदों पर रहीं. चंदा कोचर को बैंक का सीईओ बनाया गया, उस वक़्त शिखा की ओर से उन्हें तगड़ी दावेदारी मिली थी. हालांकि, उसी साल शिखा एक्सिस बैंक की प्रबंध निदेशक और सीईओ बनीं. बैंक ऑफ इंडिया की सीएमडी विजयालक्ष्मी ने 1975 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की थी. वे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक भी रह चुकी हैं. शुभालक्ष्मी पनसे 2012 में इलाहाबाद बैंक की सीएमडी बनीं. वे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कई पदों पर सेवाएं दे चुकी हैं. शुभालक्ष्मी विजया बैंक की कार्यकारी निदेशक भी रह चुकी हैं. उन्हें अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए कई पुरस्कार भी मिले हैं. बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की भारत में अध्यक्ष काकू नखाते इससे पहले जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी में वाइस चेयरपर्सन रह चुकी हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से एमएससी की डिग्री हासिल करने वाली अर्चना भार्गव बैंक ऑफ इंडिया की सीएमडी हैं. 1977 में उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में जीएम पद की जिम्मेदारी संभाली थी. अर्चना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट और फाइनेंसियल इनक्लूजन जैसे कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाएं दे चुकी हैं.

हालांकि, ऐसा कहा जाता है कि कॉरपोरेट सेक्टर ने विभिन्न तरीकों से महिलाओं के शोषण के नये दरवाज़े खोले हैं, लेकिन यह एक पक्ष हो सकता है. दूसरा पक्ष तो यह है कि महिलाओं को आर्थिक तौर पर मज़बूत स्थिति में पहुंचाने में कॉरपोरेट सेक्टर ने करिश्माई अवसर प्रदान किए हैं. हालांकि, यदि संख्या के लिहाज से देखा जाए तो अब भी स्थिति उतनी सुखद नहीं है. मार्च, 2012 में जारी ग्रांट थार्नटन इंटरनेशनल की बिजनेस रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय कंपनियों में शीर्ष पदों पर महिलाओं की उपस्थिति मात्र 14 प्रतिशत है, जबकि दुनिया भर में यह आंकड़ा 21 प्रतिशत है. इसके अलावा महिलाओं की भागीदारी को लेकर जो सुखद स्थिति बैंकिंग सेवाओं में है, यह अन्य सभी उद्योगों में नहीं है. ज़्यादातर में अभी भी शीर्ष पदों पर महिलाओं को तवज्जो नहीं दी जाती. बैंकिंग की तरह अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन संतोष की बात यह है कि यह भागीदारी साल-दर-साल लगातार बढ़ रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2011 में कंपनियों में महिलाओं की भागीदारी का यह आंकड़ा मात्र 9 प्रतिशत ही था.

चूंकि, किसी समुदाय के पिछड़े होने की मुख्य वजह आर्थिक ही होती है. इस लिहाज से कारपोरेट सेक्टर में महिलाओं को बेहतर आर्थिकी के अवसर मुहैया कराता है. आज जब कॉरपोरेट लगातार मज़बूत हो रहा है, वह राजनीति को भी दिशा देने की स्थिति में पहुंच गया है, वहां पर महिलाओं के पहुंचने से निश्चित ही उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा. जिस समाज में सदियों से महिलाएं दोयम दर्जे की हैसियत से जीती आई हों, वहां पर उनके निर्णायक पदों पर पहुंचने और उद्योग-व्यापार नया आयाम देने जैसी भूमिकाएं काफ़ी आश्वस्तकारी हैं. पिछले वर्ष कंपनी मामलों के मंत्री वीरप्पा मोइली ने कंपनियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें बड़ी ज़िम्मेदारियां दिए जाने की वकालत करते हुए कहा था कि जिन कंपनियों में शीर्ष पदों पर महिलाओं की भागीदारी बेहतर है, वहां पर आर्थिक निष्पादन बेहतर स्थिति में है. उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में महिलाएं उद्यमिता के नये अध्याय लिखेंगी और अन्य क्षेत्र की कंपनियों में भी बैंकिंग सेवाओं की तरह महिला नेतृत्व की नज़ीर कायम होगी. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

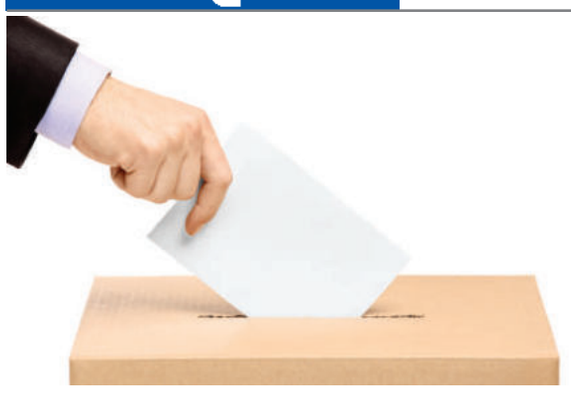

राहुल गांधी की जगदलपुर की शानदार रैली ज़रूर कांग्रेसियों में उत्साह पैदा करने वाली थी, लेकिन कर्मा की हत्या और अरविंद नेताम के पार्टी छोड़ने के बाद यहां कांग्रेस नेतृत्व संकट से जूझ रहा है. दिक्कत ये भी है कि दरभा के बाद कांग्रेस नेता बस्तर जाने से बचने लगे हैं. महंत जोगी और रवींद्र चौबे जैसे नेता तबके के बाद कभी सड़क से बस्तर नहीं गए. ये कांग्रेस के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि बस्तर की एकतरफा जीत ने ही कांग्रेस को दो बार सत्ता से दूर रखा है.

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव

कांग्रेस की कलह रमन सिंह की ताकत है

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव मुख्यत: कांग्रेस और भाजपा के बीच लड़ा जाना है. भाजपा नेतृत्व सही समय पर दिल्ली से उठकर रायपुर पहुंच गया. पार्टी ने टिकट भी बांट दिए और संगठित ढंग से राज्य में चुनाव प्रचार में जुट गई, जबकि कांग्रेस के साथ उल्टा हुआ. छत्तीसगढ़ कांग्रेस का राज्य नेतृत्व चुनावी तैयारियां करने की बजाय आपसी सिर फुटव्वल में उलझ कर झगड़ा सुलझाने के लिए दिल्ली पहुंच गया. अजित जोगी और चरणदास महंत अभी तक दिल्ली में डटे हुए हैं. दरभा में शीर्ष स्तर के कांग्रेसियों की हत्या से जो सहानुभूति उन्हें मिल सकती थी, वह उन्होंने आपसी कलह के कारण गवां दी है. अब कांग्रेस को फायदा तभी मिलेगा, जब भाजपा अपनी खूबियों से विफल हो जाए.

सुषमा गुप्ता

पांच राज्यों में सबसे पहले चुनाव त्तीसगढ़ में है. अगस्त में ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चरणदास महंत ने दावा किया था कि दो महीने पहले टिकट फाइनल हो जाएंगे, लेकिन आलम है कि एक महीने पहले तक भी कांग्रेस टिकटों का ऐलान नहीं कर पाई. टिकट को लेकर न जाने कितने दौर की बैठक चली, लेकिन महंत के सारे दावे टांय-टांय फिस्स हो गए. अब कांग्रेस नेतृत्व की दुविधा ये है कि वो इतने कम समय में टिकटें फाइनल करे या मैदान में उतरे.

कांग्रेस की राजनीति पूरी तरह दिल्ली शिफ्ट हो गई है. पहले आपसी सिर फुटव्वल और फिर टिकट को लेकर मारामारी में कांग्रेसी दिल्ली में डटे हैं. आलम ये है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता अब दिल्ली के ज़्यादा और छत्तीसगढ़ के कम लगने लगे हैं. प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और पार्टी के अंदर सबसे बड़े जनाधार वाले नेता अजीत जोगी 25 सितंबर से लगातार दिल्ली में हैं. वे दो बार रायपुर आए. पहली बार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शिरकत करने और दूसरी बार राहुल गांधी की सभा में. यही हाल प्रदेश अध्यक्ष का रहा. प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने के बाद वे रायपुर में डटे रहे, लेकिन वे बैठकों में ही व्यस्त रहे. रायपुर में बैठकों का सिलसिला खत्म हुआ तो टिकटों को लेकर दिल्ली में बैठकें शुरू हो गई. यही हाल विधानसभा में पार्टी के नेता रविंद्र चौबे, भूपेश बघेल, सत्यनारायण शर्मा, और धनेंद्र साहू का रहा, जो लगातार दिल्ली दौरों में व्यस्त रहे. नेताओं के दिल्ली परिक्रमा और आपसी खींचतान का सीधा असर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के जोश और मनोबल पर पड़ा. कार्यकर्ता मायूस हो गए. उलझनें बढ़ गईं. उसमें सत्ता परिवर्तन को लेकर कार्यकर्ता जोश से लबरेज थे. वे ठंडे और उत्साहविहीन नज़र आ रहे हैं.

दरअसल, छत्तीसगढ़ का चुनावी मुक़ाबला इस बार बेहद कठिन है. लिहाजा, मैदान में डटे रहना कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बेहद ज़रूरी था. इस बात को समझते हुए छत्तीसगढ़ से जुड़े बीजेपी के प्रभारी जेपी नड्डा और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह रायपुर में आ डटे. टिकट को लेकर मंथन और चिंतन यहीं चल रहा है. कार्यकर्ता बूथ स्तर पर डट गए और मुख्यमंत्री समेत तमाम नेता जनता के बीच. यानी बीजेपी में सबकुछ चुनाव के मद्देनज़र दिल्ली से रायपुर शिफ्ट हो गया. दूसरी तरफ कांग्रेस में ठीक उल्टा हुआ. शीर्ष नेताओं के दिल्ली दौरों, टिकट को लेकर मारामारी और गुटबाज़ी के चलते पार्टी नेतृत्व को दरभा के बाद थमी परिवर्तन यात्रा को रद्द करना पड़ा. दरभा के बाद पैदा हुई सहानुभूति को भुनाने के लिए कलश यात्रा शुरू की गई, लेकिन ये स्थानीय यातना ही बनकर रह गई.

टिकट को लेकर बीजेपी का हाल भी वही है, लेकिन बीजेपी के साथ अच्छी बात ये है कि रमन सिंह ने चुनावी घोषणा से पहले ही कम से कम डेढ़ बार प्रदेश नाप लिया. पहले विकास के ज़रिए, फिर लोकार्पण के ज़रिए. दूसरे नेता भी अपने अपने क्षेत्रों में डटे रहे. दूसरी तरफ चरणदास महंत अध्यक्ष बनने के बाद केवल बैठकों और गुटबाज़ी से निपटने में उलझे रहे. कुल मिलाकर जो मुकाबला कांटे का नज़र आ रहा था, वो ज़मीन पर बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है. कांग्रेस की आस अब पूरी तरह उनके प्रत्याशियों के प्रभाव और एंटी एनकंबेसी पर निर्भर है. हालात और नेताओं की व्यक्तिगत महात्वाकांक्षा पार्टी हितों पर इस कदर हावी हुए कि कुछ महीने पहले तक रमन सिंह की सरकार पर भारी नज़र आ रही कांग्रेस सत्ता की रेस में पिछड़ती नज़र आ रही है. हांलाकि बीजेपी विधायकों के ख़िलाफ़ असंतोष भी कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है.

दरअसल, छत्तीसगढ़ में पिछले छह महीने में राजनीति ने तेज़ी से कई दफे करवट बदली. छत्तीसगढ़ की राजनीति में 25 मई को बस्तर के दरभा में कांग्रेस नेताओं पर हुआ हमला टर्निंग प्वॉइंट साबित हुआ. 25 मई तक मुकाबला बराबरी का नज़र आ रहा था. एक तरफ रमन सिंह का काम था तो दूसरी तरफ उनकी सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ कांग्रेस मैदान में डटी थी. कांग्रेस के पास मुद्दों की भरमार थी. बालकों को जमीन देने का मामला हो या मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कृपापात्र लोगों को राज्य की खदानें देने का मामला या मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप, सभी मुद्दों पर बीजेपी ने सरकार के ख़िलाफ़ बेहद आक्रामक रवैया अख़्तियार किया था. अनुशानविहीनता और गुटबाज़ी के लिए बदनाम कांग्रेस को सिर्फ़ दो साल में स्व. नंदकुमार पटेल ने अनुशासित बना दिया था. गुटबाज़ी को ख़त्म करके नेताओं को सिखा दिया था कि पार्टी में उन्हीं की जगह होगी, जो काम करेगा. जोगी को छोड़कर पार्टी में सब गुट ख़त्म हो गए थे. जनता को ये संदेश मिल रहा था कि जोगी के बिना भी कांग्रेस पार्टी आक्रामक और असरदार तरीके से आगे बढ़ सकती है. राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद तक ये मान चुके थे कि छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने की गुंज़ाइश सबसे ज़्यादा है. आलम ये था कि बीके हरिप्रसाद दिल्ली में कम और छत्तीसगढ़ में ज़्यादा नज़र आते थे. बस्तर के झलियामारी में आदिवासी हॉस्टल में नाबालिगों के साथ रेप के मामले पर कांग्रेस ने सरकार को ऐसा घेरा कि रमन सिंह ख़ुद असहाय नज़र आने लगे.

जब चुनाव करीब आया तो रमन सिंह ने एक तरफ विकास यात्रा शुरू की. दूसरी तरफ नंदकुमार पटेल ने परिवर्तन यात्रा. दोनों अपनी-अपनी यात्राओं के ज़रिए जनता के बीच जा रहे थे, लेकिन तभी 25 मई को नक्सलियों ने दरभा में कांग्रेस के क़ाफ़िले पर हमला बोल दिया. नदंकुमार पटेल, वीसी शुक्ल, महेंद कर्मा की हत्या कर दी गई. कांग्रेस की एक पंक्ति की पूरी लीडरशिप ख़त्म हो गई. इस घटना के विरोध में जिस तरीके से प्रदेश में उबाल आया, उससे लगा कि सहानुभूति की लहर पर सवार होकर कांग्रेस रमन सिंह सकार को उखाड़ फेकेंगी. दरभा के बाद चरणदास महंत को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया. पहला महीना शोकाकुल माहौल और पार्टी को संभालने में लग लगा. दरभा कांड के मद्देनज़र महंत ने शहीद कांग्रेस नेताओं के इलाके से कलश यात्रा निकालने का फ़ैसला किया गया. दरभा से ही परिवर्तन यात्रा फिर से शुरू करने की घोषणा की गई. यहां तक माहौल पूरी तरह कांग्रेस के साथ था, लेकिन हुआ ठीक उल्टा. दरभा हमले के बाद कांग्रेस के पास एक बड़ा मुद्दा हाथ में आ गया, लेकिन इसके बाद गुटबाजी और टिकट को लेकर मारामारी ने इन मुद्दों की धार कुंठा कर दी. जोगी चरणदास महंत को अध्यक्ष बनाए जाने से ख़फ़ा थे. खुलकर महंत के ख़िलाफ़ आ गए. शुरुआत शोकसभा में ही हो गई. जब जोगी ने सबके सामने महंत का हाथ झटक दिया. फिर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह को सार्वजनिक तौर से बाहरी बताकर उनके शागिर्द महंत पर दोहरा वार किया, लेकिन ये शुरुआत भर थी.

इसके बाद जोगी पहले दिल्ली गए. आदिवासी नेतृत्व की मांग को लेकर दिल्ली में डेरा डाला. विधायकों को जुटाने की कोशिश की, लेकिन जोगी की कोशिशों के बाद भी विधायक नहीं जुटे. आलाकमान जोगी के दबाव में नहीं आया तो जोगी रायपुर आ गए. इसके बाद जोगी ने इफ्तार पार्टी और भझिया पार्टी रखी. शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी तो बगावती तेवर के साथ पार्टी के नेताओं के ख़िलाफ़ आ गए. छत्तीसगढ़ में सतनामी संप्रदाय के लिए पूजनीय मिनी माता की जंयती पर जोगी ने अपने तमाम विरोधियों के क्षेत्र में जाकर उनके ख़िलाफ़ सभाएं कीं. भूपेश बघेल, धनेंद्र साहू, सौरभ सिंह, नोबल वर्मा, रुद्रगुरु, राजकमल सिंघानिया, सबने जोगी की शिकायत की. कहा जाने लगा कि जोगी की पार्टी से विदाई तय है.

अपने समर्थकों के साथ दिल्ली पहुंचे जोगी की तीसरे मोर्चे के नेताओं के साथ मुलाक़ात भी शुरू हो गई, लेकिन तमाम कवायद के बीच अचानक अजीत जोगी ने दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से मुलाक़ात के बाद अपना इरादा बदल दिया. नाटकीय घटनाक्रम में रायपुर में बीके हरिप्रसाद जोगी से मिलने पहुंच गए. इसके बाद जोगी और महंत के बीच डिनर डिप्लोमेसी हुई और जोगी की वापसी की चर्चा पर विराम लग गया. लेकिन जोगी और संगठन के विवाद में कांग्रेस ने चुनाव से पहले के अहम तीन महीने गंवा दिए. नेता एक-दूसरे की शिकायत लेकर दिल्ली आते-जाते रहे और जोगी अपनी उपेक्षा की शिकायत और ज़ोर-आज़माइश करते रहे. विवाद का असर कांग्रेस की ज़मीनी तैयारियों पर पड़ा. पहले परिवर्तन यात्रा रद्द करनी पड़ी. गुटबाज़ी के बीच कलश यात्रा चली तो वो कब शुरू हुई, कब ख़त्म, किसी को पता भी नहीं चला. कुल मिलाकर कांग्रेस इस दौरान मैदान से पूरी तरह बाहर रही. पार्टी ने इस दौरान दरभा से पैदा हुए सहानुभूति को गंवा दिया. जो जोश और गुस्सा कार्यकर्ताओं में था, वो भी ठंडा पड़ गया. जोगी खेमे के कार्यकर्ता इस बात को लेकर उलझन में रहे कि नई पार्टी में काम करना है या कांग्रेस में ही रहना है. दूसरी तरफ संगठन खेमा इस इंतज़ार में रहा कि जोगी जाएं तो वे खुलकर मैदान में आएं. दूसरी तरफ रमन सिंह ने अपनी विकास यात्रा पूरी कर ली. इस बीच कांग्रेस नेताओं ने परिवर्तन यात्राओं के बाद अलग-अलग सम्मेलन ज़रूर आयोजित किए, लेकिन ये आयोजन वीकएंड पर होने वाले पिकनिक की तरह लगे. जो माहौल एक सम्मेलन से पैदा हुआ, वो अगले दिन के ख़ालीपन से ख़त्म हो गया. इसके अलावा इसका प्रभाव भी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहा.

हालांकि, राहुल गांधी की जगदलपुर की शानदार रैली ज़रूर कांग्रेसियों में उत्साह पैदा करने वाली थी, लेकिन कर्मा की हत्या और अरविंद नेताम के पार्टी छोड़ने के बाद यहां कांग्रेस नेतृत्व से जूझ रहा है. दिक्कत ये भी है कि दरभा के बाद कांग्रेस नेता बस्तर जाने से बचने लगे हैं. महंत जोगी और रवींद्र चौबे जैसे नेता तबके के बाद कभी सड़क से बस्तर नहीं गए. ये कांग्रेस के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि बस्तर के एकतरफ़ा जनादेश ने ही कांग्रेस को दो बार सत्ता से दूर रखा है. कांग्रेस के नेता अगर बस्तर जाने से बचते रहेंगे तो ये बीजेपी के लिए वॉकओवर देने जैसा होगा. चरणदास महंत की कार्यशैली भी इसके लिए कम ज़िम्मेदार नहीं है. नंदकुमार पटेल की विरासत ज़रूर महंत ने संभाली, लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ा पाए. उनके नेतृत्व में आक्रामकता की कमी कार्यकर्ताओं को ख़ूब खली. उन्होंने आंसू तो बख़ूबी पोछे, लेकिन कार्यकर्ताओं के जोश को गरम नहीं रख पाए. हमेशा चार चंगू-मंगू से घिरे रहने वाले महंत ने सबसे बड़ी ग़लती मैदान में न उतरकर की है. एक आम कार्यकर्त्ता की उन तक पहुंच न होना भी उनके ख़िलाफ़ जाता है.

महंत अध्यक्ष बनने के बाद बैठकों में इस कदर मशगूल रहे कि सड़क पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर पाए. हांलाकि उन्होंने पदभार विषम परिस्थियों में संभाला. जोगी द्वारा दो बार निपटने का कटु अनुभव उनके पास है.

लिहाजा, वे फूंक-फूंककर क़दम उठा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से क्रिकेट के आख़िरी ओवर में हर गेंद पर रन बनाने वाले बल्लेबाज़ की ज़रूरत होती है, महंत उसमें फिट नज़र नहीं आए. हालांकि जोगी को इस बार जिस चतुराई से उन्होंने किनारे लगाया है, वो उनका कौशल माना जाएगा, लेकिन चरणदास महंत का असली इम्तिहान चुनाव में होगा. वे या तो हाशिए पर चले जाएंगे, वर्ना जोगी ये साबित करेंगे कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में उनका विकल्प कोई नहीं. ■

feedback@chauthiduniya.com

छत्तीसगढ़ का चुनावी मुक़ाबला इस बार बेहद कठिन है. लिहाज़ा, मैदान में डटे रहना कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बेहद ज़रूरी था. इस बात को समझते हुए छत्तीसगढ़ से जुड़े बीजेपी के प्रभारी जेपी नड्डा और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह रायपुर में आ डटे. टिकट को लेकर मंथन और चिंतन यहीं चल रहा है. कार्यकर्ता बूथ स्तर पर डट गए और मुख्यमंत्री समेत तमाम नेता जनता के बीच. यानी बीजेपी में सबकुछ चुनाव के मद्देनज़र दिल्ली से रायपुर शिफ्ट हो गया.

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

राजनेताओं को अपनी छवि सुधारने की ज़रूरत है

राहुल गांधी ने अपराधियों को संरक्षण देने वाले अध्यादेश को फाड़कर फेंक देने की बात आम जनता को भ्रष्टचार मुक्त समाज देने के लिए की या इसके पीछे उनका अपना कोई मक़सद है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को पलटने के लिए राजनीतिक दलों ने अध्यादेश जारी कर दिया, जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय राजनीतिक माहौल को स्वस्थ बनाना चाहता था, यह एक ग़लत क़दम था.

देशभर में राजनेता एक बार फिर अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और उनके ख़िलाफ़ की जा रही कार्रवाइयों को लेकर ख़बरों में हैं. सत्रह वर्ष पुराने एक मामले में लालू प्रसाद यादव को झारखंड के एक न्यायालय ने सज़ा सुनाई है. दूसरी तरफ़ मुलायम सिंह यादव और मायावती को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी. ये सभी प्रकरण एक बार फिर से अन्ना हजारे की उस मांग को सही ठहराते हैं, जिसके तहत वे कहते हैं कि सत्ता के हाथों में केंद्रित भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी की आवश्यकता है. इससे निपटने के लिए उन्होंने लोकपाल बनाने का सुझाव दिया था, जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी या उनके पहले से ही लंबित चला आ रहा है. हमेशा की तरह यह सरकार भी इस मसले को टालती रही और अभी तक कोई हल नहीं निकला. दिन-ब-दिन बढ़ रहे घोटालों के बाद देश की जनता का विश्वास राजनीतिक संस्थाओं के प्रति कमज़ोर हो रहा है. इसे दोबारा से हासिल करने की ज़रूरत है. इसलिए यह ज़रूरी है कि इस विश्वास को हासिल करने के लिए एक मैकेनिज़्म बनाया जाए. इसके लिए सबसे अच्छा विचार तो यह है कि इसकी शुरुआत लोकपाल से की जाए और इस व्यवस्था के साथ जैसा कि अन्ना हजारे ने मांग की है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को इसके भीतर लाया जाए, जिनकी संख्या लाखों में होगी. अगर लोकपाल की शुरुआत केवल मंत्रियों के लिए ही की जाती है, तब भी लोगों के भरोसे को फिर से हासिल करने के लिए यह शुरुआती प्रयास तो साबित होगा ही, बशर्ते वह लोकपाल सत्तारूढ़ सरकार के प्रति उत्तरदायी न होकर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रति जवाबदेह हो. अगर आय से अधिक संपत्ति का मसला है, तो सीबीआई को भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीबीआई के पास ऐसा कोई भी मैकेनिज़्म या ज़रिया नहीं है, जिससे वह सही ढंग से जांच कर पाए.

सरकार चाहे कुछ भी दावा करे, सच्चाई तो यह है कि सीबीआई के अधिकारी भी पुलिसकर्मी ही हैं, जो कई बार संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार से प्रभावित होकर यानी उनके दबाव में काम करते हैं. अगर सीबीआई को स्वायत्त संस्था नहीं बनाया जा सकता, जिसके कि समर्थन और विरोध में भी तर्क दिया जा सकता है, तो सबसे बेहतर यह होगा कि लोकपाल केवल केंद्रीय स्तर या राज्य स्तर के मंत्रियों के लिए बनाया जाए. इनकी संख्या तकरीबन एक हज़ार से अधिक या उससे भी कम होगी, लेकिन इस स्थिति में लोकपाल को सभी मामलों की जांच करनी चाहिए और किसी भी मामले को सीबीसी, सीबीआई या अन्य किसी संस्था के पास नहीं भेजना चाहिए. जो शिकायतें जनलोकपाल के संज्ञान में लाई जाएं, उनका भी एक पैमाना होना चाहिए, क्योंकि एक-एक व्यक्ति की शिकायतों का निपटारा कर पाना संभव नहीं है और ऐसे में काम कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगा. अगर शिकायत जायज़ है, तब लोकपाल इसे संज्ञान में लेकर उस पर जांच बैठा सकता है. जांच के नतीजे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखे जाएंगे और संबंधित सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे. इस तरह से गठित लोकपाल का दफ्तर दिल्ली में हो सकता है, जो अपने आप में संपूर्ण होगा और उसके पास वही शक्तियां होंगी, जो कि न्यायालय के पास होती हैं. लोकपाल को पुलिस अधिकारियों का भी सहयोग मिलना चाहिए, लेकिन इनमें वे अधिकारी शामिल नहीं होने चाहिए, जो राज्य के अपने वरिष्ठ को रिपोर्ट करते हों, सीबीआई को रिपोर्ट करते हों या किसी अन्य राजनीतिक संस्था के प्रति जवाबदेह हों.

यह एक नया प्रयोग होगा. नई समस्याओं के लिए नये निदान की ज़रूरत होती है. हम उस दौर में रह रहे हैं, जिसमें राजनेता काफ़ी ताक़तवर हैं. ऐसे में यह कहना ग़लत होगा कि अगर हम चाहें तो उन्हें अपने बीच से हटा सकते हैं. उनके समर्थन में एक बड़ा वोट बैंक है, जिसके चलते वे फिर से सत्ता में आ सकते हैं. कुछ तो सत्ता में पहले से ही काबिज हैं, कुछ दोबारा सत्ता में आ सकते हैं. इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि जो जनप्रतिनिधि अभी जनता के समक्ष हैं, वे किसी भी संदेह से परे हों. राहुल गांधी ने अपराधियों को संरक्षण देने वाले अध्यादेश को फाड़कर फेंक देने की बात आम जनता को भ्रष्टचार मुक्त समाज देने के लिए की या इसके पीछे उनका अपना कोई मक़सद है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को पलटने के लिए राजनीतिक दलों ने अध्यादेश जारी कर दिया, जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय राजनीतिक माहौल को स्वस्थ बनाना चाहता था, यह एक ग़लत क़दम था.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भी एक सवालिया निशान है. कोर्ट के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति आरोपी साबित हो जाता है, तो वह अयोग्य साबित हो जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि आरोप किसके द्वारा साबित किया गया है. अगर निर्णय निचले न्यायालयों का है, तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि निर्णय ग़लत हो सकता है, क्योंकि निचले न्यायालयों की न्यायप्रणाली पर सवालिया निशान लगते रहे हैं. निचली न्यायपालिका किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है. वह केवल अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह है. इसलिए हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विपक्षी दल के किसी विधायक के ऊपर बेबुनियादी इल्ज़ाम लगाकर उन्हें अपराधी साबित कराकर जेल भिजवा दें. इससे उस विधायक का राजनीतिक करियर ख़त्म हो जाएगा.

यह सब कुछ उच्च न्यायालय के स्तर पर होना चाहिए. इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में संशोधन की आवश्यकता है और यह संशोधन है कि अगर हाईकोर्ट ने किसी को आरोपी साबित किया है, तब उसे पद से बेदख़ल किया जाए, न कि निचली अदालतों के निर्णय के आधार पर.

यह कुछ आवश्यक क़दम उठाए जाने की ज़रूरत है. आगामी लोकसभा चुनाव में अभी भी छह महीने का वक़्त है. अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापस आना चाहती है, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस आना चाहती है, तो इन पार्टियों को यह मुद्दे उठाने चाहिए. एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए और अगर कोई भी पार्टी इन संशोधनों के ख़िलाफ़ जाती है, तो वह जनता की निगाह में अपने आप गिर जाएगी. समय आ गया है कि राजनेता अपनी छवि सुधारें, जिससे कि लोगों की नज़रों में उनकी छवि एक नैतिक व्यक्ति के रूप में और बढ़े. साथ ही उनके अधीन काम कर रहे नौकरशाहों के मन में उस नेता के प्रति भय हो. बजाए इसके, जिस तरह से मौजूदा समय में हर कोई एक-दूसरे से लाभ उठाने की कोशिश में लगा हुआ है. ■

feedback@chauthiduniya.com

कला अकादमियां सरकारी कठपुतली बन गई हैं

ठाकुर दास बंग

यह संतोष की बात है कि लेखकों, पत्रकारों, न्यायविदों, कलाकारों तथा अन्य लोगों में ऐसे लोग हैं, जिन्होंने अपने सिद्धांतों की निर्भीकता से रक्षा की है. ऐसे अधिकारी भी हैं, जिन्होंने तमाम तरह से सताए जाने के बावजूद अपनी कर्तव्यनिष्ठा नहीं छोड़ी है. बहुसंख्यक जज ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता त्यागने से इन्कार किया तथा ऐसे पत्रकार हैं, जिन्होंने सत्य की खोज और उसका प्रसारण जारी रखा है. ऐसे युवा भी हैं, जो जनता को जगाने और उन्हें शक्ति देने के लिए उनके बीच गए हैं और ये सभी लोग मिलकर राष्ट्र की नैतिक मेरुदंड का निर्माण करते हैं.

ध्यान देने की बात है कि साहित्य, ललितकला और संगीत नाटक अकादमियां, जिन्हें लेखकों, कलाकारों, नाटककारों और अभिनेताओं का गैर-सरकारी व स्वायत्त संगठन होना चाहिए था, वे मंत्रालयों व विभागों की वास्तविक कठपुतलियां बन गई हैं. रेडक्रास सोसायटी नामक अंतरराष्ट्रीय संगठन भी इस देश में व्यवहारत: एक सरकारी विभाग है. यह चीज़ तो अंग्रेज़ी शासनकाल से चली आ रही है, लेकिन अकादमियों की स्थापना तो स्वतंत्रता के बाद साम्यवादी देशों के नमूने पर हुई थी.

हम उस विंदु पर आ गए हैं, जहां लोगों के अधिकारों को नियंत्रित रखने और सत्तावादी प्रवृतियों को मज़बूत करने के लिए चुपके से किए गए प्रयास और क़ानून, नियम तथा कार्यविधि में परिवर्तन की हर छोटी से छोटी कोशिश के संबंध में हमें सतर्क रहना होगा. पिछले वर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालयों की व्यवस्था से संबंधित अधिनियम में एक संशोधन लोकसभा में पेश किया गया. इसने राजनयिकों ध्यान आकर्षित नहीं किया, डॉ. मैलकम आदिशेशिया और डॉ. स्वरूप सिंह, क्रम से मद्रास व दिल्ली विश्वविद्यालयों के भूतपूर्व वाइसचांसलरों की दृष्टि इस पर पड़ी और उन्होंने कहा कि यदि यह विधेयक स्वीकृत हो गया तो यह केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त कर उन्हें राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बना देगा.

संभव है कुछ लोग इन काले कारनामों की सूची पर अपनी प्रतिक्रिया यह कहकर व्यक्त करेंगे कि चांद में भी धब्बे होते हैं और किसी चीज़ में सिर्फ़ दोष देखने की प्रवृत्ति एकांगी मानसिकता की परिचायक है.

हम काफ़ी राहत महसूस करते और ख़ुश होते, यदि ऊपर गिनाई गई बातें एक-दूसरे से असंबद्ध, अलग-अलग होतीं, जिनके लिए साधारण कर्मचारियों या संयोग को ज़िम्मेदार ठहराया जाता. लेकिन तथ्य स्वयं यह बता रहे हैं कि नीतियों, क्रियाओं और घटनाओं की श्रृखंला के लिए कार्य-कारण का एक ही स्रोत सक्रिय है. यह याद रखना चाहिए कि आज सारी राजनीतिक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में केंद्रित है और सारे प्रशासन में बिना उनकी इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता. ख़तरा तो इस बात में निहित है कि ऊपर वर्णित हर चाल एक मास्टर प्लान का ही अंग है.

भारतीय लोगों की आज़ादी के प्रति यह ख़तरा दूर किया सकता है, यदि लोग अपनी उदासीनता और प्रमाद त्याग दें और स्थिति के सुधार के लिए अपनी शक्ति लगाएं. लोगों में यह जागरूकता पैदा की जा सकती है यदि ऐसे काफ़ी व्यक्ति हों जो प्रवाह के साथ न बहें, बल्कि परिणामों की चिंता किए बगैर अपना अंतर्विवेकपूर्ण आधार सामने रखें. यह गहरे संतोष की बात है कि ऐसे व्यक्ति हैं. लेखकों, पत्रकारों, न्यायविदों, कलाकारों तथा अन्य लोगों में ऐसे लोग हैं, जिन्होंने अपने सिद्धांतों की निर्भीकता से रक्षा की है.

ऐसे सरकारी अधिकारी भी हैं, जिन्होंने तमाम तरह से सताए जाने के बावजूद अपनी कर्तव्यनिष्ठा नहीं छोड़ी है. अभी बहुसंख्यक जज ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता त्यागने से इन्कार किया है तथा ऐसे पत्रकार हैं, जिन्होंने सत्य की खोज और उसका प्रसारण जारी रखा है. ऐसे युवा भी हैं, जो जनता को जगाने और उन्हें शक्ति देने के लिए उनके बीच गए हैं और ये सभी लोग मिलकर राष्ट्र की नैतिक मेरुदंड का निर्माण करते हैं. इनमें से कइयों ने राष्ट्र के नाम उस अपील से सहमति व्यक्त की है जो स्वराज संगम के कार्यक्रम का आधार है. आज देश के सामने जो ख़तरा है उससे उसे बचाने के लिए कर्त्तव्यनिष्ठा वाले ऐसे सभी स्त्री-पुरुषों के सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है.

देश की स्थिति की इस समीक्षा के संबंध में कुछ रुचिकर प्रश्न पूछे गए हैं, जिन्हें समझने की ज़रूरत है. हम उन पर संक्षिप्त में निम्नांकित रूप में विचार कर रहे हैं.

प्रश्न : संसदीय लोकतंत्र का वर्तमान स्वरूप जो हमारे यहां है, वास्तव में लोगों को उसमें भागीदार नहीं बनने देता. संविधान इसे केवल वैधता प्रदान करता है. हमें इस व्यवस्था को आमूल बदलने का प्रयास करना ही चाहिए. जिस व्यवस्था को हम बदलने ही जा रहे हैं, उसमें यदि कुछ ख़राबियां आ गई हैं तो हमें चिंता क्यों?

उत्तर : संसदीय लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रताएं लोगों को धोखा देने के लिए बुजुर्वा (मध्यवर्गीय) की चालें नहीं हैं, जैसा कि मार्क्सवादी लोगों की कुछ श्रेणियां तथा अन्य हमें बताते हैं, बल्कि अपनी नियति पर अपना नियंत्रण रखने के लोगों के प्रयास की ही फलश्रुति हैं, जैसा कि अंग्रेजी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी स्वातंत्र्य युद्ध तथा छोटे-बड़े अन्य अनेक आंदोलनों में समाहित है. हमारा स्वतंत्रता-संग्राम भी इसी प्रकार का एक अंग है. सारी दुनिया में लोग अभी अपनी नियति पर वास्तविक नियत्रंण से दूर हैं, लेकिन लोकतांत्रिक देशों के लोगों ने मौलिक अधिकारों और बालिग मताधिकार के द्वारा एक प्रतिनिधि सरकार चुनने के अधिकार के माध्यम से इस व्यवस्था में निश्चित ही काफी मज़बूत पकड़ बना ली है. ये आधार ऐसे हैं जो खोए नहीं जा सकते, बल्कि अंतिम विजय के लिए उनका विस्तार और उनकी शक्तिवृद्धि होनी चाहिए.

इसके अतिरिक्त, तानाशाही लादने के प्रयास में उन मूल्यों को नष्ट करने का प्रयास भी मिला हुआ है जो सत्य और अहिंसा के आधार पर उस नई समाज-व्यवस्था के निर्माण के लिए अत्यावश्यक हैं, जिसके लिए हम प्रयत्नशील हैं. संसदीय लोकतंत्र, उसकी चाहे जो कमियां हों, इन्हीं मूल्यों में से कुछ को महत्व प्रदान करता है. जब लोग इसे स्वाभाविक मानने लगें कि नेता झूठ बोलें और जनता का पैसा अपने ऊपर बर्बाद करें, यह कि अपना वोट बेचना समझदारी है, विधायक अपने को सबसे ऊंची बोली बोलने वाले के हाथ बेचें, जज लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अच्छा लगने वाला निर्णय ही दें और यह कि ऐसी व्यवस्था के आलोचकों का ही दोष है यदि उनकी हत्या कर दी जाए, तब तो वह कोई निपट मूर्ख ही होगा, जो यह मानेगा कि ऐसे लोगों से कोई क्रांति होगी और एक नई समाज-व्यवस्था का निर्माण होगा. लोगों के मानसिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष यहीं और अभी होना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

भगवान ने कहा अलविदा

सचिन ने लगातार 24 वर्ष तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने के बाद आख़िर क्रिकेट को अलविदा कह ही दिया. सचिन बीसीसीआई अध्यक्ष को मेल के ज़रिए बता दिया किया 200वां टेस्ट मैच उनका आख़िरी मैच होगा. तेंदुलकर ने जिस प्रकार खेलते हुए नई उचाइयों को छुआ, वह उनकी प्रतिभा, मेहनत लगन को दर्शाता है. जहां खिलाड़ी चार-पांच वर्ष खेलने बाद थका महसूस करने लगते हैं, वही सचिन ने 24 वर्ष तक खेलते ही नहीं रहे, बल्कि उन्होंने इन वर्षों में कई अद्भुत रिकार्ड बनाए. सचिन ने क्रिकेट में नए रिकार्ड बनाने के साथ ही अपने प्रशंसकों को अपने खेल से ऐसा मंत्रमुग्ध किया कि वह उन्हें क्रिकेट का भगवान मानने लगे. सचिन ने क्रिकेट में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल करने बाद भी हमेशा विनम्र ही रहे. सचिन ने भारत को क्रिकेट में नए रिकार्ड तक पहुंचाया है. सचिन ने अपने शानदार करियर में काफी उतार-चढ़ाव भी देखे हैं, लेकिन सचिन को एक महानतम खिलाड़ी के रूप में याद किया जाएगा.

-सुरेश, सासाराम

कांग्रेस की यही परंपरा है

पिछले दिनों जिस प्रकार राहुल गांधी ने दागी नेताओं को बचाने वाले अध्यादेश को बकवास करार दिया और यह साबित कर दिया कि वह प्रधानमंत्री को कुछ नहीं समझते. उस अध्यादेश को उनकी ही सरकार के द्वारा लाया गया था. जिस कैबिनेट मीटिंग में अध्यादेश गया था, उसमें यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल थीं. जब भाजपा ने इसका विरोध किया और लोगों ने इस विधेयक को लेकर अपना विरोध जताया. तब अचानक राहुल गांधी विधेयक पास होने के एक महीने बाद याद आया कि यह बकवास है. कांग्रेस की यह पहले से ही परंपरा रही है केंद्र या राज्य में उसकी सरकार द्वारा जो भी अच्छी योजना लागू की जाती है, उसका श्रेय प्रथम परिवार को दिया जाता है अन्यथा जब कोई बकवास काम हो जाता है तो उसे सरकार या पार्टी के मत्थे मढ़ दिया जाता है. राहुल गांधी ने भी यही पहले उनकी पार्टी की अगुआई वाली सरकार लालू यादव को बचाने के लिए यह विधेयक लेकर, लेकिन बाद में जब कांग्रेस के प्रथम परिवार पर आंच आई तो यह विधेयक बकवास हो गया. अभी तक तो लोग केवल कहते थे कि सरकार और प्रधानमंत्री राहुल और सोनिया के इशारे पर चलते हैं, लेकिन और राहुल के विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री की पगड़ी उछालने के बाद यह साफ हो गया है कि सरकार मां बेटे के इशारे ही चलती है.

-कृष्णकुमार, लखनऊ

बेबाक समाचार पत्र

चौथी दुनिया पत्र पहले हमें प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन अब पिछले एक माह से पढ़ रहा हूं. जब से मैं पढ़ रहा हूं, तब से देख रहा हूं कि चौथी दुनिया लगातार बेबाक और तथ्यों पर आधारित ख़बरें लिखता आ रहा है. आपका और आपके सभी लेखकों का धन्यवाद. इंडियन एक्सप्रेस द्वारा झूठी खबरें जैसा कि चौथी दुनिया में अंकित है, देशद्रोह नहीं हुआ तो देश द्रोह का खुल्लम खुल्ला प्रयास है. रात को महात्मा गांधी जी, राजघाट पर अपनी समाधि पर रोते होंगे और शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सहदेव, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जरूर सोचते होंगे कि हम शहीद हुए, और देश के गद्दार देश को लूट रहे हैं. नहीं मालूम था कि घोटालेबाज तिजोरी भरेंगे व अपनी धरती पर अपनी नाक खुद कटवाएंगे. नेताओं को देश के लिए कुरबान हुए शहीदों के सम्मान के लिए और देश के लिए तो कम-से-कम देश को बर्बाद न करें.

-राजिंदर कुमार उप्पल, दिल्ली

वोटों की ख़ातिर

राहुल गांधी ने रामपुर में हुई रैली में कहा कि मुज़फ़्फ़रनगर दंगे नेताओं ने कराए. राहुल गांधी ने कोई रहस्योद्घाटन नहीं किया. जनता सब जानती है कि दंगे सियासी फ़ायदे के लिए ही कराए जाते हैं, लेकिन राहुल को यह भी बताना चाहिए था कि दंगे किसने कराए और दंगों से किसे फायदा होगा. दंगे होंगे तो कौन बदनाम होगा और किसे वोटों का फ़ायदा होगा. राजनीतिक लोग ही दंगे कराते हैं और लोगों के बीच वोटों की ख़ातिर जाति और मजहब का भेद पैदा करते हैं. यह साफ है कि सियासी दख़ल के बाद ही दंगे भड़के और एक टीवी चैनल के स्टिंग आपरेशन में पुलिस अधिकारियों ने यह बताया है कि सपा के मंत्री आंजम खां ने दंगे रोकने से पुसिल को रोका. इससे साफ है कि वोटों के लिए ही दंगे कराए गए और नेताओं को चाहिए कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की बजाय ऐसी हरकतों से बाज आएं.

-राजीव प्रसाद सिंह, बलिया

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

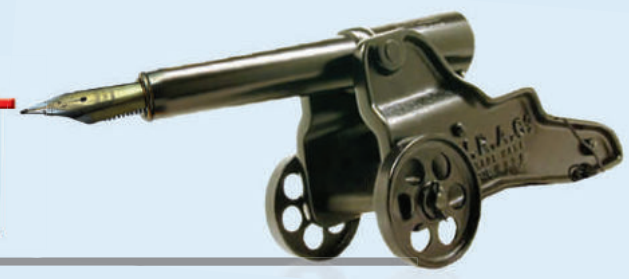

यह पहल लोकतंत्र को मज़बूत करेगी

क्या सुप्रीम कोर्ट यह भी तय करे कि अगर नाली बनानी है, तो नाली का आकार क्या होगा? ईंटें कहां से आएंगी? सीमेंट कहां से आएगा? या फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नाली यहां पर बननी चाहिए, तो उसे क्रियान्वित करने का काम उनका होगा, जिनके ऊपर इसकी ज़िम्मेदारी है? सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ़ सैद्धांतिक फ़ैसला करना होता है. उसे क्रियान्वित करने का काम सरकार का या जिससे संबंधित वह फ़ैसला होता है, उस संस्था का होता है. अफ़सोस की बात है कि यही नहीं हो रहा है.

श्री अन्ना हजारे ने सारे देश में चुनाव सुधारों के लिए कैंपेन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो उन उम्मीदवारों को नकार दे, जो उम्मीदवार लोकसभा या विधानसभाओं के योग्य नहीं हैं. योग्य से मतलब है कि अगर वे अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, सजायाफ़्ता हैं या दाग़ी हैं, तो उन्हें विधानसभा या लोकसभा में नहीं जाना चाहिए. सारे देश में अन्ना के इस सुझाव का ज़ोरदार स्वागत हुआ कि चुनाव आयोग को वोटिंग मशीन में आख़िरी लाल बटन बनाना चाहिए, जिसके माध्यम से जनता यह तय करे कि यदि उसे कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है, तो वह उस लाल बटन को दबा दे. इसका मतलब दलीय या निर्दलीय उम्मीदवार, जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले हों और यदि उससे ज़्यादा वोट जनता लाल बटन दबाकर नापसंदगी वाले खाते में डाल दे, तो वो चुनाव कैंसिल हो जाएगा. अन्ना का यह भी कहना है कि ऐसी स्थिति में दोबारा चुनाव हों और जिन उम्मीदवारों को जनता नकार चुकी है, उन उम्मीदवारों को अगली बार खड़े होने की अनुमति न मिले. अन्ना के ये सुझाव देश भर के लोगों द्वारा समर्थित हैं.

हर्ष का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट ने सैद्धांतिक रूप से यह मान लिया है कि इसी चुनाव में राइट टू रिजेक्ट का इस्तेमाल किया जाए. यानी जनता को यह अधिकार हो कि उसे अगर कोई भी उम्मीदवार पसंद न हो तो आख़िरी लाल बटन दबाकर नापसंदगी की मुहर लगा दे. सुप्रीम कोर्ट का यह सैद्धांतिक फ़ैसला जनता के हाथ में एक हथियार दे सकता है. अब इसके आगे का काम चुनाव आयोग का है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के नियम-क़ायदे बनाए, लेकिन चुनाव आयोग अभी इस पर चुप है. अगर चुनाव आयोग अन्ना के सुझाव के अनुसार पूरी प्रक्रिया का निर्माण नहीं करता और सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले को सिर्फ़ वोटिंग मशीन में एक बटन का प्रावधान करके छोड़ देता है, तो यह न केवल सुप्रीम कोर्ट का अपमान होगा, बल्कि देश के वोटरों की आशाओं पर भी अवरोध लग जाएगा. देश की जनता सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को पूरी तरह से क्रियान्वित होते देखना चाहती है.

अगर यह फ़ैसला अन्ना के सुझाव के अनुरूप क्रियान्वित होता है, तो इसके दो फ़ायदे होंगे. पहला फ़ायदा यह कि दाग़ी उम्मीदवारों के किसी पार्टी से प्रत्याशी बनने की संभावना बेहद कम हो जाएगी, क्योंकि पार्टियों को डर होगा कि लोग उसके उम्मीदवार के ख़िलाफ़ लाल बटन दबा सकते हैं. दूसरे, इस बात की संभावना भी कम हो जाएगी कि उम्मीदवार दस से पंद्रह करोड़ रुपये ख़र्च कर लोगों को दिग्भ्रमित करे, क्योंकि उस स्थिति में उसके पंद्रह करोड़ रुपये पानी में जाएंगे और वह चुनाव लड़ने से भी वंचित हो जाएगा. इससे यह संभावना बढ़ जाएगी कि राजनीतिक दल ज़्यादा से ज़्यादा सही उम्मीदवारों को खड़ा करें, पर हमारे देश में राजनीतिक दलों की मंशा हर अच्छे फ़ैसले को पलटने की होती है, जिसका सबसे ताज़ा उदाहरण सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजायाफ़्ता उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने वाला फ़ैसला है. जब इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सरकार राज्यसभा में बिल लाई, तब इस बिल का समर्थन बीजेपी समेत सभी पार्टियों ने किया और अरुण जेटली का भाषण तो पढ़ने लायक है. पर चूंकि यह बिल शीतकालीन सत्र में पास होना है, इसलिए सभी राजनीतिक दलों की सहमति से सरकार ने एक अध्यादेश बनाने का मन बना लिया.

हमें डर है कि राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले को बदलने के लिए कोई न कोई सलाह चुनाव आयोग को देंगे और चुनाव आयोग सरकार की सहमति से सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के तार्किक असर को निष्प्रभावी बना देगा. अभी तक चुनाव आयोग ने कोर्ट के इस फ़ैसले का न तो स्वागत किया है और न ही फ़ैसले को लागू करने की प्रक्रिया का कोई ड्राफ्ट राजनीतिक दलों को सर्कुलेट किया है. दरअसल, यह ड्राफ्ट सार्वजनिक रूप से सर्कुलेट होना चाहिए, ताकि जनता यह जान सके कि चुनाव आयोग क्या करना चाहता है.

सुप्रीम कोर्ट से भी एक गुज़ारिश है कि वो सबसे पहले दागियों के चुनाव लड़ने के अपने फ़ैसले के उस अंश पर विचार करे, जिसमें कहा गया कि कि अगर कोई व्यक्ति हवालात में है, तो वह भी नामांकन पत्र नहीं भर सकता. यह फ़ैसला थाने के दरोग़ा को असीमित अधिकार देता है. साथ ही भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा ज़रिया भी बन जाएगा. दूसरी तरफ़ निचली अदालतों का सम्मान करते हुए भी हम यह निवेदन करना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले को हाईकोर्ट के निर्णय से जोड़े, न कि उससे निचली अदालतों के फ़ैसले से. या फिर सुप्रीम कोर्ट एक और क्रांतिकारी फ़ैसला करे कि निचली अदालतों के जिस जज का

लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया को दूषित करना और इस प्रक्रिया का फ़ायदा निहित स्वार्थों द्वारा उठाना लोकतंत्र के ख़िलाफ़ है. लोकतंत्र में जनता द्वारा एक बार नकारे गए व्यक्ति उसी चुनाव में दोबारा न खड़े हों, इससे चुनावी प्रक्रिया के साफ़ होने की संभावना बढ़ेगी. नकारे गए उम्मीदवार अगले चुनाव में भले ही खड़े हो जाएं, पर उस चुनाव में उन्हें खड़ा न होने देने का फ़ैसला ही लोकतंत्र की अवधारणा के अनुकूल है.

फ़ैसला हाईकोर्ट पलटे, उस जज के लिए किसी न किसी तरह के दंड का प्रावधान हो. इससे निचली अदालतों में ज़िम्मेदारी की भावना आएगी और वे ऐसे फ़ैसले कम करेंगी, जो हाईकोर्ट में बदले जा सकें. एक सवाल खड़ा हुआ है कि जिस तरह कार्यपालिका और विधायिका में ज़िम्मेदारी तय करने की मांग उठ रही है, क्या वैसी ही मांग न्यायपालिका के लिए भी उठनी चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट के सामने राइट टू रिजेक्ट के फ़ैसले को लेकर कुछ सवाल और आ सकते हैं कि यदि राइट टू रिजेक्ट के अधिकार का इस्तेमाल करने वाले लोग चुनाव में खड़े लोगों को नकार देते हैं और उन्हें दोबारा चुनाव लड़ने का अधिकार आयोग नहीं देता है तो क्या यह उन उम्मीदवारों के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन तो नहीं माना जाएगा. हमारा यह मानना है कि लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया को दूषित करना और इस प्रक्रिया का फ़ायदा निहित स्वार्थों द्वारा उठाना लोकतंत्र के ख़िलाफ़ है. लोकतंत्र में जनता द्वारा एक बार नकारे गए व्यक्ति उसी चुनाव में दोबारा न खड़े हों, इससे चुनावी प्रक्रिया के साफ होने की संभावना बढ़ेगी. नकारे गए उम्मीदवार अगले चुनाव में भले ही खड़े हो जाएं, पर उस चुनाव में उन्हें खड़ा न होने देने का फ़ैसला ही लोकतंत्र की अवधारणा के अनुकूल है. अब चुनाव आयोग को जल्द से जल्द फ़ैसला लेना है. ■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

राजनीतिक दंगे

आपातकाल पर लिखी गई अपनी किताब के पुनः प्रकाशित अंक में कुलदीप नैयर ने हमें याद दिलाया है कि अक्टूबर, 1975 में हालात जलियांवाला बाग की तरह थे. यह सब कुछ संजय गांधी ने किया था, जिसे गांधी परिवार के इतिहास से ग़ायब कर दिया गया है. संजय ने निश्चय कर लिया था कि जितने मुस्लिम युवक मिल जाएं, सभी की नसबंदी कराई जाए, लेकिन मुज़फ़्फ़रनगर के मुस्लिमों के साथ वैसा नहीं हुआ, जो कि आपातकाल के समय उनके साथ हुआ था. उन्होंने प्रदर्शन किया और गोलियां खाईं, लेकिन कम से कम आपातकाल के समय सांप्रदायिक दंगों जैसी कोई बात नहीं थी.

अब अगर तेज़ी से 38 वर्ष आगे आएं तो हमें एक राजनीतिक रूप से तैयार किया गया दंगा मिलेगा. यह ऐसा है जैसे किसी ने सस्पेंस फिल्म की पटकथा लिखी हो. शुरुआत में कुछ छोटी घटनाएं, यहां-वहां छिटपुट विरोध. उसके बाद जिस तरह सस्पेंस फिल्म की रफ़्तार बढ़ती है और भावनाओं का उफ़ान होता है, कुछ वैसी ही स्थिति देखने को मिलेगी. और जब तक आप इसके बारे में जान पाते हैं, कुछ महापंचायतें और एक नरसंहार पूरा हो चुका होता है. पुलिस हमेशा की तरह देर से आती है, चाहे वह किसी के आदेश से या अपनी मौन सहमति से लेकिन दंगों में होने वाली मौतें और विनाश हमेशा सच होता है.

डच विद्वान वार्ड बेरेनस्कॉट ने हाल ही में 2002 के गुजरात दंगों के बारे में लिखा है. *रायट पॉलिटिक्स* नाम की यह किताब उन मूलभूत कारणों को व्याख्यायित करती है, जिनकी वजह से दंगे भड़कते हैं. सामान्य हालात में नागरिकों को वह अधिकार नहीं मिल पाता, जो राज्य की तरफ़ से उनके लिए निर्धारित किया गया है. उन्हें इसके लिए चमचों या एजेंटों की ज़रूरत पड़ती है. इलाक़ों के राजनीतिक रंग के हिसाब से हिंदू विधायक हिंदुओं पर, मुस्लिम विधायक अपने मुस्लिम एजेंटों पर ही ध्यान देते हैं.

जैसे ही हालात ख़राब होते हैं ये ताक़तें मशीनरी विरोधी ताक़तों की तरह काम करने लगती हैं. ऐसे समय में ये एजेंट अपने नेताओं के लिए पत्थर फेंकते हैं और चाकू फिराते हैं. उनकी ऐसी हरकतें जनता पर उनके रक्षकों के हमले को और तेज़ करती हैं. दंगे साधारणतया ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होते हैं. जल्द ही उन लोगों में सौहार्द्र कायम हो जाता है, जो कुछ दिनों पहले तक एक-दूसरे के घर जला रहे थे. विधायक जल्द ही अपने सहयोगी कार्यों में वापस लौट आते हैं और हालात सामान्य हो जाते हैं.

हालात ख़राब होते ही अगर पुलिस अपनी कार्रवाई जल्द शुरू कर दे तो दंगे नहीं भड़कते हैं. पुलिस को अक्सर अपने राजनीतिक आकाओं की बाधाएं झेलनी पड़ती हैं. ख़राब हालात के दौरान वही राजनीतिक पार्टी आपकी मदद करती है, जिसे आपने वोट दिया है. यह वोट बैंक की राजनीति है. अगर किसी राजनीतिक पार्टी के चमचे सलामत हैं, इसका मतलब पुलिस सही काम कर रही है, लेकिन किसी विधायक को इस बात के लिए तारीफ कैसी मिल सकती है कि उसने अपने चमचों को सुरक्षित बचा लिया? मेरठ में लगी महापंचायत भी राजनीतिक ही थी.

उत्तर प्रदेश साल 2014 में राजनीतिक रणक्षेत्र में तब्दील होने जा रहा है. सभी राजनीतिक पार्टियां 80 लोकसभा सीटों में से ज्यादा से ज्यादा जीतना चाहेंगीं. यहां कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा और भाजपा में चतुष्कोणीय मुकाबला है. सांप्रदायिक दंगों का इस्तेमाल मतों का ध्रुवीकरण अपनी तरफ करने के लिए किया जा रहा है. सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाएंगी, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को हो सकता है, क्योंकि इसे सांप्रदायिक पार्टी के रूप में प्रचारित किया जाएगा, वैसा नहीं जैसा मोदी चाहते हैं और यही धर्म निरपेक्ष पार्टियां चाहती हैं.

बीते आठ सालों में एक लगभग एक हज़ार सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या सिर्फ़ 965 प्रदर्शित की गई है. प्रति दंगा एक मौत से भी कम. मुज़फ़्फ़नगर में सबसे अधिक 48 मौतें हुईं. इन दंगों में अभी तक किसी पर कोई गंभीर दोषसिद्धि नहीं हुई है. कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दंगों में फंसे सांसद और विधायक जल्द ही छूट जाएंगे. इन मामलों में वास्तविक दोषियों को गिरफ़्तार किए जाने की ज़रूरत है.

यहां एक विरोधाभास देखने को मिलता है. कांग्रेस के शासनकाल में हुए भागलपुर, मेरठ और भिवानी के ऐतिहासिक दंगों में कई रिपोर्टों और जांचों के बावजूद आजतक कोई गंभीर दोषसिद्धि नहीं हुई, लेकिन गुजरात दंगे दोषसिद्धि तक पहुंचे. गोधरा मामले, जहां साबरमती एक्सप्रेस को जलाया गया, में ही नहीं, बल्कि ओड इलाके, जहां हिंदुओं ने मुस्लिमों को मारा, में भी दोषसिद्धि हुई. नरोदा पाटिया में तो भाजपा सदस्य माया कोडनानी को 28 वर्षों की सज़ा हुई. इसमें कोई शक़ नहीं कि दोनों पार्टियों में तुलना अभी तक समाप्त नहीं हुई है.

यह आश्चर्चजनक नहीं है कि अभी तक किसी भी कांग्रेसी नेता को 1984 दंगों में सजा नहीं हुई और न ही 1993 में हुए मुंबई दंगों में. इसके अलावा राजीव गांधी के दिनों में हुए भागलपुर दंगे में बहुत ज्यादा लोगों पर दोषसिद्धि नहीं हुई. क्या कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष है तो उसके शासनकाल में हुआ कोई भी दंगा सांप्रदायिक नहीं हो सकता? ■

हालात खराब होते ही अगर पुलिस अपनी कार्रवाई जल्द शुरू कर दे तो दंगे नहीं भड़कते हैं. पुलिस को अक्सर अपने राजनीतिक आकाओं की बाधाएं झेलनी पड़ती हैं. खराब हालात के दौरान वही राजनीतिक पार्टी आपकी मदद करती है, जिसे आपने वोट दिया है. यह वोट बैंक की राजनीति है. अगर किसी राजनीतिक पार्टी के चमचे सलामत हैं, इसका मतलब पुलिस सही काम कर रही है.

उत्तर प्रदेश साल 2014 में राजनीतिक रणक्षेत्र में तब्दील होने जा रहा है. सभी राजनीतिक पार्टियां 80 लोक सभा सीटों में से ज़्यादा से ज़्यादा जीतना चाहेंगीं. यहां कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा और भाजपा में चतुष्कोणीय मुक़ाबला है. सांप्रदायिक दंगों का इस्तेमाल मतों का ध्रुवीकरण अपनी तरफ़ करने के लिए किया जा रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

सूचना का अधिकार चौथी दुनिया की पहल

कहां कितना आरटीआई शुल्क

चौथी दुनिया ब्यूरो

सूचना अधिकार क़ानून के तहत आवेदन शुल्क या अपील या फोटो कॉपी शुल्क कितना होगा, यह तय करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है. मतलब यह कि राज्य सरकार अपनी मर्जी से यह शुल्क तय कर सकती है. यही कारण है कि विभिन्न राज्यों में सूचना शुल्क/अपील शुल्क का प्रारूप अलग-अलग है. इस अंक में हम आपको आरटीआई शुल्क और सूचना के बदले लिए जाने वाले शुल्क के बारे में बता रहे हैं. हम इस अंक में एक टेबल भी प्रकाशित कर रहे हैं, जिसमें देश के सभी राज्यों में तय किए गए शुल्क की जानकारी है.

इसके अलावा हम आपको यह भी बता रहे हैं कि अगर कभी आपसे कोई लोक सूचना अधिकारी सूचना के बदले ज़्यादा पैसे मांगे तो क्या करना चाहिए. सूचना क़ानून की धारा 7 में सूचना के एवज में शुल्क निर्धारण के बारे में बताया गया है, लेकिन इसी धारा की उपधारा 1 में कहा गया है कि यह शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा. इस व्यवस्था के तहत सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने विभिन्न विभागों में सूचना अधिकार क़ानून के तहत अदा किए जाने वाले शुल्क स्वयं तय करेंगी. केंद्र और राज्य सरकारों ने इस अधिकार के तहत अपने यहां अलग-अलग शुल्क नियमावली बनाई है और उसमें स्पष्ट किया गया है कि आवेदन करने और सूचना से

विभिन्न राज्यों के नियम (आवेदन/अपील/फोटोकॉपी शुल्क)

राज्य	आवेदन शुल्क	शुल्क का प्रारूप	फोटो कॉपी शुल्क	अपील शुल्क
केंद्र सरकार/दिल्ली सरकार	10 रुपये	नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पोस्टल ऑर्डर	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
आंध्र प्रदेश	ग्राम स्तर-शुल्क नहीं मंडल स्तर- 5 रुपये, अन्य जगहों पर 10 रुपये	नकद/डिमांड ड्राफ्ट/नॉन ज्यूडिसियल स्टांप/ ट्रेजरी चालान	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
अरुणाचल प्रदेश	कोई शुल्क नहीं	ट्रेजरी चालान	2 रुपये प्रति पेज	प्रथम/द्वितीय 50 रुपये
असम	10 रुपये	नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पोस्टल ऑर्डर	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
बिहार	10 रुपये	नकद/पोस्टल ऑर्डर/नॉन ज्यूडिसियल स्टांप/ डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक	2 रुपये प्रति पेज	प्रथम/द्वितीय 10 रुपये
छत्तीसगढ़	10 रुपये	नकद/ट्रेजरी चालान/नॉन ज्यूडिसियल स्टांप	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
गोवा	10 रुपये	कोर्ट फी स्टांप	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
गुजरात	20 रुपये	नकद/डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/नॉन ज्यूडिसियल स्टांप	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
हरियाणा	50 रुपये	नकद/ट्रेजरी चालान/पोस्टल ऑर्डर	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
हिमाचल प्रदेश	10 रुपये	नकद/डिमांड ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान/पोस्टल ऑर्डर	10 रुपये प्रति पेज	नहीं
झारखंड	10 रुपये	नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पोस्टल ऑर्डर	2 रुपये पेज	नहीं
कर्नाटक	10 रुपये	नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पोस्टल ऑर्डर/ पे ऑर्डर	2 रुपये पेज	नहीं
केरल	10 रुपये	कोर्ट फी स्टांप	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
मध्य प्रदेश	10 रुपये	नकद/नॉन ज्यूडिसियल स्टांप	2 रुपये प्रति पेज	प्रथम 50 रुपये/ द्वितीय 100 रुपये
महाराष्ट्र	10 रुपये	नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/कोर्ट फी स्टांप	2 रुपये पेज	प्रथम 20 रुपये/ द्वितीय 20 रुपये
मेघालय	10 रुपये	नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक	2 प्रति पेज	नहीं
मणिपुर	10 रुपये	पोस्टल ऑर्डर	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
मिजोरम	10 रुपये	नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पोस्टल ऑर्डर	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
नगालैंड	10 रुपये	नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पोस्टल ऑर्डर	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
उड़ीसा	10 रुपये	नकद/ट्रेजरी चालान/पोस्टल ऑर्डर	टाइप कॉपी 2 रुपये/ कंप्यूटर प्रिंट 10 रुपये प्रति	पेज प्रथम 20 रुपये / द्वितीय 25 रुपये
पंजाब	10 रुपये	नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/ पोस्टल ऑर्डर	10 रुपये प्रति पेज	नहीं
राजस्थान	10 रुपये	नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पोस्टल ऑर्डर	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
सिक्किम	100 रुपये	मनीऑर्डर/चेक/डिमांड ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान	2 रुपये प्रति पेज	
त्रिपुरा	10 रुपये	नकद	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
तमिलनाडु	10 रुपये	नकद/कोर्ट फी स्टांप/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
उत्तर प्रदेश	10 रुपये	नकद/पोस्टल ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/ ट्रेजरी चालान	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
उत्तराखंड	10 रुपये	नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/ट्रेजरी चालान/ पोस्टल ऑर्डर/नॉन ज्यूडिसियल स्टांप	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
पश्चिम बंगाल	10 रुपये	कोर्ट फी स्टांप	2 रुपये प्रति पेज	नहीं

संबंधित फोटोकॉपी लेने के लिए कितना शुल्क लिया जाएगा. धारा 7 की उपधारा 3 में लोक सूचना अधिकारी की ज़िम्मेदारी का विवरण है कि वह सरकार द्वारा तय किए गए शुल्क के आधार पर गणना करते हुए आवेदक को बताएगा कि उसे अमुक सूचना पाने के लिए कितना शुल्क देना होगा. उपधारा 3 में लिखा है कि यह शुल्क वही होगा, जो उपधारा 1 में सरकार द्वारा तय किया गया होगा. केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की शुल्क नियमावली में अंतर है. कहीं आवेदन के लिए शुल्क 10 रुपये है तो कहीं 50 रुपये. इसी तरह दस्तावेजों की फोटोकॉपी के लिए कहीं 2 रुपये तो कहीं 5 रुपये लिए जाते हैं. दस्तावेज़ों के निरीक्षण, काम के निरीक्षण एवं सीडी- फ्लॉपी पर सूचना लेने के लिए भी शुल्क इन नियमावलियों में बताया गया है. उम्मीद है कि हमारे पाठकों के लिए यह जानकारी काफी मददगार साबित होगी और वे जमकर आरटीआई क़ानून का इस्तेमाल करते रहेंगे. ■

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन - 201301 ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

राशिफल

आचार्य चंद्रशेखर

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
इस सप्ताह आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है और आप व्यस्तता के कारण थोड़ा थकान महसूस करेंगे. आपकी दृढ़ शक्ति के कारण आपको उम्मीद से अधिक सफलता मिलेगी. आप अपने आत्म मूल्यांकन को सर्वोपरि रखेंगे, जिसके कारण आप अपनी कार्यशैली में भी परिवर्तन का अनुभव करेंगे.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
इस सप्ताह शत्रुओं से सावधान रहें. खर्चो में वृद्धि होगी, जिसके कारण तनाव में रहेंगे. धनार्जन से आप अपने जीवन में एक नया एहसास महसूस करेंगे और धन की उपयोगिता समझेगें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. माता-पिता की सेवा करें, जिससे आपके कठिन कार्य भी आसान हो जाएंगे.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
इस सप्ताह आप जल्दबाजी या किसी के दबाव में कोई फैसला न लें. परिवार के साथ समय बीतेगा और परिवार के लोगों का खास ख्याल रखेंगे. किसी बुजुर्ग को स्वास्थ्य के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है. किसी भी दस्तावेज पर सावधानी पूर्वक हस्ताक्षर करें.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
इस सप्ताह आप विवादों से बचें अन्यथा आपके किसी नजदीकी के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं. नौकरीपेशा वाले लोग अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव महसूस कर सकते हैं. आर्थिक स्थिति उतार-चढ़ाव वाली होगी, लेकिन किसी पुराने निवेश से लाभ हो सकता है. व्यापारियों के लिए समय थोड़ा परेशानी वाला होगा.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
इस सप्ताह पहले से रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी. कोई भी निर्णय सोच-समझकर करें. व्यापारी और नौकरीपेशा वाले दोनों का समय अच्छा रहेगा. बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर चिंता होगी. दांपत्य जीवन सुखी रहेगा.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
इस सप्ताह आपको मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति अच्छा रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को प्रोन्नत्ति का समाचार मिलेगा. व्यापारी अपने व्यापार का विस्तार करेंगे, लेकिन व्यापार में भागी दारी का पूरा ख्याल रखें. परिवार को लेकर चिंता हो सकती है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
इस सप्ताह आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. किसी परेशानी से विचलित न हों हिम्मत से काम लें. खर्चों में वृद्धि होगी, लेकिन दांपत्य जीवन में वाद-विवाद से बचें. नौकरी पेशा वाले लोगों को स्थानांतरण से सम्बंधित कोई सूचना मिल सकती है.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
इस सप्ताह उत्तेजना में आकर कोई निर्णय न लें. बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उन्हें बाहर की चीजें खानें न दें. खर्चों में बृद्धि होगी, लेकिन कोई पहले से रुका हुआ धन मिलेगा. निजी कम्पनी में कार्यरत लोगों को नए ऑफर मिल सकते हैं. आपका मान सम्मान बढ़ेगा.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
इस सप्ताह आपकी रुचि धन कमाने में रहेगी और उसमें आप सफल भी होंगे. किसी की सहायता करने से आपको फायदा होगा. किसी भी दस्तावेज पर सोच-समझकर हस्ताक्षर करें. पैत्रिक संपत्ति से सम्बंधित शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
किसी भी समस्या से भयभीत न हों हिम्मत से काम लें. खर्चों में वृद्धि होगी, लेकिन दांपत्य जीवन में वाद-विवाद से बचें. नौकरी पेशा वाले लोगों को स्थानांतरण से सम्बंधित कोई सूचना मिल सकती है. इस सप्ताह आप अपने स्वास्थ्य का ख़ास ख्याल रखें.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
इस सप्ताह बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उन्हें बाहर का खाना न खाने दें. खर्चों में वृद्धि होगी और कोई पहले से फंसा हुआ धन प्राप्त होगा. नौकरी पेशा लोगों को नए ऑफर मिल सकते हैं. उत्साह में आकर कोई निर्णय न लें. आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
इस सप्ताह किसी पैत्रिक सम्बन्धी संपत्ति से अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है. धन कमाने में आपकी रुचि बढ़ेगी और उसमे आप सफल भी होंगे. किसी की सहायता करने से आपको फायदा होगा. किसी भी दस्तावेज पर सोच-समझ कर हस्ताक्षर करें.

ज़रा हट के

चलता विमान और सोते पायलट

ब्रिटेन में दो पायलट विमान को ऑटो पायलट मोड में लगाकर आराम से सो गए. विमान के एक चालक ने एयरलाइंस का नाम न बताते हुए कहा कि अचानक जब उसकी आंखें खुली, तो उसने अपने साथी चालक को भी जगाया. एक अध्ययन में पता चला है कि ब्रिटिश एयरलाइंस के लगभग आधे से ज्यादा पायलट कभी न कभी यात्रा के समय सोए हैं, लेकिन पायलटों के अनुसार ऐसा करना यात्रियों की सुरक्षा के साथ समझौते करने जैसा है. ब्रिटिश एयरलाइन पायलट एसोसिएशन के अनुसार 500 पायलटों में से 56 प्रतिशत ने माना है कि वह उड़ान के दौरान सोए हैं और हर तीन में से एक पायलट ने अपने सोए हुए सहयोगी पायलट को जगाया है. ■

दुनिया का सबसे छोटा कुत्ता

शिंआहआ प्रजाति का पॉकेट साईज कुत्ता दुनिया का सबसे छोटा कुत्ता बन गया है, जो मात्र 3.8 इंच कद का है. सिर्फ 500 ग्राम का मिरेकिल मिली नाम का ये कुत्ता अब गिनीज बुक आंफ वर्ल्ड में शामिल हो चुका है. इस कुत्ते की मालकिन पोरटो रिको की विनेसा सेमलर हैं. दिसंबर 2011 में जन्मा ये कुत्ता तस्वीर खिंचवाते समय अपनी नन्हीं से जुबान बाहर निकाल लेता है. विनेसा का कहना है कि वह तस्वीरें खिंचवाने में माहिर है. विनेसा कहती हैं कि मिरेकिल जन्म के समय इतना छोटा था कि एक चम्मच पर आ जाता था. उसके छोटे से मुंह से दूध पीना मुश्किल होता था. इसलिए उसे हर दो घंटे पर आइड्राप से दूध पिलाया जाता था. अब मिरेकिल मिली एक शिशु के पालने में सोता है और हाथ का बना खाना ही खाता है. ■

बाघ के बच्चे गाय का दूध पीते हैं

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के प्राणी संग्रहालय में दो दिन पूर्व जन्मे तीन बाघ शावकों को गाय का दूध पिला कर जीवित रखा जा रहा है. इंदौर प्राणी संग्रहालय के प्रभारी डॉ. उत्तम यादव ने बताया कि दो दिन यहां बाघिन कमलेश ने तीन शावकों को जन्म दिया.

उन्होंने बताया कि बाघिन अपने शावको से दूर रहती है और दूध नहीं पिलाती है. उन्होंने शावकों को बाघिन के पास ले जाने की तमाम कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे. अब शावकों को गाय का दूध देकर जिंदा रखा जा रहा है. शावकों के लिए बकरी के दूध की भी व्यवस्था कराई जा रही है. ■

कुत्ते ने रक्तदान किया

अगर किसी से अचानक रक्तदान के लिए कहा जाए, तो वह जल्दी तैयार नहीं होता, लेकिन इस संदर्भ में एक उदाहरण ऐसा है जो इंसानों के लिए सीख बन सकता है. न्यूजीलैंड में एक लैब्रोडोर नस्ल के कुत्ते ने बिल्ली को बचाने के लिए रक्तदान किया आमतौर पर कुत्ते और बिल्ली के बीच कभी सामान्य रिश्ते नहीं देखे जाते हैं पर कुत्ते ने ऐसे समय में बिल्ली को खून दिया जब वो लगभग मरने ही वाली थी, पशु चिकित्सक का कहना है कि बिल्ली ने गलती से चूहे मारने की दवा खा ली थी, जिससे उसकी हालत एकदम खराब हो गयी थी. बिल्ली की मालकिन किम ने बताया कि रोरी (बिल्ली) की तबियत बिल्कुल बिगड़ती ही जा रही थी, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था कि हम एक बिल्ली का खून लें और उसे लैब में मैच करवाकर रोरी को दें तभी मैनें अपने दोस्त से बात की जिनके पास लैब्रोडोर प्रजाति का कुत्ता है. उस कुत्ते के रक्त को टेस्ट करके बिल्ली को चढ़ाया गया और बिल्ली ठीक हो गई. ■

मलाला के कार्यों का ही नतीजा है कि उन्हें सखारोव जैसे विश्व के शीर्ष पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है. नोबेल पुरस्कार के लिए शीर्ष नामों में भी मलाला का नाम शामिल था. यह बात और है कि मलाला को नोबेल पुरस्कार नहीं मिल सका. मलाला को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने के पीछे यह भी कारण बताया जा रहा है कि उनकी उम्र बहुत कम थी और इस उम्र में वह नोबेल शांति पुरस्कार की प्रतिष्ठा को ज़िंदगी भर नहीं संभाल पाएंगी.

मलाला यूसुफजई

महिला शक्ति का नया अवतार

दुनिया में महिलाओं की संख्या लगभग साढ़े तीन अरब है, जिसमें लगभग 64 करोड़ महिलाएं अशिक्षित हैं. ऐसे में 16 साल की मलाला यूसुफजई उन सारी बच्चियों एवं महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण बनकर आईं हैं, जो पढ़ना चाहती हैं. जो काम अमेरिका और उस जैसे अन्य देश नहीं कर पाए, उसे मलाला ने कर दिखाया. हताश तालिबान फिर सकते में है. यही कारण है कि उसने फिर से मलाला को जान से मारने की धमकी दी है, लेकिन मलाला एक सकारात्मक सोच का प्रतीक है, जो कभी मरती नहीं.

मलाला यूसुफजई

- 12 जुलाई, 2013 को मलाला ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र को संबोधित किया.
- वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने 10 नवंबर को मलाला यूसुफजई दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी.
- गुल मकई उपनाम से मलाला डायरी लिखती थीं.
- लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने वाली मलाला को 2013 के अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
- मलाला यूसुफजई और सामाजिक न्याय कार्यकर्ता हैरी बेलाफोंटे को संयुक्त रूप से एमनेस्टी इंटरनेशनल का एंबेसेडर ऑफ कंसाइंस अवार्ड, 2013 देने की घोषणा की गई है.
- मलाला को उसकी बहादुरी और स्वात की प्रतिकूल परिस्थितियों में महिलाओं की शिक्षा के लिए आवाज उठाने हेतु वर्ल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फाउंडेशन के वीरता पुरस्कार से 19 नवंबर, 2012 को सम्मानित किया गया.
- 9 अक्टूबर 2012 को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तालिबानी आतंकियों ने मलाला के सिर में गोली मार दी थी.
- मलाला को फ्रांस के सिमोन डी बेवॉर पुरस्कार से 9 जनवरी, 2013 को सम्मानित किया गया.
- पाकिस्तान का राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार (2011) दिया गया.
- मलाला को यूरोपीय संघ के प्रतिष्ठित सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

राजीव रंजन

मलाला...मलाला...मलाला...यह वो नाम है, जिसने तालिबान को ख़ौफ़ज़दा कर दिया है. एक बार फिर से तालिबान ने मलाला को जान से मारने की धमकी दी है. सचमुच मलाला से तालिबान हार गया है. भले ही वह यह बात स्वीकार नहीं कर पा रहा हो, लेकिन यही सच है. जो काम अमेरिका और अन्य शक्तियां आज तक नहीं कर पाईं, उस काम को 16 साल की एक छोटी सी बच्ची ने कर दिखाया, वह भी बिना हथियार उठाए, सिर्फ क़लम की ताक़त के बल पर. मलाला कहती हैं कि सबसे शक्तिशाली हथियार क़लम और क़िताब है. एक शिक्षक, एक क़िताब और एक क़लम दुनिया को बदलने का माद्दा रखते हैं. निश्चय ही मलाला ने यह सच कर दिखाया है. तालिबान के सिर मलाला का ख़ौफ़ कितना सिर चढ़कर बोलता है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बार तालिबान पहले ही मलाला पर जानलेवा हमला कर चुका है. आज एक बार फिर तालिबान ने मलाला को जान से मारने की धमकी दी है. तालिबान यह भूल चुका है कि मलाला एक सोच है, एक विचार है और सोच की कभी हत्या हो ही नहीं सकती. एक बड़ा सवाल यह है कि आख़िर तालिबान इस छोटी बच्ची को क्यों मारना चाहता है? इसका सीधा सा जवाब है–हताशा. तालिबान को लग रहा है कि उसे लेकर दुनिया में जो ख़ौफ़ है, वह मलाला की वजह से लोगों के ज़ेहन से दूर होता जा रहा है. तालिबान यह समझता है कि मलाला ने अगर महिलाओं में शिक्षा का अलख जगा दी, तो उनमें जागरूकता पैदा होगी, ग़रीबी दूर होगी, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे और अगर ये सब हुआ तो तालिबान से लोग नहीं, बल्कि तालिबान लोगों से ख़ौफ़ खाएगा और ऐसी स्थिति में तालिबान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा.

मलाला यूसुफ़ज़ई का जन्म 1998 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वाह प्रान्त के स्वात जिले में हुआ. तालिबानी हमले के बाद मलाला अपने परिवार के साथ बर्मिंघम में रह रही हैं. मलाला के लिए ब्रिटेन की संस्कृति किसी आश्चर्य से कम नहीं है. वे कहती हैं कि हमने कभी नहीं सोचा था कि महिलाएं इतनी आज़ाद हो सकती हैं. मलाला मानती हैं कि पाकिस्तान में शांति व स्थायित्व के लिए तालिबान से वार्ता किया जाना ज़रूरी है.

यह मलाला के कारनामों का ही नतीजा है कि उन्हें सखारोव जैसे विश्व के शीर्ष पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है. नोबेल पुरस्कार के लिए शीर्ष नामों में भी मलाला का नाम शामिल था. यह बात और है कि मलाला को नोबेल पुरस्कार नहीं मिल सका. मलाला को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने के पीछे यह भी कारण बताया जा रहा है कि उनकी उम्र बहुत कम थी और इस उम्र में वह नोबेल शांति पुरस्कार की प्रतिष्ठा को ज़िंदगी भर नहीं संभाल पाएंगी. स्टॉकहोम शांति रिसर्च सिपरी के टिलमन ब्रुएक का कहना है कि मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि किसी बच्चे को यह पुरस्कार देना सैद्धांतिक रूप से ठीक होगा. हालांकि मलाला को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, क्योंकि मलाला जो भी कर रही हैं, वह पुरस्कार पाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कर रही हैं, महिलाओं को जागरूक करने के लिए कर रही हैं. दुनिया में अमन–चैन कायम करने के लिए कर रही हैं. यही कारण है कि मलाला के कार्यों से प्रसन्न होकर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय मिलने के लिए उन्हें बुलाती हैं. संयुक्त राष्ट्र मलाला का 16वां जन्मदिन मलाला डे के तौर पर मनाता है. मलाला के लिए दुनिया की नज़रों में सम्मान है. उनके साथ लोगों का आशीर्वाद और दुआएं हैं. ऐसा नहीं कि मलाला एक ही दिन में अचानक विश्व की आंखों का तारा बन गईं, बल्कि इसके लिए उन्होंने जो किया, वह कोई बिरला ही कर सकता है.

गुल मकई

2009 में महज 11 साल की उम्र में ही मलाला ने बीबीसी उर्दू सेवा के लिए गुल मकई नाम से डायरी लिखनी शुरू की. ये ऐसा वक्त था, जब स्वात घाटी पर चरमपंथियों का लगभग पूरी तरह कब्ज़ा हो गया था. डर के कारण कोई चरमपंथियों के ख़िलाफ़ ज़ुबान तक नहीं खोलता था. स्वात घाटी के केंद्र मिंगोरा में हालात ऐसे हो गए थे कि रोज़ाना जब लोग सुबह उठते तो उन्हें शहर के चौराहों पर या खंभों से लटकी हुई या गला रेती हुई लाशें मिलती थीं. इन्हीं हालात में मलाला बीबीसी ऊर्दू के लिए लिखी जाने वाली अपनी डायरी में वहां के हालात और चरमपंथियों के जुल्मो–सितम की कहानियां बयान करती रहीं. गुल मकई उपनाम से डायरी लिखने वाली मलाला ने अपनी डायरी में लिखा है कि आज स्कूल का आख़िरी दिन था, इसलिए हमने मैदान पर कुछ ज़्यादा देर खेलने का फ़ैसला किया. मेरा मानना है कि एक दिन स्कूल खुलेगा, लेकिन जाते समय मैंने स्कूल की इमारत को इस तरह देखा, जैसे मैं यहां फिर कभी नहीं आऊंगी.

गुल मकई की नज़र से दुनिया ने तालिबान के शासन में जिंदगी के बारे में जाना. खास तौर पर लड़कियों और महिलाओं की जिंदगी के बारे में. डायरी जनवरी से मार्च 2009 के बीच दस किस्तों में बीबीसी उर्दू की वेबसाइट पर पोस्ट हुई. स्वात से लेकर दुनिया के कई हिस्सों में इस डायरी ने तहलका मचा दिया.फौजी कार्रवाई खत्म होने के बाद दिसंबर 2009 में पता चला कि गुल मकई कोई और नहीं, बल्कि स्वात की ही बेटी है और उसका नाम मलाला यूसुफजई है. तालिबान से बचाने के लिए उसे यह नाम दिया गया था, लेकिन पहचान जाहिर होते ही वह दुनिया की नजरों में बहादुर मलाला बन गई, लेकिन तालिबान की आंखों की किरकिरी. मलाला का पूरा परिवार तालिबान के निशाने पर आ गया. मलाला को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर कई सम्मान मिले. इधर तालिबान मलाला से बदले की आग में जलता रहा और आखिरकार उसने पिछले साल 9 अक्टूबर को मलाला पर जानलेवा हमला कर ही दिया, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था. मलाला की जान बच गई. इसके बाद वह और सशक्त होकर उभरी.

उम्मीद की किरण

मलाला, उन बहुत सी बच्चियों के लिए उम्मीद हैं, जो स्कूल जाना चाहती हैं. मलाला आदिवासियों और लड़कियों की शिक्षा का पूरजोर समर्थन करती हैं. मलाला तालिबान के ख़ौफ़ की कभी परवाह नहीं की और अपने उद्देश्य को पूरा करने में लगी रहीं. तालिबान के मलाला पर हमले के पीछे भी यही कारण था.

तालिबान फिर से मलाला को जान से मारने की धमकी दे रहा है. मलाला को अपनी जान की परवाह नहीं है. वे कहती हैं कि मैं आख़िरी दम तक महिलाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष करती रहूंगी. मलाला बेनजीर भुट्टो को अपना आदर्श मानती हैं और उनके पदचिन्हों पर चलते हुए भविष्य में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, ताकि वे पाकिस्तान में हर उस महिला को शिक्षित कर सकें, जो निरक्षर है. मलाला कहती हैं कि किसी की हत्या करना, शोषण करना और सज़ा देने को इस्लाम में बिल्कुल भी जगह नहीं दी गई है. तालिबान इस्लाम को बदनाम कर रहा है. मलाला ने उम्मीद जताई है कि ऐसा भी एक वक्त आएगा, जब पाकिस्तान इन सभी सामाजिक बुराइयों से मुक्त होगा, वहां शांति होगी, सभी लड़कियां स्कूल जाएंगी. इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने मलाला को साहस और उम्मीद की एक किरण बताया था. वे कहती हैं कि मैं अपने देश का भविष्य बदलना चाहती हूं. मैं शिक्षा को अनिवार्य बनाना चाहती हूं. मुझे उम्मीद है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, जब मेरे देश के लोग आज़ाद होंगे. उनके पास उनके अधिकार होंगे. सभी लड़के और लड़कियां स्कूल जाएंगे. हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी यह है कि हम सुधार के लिए किसी दूसरे की पहल का इंतज़ार करते हैं.

तालिबान फिर से मलाला को जान से मारने की धमकी दे रहा है. मलाला को अपनी जान की परवाह नहीं है. वे कहती हैं कि मैं आखिरी दम तक महिलाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष करती रहूंगी. मलाला बेनजीर भुट्टो को अपना आदर्श मानती हैं और उनके पदचिन्हों पर चलते हुए भविष्य में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, ताकि वे पाकिस्तान में हर उस महिला को शिक्षित कर सकें, जो पढ़ना चाहती हैं.

आई एम मलाला

द गर्ल हू स्टुड अप फॉर एजुकेशन एंड वाज शॉट बाय तालिबान नाम से मलाला ने एक पुस्तक लिखी है. यह मलाला की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव का उल्लेख किया है. पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग से प्रेरित हैं. मलाला चाहती हैं कि तालिबान समेत सभी आतंकियों के बेटे और बेटियों को शिक्षा मिले. वे कहती हैं कि अहिंसा का पाठ मैंने गांधीजी, ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान और मदर टेरेसा से सीखा है. गौरतलब है कि 16 साल की मलाला उस वक्त ख़बरों में आई थीं, जब एक साल पहले अक्टूबर 2012 में पाकिस्तान के स्वात घाटी इलाके में उस पर तालिबानी हमलावर ने गोली चलाई थी. आज मलाला एक सिलेब्रिटी बन गई हैं. वह जो कुछ बोलती हैं, सोचती हैं, उस पर विश्व मीडिया का ध्यान रहता है और वह बड़ी ख़बरों में शुमार हो जाती हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई

> बाबा की र्जि वा को कोई स्वाद–रुचि न थी क्योंकि उन्होंने उसे अपने वश में कर लिया था. इसलिए वे भिन्न–भिन्न वस्तुओं के स्वाद की चिंता क्यों करते. जो कुछ भी भिक्षा में उन्हें मिल जाता, उसे ही वे मिश्रित कर संतोषपूर्वक ग्रहण करते थे.

एक बार...

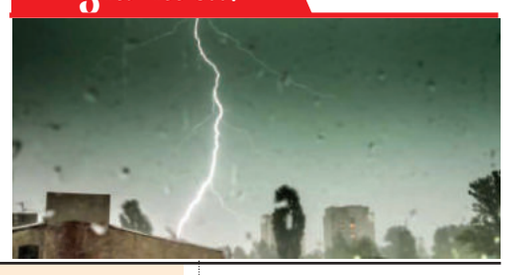

करुणा के सागर साई

चौथी दुनिया ब्यूरो

शिरडीवासियों के भाग्य की कौन कल्पना कर सकता है कि जिनके द्वार पर ब्रह्मा भिक्षुक के रूप में खड़े रहकर पुकार करते थे. और साई एक रोटी का टुकड़ा मिले और उसे प्राप्त करने के लिए अपना हाथ फैलाते थे.

इस विचित्र संसार में ईश्वर ने लाखों प्राणियों (हिंदू शास्त्र के अनुसार 84 लाख योनियों) को उत्पन्न किया है (जिनमें देव, दानव, गंधर्व, जीवजंतु और मनुष्य आदि सम्मिलित हैं), जो स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, समुद्र तथा आकाश में निवास करते और भिन्न–भिन्न धर्मों का पालन करते हैं. इन प्राणियों में जिनका पुण्य प्रबल है, वे स्वर्ग में निवास करते और अपने सत्कृत्यों का फल भोगते हैं. पुण्य के क्षीण होते ही वे फिर निम्न स्तर में आ जाते हैं और वे प्राणी, जिन्होंने पाप या दुष्कर्म किए हैं, नरक में जाकर अपने कुकर्मों का फल भोगते हैं. जब उनके पाप और पुण्यों का समन्वय हो जाता है, तब उन्हें मानव–जन्म और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है. जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब वे मुक्त हो जाते हैं.

जब ईश्वर ने देखा कि मानव उसकी लीला, अद्भुत रचनाओं तथा ज्ञान को समझने के योग्य है, तब उन्हें अति हर्ष एवं संतोष हुआ. (भागवत स्कंध 11–9–28 के अनुसार). इसलिये मानव जन्म प्राप्त होना बड़े सौभाग्य का सूचक है. उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो परम सौभाग्य का लक्षण है, परंतु श्री साई–चरणाम्बुजों में प्रीति और उनकी शरणागति प्राप्त होना इन सभी में अति श्रेष्ठ है. शिरडीवासियों के भाग्य की कौन कल्पना कर सकता है कि जिनके द्वार पर ब्रह्मा भिक्षुक के रूप में खड़े रहकर पुकार करते थे. और साई एक रोटी का टुकड़ा मिले और उसे प्राप्त करने के लिए अपना हाथ फैलाते थे. एक हाथ में वे सदा टमरेल लिए रहते तथा दूसरे में एक झोली. कुछ घरों में तो वे प्रतिदिन ही जाते और किसी–किसी के द्वार पर केवल फेरी ही लगाते थे. वे साग, दूध या छाछ आदि पदार्थ तो टिनपॉट में लेते तथा भात व रोटी आदि अन्य सूखी वस्तुएं झोली में डाल लेते थे. बाबा की र्जि वा को कोई स्वाद–रुचि न थी क्योंकि उन्होंने उसे अपने वश में कर लिया था. इसलिए वे भिन्न–भिन्न वस्तुओं के स्वाद की चिंता क्यों करते? जो कुछ भी भिक्षा में उन्हें मिल जाता, उसे ही वे मिश्रित कर संतोषपूर्वक ग्रहण करते थे.

अमुक पदार्थ स्वादिष्ट है या नहीं, बाबा ने इस ओर कभी ध्यान ही न दिया, मानो उनकी जिह्वा में स्वाद बोध ही न हो. वे केवल मध्याह्न तक ही भिक्षा–उपार्जन करते थे. यह कार्य बहुत अनियमित था. किसी दिन तो वो छोटी–सी फेरी ही लगाते तथा किसी दिन बारह बजे तक. वे एकत्रित भोजन एक कुंडी में डाल देते, जहां कुत्ते, बिल्लियां, कौवे आदि स्वतंत्रतापूर्वक भोजन करते थे. बाबा ने उन्हें कभी नहीं भगाया. एक स्त्री भी, जो मास्जिद में झाड़ू लगाया करती थी, रोटी के दस–बारह टुकड़े उठाकर अपने घर ले जाती थी, परंतु किसी ने कभी उसे नहीं रोका. जिन्होंने स्वप्न में भी बिल्लियों और कुत्तों को कभी दुत्कार कर नहीं भगाया, वे भला निस्सहाय गरीबों को रोटी के कुछ टुकड़ों को उठाने से क्यों रोकते. ऐसे महान पुरुष का जीवन धन्य है. शिरडीवासी तो पहले पहले उन्हें केवल एक पागल ही समझते थे और वे शिरडी में इसी नाम से विख्यात भी हो गए थे. जो भिक्षा के कुछ टुकड़ों पर निर्वाह करता हो, भला उसका कोई आदर कैसे करता, लेकिन वे तो उदार हृदय और धर्मात्मा थे. यद्यपि वे बाहर से चंचल और अशांत प्रतीत होते थे, परंतु अन्तःकरण से दृढ़ और गंभीर थे. उनका मार्ग गहन तथा गूढ़ था. फिर भी ग्राम में कुछ ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति थे, जिन्होंने उन्हें पहचान कर एक महान व्यक्ति माना. ■

feedback@chauthiduniya.com

विंध्याचल का महात्म्य

पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा दक्ष की यज्ञ स्थली जहां पर सती ने आत्मदाह किया था और भगवान शंकर के तांडव नृत्य करते समय जब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटकर सती के अंग जहां–जहां कट कर गिरे हैं, वहां–वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई है. 108 शक्तिपीठों में 12 महापीठ हैं, जिसमें एक स्थान मां विंध्यवासिनी का है. यह शक्तिपीठ उतना ही प्राचीन है जितनी हमारी सृष्टि. इसलिए शक्ति का वर्णन रामायण और महाभारत तथा पुराणों से लेकर सभी ग्रंथों में 108 शक्तिपीठों में यहां की गिनती महापीठ में होती है. जहां की गुफाओं में अनेक साधु संत सनातन काल से तपस्या करते चले आ रहे हैं मान्यता है कि वे आज भी भोर में गुफा से निकलकर गंगा स्नान करने जाते हैं. विंध्याचल वही शक्ति पीठ है जहां ब्रह्मा जी के पुत्र मनु ने तप किया था और उन्हें सृष्टि निर्माण का वरदान मिला था. मंदिर में प्रवेश करते समय जब भक्त मां की मूर्ति के सामने होते हैं तो अपने को भूल जाते हैं और रह जाती है उनकी आस्था. यहीं से शुरू होता है दर्शन पूजन का प्रारम्भ जो काली खोह होते हुए अष्टभुजा मंदिर जाकर समाप्त होता है जहां त्रिकोण यात्रा पूरी होती है. इसके अलावा यहां पर तांत्रिक साधना करने वालों के लिए श्री यंत्र तथा अनेक धार्मिक स्थल भी है. यद्यपि दर्शनार्थी यहां साल भर आते रहते हैं, लेकिन वर्ष में लगने वाले दोनों नवरात्रो में लाखों भक्त दर्शनार्थ हेतु एकत्रित होते हैं, जिला प्रशासन उनकी व्यवस्था करता है, परन्तु सरकार द्वारा अभी तक राष्ट्रीय मेला घोषित नहीं हुआ. विंध्याचल महत्व के बारे में निम्न श्लोक ध्यान देने योग्य हैं.

नन्द गोप गृहे जाता, यशोदा–गर्भ–सम्भवा.
ततस्तौ नाशयिष्यामि, विन्धायचल निवासिनी.

पौराणिक मान्यता के अनुसार विष्णु ने असुरों का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र भगवान शंकर से यहीं प्राप्त किया, त्रेतायुग में भगवान राम ने विंध्याचल आकर अपने पितरों का तर्पण यहीं रामगया घाट में किया. अष्टभुजा पर्वत पर एक गुफा में वना श्रीयंत्र, जो सर्वोच्च तांत्रिक शक्ति का प्रतीक है, जिससे जनसाधारण से लेकर बहुत बड़े तांत्रिक अपनी साधना के अनुसार पूजा किया करते हैं. पूर्व में सैकड़ों मंदिर एवं गुफाए हैं जहां पर अपनी–अपनी मान्यता परम्परा के अनुसार भक्तजन साधना किया करते हैं. यदि एतिहासिक दृष्टि से विश्लेषण करें तो विंध्यपर्वत ही केंद्र विंदु है, जिसके दक्षिण में द्रविण सभ्यता और आर्य सभ्यता विकसित हुई. मानवशास्त्र एवं पुरातत्व की दृष्टि से अध्ययन करें तो यह विश्लेषण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. मनुष्य जीवन का जो भी रहस्य उद्घाटित करना है इसके लिए पूरे विश्व में विध्याचल से महत्वपूर्ण कोई स्थान नहीं है. ■

– सत्यभामा मिश्रा

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@ chauthiduniya.com

व्यायाम कर हृदयरोग से बचें

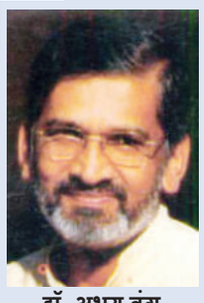

डॉ. अभय बंग

हमारे स्नायु जब काम करते हैं, तब उन्हें आवश्यक ऊर्जा दो तरह से मिल सकती है. अचानक थोड़ी देर तीव्र व्यायाम करते समय स्नायुओं को रक्त का पूरा संचार न होते हुए भी काम करना पड़ता है. तब वह ऐनराबिक (प्राणवायुविहीन) पद्धति से उर्जा का निर्माण करते हैं. इससे जल्दी ही थकान आती है. इसका शरीर पर ट्रेनिंग इफेक्ट नहीं होता. थोड़ी देर व्यायाम और थोड़ी देर आराम–इस प्रकार के व्यायाम के दरम्यान अनरोबिक पद्धति से ऊर्जा उपलब्ध की जाती है.

हृदयरोग से मुक्ति के लिए केवल आहार में परिवर्तन काफी नहीं है. शराब, धूम्रपान व तंबाकू मैं छू नहीं सकता था, क्योंकि पहले भी कभी नहीं लेता था. व्यायाम और तनावमुक्त मन, ये दोनों भी उतने ही आवश्यक थे. मध्यम उम्र में शुरू होने वाले मधुमेह का मुख्य कारण व्यायाम के अभाव में शरीर की मांसपेशियों का इन्सुलिन को प्रतिसाद न देना है. इसी से आगे हृदयरोग और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के निर्माण होते हैं. सच पूछा जाए तो यह रोग एक्सरसाइज डेफिसिएंसी डिजीज है. व्यायाम के अभाव का रोग! अतएव इसका प्रभावशाली उपाय व्यायाम ही हो सकता है. टी. वी. पर और व्यायाम की पुस्तक में हर जगह ऐरोबिक्स का उल्लेख आता है. यह एरोबिक क्या है? 25–30 वर्ष पहले मेडिकल कॉलेज के प्रथम वर्ष में पढ़ी हुई कुछ जानकारी से इसका संबंध निकला. हमारे स्नायु जब काम करते हैं, तब उन्हें आवश्यक ऊर्जा दो तरह से मिल सकती है. अचानक थोड़ी देर तीव्र व्यायाम करते समय स्नायुओं को रक्त का पूरा संचार न होते हुए भी काम करना पड़ता है. तब वह ऐनरॉबिक (प्राणवायुविहीन) पद्धति से ऊर्जा का निर्माण करते हैं. इससे जल्दी ही थकान आती है. इसका शरीर पर ट्रेनिंग इफेक्ट नहीं होता. थोड़ी देर व्यायाम और थोड़ी देर आराम–इस प्रकार के व्यायाम के दरमियान अनरोबिक पद्धति से ऊर्जा उपलब्ध की जाती है. उदाहरण–क्रिकेट में फील्डिंग और बॉलिंग. उसके विपरीत, शुरू में वार्मअप करके फिर लंबे समय तक नियमित गति से स्नायुओं का आकुंचन और प्रसरण करने वाला व्यायाम सतत करते समय एरोबिक पद्धति से ऊर्जा मिलती है.

प्रारम्भ के वार्मअप के बाद स्नायुओं को पूरा रक्तसंचार और प्राणवायु उपलब्ध होती है. इस कारण बिना थकान के लम्बे समय तक यह व्यायाम किया जा सकता है. शरीर के बड़े स्नायु एक स्थिर गति से लम्बे समय तक काम करें, इस तरह के एरोबिक व्यायाम करने से (उदाहरण–चलना, दौड़ना, साइकिलिंग, तैरना) शरीर पर ट्रेनिंग इफेक्ट होता है, शरीर की फिटनेस सुधरती है व हृदयरोग में भी फायदा होता है. कौन–सा व्यायाम करूं? मैं खोजने लगा. खेलना नियमित नहीं हो पाता था. जो लोग 30 मिनट तीव्र गति से चलते हैं, उन्हें आवश्यक व्यायाम भी मिलता है व हृदयरोग का खतरा आधे से भी कम हो जाता है–ऐसा मैंने ऑर्निश की किताब में पढ़ा था. व्यायाम करना खिलाड़ी अथवा पहलवान होना नहीं है. मध्यम व्यायाम पर्याप्त है. मध्यम व्यायाम यानी रोज 30 मिनट तक तेज गति से चलना अथवा उसके समकक्ष और कुछ. सांस फूलने तक दौड़ना, भार उठाना, दंड बैठक करना आदि भारी व्यायाम हृदयरोग टालने के लिए आवश्यक नहीं है. मेरे लिए यह काफी दिलासा देने वाली बात थी. विशेषज्ञों में मान्य दूसरी बात यह जानी कि नो पेन, नो गेन, ये मंत्र गलत है. शरीर तंदुरुस्त करने के लिए व्यायाम में वेदना, दुख होंगे ही; उसके बिना व्यायाम का उपयोग नहीं–यह कल्पना गलत है. उलटे इस वजह से लोग बिना कारण व्यायाम से डरने लगते हैं. यह पढ़कर अच्छा लगा. मुझे बॉडी बिल्डर या एथलीट नहीं बनना था. मुझे आवश्यक मध्यम व्यायाम के लिए शरीर को वेदना तथा कष्ट देने की जरूरत नहीं थी. व्यायाम के अनुभव आनन्ददायी लगते हैं. कितना चलूं? कितनी गति से चलूं? कैसे चलूं? किन बातों का ध्यान रखूं? इनका भी शास्त्र है. चलना–यह मानव के तीस लाख वर्ष के इतिहास का सबसे लंबे समय से चला आ रहा काम है. उसे बचपन में एक–डेढ़ वर्ष की आयु में सीखे हुए तंत्र पर छोड़ देने से नहीं चलेगा. चलने का शास्त्र बनाना पड़ेगा, उसे सीखना पड़ेगा. वह स्वतंत्र एक योग ही होगा. मुझे न आने वाली संस्कृत भाषा में मैंने इस योग को चर योग नाम दे डाला. चलना–यह मानव–संस्कृति में कितना महत्व का है, इसकी एक झलक चर, शब्द से निर्माण हुए शब्दों एवं उनके अर्थों से हमें मिल सकती है. चर (चलने वाला, हिलने–डुलने वाला, जड़ के विपरीत, जंगम) चर (सजीव), चराचर, चरण, चरक (अध्ययन के लिए व्रत रखने वाला) चर्या (घूमना, संस्कार, व्यवहार), दिनचर्या, आचार, आचरण, आचर्य. चलने–खाने से कितना नजदीकी संबंध था, यह चरना शब्द दिखाता है. रोज आधा किलोमीटर चलने से प्रारम्भ करके दो महीने में रोज धीमी गति से तीन किलो मीटर चलने लगा. एंजिओप्लास्टी के 2 माह बाद, जुलाई में मेरा ट्रेडमिल टेस्ट हुआ. उसमें हृदयगति 189 प्रति मिनट होने तक मैं चलने की गति बढ़ा सका. अर्थात एंजिओप्ल–ास्टी से मेरे हृदय की रक्तवाहिनियां अच्छी तरह खुल गई थीं. व्यायाम में खतरा नहीं था. उसके बाद मैं व्यायाम की गति बढ़ाकर 10 मिनट में एक किलोमीटर कर दी और इस गति से रोज 3 किलोमीटर चलने लगा. हर रोज शुरू में वार्मअप के लिए आधा किमी से धीरे–धीरे गति बढ़ाना और 3 किलोमीटर तीव्र गति से चलने के बाद अंत में गति कम करके आधा किमी कूलिंग डाउन के लिए धीरे–धीरे चलना इस प्रकार कुल चार किलोमीटर चलने से बढ़िया व्यायाम होता है. सामान्य मनुष्य के लिए इतनी गति और इतना अन्तर योग्य है. ■

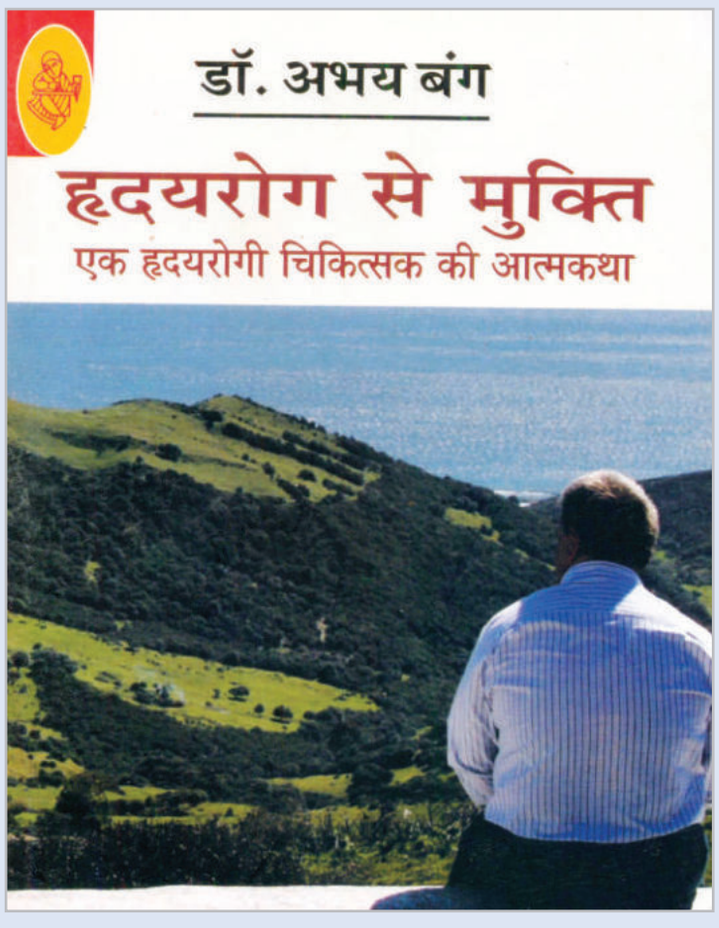

राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित

feedback@chauthiduniya.com

एक बार...

बिजली और तूफान

बहुत समय पहले बिजली और तूफान धरती पर मनुष्यों के बीच रहा करते थे. राजा ने उन्हें मनुष्यों की बस्ती से दूर रखा था. बिजली तूफान की बेटी थी. जब कभी किसी बात पर बिजली नाराज हो उठती तो, वह तड़प कर किसी घर पर गिरती और किसी को जला देती या किसी पेड़ को राख कर देती या खेत की फसल नष्ट कर देती. मनुष्य को भी वह अपनी आग से जला देती थी. जब–जब बिजली ऐसा करती. उसके पिता तूफान गरज–गरज कर उसे रोकने की चेष्टा करते. किन्तु बड़ी ढीठ थी. वह पिता का कहना बिल्कुल नहीं मानती थी. यहां तक की तूफान का लगातार गरजना मनुष्यों के लिए परेशानी बन गया. उसने जाकर राजा से इसकी शिकायत की. राजा को उसकी शिकायत वाजिब लगी. उन्होंने तूफान और उसकी बेटी बिजली को तुरंत शहर छोड़ देने को कहा और बहुत दूर जंगलों में जाकर रहने को कहा. किंतु इससे भी समस्या का समाधान नहीं हुआ. बिजली जब नाराज होती, जंगल के पेड़ जला डालती. कभी–कभी पास के मनुष्यों के खेतों को भी नष्ट कर देती. मनुष्यों को यह भी सहन नहीं हुआ. उसने फिर राजा से शिकायत की. राजा बेहद नाराज हो उठा उसने तूफान और बिजली को धरती से भगा दिया और उन्हें आकाश में रहने की आज्ञा दी, जहां से मनुष्य का उतना नुकसान नहीं कर सकते थे, जितना की धरती पर रहकर करते थे. ■

शिक्षा : क्रोध का फल हमेशा बुरा होता है

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

विवेकानंद विशेष

कई चांद थे सरे–आसमां उपन्यास के बारे में वरिष्ठ आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी का कहना है, कई चांद थे सरे आसमां एक विशिष्ट रचना है. यह उपन्यास दर्शाता है कि जब कोई विद्वान कोई रचनात्मक कृति रचता है तो वह अपने समय के ज्ञान को कथानक में कैसे ढालता है. हिंदी में ऐसी क्षमता हजारी प्रसाद द्विवेदी में थी. शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी जी काफ़ी विद्वान लेखक हैं और इस उपन्यास में अपनी विद्वता को उन्होंने बड़ी ख़ूबसूरती से ढाला है.

रचना संसार

विवेकानंद पर पुनर्पाठ

साहित्य अमृत ने अपने अगस्त अंक को स्वामी विवेकानंद पर केंद्रित किया है. सवा तीन सौ पन्नों के इस महाविशेषांक को पढ़ने के बाद विवेकानंद के विचारों और उनके व्यक्तित्व को मोटे तौर पर समझा जा सकता है. इस अंक में विवेकानंद पर निराला जी का लिखा चर्चित लेख-वेदांत केशरी स्वामी विवेकानंद भी है. अपने इस लेख में निराला ने स्वामी विवेकानंद के चमत्कारी व्यक्तित्व और पराधीनता के दौर में लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करने की उनकी क्षमता को उकेरा है. इसके अलावा इस अंक में विवेकानंद पर लिखे-प्रेमचंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रोम्या रोलां, भगिनी निवेदिता आदि कई विद्धानों के लेख संकलित किए गए हैं.

अनंत विजय

मेरा मानना है कि साहित्यिक पत्र–पत्रिकाएं साहित्य का वो मंच हैं, जहां साहित्य की सभी विधाओं में नई छप रही रचनाओं के अलावा समकालीन साहित्यिक विमर्श और विवादों पर लेखकों की राय और पाठकों की प्रतिक्रिया होती है. हिंदी में इस वक्त नया ज्ञानोदय, हंस, कथादेश और पाखी के अलावा साहित्य अमृत निरंतरता के साथ निकल रही है. हंस और पाखी तो अपने यहां साहित्यिक विवादों को नियमित रूप से जगह देते रहे हैं. कथादेश भी अपने खांचे में अपने पसंदीदा लेखकों से विवादों पर विमर्श करवाते रहते हैं. छिनाल विवाद के पहले ज्ञानोदय में भी साहित्यिक विवादों को जगह मिलती रही थी. लेकिन छिनाल विवाद के बाद ज्ञानोदय ने अपने आपको साहित्यिक विधाओं पर केंद्रित कर लिया है. इन सबके बीच साहित्य अमृत में कभी भी विवादों को जगह नहीं मिली. मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन एक बार मैंने किसी साहित्यिक विवाद पर साहित्य अमृत को एक लेख भेजा था. लेकिन पियूष जी ने बेहद विनम्रतापूर्वक अपनी संपादकीय नीति की जानकारी देते हुए मेरा लेख वापस कर दिया था. पिछले दो साल से मैं लगातार साहित्य अमृत को देख–पढ़ रहा हूं. चौथी दुनिया में एकाधिक बार उसके अंकों और संपादकीयों के बहाने टिप्पणी भी कर चुका हूं. अभी–अभी साहित्य अमृत ने एक बेहद महत्वपूर्ण काम किया है, जिसको हिंदी साहित्य में रेखांकित किया जाना चाहिए. साहित्य अमृत ने अपने अगस्त अंक को स्वामी विवेकानंद पर केंद्रित किया है. सवा तीन सौ पन्नों के इस महाविशेषांक को पढ़ने के बाद विवेकानंद के विचारों और उनके व्यकतित्व को मोटे तौर पर समझा जा सकता है. इस अंक में विवेकानंद पर निराला जी का लिखा चर्तित लेख–वेदांत केशरी स्वामी विवेकानंद भी है. अपने इस लेख में निराला ने स्वामी विवेकानंद के चमत्कारी व्यक्तित्व और पराधीनता के दौर में लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करने की उनकी क्षमता को उकेरा है. इसके अलावा इस अंक में विवेकानंद पर लिखे–प्रेमचंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रोम्या रोलां, भगिनी निवेदिता से लेकर गिरिराज किशोर, देवेंद्र स्वरूप, कृष्णदत्त पालीवाल, बीके कुठियाला, मृदुला सिन्हा तक के लेख संकलित किए गए हैं. संयोग यह है कि इस अंक से साहित्य अमृत के साथ वरिष्ठ लेखक प्रकाश मनु भी संयुक्त संपादक के रूप में जुड़े हैं. अपने संपादकीय में त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी ने विवेकानंद के कोलकाता के एक भाषण का अंश उद्धृत किया है– क्या हमें हमेशा पाश्चात्यों के चरणों में बैठकर हर चीज उनसे सीखनी होगी, यहां तक कि धर्म भी? हम उनसे क्रियाविधि सीख सकते हैं. हम उनसे और कई चीजें सीख सकते हैं. लेकिन हमें भी उन्हें कुछ पढ़ाना होगा और वह है हमारा धर्म, हमारी आध्यात्मिकता. अत: बाहर जाना चाहिए. समानता के बिना मैत्री नहीं हो सकती और हमारा एक पक्ष सदा अध्यापक की तरह रहे और दूसरा सदैव शिष्य की तरह चरणों में बैठे तो समानता नहीं हो सकती. यदि तुम अंग्रेजों अथवा अमेरिकनों से बराबरी चाहते हो तो तुम्हें पढ़ना और उनसे कुछ सीखना होगा और तुम्हारे पास उनको सदियों तक पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है. अब इस कथन से स्वामी विवेकानंद की उस वक्त की सोच को समझा जा सकता है. अपने देश के धर्म और दर्शन में विवेकानंद की अगाध श्रद्धा थी और उनको उसपर भरोसा भी था. उनके उक्त कथन– तुम्हारे पास उनको सदियों तक पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है– से उनका भरोसा साफ तौर पर दिखता है. कुल मिलाकर विवेकानंद पर साहित्य अमृत का यह अंक बेहद उपयोगी और संग्रहणीय है.

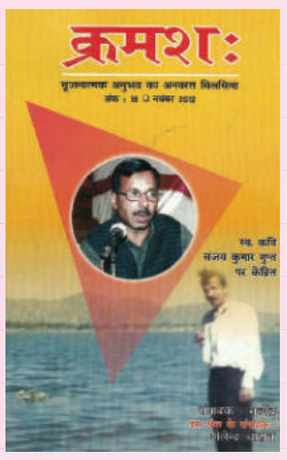

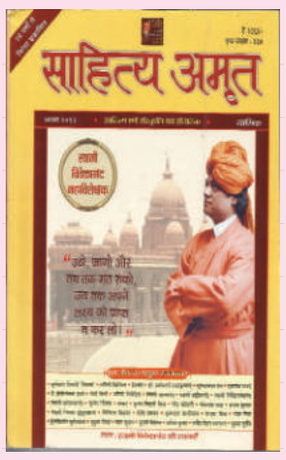

हाल ही में हंस संपादक राजेंद्र यादव ने भागलपुर, बिहार से निकलने वाली पत्रिका किस्सा का अंक भिजवाया. इसके प्रधान संपादक शिवकुमार शिव और संपादक डॉ. योगेंद्र हैं. पत्रिका के मुखपृष्ठ पर भागलपुर विश्वविद्यालय में शिक्षक रहे डॉ. राधाकृष्ण सहाय की भव्य फोटो छपी है. पत्रिका का कवर देखकर मैं एकदम से ठिठका. नब्बे के शुरुआती दशक में एक बार कभी डॉक्टर सहाय से मेरी मुलाकात हुई थी. उस मुलाकात की बहुत धुंधली सी तस्वीर मेरे मन पर है. संभवत: साहित्यिक पत्रिका संवेद के जमालपुर से निकलने का दौर था. डॉ. राधाकृष्ण सहाय को तब मैं एक गंभीर नाटककार के रूप में जानता था. बाद में मुझे पता चला कि वो कहानियां भी लिखते हैं. बाद में यह भी पता चला कि डॉ. सहाय हमारे परिवार से जुड़े हैं. मेरी भाभी बेहद श्रद्धा के साथ डॉ. सहाय और उनकी पत्नी प्रोफेसर मालती को याद करती रहती हैं. इस साल जून में भागलपुर गया था तो यह सोचकर गया था कि डॉ. सहाय से मिलूंगा, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई. शादी में रात भर जगा होने के बाद जब मैं सुनील भैया से मिलने महेश अपार्टमेंट गया तो डॉ. सहाय के बारे में दरियाफ्त की. उनके बारे में काफी चर्चा भी हुई. भैया और बड़की बहिन दोनों बहुत आदर के साथ डॉक्टर सहाय के बारे में बात कर रहे थे. मिलने की इच्छा और प्रबल हो रही थी. लेकिन डॉ. सहाय के भागलपुर से बाहर होने की वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई. अब जब किस्सा के अंक के कवर पर उनकी फोटो देखी तो मुलाकात नहीं हो पाने का अफसोस और बढ़ गया. इस अंक में डॉ. सहाय की कहानी–खुदा हाफिज और संस्मरण के तौर पर ढंग अपना–अपना प्रकाशित है . ढंग अपना–अपना में उनके जर्मनी प्रवास के दौरान पान और पारिवारिक संस्कार का बेहतरीन चित्रण है. संपादकीय में डॉ योगेंद्र ने बताया है कि उनकी कहानी खुदा हाफिज का 1971 में अज्ञेय ने अनुवाद किया था और वॉक पत्रिका में उसको प्रकाशित किया था. डॉ. सहाय की दो रचनाएं पढ़ने के बाद उनकी कहानियां पढ़ने की ललक पैदा हुई है. इस अंक में इसके अलावा राजेंद्र यादव पर दिनेश कुशवाह का लेख देखा जा सकता है. किस्सा पत्रिका का प्रोडक्शन शानदार है. चमकते हुए कागज का उपयोग किया गया है. छपाई सफाई अच्छी है. इसके पहले के दो अंक मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन अगर संपादकगण पत्रिका की निरंतरता बरकरार रख सकें तो आने वाले दिनों में इस पत्रिका में अपनी पहचान बना लेने के संकेत मिल रहे हैं.

एक और पत्रिका–क्रमश: मुझे डाक से मिली. यह पत्रिका सृजनात्मक अनुभव का अनवरत सिलसिला होने का दावा करती है. इसके संपादक सत्येंद्र हैं. पत्रिका का यह अंक कवि लेखक स्व संजय कुमार गुप्त पर केंद्रित है. इस अंक का संपादन शैलेंद्र चौहान ने किया है. संजय कुमार गुप्त बालाघाट में कॉलेज शिक्षक थे और समकालीन हिंदी साहित्य में कविताएं और टिप्पणियां लिखकर हस्तक्षेप कर रहे थे. उनकी असमय मौत से एक संभावनाशील लेखक हमारे बीच नहीं रहा. क्रमश: के इस अंक में स्वर्गीय संजय की रचनाओं को एक जगह इकट्ठा कर पाठकों के सामने रखा गया है. संजय की कविताओं में एक खास किस्म का विद्रोह और विट दोनों दिखाई देता है. जब वो कहते हैं– आओ/गालियों को एक नए सिरे से जिंदा करें/गालियों की प्रशस्ति में गीत लिखें/आज नपुंसकता के देह समय में/शायद गालियां वियाग्रा की गोलियां सिद्ध हों. इस कविता के बिंब आधुनिक हैं. आज की आपाधापी में जब किसी को सिवाए अपने, दूसरे की फिक्र नहीं, वैसे समय में अपने स्वर्गीय मित्र पर अंक पत्रिका का अंक केंद्रित करना आश्वस्तिकारक है. जो रचेगा वो जरूर बचेगा. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं.)

anant.ibn@gmail.com

कविता

तुम कौन हो?

अनिंध्या तोगडे

तुम कौन हो
जो अक्षर के ओठों पर
सरगम रख जाते हो

तुम कौन हो
जो बूंदों के मौसम को
इत्र में भिगो जाते हो

तुम कौन हो
जो बदरियों की आंखों में
कजली आंज जाते हो

तुम कौन हो
जो बात बे–बात याद आते हो
और इक नज़्म हो जाते हो

तुम कौन हो
जो मेरी चुनरी को
आशनाई लगाते हो

तुम कौन हो
जिसने जी लिया मेरा बाहरी मौन
सुन लिया भीतर का शोर
अब, जो शोर और मौन की
भीतर बाहर खाई को पाटने में लगा है
तुम कौन हो आधा सच, आधा झूठ
या आधा–आधा मिलकर
पूरा हो जाने वाला मुकम्मल किरदार
तुम कौन हो
तुम कौन हो
जो अक्सर मेरा
अनलिखा गीत गुनगुनाते हो
मिजाज़ की रज़ा हो जाते हो
तुम कौन हो
तुम कौन हो?

किताब मिली

पुस्तक	लेखक
क़यामत	राही मासूम रज़ा
प्रकाशक	मूल्य
राजकमल प्रकाशन	250 रुपये

आधा गांव, टोपी शुक्ला और ओस की बूंद जैसे उपन्यासों के लेखक राही मासूम रज़ा का राजकमल प्रकाशन से नया उपन्यास आया है–क़यामत. राही ने अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय की तमीज़, तहज़ीब और तालीम को केंद्र में रखकर अपने इस उपन्यास की रचना की है. उन्होंने विश्वविद्यालय संस्कृति को बड़े कलात्मक ढंग से पेश किया है. इस उपन्यास में प्रेम–विवाह और बेरोज़गारी की समस्याओं को भी उन्होंने उठाया है. राही के प्रशंसकों को यह उपन्यास ख़ूब पसंद आएगा.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई–मेल: feedback@chauthiduniya.com

पुस्तक चर्चा

हिंद-इस्लामी तहज़ीब का ऐतिहासिक दस्तावेज़

कृष्णकांत

शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी मौजूदा दौर के महत्वपूर्ण लेखकों में हैं, जिन्होंने उर्दू साहित्य को ऐतिहासिक तौर पर समृद्ध किया है. उन्होंने अपने लेखन और आलोचना के ज़रिये उर्दू साहित्य में एक तरफ़ जहां नये विचारों को जगह दी, वहीं आज के परिदृश्य के मद्देनज़र बेहद रचनात्मक साहित्य रचा है. अपनी बेहतर रचनात्मकता के कारण पद्मश्री प्राप्त फ़ारूक़ी साहब पूरे महाद्वीप में पढ़े और सराहे जाते हैं. पाकिस्तान ने इस वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस के मौक़े पर शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी को अपने मुल्क़ के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार सितारा–ए–इम्तियाज़ से नवाजा. हाल ही पेंगुइन बुक्स प्रकाशन से उनका उपन्यास छपा है– *कई चांद थे सरे–आसमां*, जिसने साहित्य–प्रेमियों की बीच धूम मचा दी. यह उपन्यास 18वीं और 19वीं सदी की हिंद–इस्लामी तहज़ीब से रूबरू कराता है, जिसे उपन्यास की शक़्ल में ऐतिहासिक दस्तावेज़ कहा जा सकता है. सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की रचनाएं पसंद करने वाले पाठकों और आलोचकों से इस उपन्यास की काफ़ी सराहना मिली है. यह कृति जितनी ऐतिहासिक है, उतनी ही राजनीतिक भी है. उपन्यास की कहानी राजपूताने से शुरू होती है और दिल्ली के लालक़िले पर जाकर समाप्त होती है. कहानी में उस दौर की तहज़ीब, साहित्य, समाज, अंग्रेज़ी सियासत और बदलते इतिहास की झलक मिलती है. पाकिस्तानी साहित्यकार इंतज़ार हुसैन ने इस उपन्यास के बारे में टिप्पणी की है कि मुद्दतों बाद उर्दू में एक ऐसा उपन्यास आया है, जिसने हिंदो–पाक की अदबी दुनिया में हलचल मचा दी है. क्या इसका मुक़ाबला उस हलचल से किया जाए जो उमरावजान अदा ने अपने वक़्त में पैदा की थी. इस उपन्यास को उस सदी की हिंद–इस्लामी तहज़ीब में कौमी एकजुटता, ज़िंदगी, मुहब्बत और फ़न की तलाश की दास्तान कहें तो सही होगा.

कई चांद थे सरे–आसमां एक महिला वज़ीर ख़ानम की कहानी है. वज़ीर से ही उपन्यास की शुरुआत होती है. वज़ीर ख़ानम महरौली शरीफ़ ख़्वाजा कुतुबशाह के दरगाह फ़लक बारगाह से अन्य मुसाफ़िरों के साथ लौट रही हैं, तभी रास्ते में ज़बर्दस्त तूफ़ान के चलते वज़ीर की बहली के पहिए टूट जाते हैं. बहली पर सवार सभी मुसाफ़िर रास्ते में ही रुक जाते हैं, तभी एक घुड़सवार और सांडनी पर सवार कुछ लोग आ पहुंचते हैं. इनमें एक अंग्रेज़ मार्स्टन ब्लैक भी है. उन लोगों ने क़ाफ़िले के लोगों को गंतव्य तक पहुंचाया. इस घटना के बाद ब्लैक कभी–कभार वज़ीर से मिलने आने लगा. चंद महीने बाद वह जयपुर रियासत में असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट के ओहदे पर तैनात होकर जयपुर चला जाता है. एक–सवा महीने बाद ब्लैक वापस आता है और वज़ीर ख़ानम को बेग़म बनाकर अपने साथ ले जाता है.

पुस्तक- कई चांद थे सरे-आसमां
लेखक-शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी
प्रकाशन- पेंगुइन बुक्स
मूल्य- 399 रुपये

कुछ समय बाद जयपुर में महाराजा के क़त्ल की आशंका में भीड़ मार्स्टन ब्लैक को मार डालती है. वज़ीर के मार्स्टन ब्लैक से दो औलादें होती हैं, लेकिन उन्हें ब्लैक की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता. उपन्यास की ख़ामी कहें या ख़ूबी कि इसकी कहानी सीधे तौर पर नहीं चलती. इसका शिल्प इस ढंग से बुना गया है कि कहानी बिल्कुल वैसी चलती है, जैसे दुनिया में एक साथ कई–कई घटनाएं घटती हैं और उनका रोज़नामचा आपस में उलझा हुआ रहता है. कहानी के बीच–बीच में तमाम प्रसंग आते हैं. इतिहास आता है. समाज और साहित्य आता है. घटनाओं को लेखक ख़ूब तफ़्सील से बयान करता है. कहानी के केंद्र में वज़ीर ख़ानम हैं, जिनके बहाने लेखक इतिहास के कई अनछुए पहलुओं की पड़ताल करता है. वज़ीर की भी कहानी उपन्यासकार तमाम पात्रों के ज़रिये जुटाता है. बाद में वज़ीर दिल्ली आ जाती हैं. एक दिन वज़ीर दिल्ली के रेजिडेंट बहादुर विलियम फ्रेजर के बुलावे पर एक मुशायरे में जाती है, जिसमें ग़ालिब भी हैं. फ्रेजर, वज़ीर पर फ़िदा था, लेकिन वज़ीर की निगाह शमसुद्दीन खान पर लग जाती है. फ्रेजर और शमसुद्दीन में टकराव की स्थिति बनती है और इस प्रेमयुद्ध में शमसुद्दीन की विजय होती है. इसके बाद फ्रेजर शमसुद्दीन के ख़िलाफ़ षडयंत्र करता है और उनकी जागीर छिन जाती है. शमसुद्दीन इससे बेहद दुखी रहने लगते हैं. इसे देखते हुए शमसुद्दीन का एक विश्वस्त फ्रेजर की हत्या कर देता है. इस प्रकरण में शमसुद्दीन को फांसी हो जाती है. शमसुद्दीन और वज़ीर का प्रेम–प्रसंग काफ़ी रोचक है, जिसका वर्णन उपन्यास के बड़े हिस्से में फैला हुआ है. शमसुद्दीन और वज़ीर ख़ानम से जो बेटा हुआ, वही आगे चलकर दाग़ देहलवी के नाम से मशहूर हुआ. दूसरी ओर शमसुद्दीन की क़ब्र क़दम शरीफ़ के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है और वहां लोग दुआ मांगने पहुंचने लगते हैं. बाद में वज़ीर ख़ानम की तीसरी शादी आगा मिर्ज़ा तुराब से होती है. शायराना मिजाज़ मिर्ज़ा के साथ वज़ीर की भी शायरा जाग उठती है. हालांकि, हाथी–घोड़ों की ख़रीद के लिए सोनपुर गए मिर्ज़ा जब लौट रहे थे, ठगों ने उनका भी क़त्ल कर दिया.

वज़ीर अपने अब बेटे को लेकर दिल्ली में रहने लगती हैं, तभी उनकी ख़ूबसूरती के क़िस्से फैलते हैं. दिल्ली बादशाह के वली अहद सोयम मिर्ज़ा फ़तहुल मुल्क ने उनकी तस्वीर मंगवाई और इश्क़ कर बैठे. वज़ीर की चौथी शादी हो गई. नसीब ने वज़ीर को बादशाहत से मिलवाया तो लेकिन फिर धोखा दे दिया और फ़तहुल मुल्क स्वर्ग सिधार गए और वज़ीर को क़िले से बाहर निकलना पड़ा. क़िले से निकलते वक़्त वज़ीर कहती है–हक़ क्या चीज़ है साहिबे–आलम? सारी ज़िंदगी मैं हक़ की तलाश में रही हूं. वह पहाड़ों की किसी खोह में मिलता हो तो मिलता हो, वरना आसमान तले तो कहीं देखा नहीं गया. इस उपन्यास के बारे में वरिष्ठ आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी का कहना है, कई चांद थे सरे आसमां एक विशिष्ट रचना है. यह उपन्यास दर्शाता है कि जब कोई विद्वान कोई रचनात्मक कृति रचता है तो वह अपने समय के ज्ञान को कथानक में कैसे ढालता है. हिंदी में ऐसी क्षमता हजारी प्रसाद द्विवेदी में थी. फ़ारूक़ी जी काफ़ी विद्वान लेखक हैं और अपनी विद्वता को उन्होंने बड़ी ख़ूबसूरती से ढाला है. उपन्यास मूलत: उर्दू में लिखा गया है और नरेश नदीम से इसका उम्दा अनुवाद किया है. भाषा की रवानगी पढ़ते वक्त ख़ूब मज़ा देती है. हालांकि, 748 पृष्ठों का यह उपन्यास आकार में काफ़ी भारी–भरकम बन पड़ा है, लेकिन धैर्यवान पढ़ाकू पाठकों के लिए यह निश्चित ही अद्भुत उपन्यास साबित होगा. ■

सेल्कॉन ने संगीत प्रेमियों को समर्पित करते हुए अपना नया सेगमेंट रहमान इश्क के नाम से पेश किया है. इसमें ए आर रहमान के संगीत लोड किए गए हैं. मधुर संगीत का मजा लेने के लिए क्लास एंप्लीफायर के साथ डुअल स्पीकर भी दिया गया है.

Windows 8.1 Preview

माइक्रोसॉफ्ट का नया वर्जन 8.1

माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 8 का नया वर्जन 8.1 आ गया है. इसे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से फ्री अपडेट किया जा सकता है. नए बिकने वाले विंडोज कंप्यूटरों में यह ऑपरेटिंग सिस्टम इन्स्टॉल मिलेगा. हम आपको बता रहे हैं, क्या है इसकी खासियत...

विंडोज 8 के जरिए माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को नया रंगरूप मिला था, इसे मेट्रो या मॉडर्न इंटरफेस कहा जा सकता है. सबसे पहले खुलने वाली स्क्रीन पर चौकोर टाइलों में अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स को खोलने की सुविधा है. इसमें मौसम, ट्विटर अपडेट्स एवं खबरें आदि खुद-ब-खुद अपडेट हो जाती हैं. इसके इनोवेटिव फीचर्स लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो कुछ बातों को लेकर यूजर्स में निराशा भी है. इसकी सबसे बडी खामी है स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेन्यू का न होना, जिसकी वजह से यूजर्स अपने मनपसंद सॉफ्टवेयर्स को नहीं खोल सकते. हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने यूजर्स की शिकायतों पर गौर करते हुए विंडोज 8.1 में कुछ नए बदलाव किए हैं. अब इसमें कुछ फीचर्स हटा दिए गए, कुछ बदल गए और कुछ नए ऐड कर लिए गए हैं.

खास बदलाव

1. स्टार्ट बटन: विंडोज 8.1 में भी स्टार्ट मेन्यू नहीं है, लेकिन स्टार्ट बटन एक अलग स्टाइल में लगाया गया है. स्टार्ट स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में नीचे की ओर एक गोल बटन है, जिसे दबाने पर कंप्यूटर के ज्यादातर सॉफ्टवेयर्स और सर्विसेज के आइकन दिखाई देते हैं. इस पर राइट क्लिक करने से भी एक मेन्यू खुलता है, जिस पर कई उपयोगी सॉफ्टवेयर्स-सर्विसेज मौजूद हैं.

2. स्टार्ट स्क्रीन: विंडोज 8 में सॉफ्टवेयर्स और सर्विसेज के लिए बतौर आइकन इस्तेमाल की जाने वाली टाइल्स सिर्फ दो आकार, छोटे और बड़े, में उपलब्ध थीं. अब ये चार आकारों में मिलेगी. यानी स्टार्ट स्क्रीन पर ज्यादा ऐप्लिकेशन और सॉफ्टवेयर्स लाए जा सकते हैं. अब स्टार्ट स्क्रीन का बैकग्राउंड भी बदला जा सकता है.

3. डेस्कटॉप: कुछ लोग विंडोज 8 खोलने पर टाइल्स वाली स्टार्ट स्क्रीन की बजाए पुराने विंडोज वाले डेस्कटॉप को ही पसंद कर रहे हैं. अब विंडोज के कनफिगरेशन में ऐसा बदलाव किया जा सकता है, जिससे सिस्टम स्टार्ट होने पर सीधे डेस्कटॉप दिखाएगा. ठीक वैसे ही जैसे विंडोज 7 में होता है.

4. दो इंटरनेट एक्सप्लोरर: विंडोज 8 में इंटरनेट ब्राउजर के दो अलग-अलग एडिशन थे, जो यूजर को कन्फ्यूज करते हैं. नए विंडोज में भी दोनों ज्यों के त्यों बने हुए हैं. हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसे ब्राउजर के नए वर्जन (इंटरनेट एक्स्प्लोरर 11) से लैस किया है, जो पहले से ज्यादा तेज है.

5. सर्च: विंडोज 8 में सर्च को तीन अलग-अलग सेक्शन में बांटा गया था, जो कभी-कभी कंफ्यूज करता था. नए एडिशन में इन्हें मिलाकर एक ही सर्च ऑप्शन दिया गया है. यह हर तरह की सर्च कर सकता है- ऐप्लिकेशन, फाइलें, फोल्डर, सेटिंग्स, सॉफ्टवेयर और वेब भी.

6. ऑनलाइन अकाउंट: विंडोज 8.1 टैबलेट्स की ही तरह आपके इंटरनेट अकाउंट के साथ जुड़े रहना चाहता है. यानी लॉग-इन के समय आपको माइक्रोसॉफ्ट आईडी और पासवर्ड डालना होगा. यह यूजर्स को अखर सकता है. हालांकि आप चाहें तो अपने लोकल अकाउंट के जरिए भी कंप्यूटर चला सकते हैं.

7. विंडोज स्टोर: विंडोज 8 ने टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तर्ज पर अपने ऐप स्टोर की शुरुआत की थी. जहां से मनचाहे ऐप्लिकेशन्स डाउनलोड किए जा सकते थे. विंडोज 8.1 में इनकी संख्या काफी बढ़ी है.

8. अन्य बदलाव: विंडोज के नए एडिशन में वायरलेस तकनीकों में कई सुधार हुए हैं, जैसे वायरलेस प्रिंटिंग और वायरलेस डिस्प्ले के लिए बेहतर सपोर्ट. इन दिनों 3 डी प्रिंटिंग काफी चर्चा में है. नई विंडोज में 3डी प्रिंटर का भी सपोर्ट है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

माइक्रोमैक्स फनबुक टैब

इस टैबलेट में 3जी के साथ 2जी डाटा भी है. माइक्रोमैक्स फनबुक टैब मिनी पी 410 में कपैसिटिव टच इनपुट और 1024 गुणा 600 पिक्सल रिज्योलूशन के साथ 7 इंच का डिस्प्ले भी है. इसके अलावा माइक्रोमैक्स फनबुक टैब मिनी पी 410 में ब्लुटूथ कनेक्टिविटी भी है.

पहले कैनवास सीरीज टैबलेट कैनवास टैब पी 650 को लांच करने के बाद माइक्रोमैक्स ने अपना दूसरा टैबलेट फनबुक टैब मिनी पी 410 लांच किया है. इसमें डुअल सिम कनेक्टिविटी का ऑप्शन दिया गया है. कॉलिंग की सुविधा दोनों सिम से उपलब्ध है. इस टैबलेट में 3जी के साथ 2जी डाटा भी है. माइक्रोमैक्स फनबुक टैब मिनी पी 410 में कैपसिटिव टच इनपुट और 1024 गुणा 600 पिक्सल रिज्योलूशन के साथ 7 इंच का डिस्प्ले भी है. माइक्रोमैक्स फनबुक टैब मिनी पी 410 में ब्लुटूथ कनेक्टिविटी भी है. फनबुक टैब मिनी पी 410 में एंड्रायड जेली बीन 4.1 के साथ इसके पार्श्वभाग में 2 मेगापिक्सल फोकस कैमरा और अग्रभाग में 0.3 मेगापिक्सल कैमरा है जो वीडियो चैटिंग को सुविधाजनक बनाता है. साथ ही इसमें डुअल कोर प्रोसेसर है, जो 1 जीएचजेड, 1 जीबी रैम और 4 जीबी के ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ उपलब्ध है. इसमें से यूजर्स 2.4 जीबी का उपयोग कर सकते हैं. यूजर्स माइक्रोएसडी कार्ड से 32 जीबी स्टोरेज का उपयोग भी कर सकते हैं. इसमें 2800 एमएएच बैटरी है, जो 4 घंटे का इंटरनेट उपयोग प्रदान करती है. माइक्रोमैक्स फनबुक टैब पी 410 की कीमत 8,820 रुपये रखी गई है. ■

खास है रहमान इश्क

सेल्कॉन ने रहमान इश्क नाम से नया एंड्रायड स्मार्टफोन लांच किया है. इसे कंपनी ने जाने माने भारतीय संगीतकार ए आर रहमान को समर्पित किया है. सेल्कॉन रहमान इश्क एआर45 में ए आर रहमान के संगीत लोड किए गए हैं. संगीत प्रेमियों को समर्पित करते हुए मोबाइल फोन कंपनी ने अपना पहला म्यूजिक फोन लॉन्च किया है. इसमें 1.2 जीएचजेड डुअल कोर प्रोसेसर व ग्राफिक प्रोसेसर है. ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रायड जेली बिन 4.2.2 पर आधारित यह फोन 512 एमबी व 4जीबी इंटरनल मेमोरी के साथ है, मेमोरी को माइक्रोएसडी कार्ड के सहारे 32 जीबी तक किया जा सकता है. इसमें स्टीरियो एफएम रेडियो रिसीवर इनबिल्ट है. साथ ही इसमें 5 मेगापिक्सल रियर कैमरा तथा विडियो रिकॉर्डिंग भी है. इसकी कीमत 7,999 रुपये रखी गई है.■

नई इनोवा

टोयोटा किर्लोस्कर ने अपनी नई सेगमेंट पेश की है. इसकी कीमत 12.45-15.06 लाख रुपये है. नई इनोवा स्पोर्ट्स में अन्य फीचर्स के साथ ही नई फ्रंट ग्रिल, क्रोम लाइंड फॉग लैंप शामिल हैं.

टोयोटा किर्लोस्कर ने अपने फ्लैगशिप मॉडल इनोवा की सेल्स बढ़ाने के लिए इसका नया वर्जन लॉन्च किया है. फेस्टिव सीजन में सेल्स बढ़ाने की मकसद से पेश किए गए इस वर्जन की कीमत 12.45-15.06 लाख रुपये. नई इनोवा स्पोर्ट्स में अन्य फीचर्स के साथ ही नई फ्रंट ग्रिल, क्रोम लाइन्ड फॉग लैम्प शामिल हैं. इसमें एडीशनल प्रीमियम ग्रेड जेड वेरिएंट भी है, जिसमें बॉडी ग्राफिक्स, स्पोर्टी रियर स्पॉइलर और प्रीमियम इंटीरियर्स दिए गए हैं. इसकी गियर नॉब वुड फिनिश वाली है और इसके साथ ही वुड पैनल डैशबोर्ड और लेदर सीट्स दी गई हैं. टोयोटो किर्लोस्कर मोटर के डीएमडी और सीओओ संदीप सिंह कहते हैं कि नई इनोवा से फेस्टिव सीजन में इस मॉडल की सेल्स 10-15 फीसदी और बढ़ सकती है. ■

सैमसंग गैलेक्सी ट्रेंड ड्यूओस

सैमसंग गैलेक्सी ट्रेंड ड्यूओस ऑफिशली भारत आ गया है. यह कंपनी की ऑफिशल वेबसाइट से 8,700 रुपए में खरीदा जा सकता है. हालांकि कुछ ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर यह 8,500 रुपए से कम में भी उपलब्ध है. सैमसंग ने अभी तक भारत में इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है. ड्यूल सिम सपोर्ट वाले इस स्मार्टफोन में 480-800 पिक्सल्स रेजोलूशन वाला 4 इंच का डिस्प्ले है. यह एंड्रायड 4.0 आइसक्रीम सैंडविच ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है. 1 गीगाहर्ट्ज डुअल-कोर प्रोसेसर और 512 एमबी रैम है. पीछे की तरफ 3 मेगापिक्सल का कैमरा है. फ्रंट कैमरा नहीं है. 4 जीबी इंटरनल स्टोरेज है और 32 जीबी तक का मेमोरी कार्ड लगाया जा सकता है. बैटरी 1600 एमएच की है. कनेक्टिविटी ऑप्शंस में 3जी, ब्लुटूथ, वाई-फाई और जीपीएस/एजीपीएस शामिल हैं. इसमें हिंदी, बंगाली, पंजाबी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तेलगु और तमिल जैसी भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है. ■

दमदार माइलेज देगी महिंद्रा सेंचुरो

पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए महिंद्रा सेंचुरो एक अच्छा विकल्प हो सकती है. यह बाइक आपको कम कीमत में ज्यादा माइलेज देगी. इसके स्टाइल और डिजाइन की बात करें तो सबसे पहली नजर इसके सुनहरे गोल्ड फ्रेम पर जाती है. यह फ्रेम इसे एक अलग हैवी लुक देता है. इस बाइक की व्हील बेस भी काफी लार्ज है. सीट लंबी और आरामदेह है. कंपनी ने राइडर की पोजीशन को भी ध्यान में रखा है, जिससे बाइक राइडर लंबे सफर में भी ज्यादा थकान महसूस नहीं करेगा. इसकी हैंडलिंग काफी स्मूथ है. वजन 111 किलो है, जो शहरी ट्रैफिक के मद्देनजर काफी अच्छा है. तेल की टंकी 12.7 लीटर की दी गई है. इसके अलावा, कंपनी ने इसमें अलार्म भी दिया है, जो आपको सैकड़ों बाइक में आपकी बाइक को ढूंढ़ने में मदद करेगा. इसका सबसे बढ़िया पार्ट इसका एंटी थेफ्ट सिस्टम है. कंपनी का दावा है कि यह बाइक चोरी नहीं हो सकती है. इंजन 106.7 सीसी का है. इसका इंजन 4 स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर एवं एयर कूल्ड है. इसके इंजन में एमसीआई5 तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो इसकी पॉवर और माइलेज में एक बढ़िया सामंजस्य बैठाती है. इसका इंजन टॉप 7500 आरपीएम पर 8.5 एनएम का टार्क पॉवर देता है. सेंच्यूरो चार गेयर ट्रांसमिशन वाली बाइक है, जिसकी अधिकतम रफ्तार 95 किमी प्रतिघंटा है. इसकी मेंटेनेंस फ्री बैटरी चालक को टेंशन फ्री रखती है. इसके अलावा, इसकी एमसीआई5 तकनीक इसे शानदार माइलेज देती है. हाइवे पर इसका माइलेज 85 किमी तक है, जबकि शहर में ये 60-70 किमी तक का एवरेज देती है. बाइक में सुरक्षा को लेकर भी किसी तरह का समझौता नहीं किया गया है. इसकी रिमोट फ्लिप इसे चोरी होने के भय से मुक्त रखती है. इसमें एलईडी टॉर्च भी दिया गया है. बाइक का अलार्म आपको पार्किंग में भी बाइक खोजने में मदद करता है. वहीं चोरी होने पर आप अपनी की से इसका इंजन बंद कर सकते हैं. कम दाम में फीचर के मामले में ये शानदार है. इसके अलावा पांच साल की वारंटी, कम कीमत, शानदार सेफ्टी फीचर, बढ़िया आरामदायक सफर और माइलेज इसका प्लस पाइंट है. लुक थोड़ा पुराना, ओल्ड फैशन है, इसका फ्रेम काले रंग में तो बेहतर है, लेकिन बाकी रंगों के साथ जंचता नहीं है, 60 की रफ्तार से पर बाइक स्मूथ नहीं रहती है. इस बाइक की ये कुछ खामिया हैं. इस बाइक की एक्स शो रूम कीमत मात्र 45 हजार है, जबकि इस सेगमेंट की बाइक की कीमत इससे ज्यादा है. ■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

सचिन के पिता ने उनका नाम संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा था. सचिन ने मैदान पर बल्लेबाज़ी की ऐसी तान छेड़ी कि विरोधी भी उनकी प्रशंसा करने से नहीं चूके. जिस किसी ने उनके साथ क्रिकेट खेला और ड्रेसिंग रूम शेयर किया, उनमें कोई भी ऐसा नहीं था, जो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित न हुआ हो.

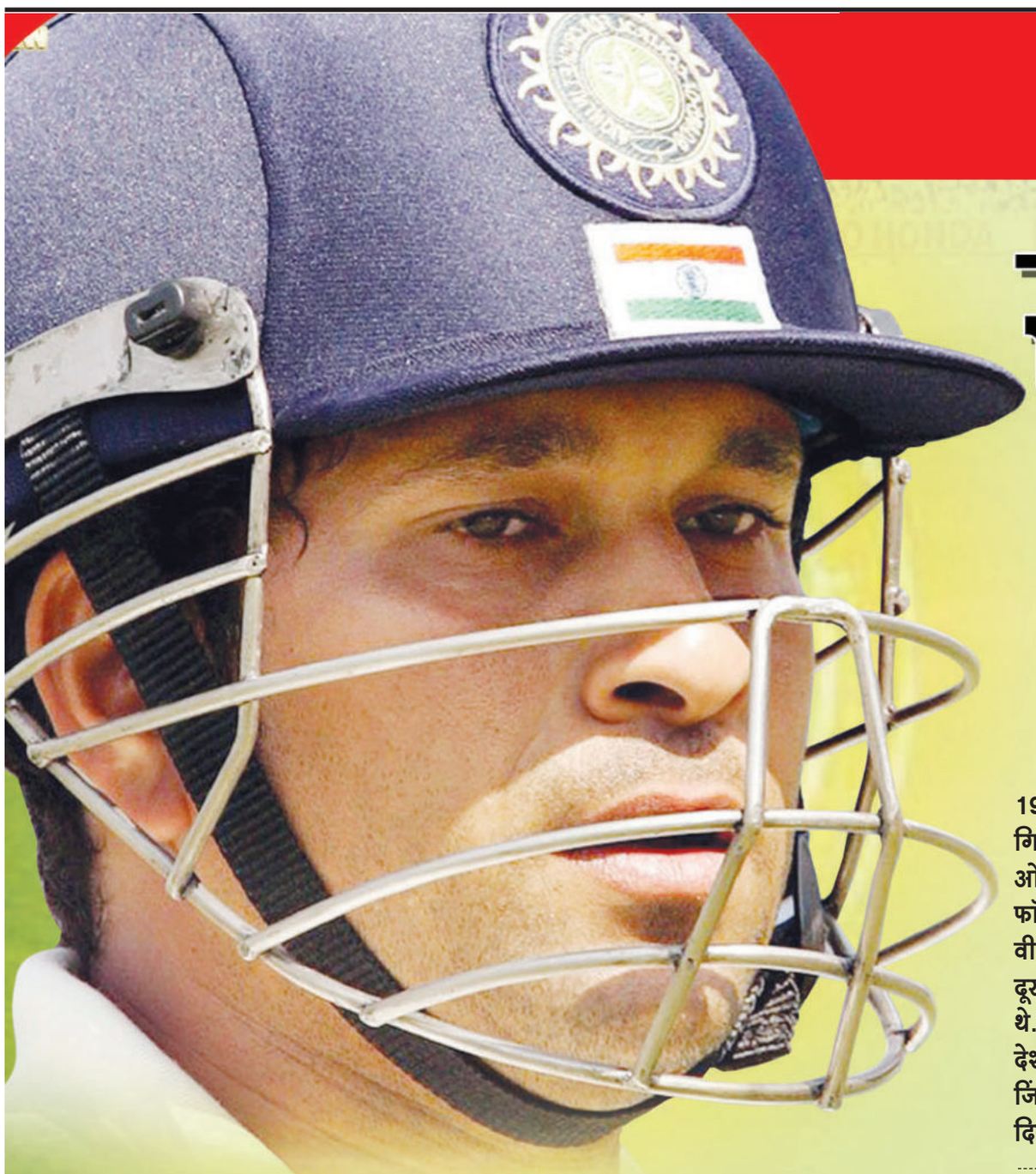

अलविदा

सचिन रिकॉर्ड तेंदुलकर

1989 में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ सचिन ने अपना पहला टेस्ट खेला. यह वह दौर था जब बर्लिन की दीवार गिराई जा रही थी. मार्गेट थ्रेचर इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थीं. सोवियत संघ विघटित नहीं हुआ था. अमेरिकी राष्टपति बराक ओबामा हॉवर्ड लॉ स्कूल में दाखिला ले रहे थे. पीट सैंप्रास ने एक भी ग्रैंड स्लैम नहीं जीता था. माइकल शूमाकर ने फॉर्मूला वन करियर की शुरुआत भी नहीं की थी. देश में राजीव गांधी सरकार को सत्ता से बेदखल कर पूर्व प्रधानमंत्री वी पी सिंह पहली अल्पमत की सरकार बना रहे थे. देश की अर्थव्यवस्था को खोलने की प्रक्रिया शुरू तक नहीं हुई थी. दूरदर्शन इकलौता टीवी चैनल था. हमारी जिंदगी में मोबाइल शामिल नहीं हुआ था और लोगों के फोन पड़ोस में आते थे. मौजूदा भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ आठ साल के थे. 1989 से 2013 तक इन 24 सालों में देश और दुनिया ने कई करवटें बदलीं. लेकिन सचिन तेंदुलकर नहीं बदले. 11 साल की उम्र में क्रिकेट सचिन की जिंदगी का हिस्सा बना और 24 साल के इस मैरथन सफर में सचिन ने क्रिकेट को सभी की जिंदगी का हिस्सा बना दिया. इसीलिए संन्यास की घोषणा करते हुए सचिन ने कहा कि मैं बिना क्रिकेट के कैसे जिंदा रहूंगा?

नवीन चौहान

	मैच	पारी	रन	औसत	शतक	अर्धशतक	उच्चतम
टेस्ट	198	327	15837	53.86	51	67	248*
वन-डे	463	452	18426	44.83	49	96	200*
टी-20	96	96	2797	32.90	1	16	100*

सब धरती कागद करूं, लेखन सब बनराय, सात समुद्र की मसि करूं, सचिन गुन लिखा न जाए. सारी धरती को कागज़ कर दूं, और दुनिया की सारे पेड़ों को लेखनी बना लूं और सातों समुद्र को स्याही की तरह उपयोग में लाऊं, बावजूद इसके सचिन के गुणों और रिकॉर्डों का बखान करने में सब कुछ कम पड़ जाएगा. क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर ने आखिरकार क्रिकेट को अलविदा कह दिया. सचिन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट खेला नहीं उसे जिया. शायद उस दिन क्रिकेट खुद सबसे ज्यादा दुःखी होगा, जब उसका सबसे प्यारा लाड़ला आखिरी बार मैदान पर अपने बल्ले का हुनर दिखाने उतरेगा. उसके बाद यह बहस होनी बंद हो जाएगी कि सचिन टीम में शामिल हों या न हों या उम्र अब सचिन पर भारी हो रही है. लेकिन इस बात को लेकर किसी बहस की उम्मीद नहीं की जा सकती है कि जब भी पूरे विश्व में क्रिकेट का जिक्र किया जाएगा निर्विवाद रूप से सचिन की तस्वीर सबसे पहले उभर आएगी. आज से 24 साल पहले वर्ष 1989 में महज 15 साल की उम्र में टेस्ट पदार्पण करना किसी अजूबे से कम नहीं था. लेकिन आज 24 साल बाद वह छोटे कद का खिलाड़ी अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को 200 वां टेस्ट मैच खेलने का विश्व कीर्तिमान बनाकर अलविदा कहने जा रहा है. निश्चित तौर पर यह दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों खासकर सचिन के प्रशंसकों के लिए सबसे निराशा भरा दिन होगा.

सालों भारतीय टीम को वन मैन आर्मी के रूप में जाना गया. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मार्क टेलर के शब्दों में कहें तो हम भारत कहलाने वाली टीम से नहीं हारे, बल्कि हम सचिन नाम के शख्स से हारे. सचिन सालों, अकेले अपने कंधों पर एक अरब भारतीयों की आशाओं का बोझ लिए चलते रहे और भारतीय क्रिकेट को सुनहरे लम्हे देते रहे. आज उनके नाम क्रिकेट में बल्लेबाजी के अधिकांश रिकॉर्ड दर्ज हैं. एक बार सचिन के खेल की तारीफ करते हुए जिंबाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर ने कहा था कि दुनिया में दो तरह के बल्लेबाज़ हैं, पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा अन्य. इसी तरह सचिन को भगवान मानने वाले खिलाड़ियों की भी कमी नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रारंभिक बल्लेबाज मेथ्यू हेडेन ने कहा था कि मैंने भगवान को देखा है और वह भारत के लिए टेस्ट मैचों में नंबर चार पर बल्लेबाज़ी करता है. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बार कहा कि मैं क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, बावजूद इसके मैं सचिन को खेलता देखता हूं. इसलिए नहीं कि मैं सचिन का खेल पसंद करता हूं बल्कि इसलिए क्योंकि मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सचिन बल्लेबाज़ी कर रहे होते हैं तो हमारे देश के उत्पादन में पांच प्रतिशत की गिरावट क्यों आती है? आम हो या खास हर कोई सचिन को बहुत प्यार करता है. किसी को सचिन में एक संपूर्ण खिलाड़ी नजर आता है, तो किसी को एक अच्छा इंसान. शायद इसी वजह से क्रिकेट के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक ब्रायन लारा अपने बेटे को सचिन तेंदुलकर बनाना चाहते हैं.

पिछले साल दिसंबर में सचिन ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली एक दिवसीय सीरीज के पहले बीसीसीआई को पत्र लिखकर एकदिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी. तब सचिन ने ऐसा करके अपने प्रशंसकों को निराश किया था. लोग अपने हीरो को पर एक बेहतरीन विदाई देना चाहते थे. लेकिन इस बार सचिन ने पहले ही अपने संन्यास की घोषणा कर दी है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने अंतिम दिन की घोषणा करते हुए सचिन ने कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन में देश के लिए क्रिकेट खेलने का सपना देखा था. पिछले 24 वर्षों में मैं रोजाना इसी सपने के साथ जिया. मेरे लिए इस बात की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है कि क्रिकेट के बिना मेरा जीवन कैसा होगा. मेरे लिए क्रिकेट के बिना खुद को महसूस कर पाना भी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि 11 वर्ष की उम्र से मैं यही करता आ रहा हूं. पूरी दुनिया में क्रिकेट खेलते हुए अपने देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गौरव की बात रही है. इतने सालों में बीसीसीआई से मुझे जो कुछ मिला है, उसका मैं बहुत आभारी हूं. उसने मुझे वह फैसला लेने की इजाजत दी है जो मेरा दिल कह रहा है. मैं अपने परिवार का उनके धैर्य और समझ के लिए शुक्रिया अदा करता हूं. मैं अपने प्रशंसकों और शुभचिंतकों का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अपनी प्रार्थनाओं और दुआओं से मुझे मैदान में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की ताकत दी. मैं अपने घरेलू मैदान पर करियर का आखिरी टेस्ट मैच खेलूंगा.

सचिन ने एक नन्हे से खिलाड़ी के रूप में अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरूआत करके पूरी दुनिया को अपनी बल्लेबाजी से चमत्कृत कर दिया था. उनके मुरीदों में क्रिकेट के डॉन, सर डॉन ब्रैडमैन भी शामिल थे. जिन्हें अपनी बल्लेबाजी की झलक सचिन की बल्लेबाजी में नज़र आती थी. शायद ही दुनिया में कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो तीन पीढ़ी के खिलाड़ियों के साथ खेला हो और जिसे तीन पीढ़ियों ने खेलते भी देखा हो. इतना ही नहीं, तीनों ही पीढ़ी के लोग उसके खेल के प्रशंसक हों. सचिन की धैर्य, संयम और तकनीकि से परिपूर्ण बल्लेबाजी शैली ने उन्हें दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज बनाया. उनका 24 साल लंबा करियर चोटों से प्रभावित रहा, लेकिन हर बार चोट से उबरकर सचिन ने न केवल धमाकेदार वापसी की बल्कि हर बार ऐसा मुकाम हासिल किया जिसके आस पास भी भटक पाना किसी भी बल्लेबाज़ के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. सचिन अपने टेस्ट करियर में तिहरा शतक नहीं लगा सके जबकि उनके समकक्ष रखे जाने वाले अधिकाश बल्लेबाज़ तिहरा शतक लगाने में कमयाब रहे. वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज़ सर विवियन रिचर्डस सचिन के आदर्श थे. सचिन उनकी तरह आक्रामक शैली में बल्लेबाज़ी करने के लिए जाने जाते हैं, सचिन ने अपनी बल्लेबाजी से एकदिवसीय क्रिकेट का चरित्र ही बदल डाला. क्रिकेट के मैदान में आई तेजी का श्रेय सचिन को दिया जाना चाहिए.

सचिन के पिता ने उनका नाम संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा था. सचिन ने मैदान पर बल्लेबाजी की ऐसी तान छेड़ी कि विरोधी भी उनकी प्रशंसा करने से नहीं चूके. जिस किसी ने उनके साथ क्रिकेट खेला और ड्रेसिंग रूम शेयर किया, उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित न हुआ हो. सचिन एक बेहतरीन खिलाड़ी होने के साथ ही एक बेहतरीन व्यक्तित्व वाले इंसान हैं. उनके जितना विनम्र स्वाभाव का खिलाड़ी होने अनोखी बात है. क्रिकेट के मैदान पर सचिन ने बल्लेबाजी से ऐसा मंत्रमुग्ध किया कि शेनवार्न के साथ साथ प्रशंसकों को भी सपनों में उनके छक्के लगाते नज़र आते थे.

सचिन ने एक बार फिर यह साबित किया कि उम्र तो महज एक आंकड़ा है. खेल के लिए जब्बे और जुनून की जरूरत होती है. और सचिन के अंदर दोनों ही कूट कूट कर भरा हुआ है. आज भी सचिन नेट प्रेक्टिस में पहुंचने वाले सबसे पहले और वापस जाने वाले सबसे अंतिम खिलाड़ी होते हैं. सचिन के समकक्ष और समकालीन ब्रायन लारा जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी सचिन से बहुत पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. लेकिन सचिन अब तक मैदान में खूंटा गाड़े हुए हैं. सचिन पर किसी ने संन्यास लेने का दबाव नहीं डाला उन्होंने यह फैसला स्वयं बहुत सोच समझ कर लिया है. जिस मुंबई की धरती पर उन्होंने पहली बार बल्ला थामा, जिस धरती पर उन्होंने विश्वकप पर कब्जा किया, उसी मुंबई की धरती पर वह आखिरी बार अपने बल्ले का जौहर दिखाते नज़र आएंगे.

सचिन को पूरे करियर में बेइंतहां प्यार, पैसा और प्रसिद्धि मिली. यह सब कभी भी सचिन के सिर चढ़कर नहीं बोला. न ही सचिन का नाम कभी किसी विवाद में आया. 1999 में फिक्सिंग के दौर में वह काजल की कोठरी से बेदाग निकल आए और क्रिकेट में लोगों का विश्वास बनाए रखने में बेहद अहम भूमिका अदा की. सही मायने में वह क्रिकेट के ब्रैंड एंबेस्डर हैं. उम्र के चालीसवें पड़ाव पर पहुंचने के बावजूद वह युवाओं के आदर्शष हैं. सचिन ने भारत का नेतृत्व करके देश के सम्मान में चार चांद जड़ दिए. आज सचिन भारत में खेलों के पर्याय हैं. सचिन ही वह सख्श हैं जिसके कारण हमारे देश में खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब वाली सोच बदल सकी और लोग खेलों को करियर के रूप में स्वीकार कर सके. इसका सारा श्रेय सचिन को ही जाता है.

भारतीय क्रिकेट के पितामह सचिन तेंदुलकर को भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित नज़र आने लगा है, शायद इसीलिए उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया है. किसी भी खेल में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो उस खेल का हिस्सा बन जाते हैं और कुछ खिलाडी ऐसे होते हैं जो स्वयं खेल का पर्याय बन जाते हैं. सचिन एक ऐसे खिलाड़ी है जिसने क्रिकेट का ऐसा इतिहास लिखा है जिसे क्रिकेट जगत हमेशा याद रखेगा. दुनिया भर में जब–जब इस इतिहास को पढ़ा जाएगा तब– तब सचिन को सराहा जाएगा. 15 नवंबर 1989 को जब सचिन ने पदार्पण किया था तो वह भारतीय क्रिकेट के लिए स्वीट नवंबर बन गया, लेकिन इस बार सचिन का बल्ला उसी नवंबर के महीने में थमने जा रहा है, सचिन के करोड़ों प्रशंसकों के लिए अब नवंबर अब स्वीट नवंबर नहीं रह जाएगा. ■

सालों भारतीय टीम को वन मैन आर्मी के रूप में जाना गया. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मार्क टेलर के शब्दों में कहें तो हम भारत कहलाने वाली टीम से नहीं हारे, बल्कि हम सचिन नाम के शख्स से हारे. सचिन सालों, अकेले अपने कंधों पर एक अरब भारतीयों की आशाओं का बोझ लिए चलते रहे और भारतीय क्रिकेट को सुनहरे लम्हे देते रहे.

feedback@chauthiduniya.com

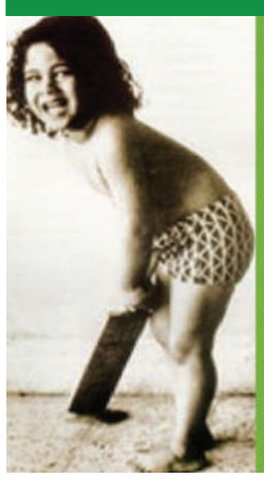
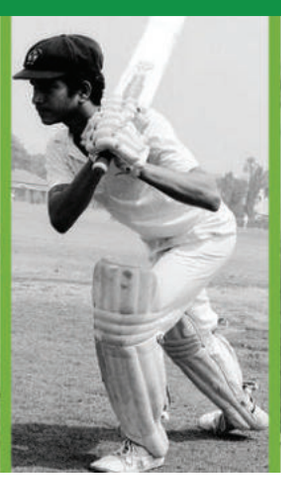
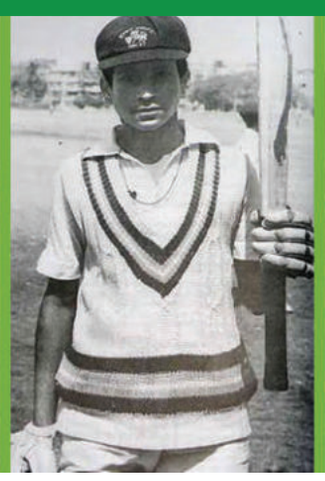

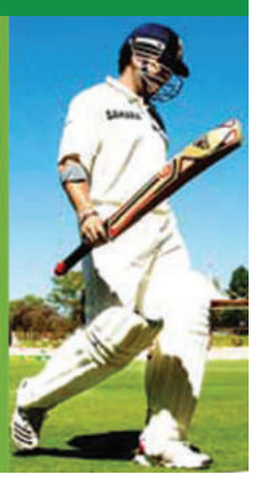

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

www.chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

जगमग दुनिया

21 अक्टूबर–27 अक्टूबर 2013

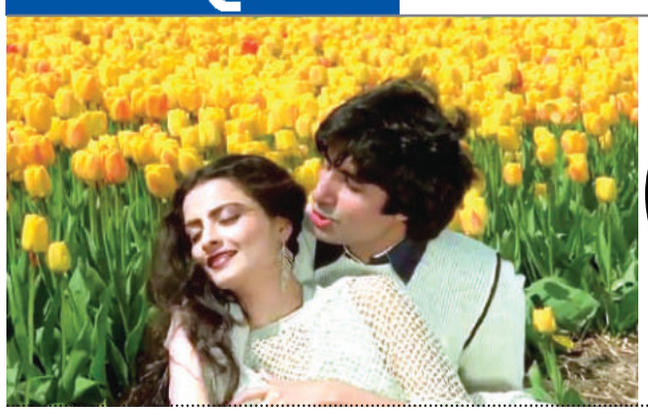

वर्ष 1996 में रेखा कि फिल्म आई कामसूत्र. इस फिल्म में उनके बोल्ड अवतार की काफ़ी निंदा हुई, क्योंकि लोग अब रेखा से प्यार करने लगे थे. वे हर वर्ग की पसंद बन गईं थीं, उनकी फिल्मों को लोग परिवार के साथ बैठ कर देखते थे. ऐसे में उन्हें रेखा को इस तरह की फिल्मों में देखना कतई गंवारा न था. हालांकि रेखा ने सिर्फ़ एक कलाकार के तौर पर इस फिल्म को किया था.

मैं और मेरी तन्हाई

इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारो हैं
इन आंखों से बावस्ता अफसाने हजारों हैं
एक तुम ही नहीं, तन्हा उल्फत में मेरी रुसवा
इस शहर में तुम जैसे, दीवानें हज़ारों हैं
एक सिर्फ़ हम ही मय को आंखों से पिलाते हैं
कहने को तो दुनिया में मयखाने हज़ारों हैं
इस शम-ए-फ़रोज़ा को आंधी से डराते हो
इस शम-ए-फ़रोज़ा के परवाने हज़ारों हैं

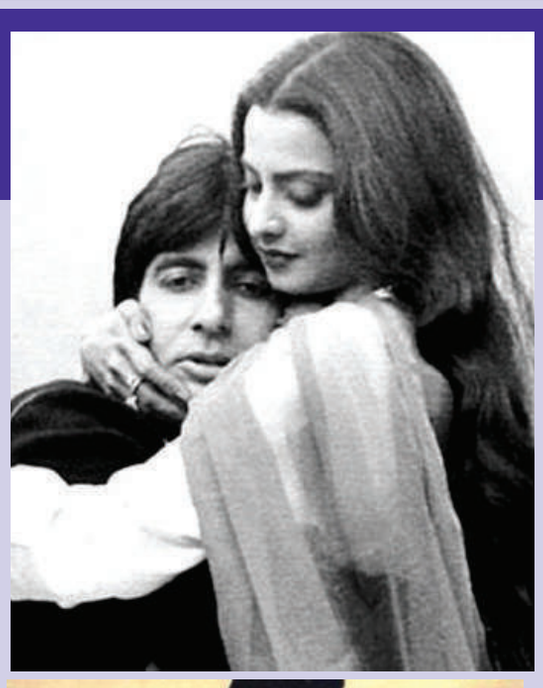

प्रियंका तिवारी

अपनी ख़ूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी के लिए जानी जाती हैं रेखा. इतने वर्षों बाद भी रेखा का जादू कुछ इस तरह बरक़रार है कि आज भी उनका जिक्र होने पर लोग दिल थाम लेते हैं. रेखा के बारे में कहा जाता है कि उनकी ज़िंदगी रहस्यों से भरी हुई है. लोग उन्हें जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं. अपने समय में रेखा ने सिल्वर स्क्रीन पर रूल किया था और आज भी उनके लिए लोगों की चाहत कुछ कम नहीं हुई है. वह लाखों करोड़ों दिलों की मल्लिका हैं, लेकिन उन्हें कभी सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ.

रेखा का जन्म 10 अक्टूबर, 1954 हुआ था. उनका असली नाम भानुरेखा गणेशन है, लेकिन हिंदी सिनेमा में वह रेखा के नाम से ही जानी गईं. रेखा के पिता जेमिनी गणेशन दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार थे. उनकी मां पुष्पावल्ली भी अभिनेत्री थीं. रेखा की मां जेमिनी गणेशन की दूसरी पत्नी थी. रेखा की एक और बहन है राधा, लेकिन रेखा के पिता की कुल आठ संतानें थी. रेखा को अपने पिता का भरपूर प्यार नहीं मिल पाया. पारिवारिक स्थिति को देखते हुए रेखा वक्त से पहले ही बड़ी हो गईं. उनके नाजुक कंधों पर परिवार की ज़िम्मेदारी आ गई. रेखा आर्थिक तंगी की वजह से 12 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करने लगी थीं. उनकी पहली फिल्म थी तेलुगू फिल्म रंगुला रत्नम. इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा की तरफ़ रुख किया. कुछ छोटी भूमिकाओं के बाद नवीन निश्चल के साथ उनकी फिल्म आई सावन भादो. इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया. हालांकि उन्हें उन दिनों उनकी रंगत, वजन और तमिलभाषी होने के कारण भारी आलोचना का सामना करना पड़ता था. रेखा अपनी समकालीन अभिनेत्रियों की तुलना में उन मानकों पर फिट नहीं बैठती थीं, जो बॉलीवुड में चला आ रहा था. रेखा न तो बंगाली थीं, न पंजाबी और न ही मुस्लिम. और यही वे लोग थे जिनका इंडस्ट्री पर उन दिनों राज था. ऐसे में एक तमिलभाषी लड़की के लिए इंडस्ट्री में जगह बना पाना बेहद मुश्किल था, लेकिन रेखा इरादों की पक्की थीं. उन्होंने खूब मेहनत की और आखिरकार वो सफल भी हुईं. उनकी एक के बाद एक फिल्में हिट होती गईं. उन्होंने सभी बड़े स्टार्स के साथ काम किया और एक दिन वह बॉलीवुड की की दिवा बन गईं. उन्होंने अपनी सभी समकालीन अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ दिया. रेखा अपने आप में एक मिसाल बन गईं. उनकी किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती. उन्होंने अपनी अदाकारी से हर भूमिका को जीवंत कर दिया. रेखा की ख़ूबसूरती के अलावा लोगों को उनकी बोल्डनेस भी ख़ूब भाई. बोल्ड रोल में भी वह अश्लील नहीं लगीं. उनकी फिल्में उमराव जान, ख़ूबसूरत, मुकद्दर का सिकंदर, सिलसिला, विजेता, उत्सव, ख़ून भरी मांग, जुबैदा, भूत, कृष और खिलाड़ियों का खिलाड़ी ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बना दिया. उमराव जान में रेखा के नृत्य की काफ़ी सराहना हुई. फिल्म ख़ूबसूरत के लिए रेखा को पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर खिताब मिला.

कहते हैं फिल्म सिलसिला रेखा के जीवन पर बनी थी. एक प्रेमिका के किरदार में उन्होंने पर्दे पर इस भूमिका को ऐसा जीवंत किया कि लोगों को यह रेखा का दर्द भी लगने लगा. साल 1996 में रेखा कि फिल्म आई कामसूत्र. इस फिल्म में उनके बोल्ड अवतार की काफ़ी निंदा हुई, क्योंकि लोग अब रेखा से प्यार करने लगे थे. वे हर वर्ग की पसंद बन गईं थीं, उनकी फिल्मों को लोग परिवार के साथ बैठ कर देखते थे. ऐसे में उन्हें रेखा को इस तरह की फिल्मों में देखना कतई गंवारा न था. हालांकि रेखा ने सिर्फ़ एक कलाकार के तौर पर इस फिल्म को किया था. लेकिन कामयाबी के इस खूबसूरत सफर में रेखा दिल के किसी कोने में खालीपन बार-बार आता रहा. पर्दे पर रूमानी प्यार को जीती हुई रेखा अपने असल जीवन में बेहद एकाकी रहीं. रेखा के जीवन में सबकुछ था, कुछ नहीं था तो बस प्यार. बचपन में भी उन्हें अपने माता पिता का प्यार नहीं मिल पाया. उन्हें भरपूर प्यार चाहिए था, लेकिन वह प्यार से मरहूम ही रहीं. उनका नाम कई समकालीन अभिनेताओं से जुड़ा. नवीन निश्चल, विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन, किरण कुमार वगैरह का नाम रेखा के साथ जुड़ा. हालांकि सदी के महानायक अमिताभ और रेखा के प्यार की कहानी को आज भी लोग सच मानते हैं. कहते हैं कि अमिताभ और रेखा पहली बार चेन्नई में मिले थे. दोनों ने फिल्म दो अनजाने में साथ काम किया. रेखा ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने अमिताभ से बहुत कुछ सिखा है. इस फिल्म के दौरान ही दोनों साथ आए और रेखा अमिताभ के पसंद के मुताबिक खुद को बदलने लगीं, क्योंकि इस फिल्म के बाद से ही रेखा में जबरदस्त बदलाव देखा गया. अपनी कमियों को दूर करने के लिए रेखा ने योग, संतुलित आहार, हिंदी कोचिंग, उर्दू सीखी और अपने ड्रेसिंग सेंस में बदलाव लाया. कहते हैं कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है.

आख़िर रेखा को भी प्यार की मंजिल नहीं मिल सकती थी, लेकिन रेखा अपनी मां की तरह अधूरी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी. वह घर बसाना चाहती थीं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन बिना पिता के वह अपने बच्चे को एक ऐसी जिंदगी नहीं दे सकतीं जैसी उन्होंने खुद जी है. हालांकि उन्होंने वर्ष 1990 में दिल्ली के व्यवसायी मुकेश अग्रवाल से शादी भी की, लेकिन शादी के एक साल बाद ही मुकेश ने आत्महत्या कर ली. उस दौरान रेखा अमेरिका में थीं. यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अभिनेता विनोद मेहरा से भी 1973 में उन्होंने शादी की थी. जीवन के इन तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद रेखा का अमिताभ के प्रति लगाव कुछ कम नहीं हुआ, लेकिन अमिताभ और रेखा कभी अपने दायरे को तोड़कर आगे नहीं बढ़े. आज भी रेखा और अमिताभ के बारे में जानने को लोग उत्सुक रहते हैं. रेखा ने दर्जनों फिल्में अमिताभ के साथ कीं, लेकिन फिल्म सिलसिला के बाद रेखा और अमिताभ ने एक साथ कोई फिल्म नहीं की. फिल्म उमराव जान का यह गाना उनकी असल कहानी भी बयां करता है.

ज़िंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें
ये ज़मीं चांद से बेहतर नज़र आती है हमें
सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें
दिन ढले यूं तेरी आवाज़ बुलाती है हमें
याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से
रात की पिछली पहर रोज़ जगाती है हमें
हर मुलाक़ात का अंजाम जुदाई क्यों है
अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें ■

feedback@chauthiduniya.com

डर्टी गर्ल विद्या बनीं बॉबी जासूस

डर्टी गर्ल विद्या बालन अपनी आने वाली फिल्म में जासूस की भूमिका में दिखेंगी. जी हां अभिनय से निर्देशन में उतरी दीया मिर्जा और उनके ब्वायफ्रेंड साहिल संघा विद्या को लेकर फिल्म बना रहे हैं. फिल्म की पूरी कहानी बॉबी जासूस बनीं विद्या बालन के इर्द गिर्द घुमती है. आपको बता दें कि बॉलीवुड में अब तक जासूसी पर काफी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन विद्या बालन बॉलीवुड की पहली महिला जासूस होंगी. हालांकि उनसे पहले अभिनेत्री कटरीना कैफ भी जासूस की भूमिका में दिख चुकी हैं. सलमान स्टारर फिल्म एक था टाइगर में वह एक पाकिस्तानी जासूस की भूमिका में नजर आई थीं, लेकिन बॉर्न एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही इस फिल्म में विद्या भारतीय जासूस के रूप में नजर आएंगी. दीया कहती हैं कि इस भूमिका के लिए विद्या का चुनाव हमने काफी सोच समझ कर किया. शायद ही कोई और अभिनेत्री इस किरदार के साथ न्याय कर पाती. विद्या की अभी हाल ही में फिल्म आई थी घनचक्कर, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई. फिल्म में उनके साथ इमरान हाशमी भी थे. विद्या ने फिल्मों में कई बेहतरीन तो कई अजीबो-गरीब किरदार निभाए हैं. परिणीता, लगे रहो मुन्ना भाई, भूल भूलैया, पा, कहानी जैसी फिल्मों में उनके अभिनय की काफी सराहना हुई, वहीं हे बेबी और घनचक्कर जैसी फिल्मों को लेकर अनकी अलोचना भी काफी हुई. हालांकि उन्हें उम्मीद है कि इस फिल्म में उनके अभिनय को सराहा जाएगा. आपको बता दें कि इन दिनों बॉलीवुड में जासूसी प्रधान फिल्में काफी पसंद की जा रही हैं. अनिल, कपूर, शाहरुख खान, इमरान हाशमी, संजय दत्त, सैफ अली खान, सलमान खान, अक्षय खन्ना से लेकर अक्षय कुमार भी जासूस के किरदार में नजर आ चुके हैं. इन दिनों बन रही कुछ फिल्मों में विद्या के अलावा रणवीर कपूर और काई पो चे फेम सुशांत सिंह राजपूत भी जासूसी वाले किरदार कर रहे हैं. जी हां विद्या बालन बॉबी जासूस के किरदार में नजर आएंगी तो वहीं रणवीर कपूर जग्गा जासूस और सुशांत सिंह राजपूत ब्योमकेश बक्शी के किरदार में नजर आएंगे. बॉबी जासूस दीया मिर्जा की फिल्म है तो जग्गा जासूस अनुराग बसु की फिल्म है, वहीं सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म को दिबाकर बैनर्जी निर्देशित कर रहे हैं. तीनों ही फिल्में 2014 में रिलीज होंगी. अब देखना यह है कि इन तीनों जासूसों में से किसकी जासूसी दर्शकों को ज्यादा पसंद आती है. ■

प्रीव्यू

सत्या 2

डाइरेक्टर : राम गोपाल वर्मा
प्रोड्यूसर : एम सामंथ कुमार रेड्डी
लेखक : राधिका आनंद
स्टारकास्ट : पुनीत सिंह रतन, अनिका सोती, महेश ठाकुर, नीरा, अराधना गुप्ता, राज प्रेमी, अमल शेरावत, कौशल कपूर, विक्रम सिंह, अमर मोहील
रिलीज डेट : 25 अक्टूबर, 2013
भाषा : हिंदी एवं तमिल

जाने माने फिल्म निर्देशक रामगोपाल वर्मा अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म सत्या का सीक्वल लेकर आ रहे हैं. सत्या 1998 में रिलीज हुई थी. सत्या में जहां जेडी चक्रवर्ती, उर्मिला मातोंडकर, मनोज बाजपेयी और शफाली शाह जैसे कलाकार थे, वहीं सत्या-2 में नए चेहरे होंगे. पुनीत सिंह रतन फिल्म में सत्या के किरदार में, अनिका सोती(चित्रा), महेश ठाकुर (लाहोती), नीरा (अमित्रियान), राज प्रेमी (आरके), अमल शेरावत, (टीके), कौशल कपूर (पुरूषोत्तम), और विक्रम सिंह (अन्ना) की भूमिका में हैं. सत्या-2 एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है. यह फिल्म मैमथ मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले निर्मित होगी. सत्या-2 एक ऐसे युवक की कहानी है जो 2013 में मुंबई आता है और वहां खत्म हो चुके अंडरवर्ल्ड को फिर शुरू करता है. सत्या-2 की कहानी राधिका आनंद ने लिखी है. सत्या-2 हिंदी और तेलुगु दोनों भाषा में बनाई गई है. तेलुगु वर्जन में लीड रोल में शेरवानंद होंगे. सत्या-2 का प्लॉट दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अबु सलेम और अरुण गवली जैसे माफिया डॉन द्वारा की गई गलतियों से प्रेरित है. सत्या-2 में आज की पुलिस व्यवस्था और अंडरवर्ल्ड के नए रिवेन्यू मॉडल को भी दर्शाया गया है. इसका म्यूजिक विक्रम बिस्वास ने दिया है, वहीं सिनेमेटोग्राफर विकास सर्राफ है. राम गोपाल वर्मा की फिल्में कंपनी, सरकार और गैंग्स्टर भी काफी सफल रही थीं. माना जा रहा है कि सत्या 2 अंडरवर्ल्ड पर बनी राम गोपाल वर्मा की आखिरी फिल्म होगी. ■

शाहिद में दिखेंगे राजकुमार

काई पो चे से चर्चा में आए ऐक्टर राजकुमार को अब लोग पहचानने लगे हैं. इन दिनों वह फिल्म शाहिद में बिजी हैं. इस फिल्म को लकर वह काफी उत्साहित हैं. उन्हें उम्मीद हैं कि यह फिल्म बतौर ऐक्टर उनके करियर को एक नई पहचान देगी. वह कहते हैं कि दरअसल यह फिल्म रियल कैरक्टर पर बेस्ड है. फिल्म को बनाने से पहले हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा. मगर हम सब इसे बनाने के लिए पैशनेट थे. मैं जानता था कि एक अच्छी फिल्म बनने जा रही है, इसलिए हम सब जुटे हुए थे. हालांकि फिल्म के लिए उन्होंने हां कर दिया था, लेकिन अपने किरदार के बारे में उन्हें नहीं पता था. ऑफर स्वीकार करने के बाद उन्होंने रिसर्च की. वह शाहिद के घरवालों से मिले, इससे उन्हें किरदार को समझने में काफी मदद मिली. फिल्म में वह एक मुस्लिम लडके के किरदार में हैं, जो एक वकील है. इस किरदार के जरिए उन्होंने इस्लाम के बारे में भी पढ़ा. अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में वह कहते हैं कि करीब डेढ़ साल तक मुझे स्ट्रगल करना पड़ा. जहां भी ऑडिशन देने जाता था, तो कुछ न कुछ कमी बताकर लोग रिजेक्ट कर ही देते थे. कभी कहते कि रोल में गोरा लड़का चाहिए और कभी कहते कि थोड़ा हेल्दी चाहिए. हालांकि अब उनके पास अच्छे ऑफर्स आने लगे हैं. इंडस्ट्री में उनके हंसल मेहता, अनुराग कश्यप और अभिषेक कपूर जैसे कुछ अच्छे दोस्त हैं, जिन पर वो आंख बंद कर के भरोसा करते हैं. ■

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

21 अक्टूबर–27 अक्टूबर 2013

बिहार – झारखंड

कोसी विस्थापितों को न्याय नहीं मिला

कोसी आपदा को कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी कोसी विस्थापित इस आपदा की मार से नहीं उबर सके हैं. विकास का दावा करने वाली नीतीश सरकार में कोसी विस्थापितों का दर्द समझने वाला कोई नहीं है. खेत हैं कि दिनोंदिन रेगिस्तान बनते जा रहे हैं और खेती पर निर्भर रहने वाले लोग दाने-दाने को मोहताज होते जा रहे हैं. हालात यह है कि दो जून के निवाले के लिए मजबूर होकर लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं. पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और कोसी इलाके के जिलों की यही बानगी है.

शशि सागर

सहरसा से पटना होते हुए हटिया जाती है कोसी एक्सप्रेस. यह ट्रेन रोज गवाह बनती है कोसी से होने वाले पलायन की. काम-धंधे की तलाश में कोसी से बाहर जा रहे लोगों ने बातचीत में बताया कि हम सब दिल्ली जा रहे हैं. ललन कहते हैं कि भैया ठेकेदार का फोन आया था काम के लिए. अपना घर छोड़कर जाना किसे अच्छा लगता है, लेकिन पापी पेट का सवाल है. वह कहते हैं कि सरकार विकास के दावे करती है, पर काहे का विकास. खेत तो हमरा पूरा रेगिस्तान बनल है. हम लोग दाने-दाने को मोहताज हैं. पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल कोसी इलाके के इन जिलों की यही बानगी है.

वर्ष 18 अगस्त, 2008 को कोसी त्रासदी हुई. इस आपदा में लाखों लोग बेघर हो गए और हजारों लोगों की जानें चलीं गईं. कई गांव महीनों जलमग्न रहे. कहने को तो इस त्रासदी को पांच साल हो गए, लेकिन आज भी यहां के लोगों का दर्द कम नहीं हुआ. दरअसल, कोसी ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया. घटना के बाद बिहार सरकार ने 10 सितंबर, 2008 में कोसी कटान न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था. पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश राजेश वालिया की एकल सदस्यीय जांच कमेटी का मुख्य उद्देश्य था उन कारणों का पता लगाना, जिनकी वजह से कोसी का पूर्वी तटबंध टूटा और जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति भी न हो. साथ ही इस आयोग को अपनी रिपोर्ट छह महीने बाद ही सौंप देनी थी, लेकिन आज तक यह विस्तारित होती रही है. स्थिति यह है कि अब तक आयोग ने प्रथम दृष्टया कार्रवाई तक शुरू नहीं की है. मालूम हो कि आयोग के गठन के बाद से ही इसकी निष्प-क्षता पर सवाल उठने लगे थे. यहां तक कहा गया कि जांच के बिंदुओं को इस हिसाब से तय किया गया है, जिससे सरकार और उसके मंत्री साफ-साफ बच सकें. जानकारों ने बताया कि आयोग ने साल भर पहले ही अंतिम सुनवाई तक कर ली है, लेकिन रिपोर्ट सौंपने के बजाय फिर इसके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है. कोसी नव निर्माण मंच के महेंद्र यादव कहते हैं कि सुनवाई पूरा होने के एक साल बाद भी आयोग ने रिपोर्ट नहीं सौंपी है. सरकार और आयोग की मिलीभगत से दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और हमारा मंच इसकी निंदा करता है. विनय शर्मा सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता हैं. कोसी के इलाके में लंबे समय तक तैनात भी रहे हैं. यही वजह है कि उन्हें पता है कि तटबंध की सुरक्षा के नाम पर कैसे-कैसे खेल खेले जाते हैं. उन्होंने कोसी आयोग को ढेर सारी जानकारियां भी उपलब्ध कराई हैं. 2012 से अब तक उनके तीन सबमिशन कोसी न्यायिक जांच आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. इसमें उन्होंने बताया है कि तटबंध टूटने की असली वजह बाढ़ नियंत्रण और तटबंध सुरक्षा के कामकाज में भ्रष्टाचार का होना ही है. उन्होंने अपने सबमिशन में सवाल उठाया है कि आयोग के माध्यम से सरकार और उसके मंत्रियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसके गठन के वक्त ही तकनीकी रूप से कह दिया गया था कि इसके जरिये ठेकेदारों और अधिकारियों की चूक का पता लगाना है, जबकि ठेकेदार, अधिकारी और मंत्री की मिलीभगत के कई किस्से इलाके के लोग सुनाते हैं. पटना स्थित आयोग का दफ्तर वीरान पड़ा है. ऐसा लगता है जैसे महीनों से कोई यहां नहीं आया. आदेशपाल महेंद्र राय ने बताया कि पर्व का समय है, इसीलिए कोई नहीं आया. वालिया साहब भी आ जाते हैं, महीने में एक दो बार. बहरहाल नेपाल और बिहार की नदियों के विशेषज्ञ कहे जाने वाले दिनेश मिश्र कहते हैं कि बराज के निर्माण के वक्त ही इसकी आयु 25 साल तय की गई थी, जबकि इसके निर्माण के 50 साल से अधिक हो गए हैं. तटबंध को तो टूटना ही था. बिहार सरकार को पिछले सात-आठ वर्षों के अनुभवों के आधार पर डिजास्टर मैपिंग करानी चाहिए. मिश्र के मुताबिक, पिछली आपदा को अगर आप देखेंगे तो पता चलता है कि जब-जब हालात बुरे हुए हैं, सेना को उतारे बिना काम नहीं चला. फिर आपदा प्रबंधन के नाम पर जो अरबों-खरबों खर्च होते हैं, वह किसलिए?

बताते चलें कि बिहार सरकार, वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल फैसलिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन ऐंड रिकवरी की ज्वॉइंट रिपोर्ट के आधार पर त्रासदी से 2 लाख, 36 हजार, 6 सौ 32 लोगों ने अपना घर-बार खोया था. वहीं बिहार सरकार का आपदा के वक्त आंकलन था कि 14,800 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है. इस भयानक त्रासदी के बाद बिहार सरकार को कोसी के पुनर्निर्माण के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, अन्य राज्यों से अनुदान स्वरूप और साथ ही वर्ल्ड बैंक से भी पैसे मिले थे, लेकिन इतने सालों बाद भी कोसी के पीड़ितों के जख्म पर मरहम तक नहीं लगाए जा सके हैं. कहा गया था कि चार चरणों में पुनर्वास के काम को पूरा कर लिया जाएगा. 31 जनवरी, 2010 से पुनर्वास का काम शुरू हुआ और कहा गया कि छह-छह महीने के चार चरणों में कुल एक लाख घर बन जाएंगे. हैरत की बात तो यह है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी अब तक मात्र 12 हजार लोगों को ही घर का सुख मिल पाया है. ऐसा नहीं है कि पुनर्वास के लिए पैसों की कमी है. रंजन को मिले आरटीआई से पता चलता है कि भारत सरकार और इसके विभिन्न मंत्रालयों से बिहार को 29 सौ करोड़ की राशि मिली थी. वर्ल्ड बैंक से भी कोसी के पुनर्निर्माण के लिए 1009 मिलियन डॉलर (6200 करोड़ रुपये) का फंड मिला था, लेकिन इच्छाशक्ति और लापरवाही की वजह से पुनर्वास का काम धीमी गति से चल रहा है. लापरवाही का एक नमूना बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी के बैलेंस सीट से पता चलता है. बैलेंस सीट के अनुसार 2012 के अंत में 5 करोड़, 74 लाख के आसपास की राशि खर्च नहीं हो पाई थी. इतना ही नहीं ऑडिट रिपोर्ट भी बताती है कि पुनर्वास के काम में भ्रष्टाचार और लापरवाही कायम है. ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि ऐसे बहुत से लोग हैं, जिन्हें आवंटित राशि से अधिक का भुगतान किया गया है और कई भुगतान ऐसे हैं, जो प्रोजेक्ट के मैनुअल के हिसाब से नहीं हुए हैं.

इलाके के कई गांवों के खेतों में आज भी बालू भरे हुए हैं. महेंद्र यादव के आरटीआई के जवाब में सरकार ने स्वीकारा है कि आज भी 14, 129.70 एकड़ जमीन पर बालू जमा है. कई खेतों में तो दो से चार फीट तक बालू है. सरकार की तरफ से बालू हटाने के लिए चार से पांच हजार रुपये प्रति एकड़ दिया गया था, लेकिन स्थानीय किसान बताते हैं कि बालू हटाने में 50 हजार प्रति एकड़ से कम नहीं लगता है. साथ ही यह भी समस्या है कि आखिर बालू हटाकर रखा कहां जाए. यही वजह है कि इलाके की खेती ठप्प पड़ी हुई है. बताते चलें कि कभी यह इलाका पश्चिम बंगाल और असम के बाद जूट उत्पादन में देश में तीसरे नंबर पर था, लेकिन लगातार स्थितियां प्रतिकूल होती जा रही हैं और अब इलाके में जूट का उत्पादन भी खतरे में हैं. स्थानीय लोग बताते हैं कि मधेपुरा जिले का मुरलीगंज नगर पंचायत और सुपौल के विरपुर नगर पंचायत में ही सबसे पहले पानी आया था, लेकिन आज तक यह इलाका पुनर्वास के कार्यक्रमों से वंचित है. मालूम हो कि उद्योग मंत्री रेणु कुशवाहा इसी इलाके से आती हैं. एक बार वे कोसी के पुनर्वास के मसले पर मिलने गए, उन्होंने सामाजिक कार्यकताओं से कहा था कि आप लोग आंदोलन कीजिए, हम सीएम से बात करेंगे. अभी पिछले दिनों ही मधेपुरा जिले में कोसी पुनर्वास योजना की समीक्षात्मक बैठक हुई थी. बैठक में यह बात सामने आई कि राहत कार्य में कोताही बरती जा रही है. साथ ही वित्तीय अनियमितता की बात भी सामने आई. बैठक में परियोजना के निदेशक ने स्वीकारा कि योजना पांच वर्षों के बाद भी लक्ष्य से काफी पीछे है. साथ ही उन्होंने बताया कि इसी अव्यवस्था की वजह से विश्व बैंक ने भी राशि निर्गम पर रोक लगा दी है. राज्य सरकार को ढेरों पैसे भी मिले पुनर्वास के नाम पर. आयोग भी गठित हुए, जिसे लगातार विस्तार दिया जा रहा है. बावजूद इसके, यहां के लोगों के जख्म अभी भी नहीं भरे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

पुनर्वास के नाम पर गबन

जुबैर अंसारी

नीतीश कुमार ने दावा किया था कि वे कोसी को फिर से बसाएंगे, लेकिन उनके वादे खोखले साबित हुए. सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया जिले की जो जमीन कभी सोना उगलती थी, अब रेगिस्तान बन गई है. कोसी कटान की जांच कर रहा जस्टिस वालिया आयोग अब तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप सका है. बताते चलें कि सबसे पहले वीरपुर में बाढ़ आई थी. इसके बाद राज्य और केंद्र दोनों की टीमें यहां आईं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. आज भी वीरपुर स्थित बसमतिया रोड में दर्जनों ध्वस्त मकान कुसहा त्रासदी की गवाही देने के लिए काफी हैं. पिछले 18 अगस्त को बाढ़ पीड़ित अपने हक के लिए अनुमंडल परिसर वीरपुर पहुंचे, लेकिन उन्हें धमकाने-डराने के लिए पुलिस ने 18 चक्र हवा में गोलियां और लाठियां भी चलाई. साथ ही तीन हजार उन्चास निरीह बाढ़ पीड़ितों पर मुकदमा भी ठोक दिया गया. बाढ़ पीड़ितों का आरोप था कि बाढ़ राहत वितरण में करोड़ों रुपये का घपला किया गया है, बाढ़ पीड़ितों को वाजिब हक नहीं मिला है, बिचौलियों का बोलबाला है. इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन हैरत की बात यह है कि प्रशासन इसे दबाने का प्रयास कर रहा है, जबकि जिले के छातापुर प्रखंड में बाढ़ राहत घोटाला उजागर हो चुका है. नगर पंचायत वीरपुर में बाढ़ राहत राशि के गबन का मामला थाने में दर्ज है. बिचौलियों समेत बैंक पदाधिकारी और नगर पंचायत के तत्कालीन मुख्य पार्षद व कनीय अभियंता बनवारी साह पर आरोप लग चुका है. विभागीय सूत्रों की मानें तो अगर मामले की सही जांच होती है, तो करोड़ों रुपये का घोटाला उजागर होगा. ■

एक नज़र

नाव चालक शोषण कर रहे हैं

सीतामढ़ी जिले को पूर्वी चंपारण से जोड़ने वाली लाल बकेया नदी पर अवैध रूप से नाव चालकों द्धारा वर्षों से यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है. इस संबंध में नागरिक अधिकार मोर्चा के अध्यक्ष देवेंद्र सिन्हा एवं वार्ड पार्षद कैलाशी देवी ने डीएम से एक आवेदन देकर शिकायत की है. बताया गया है कि उक्त वसूली में कुछ सफेदपोश से लेकर स्थानीय प्रशासन तक की भूमिका है. आलम है कि प्रति व्यक्ति 10 रुपये और मोटरसाइकिल वालों से 50 रुपये तक की वसूली की जा रही है. बताया जा रहा है कि नाव चालकों की दबंगई के कारण लोग चुप रहने को मजबूर हैं. बताते चले कि तकरीबन दो दशक पूर्व उक्त स्थान पर एक करोड़ की लागत से स्क्रू पाइल पुल का निर्माण कराया गया था, जिसे राजनीतिक विद्धेश के कारण कुछ लोगों ने क्षतिग्रस्त कर बाढ़ के पानी में बहा दिया, लेकिन इस दिशा में सरकार से लेकर प्रशासन तक की नींद नही खुल सकी है. नतीजा है कि आम लोग खामियाजा भुगतने को मजबूर हैं. *–विनोद कुमार*

राष्ट्रपिता और शास्त्री जी को नमन

सीतामढ़ी शहर स्थित कांग्रेस कार्यालय ललित आश्रम में जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया. कांग्रेस जिलाध्यक्ष विमल शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में उपाध्यक्ष सीताराम झा, डॉ. भुवनेश्वरी प्रसाद मिश्र, प्रो. बच्चा मिश्र, परवेज आलम अंसारी, मो. असद, रामबली महतो, सीमा गुप्ता, शिव शंकर शर्मा, अनवर हुसैन, वीरेंद्र कुशवाहा समेत अन्य उपस्थित थे.

–ब्रजेश कुमार

राजद हताश नहीं : डॉ. पूर्वे

पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के जेल की सलाखों में कैद होने से कार्यकर्ता निराश जरूर हैं, लेकिन हताश नहीं हैं. आगामी लोकसभा चुनाव में सूबे बिहार की जनता राजद के पक्ष में एकजुटता दिखाकर विरोधियों की अक्ल ठिकाने लगाएगी. सीतामढ़ी शहर स्थित पार्टी के जिलाध्यक्ष मो शफीक खां के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में राजद के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामचंद्र पूर्वे ने उक्त बातें कहीं. पूर्वे ने कहा कि लालू को एक साजिश के तहत फंसाया गया है. आने वाले दिनों में इस पर से भी पर्दा उठेगा. कार्यकर्ताओं का उत्साह आगामी चुनाव में आपसी एकता के बूते पार्टी को मजबूत स्थिति में कायम करेगा. मौके पर पूर्व सांसद मो. अनवारुल हक, पूर्व मंत्री सूर्यदेव राय, जिलाध्यक्ष मो. शफीक खां, युवा राजद अध्यक्ष चंद्रजीत प्रसाद यादव, गणेश गुप्ता व लक्ष्मी साह समेत अन्य थे. *–ब्रजेश*

बाजपट्टी में धरना

बाजपट्टी : पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बाजपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर में एक दिवसीय सर्वदलीय धरना का आयोजन किया गया. प्रखंड मुख्यालय के करीब स्थित निर्माणाधीन संढ़वारा घाट पुल निर्माण कार्य को अविलंब पूरा कराने समेत छह सूत्री मांगों को लेकर आयोजित कार्यक्रम में पूर्णिया के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी मौजूद थे. कार्यक्रम के मौके पर पूर्व सांसद ने लोगों से आंदोलन का राजनीतिकरण करने से परहेज करने की अपील की. इससे पूर्व सीपीआई के नवल किशोर रावत व प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष ताराकांत झा ने भी अपने विचार रखे. बिंदु ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के मौके पर अजय कुमार गुप्ता ने संचालन की कमान थामी. पुल निर्माण कार्य पूरा कराने के अलावा, प्रखंड को अनुमंडल बनाने, प्रखंड कार्यालय परिसर में शहीद रामफल मंडल के नाम से पार्क बनाने व आदमकद प्रतिमा स्थापित कराने, शहीद के नाम से डाक टिकट जारी करने, रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेनों का ठहराव कराने एवं स्थानीय उच्च विद्यालय में पढ़ाई की सुविधा बहाल कराने की मांग शामिल थी. मौके पर पूर्व पार्षद कौशल किशोर यादव, मो अली, जिला पार्षद मीना देवी, सरिता देवी, दिलीप खिरहर, मुखिया किशुन चंद्रवंशी, संतोष कुमार सिंह, सियाराम मंडल, महेंद्र सिंह यादव, चंद्रजीत प्रसाद यादव, आफताब अंजुम बिहारी, धीरेंद्र कुंवर, कपिलेश्वर मंडल, पशुपति सिंह कुशवाहा, गणेश प्रसाद व रामबाबू राय समेत अन्य थे. *–अभिलाषा द्विवेदी*

जनाक्रोश रैली ऐतिहासिक होगी

गांधी मैदान में आहूत जनाक्रोश रैली ऐतिहासिक होगी. भाकपा सीतामढ़ी जिला कार्यालय अजय भवन में अवनींद्र कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में जिला परिषद की बैठक हुई. राज्य पर्यवेक्षक सह पूर्व विधायक राम नरेश पाडेय एवं चंद्रकेतु शर्मा की उपस्थिति में संपन्न बैठक में रैली की सफलता पर विचार विमर्श किया गया. कहा कि रैली में सीतामढ़ी से करीब 10 हजार कार्यकर्ता शामिल होंगे. रैली से पूर्व 25 अक्टूबर को मशाल जुलूस भी निकालने का निर्णय लिया गया. बैठक में पार्टी के जिला सचिव जय प्रकाश राय, सुरेंद्र प्रसाद यादव, सहायक जिला सचिव नवल किशोर रावत, रामानेक ठाकुर, सोने लाल साह, अतुल बिहारी मिश्रा, ग्यासुद्दीन, उमा शंकर सिंह, खेदू महतो, राज किशोर ठाकुर, मौजे लाल शर्मा, डा वीरेंद्र प्रसाद, अमित कुमार, सुमित कुमार व सुमन कुमार समेत अन्य थे. *–ब्रजेष*

बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम को मान्यता मिली

अगमकुआं के आइडीएच कॉलोनी स्थित कल्याण सेवा संस्थान द्धारा संचालित नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ हेल्थ एजूकेशन एण्ड रिसर्च केन्द्र में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ने सत्र 2013-2014 की मान्यता दी है. संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी देते हुए संस्था के सचिव डॉ. यूपी गुप्ता ने बताया कि बिहार मे नर्सिंग स्टाफ व ट्यूटर की कमी है. संस्थान को मान्यता मिलने से नर्सिंग स्टाफ की कमी दूर होगी. सचिव ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही संस्थान को एमएससी नर्सिंग पाठयक्रम की मान्यता भी मिल जाएगी. इसके लिए प्रक्रिया चल रही है. ंसंस्थान की निदेशक माया गुप्ता ने बताया कि नर्सिंग के बैचलर पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थियों को दूसरे प्रांतों मे जाना पड़ता था, लेकिन अब विद्यार्थी राज्य के अंदर ही इसकी पढ़ाई कर सकेंगे. संवाददाता सम्मेलन में प्राचार्य संदीप के राजू, पुष्पलता देवी, निविदेता रानी साहा, सिपरा भट्टाचार्या, बालचंद्रन, जीतेन्द्र सिंह शेखवता, सिन्नी रवि, नवज्योति समेत अन्य उपस्थित थे. *–अमृता कुमारी*

जनता दल राष्ट्रवादी का सम्मेलन

पिछले दिनों पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में जनता दल राष्ट्रवादी का राज्य स्तरीय सम्मेलन सह स्थापना दिवस मनाया गया. पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अशफाक रहमान ने कहा कि हमारी पार्टी अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों और आम आदमी की आवाज बनेगी. उन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो आबादी के हिसाब से भागीदारी मिलेगी. साथ ही यह भी कहा कि हमारी पार्टी में अल्पसंख्यक व दलित प्रकोष्ठ नहीं होगा, बल्कि इन वर्गों के लोग मुख्यधारा में होंगे. जौहर आजाद ने कहा कि युवाओं को पार्टी में अधिक भागेदारी मिलेगी. वहीं अमरजीत सिन्हा ने कहा कि पार्टी में महिलाओं को पचास प्रतिशत भागीदारी मिलेगी. मौके पर डॉ. अब्दुल वाहिद रहमानी, नौशाद अहमद, प्रिया देवी, दिलीप चौधरी, मो. अली, गुल सलाम नदवी एवं ई. शमीमअख्तर उर्फ शहवर्दी सहित कई लोग मौजूद थे. *–अमृता कुमारी*

गांधी महायज्ञ का आयोजन

गांधीवादी तारकेश्वर प्रसाद के आवास पर गांधी पूजन यज्ञ समिति द्धारा 14 वां भगवान गांधी पूजन महायज्ञ का आयोजन किया गया. यज्ञ का उद्घाटन सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी संगीता रानी ने किया. अध्यक्षता हरीश चन्द्र चौधरी ने की, जबकि मंच का संचालन विनोद तिवारी ने किया. अतिथियों का स्वागत तारकेश्वर प्रसाद ने किया, वहीं मौके पर रवीन्द्र नाथ मुखर्जी, आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य हरिशंकर सिंह ब्रहमचारी, एडीजे आनंद सिंह, न्यायिक दंडाधिकरी एसके सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी आरके रजक, आरके भारती, ब्रह्मा कुमारी इश्वरीय विश्व विद्यालय की पूनम बहन, प्रो. शोभाकान्त चौधरी, डॉ. अरूण कुमार मिश्रा, जयराम सिंह, अधिवक्ता महेन्द्र प्रसाद यादव, अधिवक्ता अखिलेश शरण, प्राचार्या शशिकला, नसीमा खातुन, जमुना प्रसाद, सीताराम चौधरी, अनिल जायसवाल, प्रो. श्रीकान्त प्रसुन्न, डॉ. देवाशीष मुखर्जी, धर्मेन्द्र मिश्रा, जगदीश विद्रोही आदि ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये. मौके पर आरके इंटरनेशनल स्कूल, ज्ञान पब्लिक स्कूल आदि विद्यालयों के छात्र-छात्रों द्धारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया.

–इंतेजारूल हक

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

मधेपुरा

पल्ला झाड़ने की जुगत में शरद

डॉ. देवाशीष बोस

जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा मधेपुरा के सांसद शरद यादव अगला चुनाव अपने संसदीय क्षेत्र से नहीं लड़ेंगे. पूर्व में भी वह हरियाणा से चुनाव लड़ने की संभावना तलाश चुके हैं. मधेपुरा में शरद ने कहा कि उनका मधेपुरा से चुनाव लड़ना पार्टी तय करेगी. पार्टी तय करेगी कि उन्हें चुनाव कहां से लड़ना है, वह पार्टी के आदेश का आदर करते हैं.

माना जा रहा है कि शरद की स्थिति दिनों दिन जॉर्ज फर्नांडीज की तरह होती जा रही है और वह लगातार हाशिये पर जा रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि वह स्वयं अपनी सीट भी तय न कर सकें. मधेपुरा में उनके लगातार विरोध और सांसद के रूप में अलोकप्रियता ने उन्हें भयभीत कर रखा है. लिहाजा वह मधेपुरा से चुनाव लड़ने के बजाय अन्य आसान सीटों से चुनाव जीत कर संसद में दाखिल होना चाहते हैं. इसके लिए वे अपने करीबी नेताओं से रायशुमारी भी कर रहे हैं. इस मामले में उन्होंने अपना पत्ता गोपनीय रखा है, जबकि उनकी निगाहें सुपौल अथवा खगड़िया संसदीय क्षेत्र पर लगी हुई हैं.

मधेपुरा में शरद यादव ने कहा था कि वे राष्ट्रीय नेता होने के कारण छोटे कामों के बजाय बड़े कामों को तरजीह देंगे. चुनाव जीतने के बाद भी कई मौके पर शरद यादव ने अपने इस बयान को दोहराया था. मधेपुरा के लोगों को कोई बड़ा तोहफा देने में शरद यादव अब तक सफल नहीं हुए हैं. मधेपुरा में दो राष्ट्रीय राजमार्ग अस्तित्व में हैं. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-106 बिहपुर-वीरपुर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-107, महेशखूंट-पूर्णिया कोसी की जीवन रेखा है तथा दोनों सड़कें मधेपुरा से होकर गुजरती हैं. बिहपुर-वीरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-106 पर एक साथ दो गाड़ियां नहीं गुजर सकतीं, यहां सड़क का फ्लैंक भी ठीक नहीं है, जिससे यहां वाहनों का दुर्घटनाग्रस्त होना आम बात है. मधेपुरा के पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार शाह भी दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं. इसके बाद भी शरद यादव दिल्ली से फंड नहीं ला पा रहे हैं. बिहपुर-वीरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-106 में फुलौत के पास कोसी नदी पर पुल नहीं होने के कारण यह सड़क अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पा रही है. इस बड़े पुल के निर्माण में भी शरद यादव उदासीन हैं, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-106 की पूर्णता संकट में है. इधर कोसी भी अपना रौद्ररूप दिखा रही है. मुरौत, बड़ी खाल तथा फुलौत आदि गांव कटाव से ग्रस्त हो गए हैं. बड़ी खाल तो मधेपुरा के नक्शे से समाप्त ही हो गया है. मुरौत के लोग अपने गांव के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं. कोसी का भीषण कटाव मुरौत पर लगातार हमला कर रहा है. करोड़ों रुपये पानी में बहाने के बाद भी मुरौत में कटाव जारी है और लोग विस्थापित होकर अन्यत्र शरण ले रहे हैं, लेकिन शरद यादव पुनर्वास के लिए प्रभावितों को राज्य सरकार से अनुदान नहीं दिला पाये हैं. थियेटर कंपनी के मालिक सियाराम यादव जब राजद के टिकट पर मधेपुरा से चुनाव लड़े थे, तब वे शरद यादव की ओर से उपहास का पात्र बने थे. शरद ने स्वयं कहा था कि लालू ने अपसंस्कृति फैलाने वाले थियेटर कंपनी के मालिक को टिकट देकर अपना नजरिया जाहिर कर दिया है, लेकिन वक्त गुजरते ही सियाराम यादव शरद के शरण में आ गये और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपसंस्कृति फैलाने वाले इसी सियाराम यादव को अपने क्षेत्र का सर्वेसर्वा बना दिया. फिलहाल वे मधेपुरा जिला जनता दल यू के अध्यक्ष हैं. शरद के इस कदम को पार्टी के पुराने साथियों ने नापसंद किया और जिला जनता दल इस मसले पर विभाजित हो गई है, जिससे शरद यादव के प्रति सहानुभूति तथा समर्थन में कमी दिखती है.

वर्ष 2008 में प्रलयंकारी बाढ़ ने मधेपुरा को काफी क्षति पहुंचाई. लगभग

15 दिनों तक जिले में प्रशासन की पहुंच नाकाम रही. सुदूर गांवों में पहुंचने में उसे काफी वक्त लगा. बाढ़ से हुई क्षति की भरपाई शरद यादव केंद्र सरकार से आज तक नहीं करा पाये, बाढ़ के बाद रेल संपर्क भंग हो गया और अमान परिवर्तन के नाम वर्षों यातायात अवरुद्ध रहा. इतना ही नहीं अमान परिवर्तन हो जाने के बाद भी रेल लाइन रेल के आवागमन का इंतजार करती रही, लेकिन शरद ने रुचि नहीं ली. आखिर स्थानीय जनता ने एकजुट होकर आवाज मुखरित की. तब जाकर शरद यादव ने एक सवारी गाड़ी को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया, लेकिन इस रेल का अगले दिन से मधेपुरा आना बन्द हो गया. कई दिनों के बाद रेल का परिचालन संभव हुआ. मधेपुरा-सहरसा के बीच फिलहाल गाड़ियां चल रही है, लेकिन यात्री परेशान हैं. लंबी दूरी की रेल गाड़िया मधेपुरा से नहीं चलती है. मधेपुरा से जानकी नगर तक रेल लाइन बन कर तैयार है, लेकिन एक अदद नेता के अभाव में रेल का परिचालन नहीं हो पा रहा है, जबकि वर्ष 2002 में ही तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने शरद यादव की उपस्थिति में सहरसा-पूर्णिया रेलखंड के अमान परिवर्तन के कार्य का शुभारंभ किया था. ग्यारह वर्ष बीत जाने के बाद भी सहरसा-मधेपुरा-पूर्णिया रेलखंड का अमान परिवर्तन नहीं हो पाया है. फिलहाल इस रेलपथ पर राशि के अभाव में कार्य धीमा है, पिछले दिन रेल अधिकारियों के साथ सहरसा परिसदन में शरद यादव ने बैठक की, लेकिन सहरसा में रेल ओवर ब्रिज निर्माण को छोड़कर मधेपुरा या कोसी के रेल सुविधाओं पर अपनी जुबान नहीं खोला और महज सात मिनटों में बैठक की कार्यवाही समाप्त कर दी गई, जबकि रेल अधिकारी लाखों रुपये खर्च कर शरद के बैठक में उपस्थित हुए थे. सांसद विकास निधि में व्यवहारिक योजनाओं का चयन नहीं किया जा रहा है. इनके सलाहकारों के पास दृष्टि का अभाव है और जानकार लोगों को शरद के सलाहकार इनसे जुड़ने नहीं देते हैं. शरद भी ऐसे मसले पर कोई अभिरुचि नहीं लेते हैं. लिहाजा इनकी योजनाओं में लूट मची हुई है और लोगों के बीच शरद अलोकप्रिय हो गये हैं, शरद यादव के लालू विरोध और नीतीश का पक्ष लेने के कारण कारण यादवों का उन्हें मुखर विरोध का सामना करना पड़ रहा है.

इसके अलावा, गैर यादव मतदाता मधेपुरा का अपेक्षित विकास नहीं होने और सांसद की निष्क्रियता के कारण उनके विपक्ष में उतर आये हैं, जबकि राजपूत और ब्राह्मण मतदाता पहले से ही शरद यादव के विरोध में हैं, लेकिन शरद यादव को पटकनिया देने वाले पहलवान का मतदाता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ऐसे हालात को पारखी शरद ताड़ गए हैं और अपनी सीट बदलने की जुगत में हैं. भाजपा से संधि विच्छेद के सवाल पर शरद की किचकिच ने नीतीश को आहत किया है और नीतीश भी अंदर ही अंदर शरद को जॉर्ज की तरह ठिकाने लगाने पर उतर आये हैं. सरकार में शरद को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है. मतदाताओं के लाख अनुरोध के बावजूद भी शरद जनहित में सरकार से कोई पैरवी नहीं कर पाते हैं. छह माह के बाद चुनाव होना है और अभी से नीतीश कुमार ने प्रशासनिक बिसात बिछाना प्रारंभ कर दिया है. चुनाव को देख कर ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों का ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन मधेपुरा में शरद के चहेता के बजाय एक शुद्ध ईमानदार और कड़क जिलाधिकारी की पदस्थापना कर नीतीश ने शरद के संसद जाने का रास्ता दुर्गम कर दिया है. इन प्रतिकुल परिस्थितियों को भांपकर शरद यादव अब अपना संसदीय क्षेत्र बदलने की जुगत में दिख रहे हैं. इसीलिए वे अपनी इज्जत बचाने के लिए बोल रहे हैं कि उनका चुनाव लड़ना पार्टी तय करेगी और पार्टी के इच्छानुसार वे कहीं से भी चुनाव लड़ लेंगे. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की यह हताशा अब साफ दिखने लगी है. ■

» एक नज़र «

कांग्रेस में गुटबाजी

जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है कांग्रेस में गुटबाजी भी तेज होते जा रही है. इस बिखराव का नजारा हाल ही में हुए चतरा जिला स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक में भी देखने को मिला. शंकर साहू की हत्या के बाद उनके पुत्र धर्मेंद्र साहु और मो. इमदाद हुसैन को कार्यकारी जिलाध्यक्ष बनाया गया. इसके बाद से ही जिला कांग्रेस में विरोध की आवाज बुलंद होने लगी और जिला कांग्रेस चार खेमे में बंट गया. वैश्य, अल्पसंख्यक, सवर्ण और हरिजन. हर खेमा अपनी जाति का नेता चाहता है. प्रदेश प्रभारी मनोज नाथ सहदेव की कोशिश जारी है कि यह मतभेद खत्म हो, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होता नजर आ रहा है. जानकार बताते हैं कि इसका असर आने वाले चुनाव पर भी पड़ सकता है. *-अमरेंद्र प्रताप सिंह*

चतरा में शिक्षा बदहाल

चतरा जिले में शिक्षा की बदहाली अपने चरम पर है. उदाहरण के तौर पर प्रतापपुर प्रखंड के परियोजना बालिका उच्च विद्यालय को देखा जा सकता है. प्रखंड मुख्यालय से सटे इस विद्यालय की हकीकत यहां के स्थानीय लोग बताते हैं. आदेशपाल संजय कहते हैं कि यहां एक सौ चालिस छात्र नामांकित है, जिसमें से मात्र एक या दो ही स्कूल आते हैं. स्थानीय लोग बताते हैं कि यहां के प्रभारी मो. जफर आलम और सहायक शिक्षक सर्वेश सिंह और दलर्क संतोष सिन्हा हैं, लेकिन ये यदा-कदा ही विद्यालय आते हैं. इनके द्वारा कभी कोई प्रयास नहीं किया जाता है, जिससे बच्चे स्कूल आएं. फिलहाल इसकी सूचना चतरा जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी गई है. उन्होंने स्कूल के प्रभारी और सहायक शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है. साथ ही यह भी कहा है कि लापरवाही बरतने के आरोप में उनके वेतन पर रोक लगा दी जाएगी. *-अमरेंद्र प्रताप सिंह*

रक्तदान शिविर

खगड़िया के समीर नगर स्थित मेहता फाउंडेशन कार्यालय में दो दिवसीय रक्तदान शिविर का उद्घाटन डीएम संजय कुमार सिंह ने किया. अपने संबोधन में डीएम ने कहा कि 18 से 65 वर्ष उम्र का कोई भी स्वस्थ्य व्यक्ति रक्तदान कर सकता हैं. रक्तदान से बढ़ कर कोई दान नहीं है. डीएम ने मेहता फाउंडेशन की सराहना करते हुए कहा कि रक्तदान शिविर का आयोजन कर मानव सेवा के प्रति एक मिशाल कायम किया है. रक्तदान शिविर में मेहता फाउंडेशन के सचिव योगेंद्र कुमार मेहता, किरण कुमारी, नवआकांक्षा, सुनील श्रीवास्तव, रिंकू कुमार, अभिषेक कुमार, राजेश कुमार, दिलीप, शंभू, पप्पू, कोमल, नूतन, मुन्ना एवं राजेश सहित दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया. मौके पर सिविल सर्जन सुरेश प्रसाद, सदर अस्पताल उपाधीक्षक वाईएस प्रयासी, रेडक्रॉस के सचिव रंजीत प्रसाद, नेहरू युवा केंद्र के सज्जाद आलम, आदि उपस्थित थे. *-नंदकिशोर शर्मा*

ओवरब्रिज के नक्शे में संशोधन

खगड़िया शहर के पूर्वी केबिन ढाला पर बन रहे ओवरब्रिज सड़क के नक्शे में संशोधन होने से जिलेवासियों में खुशी है. यह बात जदयू के जिला महासचिव पंकज कुमार गुप्ता ने बताई. उन्होंने कहा कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा बनाये जा रहे पूल के नक्शे में जनहित के लिए संशोधन करने की मांग की गई थी, जिसके आलोक में पथ निर्माण विभाग पटना द्वारा 23 सितंबर को नक्शे में संशोधन का आदेश पारित कर इरकॉन कंपनी का दे दिया गया. नक्शे में संशोधन होने से निर्माणाधीन पूल की ऊंचाई को और जन समस्याओं को देखते हुए 7.5 मीटर से घटाकर 6.6 मीटर करने का निर्णय लिया गया. पूल की ऊंचाई कम होने के कारण 116.82 मीटर रास्ता कम हो जायेगा और और शहर की सूरत भी बिगड़ने से बच जाएगी. इसके लिए गुप्ता ने सरकार को साधुवाद कहते हुए कहा कि गोशाला रोड एवं कचहरी रोड के पुल की ऊंचाई भी घटने की संभावना है. *-नंदकिशोर शर्मा*

सीतामढ़ी

चुनावी तैयारियों में लगे पप्पू यादव

तकरीबन ढ़ाई दशक से सीतामढ़ी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते आ रहे पूर्णिया के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव इन दिनों सीतामढ़ी जिले की टोह लेने मे लगे हैं. जेल से निकलने के बाद यादव का यहां दूसरा दौरा हाल ही में हुआ है. आगामी लोकसभा चुनाव में वे किस्मत आजमाने की बात तो करते हैं, लेकिन किस पार्टी से और कहां से चुनाव लड़ने की मंशा है, खुलासा नही कर रहे हैं. बावजूद इसके सीतामढ़ी में पप्पू यादव के चुनावी पोस्टर सटेंगे, इसका कयास भी लगाया जाने लगा है...

वाल्मीकि कुमार

बिहार में एनडीए गठबंधन का तलाक और चर्चित चारा घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सजा के बाद राजनीतिक विसात पर मोहरे बिछाने का काम जोर पकड़ने लगा है. सत्ताधारी जदयू व कल तक उसके साथ रहने वाली भाजपा के बीच आरोप व प्रत्यारोप का दौर सीतामढ़ी जिले में भी चरम पर है. इसी बीच राजद निराशा के भंवर में हताश पार्टी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह व उफान लाने की योजना भी बनाने लगी है. करीब ढ़ाई दशक से बिहार की राजनीति से बेदखल कांग्रेस भी अब अपना खोया अस्तित्व पाने को जी जान से लगी है. ऐसे ही माहौल में सीतामढ़ी जिले में पूर्णिया के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का आगमन लोगों में चर्चा का विषय बना है. महज एक माह के अंदर दूसरी बार सीतामढ़ी में लोगों के बीच आकर जिस अंदाज में पप्पू अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं. यह कहने में कोई हिचक नहीं कि फिलहाल उनका अंदाज बिल्कुल ही गैर राजनीतिक है. पिछले दिनों

सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर में शहीद रामफल मंडल जनक्रांति मोर्चा के तत्वावधान में छह सूत्री मांगों के समर्थन में आयोजित एक दिवसीय धरना में यादव ने भी भागीदारी दी. उन्होंने यह भी कहा कि अगर धरने की पूर्व सूचना होती तो शायद आने से परहेज करते. यानी की राजनीतिक कार्यक्रम से फिलहाल वे पूर्णत: अलग रहकर आमजनों की भावना को समझने का प्रयास कर रहे हैं. साथ ही समाज की मजबूती व तरक्की की तरकीब भी जनता के बीच रखना चाहते हैं. जिला मुख्यालय डुमरा स्थित बागमती परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा कि जब भी समाज से आवाज आती है अथवा स्वयं समाज के बीच जाना मुनासिब समझते हैं जाते हैं. सीतामढ़ी तो घर जैसा ही है. उन्होंने अपने अभियान के संदर्भ में कहा कि उत्तरी बिहार को अब भी विकास की दरकार है. कारण कि अब तक की तमाम सरकारों ने इसे उपेक्षित रखने का काम किया है. जबकि सर्वाधिक विधायक देने वाला क्षेत्र यही है. बावजूद इसके अभी तक इस क्षेत्र में एक भी उद्योग नहीं लगाया गया है. अपने चुनावी घोषणा के संबंध में बिना किसी पार्टी का नाम लिए कहा कि नवंबर 2013 के बाद क्षेत्र का खुलासा जनता के आकांक्षा पर पार्टी के साथ हो जाएगा. उन्होंने कहा कि समाज में बुराई का आगमन तभी संभव है, जब अच्छे लोगों की कमी होती है. इससे पूर्व बाजपट्टी के धरना में उन्होंने आम लोगों में जागरुकता का प्रवाह करते हुए कहा कि वर्तमान में कोई भी प्रतिनिधि गरीबों का कार्य करने का साहस नहीं दिखा रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज समाज के विकास व तरक्की के लिए आर्थिक व शैक्षणिक विकास आवश्यक है. उन्होंने लोगों से जनांदोलन का राजनीतिकरण होने से रोकने की अपील की. कहा कि सूबे में क्रूर शासक है. लोकतंत्र की मर्यादा को समाप्त करने वाली हिटलरशाही सरकार है. यादव ने कहा कि सरकार के मंत्री टैक्स तो प्रशासक गुंडा टैक्स वसूलता है. जिला पार्षद सरिता यादव के पति महेंद्र सिंह यादव पर लगाए गए गुंडा एक्ट पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पूंजीपति व राजनेता गठजोड़ के साजिश का नतीजा है कि महेंद्र सिंह यादव के जान पर खतरा मंडराने लगा है. स्थानीय प्रशासन किसी मामले में फंसा सकती है. कुल मिला कर पूर्व सांसद पप्पू का लालू प्रसाद के प्रति नरमी व नीतीश सरकार के प्रति रोष उनके राजनीतिक मंच की ओर अस्पष्ट इशारा करता प्रतीत होने लगा है. वैसे भी लालू प्रसाद यादव के जेल यात्रा के बाद अब यादव के अलावा राजद मतदाताओं को एक ऐसे मजबूत केवट की दरकार जरुर है, जो पार्टी की डूबती नैया को मझधार से सकुशल बाहर निकाल सके. वैसे अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में पप्पू का टोही अभियान लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बनने लगा है. चर्चाओं पर भरोसा करे तो पूर्व सांसद पप्पू यादव सीतामढ़ी तो अपनी पत्नी रंजीता रंजन को अपने पुराने गढ़ से चुनावी समर में दमखम के साथ उतार सकते हैं. उधर पप्पू यादव के सीतामढ़ी जिले के परिहार व बाजपट्टी में दौरा के बाद जिले की राजनीति में समीकरणों की जोड़-तोड़ भी चुनावी चौपाटी पर की जाने लगी है. ■

गुटबाजी की शिकार जिला भाजपा

नमो मिशन 2014 को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 27 अक्टूबर को पटना में आहूत हुंकार रैली को सफल बनाने के लिए जी जान लगा दी, लेकिन युवा कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में पार्टी के स्थानीय सांसद, विधायक व विधान पार्षद का सहयोग महज एक आश्वासन तक ही सिमट कर रह गया. भाजपा के प्रवक्ता व भागलपुर के सांसद शाहनवाज हुसैन ने पार्टी के युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं में उफान का संचार करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिमाग को इमरजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक घोषित कर दिया...

वाल्मीकि कुमार

सीतामढ़ी शहर स्थित लक्ष्मी किशोरी उच्च विद्यालय के सभागार में भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वावधान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन का उत्साह चरम पर रहा. भाजपा की महत्वपूर्ण इकाई के तौर पर कार्य कर रहे मोर्चा कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की सफलता को लेकर काफी माथा पच्ची करनी पड़ी, क्योंकि पार्टी के एकमात्र सांसद ने जहां खुद को सहयोग लेने वाला कह कर आर्थिक सहयोग करने से कन्नी काट ली, वहीं विधायक ने पहले ही बहुत खून चूस लिए जाने की बात कहते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया. भाजपा विधान पार्षद तो सहयोग का भरोसा देकर विदेश दौरे पर निकल पड़े. तकरीबन सवा लाख रुपये सम्मेलन के लिए खुद ही युवा मोर्चा को व्यवस्था करनी पड़ी. इसके बाद भी पार्टी के कुछ नेताओं ने कार्यक्रम को विफल करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी. पार्टी के एक ओहदेदार व जिम्मेदार कार्यकर्ता ने यहां तक कहा कि पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन को यह कह कर सीतामढ़ी आने से रोकने का भी प्रयास किया गया कि आपके आगमन से माहौल खराब हो सकता है. जब शाहनवाज कार्यक्रम में भाग लेकर लौटने लगे तब कुछ लोगों ने उन्हें काला झंडा तक दिखा दिया. मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यक्रम से लौटने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिलाध्यक्ष से उक्त साजिश में शामिल कार्यकर्ताओं का पहचान कर पद से मुक्त करने का फरमान भी जारी कर दिया है. पार्टी प्रवक्ता को माहौल का हवाला देकर आने से रोकने के मामले में भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मो. नन्हे के पद पर भी आफत मंडराने लगी है. युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कार्तिकेश झा ने पार्टी के जिलाध्यक्ष को साजिश में शामिल कुछ कार्यकर्ताओं के नामों की सूची भी मुहैया करा दी है. संभव है अगर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष की कुर्सी हिली तो युवा मोर्चा के साथ ही पूर्व से गुटबाजी का शिकार जिला भाजपा में एक और कलह का बीजारोपण तय है. अल्पसंख्यकों का हितैशी होने का दंभ भरने वाले नीतीश मुसलमानों का टोपी पहनकर मजाक उड़ाते हैं, जबकि भाजपा इंसानियत व सर्वधर्म समभाव की पार्टी है. भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि आज बिहार के युवाओं में उत्साह है. इस धरती से जदयू-कांग्रेस का खात्मा हो जाएगा. ■

पूर्व मध्य रेलवे ने की अनोखी पहल

चौथी दुनिया ब्युरो

भारतीय रेल 160 वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है. इसी आलोक में देश भर में भारतीय रेल ने अपनी विकास यात्रा की प्रदर्शनी लगाई. एक से सात अक्टूबर तक पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर में भी पूर्व मध्य रेलवे ने भी प्रदर्शनी का आयोजन किया. यह प्रदर्शनी नि:शुल्क था. पूर्व मध्य रेल को बने 11 साल हो गए हैं. अभी इसके पास समृद्ध संग्रहालय का भी अभाव है. इसके बावजूद जोन का यह प्रयास सराहनीय रहा. जनसंपर्क अधिकारी यूके झा कहते हैं कि हमारा जोन अभी मात्र ग्यारह साल का हुआ है. हमने कोशिश की है कि आम-अवाम को रेलवे और अपने जोन के समृद्ध इतिहास से अवगत कराएं. हमारी कोशिश रहेगी कि पूर्व मध्य रेलवे के संग्रहालय को भी समृद्ध बनाया जाए. इस प्रदर्शनी का उद्घाटन पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक मधुरेश कुमार ने किया. उन्होंने कहा कि यह फोटो प्रदर्शनी शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है, बच्चों व आमजनों के आकर्षण का केंद्र साबित होगी. प्रदर्शनी में 1853 से लेकर अब तक के रेल इतिहास का बेहतर समायोजन रहा. रेलवे के पुरालेखों, दुर्लभ चित्रों आदि के जरिए रेलवे के महत्व और इसकी भूमिका से लोगों को अवगत कराया गया. ट्रेन के विभिन्न मॉडलों की भी प्रदर्शनी लगी थी. सर्कुलर ट्रेन मुख्य आकर्षण रहा. इस मॉडल द्वारा ट्रेन के परिचालन में प्रयुक्त होने वाले सिग्नल व अन्य उपकरणों के कार्यप्रणाली को समझाया गया. साफ-सफाई से जुड़े वीडियो मैसेज को भी बच्चों ने ध्यानपूर्वक देखा-सुना. प्रदर्शनी आमजनों के बीच रोचक व ज्ञानवर्धक तथ्यों से भरपूर होने के कारण काफी लोकप्रिय रहा. महापुरुषों की रेलवे से जुड़ी यादें भी तस्वीर के रूप में लगाई गई थी, जिसे आगंतुकों ने खूब सराहा. प्रदर्शनी में लगभग बीस हजार लोगों ने हिस्सा लिया. पूर्व मध्य रेल द्वारा इस फोटो प्रदर्शनी में स्वच्छता, गंगा नदी पर निर्माणाधीन रेल-सह-सड़क महासेतु के निर्माण की जटिलताओं, रेल पहिया कारखाना में रेल पहिया के निर्माण की प्रक्रिया के साथ ही संरक्षण, साफ-सफाई आदि के संबंध में जन-जागरूकता से संबंधित पहलुओं को फोटो और वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित किया गया. प्रदर्शनी में हेरिटेज की श्रेणी में आने वाले, पूर्व में रेलवे के प्रयोग में लाए गए उपकरणों को भी रखा गया है, जो काफी रोचक हैं. ■

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

www.chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

21 अक्टूबर–27 अक्टूबर 2013

15 सितंबर को ज़िला स्कूल, गया के प्रांगण में गया शहरी विधानसभा क्षेत्र के जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में जदयू कार्यकर्ता आए. प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने गया महानगर जदयू के अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद उर्फ राजू बर्णवाल को गया विधानसभा से जदयू का संभावित प्रत्याशी घोषित किया.

शेखपुरा में दलों की मुश्किलें

अरुण कुमार

शेखपुरा जिला राजद की बैठक में जब कुर्सियां चलीं तो एकबारगी पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव भी हैरान रह गए. उन्होंने कार्यकर्ताओ को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने. वहीं अगले ही दिन जदयू के जिला सम्मेलन में जिप सदस्य एवं जदयू नेत्री रेशमा भारती को भाषण नहीं देने पर बवाल हो गया. इससे पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष चुनाव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे उलझे की जमकर लाठियां चलीं और शेखपुरा से पटना तक जिलाध्यक्ष बनने के लिए सिर फुटव्वल होने लगी और कांग्रेस के आंतरिक कलह से तो जिलावासी वाकिफ है ही, इससे विधानसभा की दोनों सीटों से कांग्रेस का गढ़ माने जाने के बाद भी कांग्रेस की हार हुई. दरअसल, राजनीति में यह आंतरिक सिर फुटव्वल जिले में हो गई है और इसकी वजह से आए दिन पार्टियों की एकता खत्म होती दिख रही है. बात यदि जदयू की करें तो शेखपुरा विधायक रणधीर कुमार सोनी एवं बरबीघा विधायक गजानंद शाही दोनों में काफी अनबन है. इसी अनबन के परिणामस्वरूप जिप अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की कुर्सी गिरी और इसका अंत शेखपुरा जिला सम्मेलन में देखने को मिला. पार्टी के जिला सम्मेलन में जिला प्रभारी मंत्री रमई राम, वरिष्ठ नेता शिवानन्द तिवारी सहित अन्य लोग भाग ले रहे थे. दोनों खेमे की खींचतान का परिणाम यह हुआ कि रणधीर कुमार सोनी द्वारा जिप सदस्य एवं जदयू नेता रेशमा भारती को भाषण देने से रोक दिया गया और जब जदयू विधायक गजानंद शाही की बोलने की बारी आई तो उन्होंने अपनी जगह रेशमा भारती को बोलने का मौका देकर विवाद को हवा दे दी.

वहीं राजद के जिला सम्मेलन में विजय सम्राट एवं शंभू यादव खेमा आपस में उलझ गए. दोनों तरफ से कुर्सियां चलने लगीं और लाठियां भी निकल गईं. मंच पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव भी उपस्थित थे. असल में राजद में दोनों नेता वर्चस्व की राजनीति कर रहे है. शंभू यादव अपने दिवंगत पिता काशी पहलवान और पार्टी से पुराने जुड़ाव के सहारे राजद की राजनीति पर कब्जा करना चाहते हैं, वहीं विजय सम्राट अपनी सक्रियता से शंभू यादव को मात देना चाहते हैं. दोनों ही राजद विधानसभा से टिकट के उम्मीदवार हैं और पार्टी पर इसी वजह से दबदबा बनाना चाहते हैं. विजय सम्राट की सक्रियता की वजह से राजनीति सिंह राजद के जिलाध्यक्ष भाजपा छोड़कर बन गए, वहीं संगठन पर भी कब्जा बनाया, जबकि शंभू यादव जदयू के नेता एवं मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के करीबी हैं और उनके कार्यक्रमों में अक्सर देखे जाते है. वहीं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजीत प्रभाकर पर पार्टी के पुराने नेता पार्टी को हाइजैक करने का आरोप लगाते है. जिलाध्यक्ष के होने वाले चुनाव को लेकर शेखपुरा के माहुरी पंचायत भवन हो रही बैठक में संजीत प्रभाकर के साले एवं नीमी पंचायत के मुखिया संजीव सिंह ने खुल कर दबंगई की और जिलाध्यक्ष के उम्मीदवार बनने की मंशा पाले अजय कुमार अक्षय की जमकर पिटाई की. अपने कई समर्थकों के साथ लाठी डंडे से हुए इस हमले में अक्षय सिंह कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे और एफआईआर भी दर्ज किया गया. बाद में इसी को लेकर पटना में संजीव सिंह की दबंगई दिखी और वहां भी अक्षय सिंह से मारपीट की गई. बाद में पार्टी के निर्वाची पदाधिकारी और कुछ अधिकारियों की मिली भगत से संजीव सिंह को भाजपा का जिलाध्यक्ष बना दिया गया. विरोधी खेमा इस सब में पैसे की लेन देन का आरोप भी प्रदेश पदाधिकारियों पर लगाते है. हालांकि संजीत प्रभाकर सारे आरोपों को निराधार बताते हुए कहते हैं कि पार्टी को आगे नहीं बढ़ने देने वाले नेता ही इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, जबकि उनके द्वारा पार्टी के विकास को लेकर ही यह सब किया जा रहा है. वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता एवं सांसद प्रतिनिधि रामविलास सिंह, पिंजड़ी मुखिया पवन किशोर, पूर्व मंडल अध्यक्ष उमेश सिंह, स्वराज सिंह सहित सौ भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया है, जबकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विश्वनाथ भगत इसे ब्लैकमेल की राजनीति बताते हैं. वहीं सांसद भोला सिंह पार्टी के जनाधार विहीन नेताओं द्वारा पार्टी में विवाद खड़ा कर पार्टी को कमजोर करने की बात कहते हैं.

जदयू की सभा में बोलते शिवानन्द तिवारी.

राजद की सभा में कार्यकताओं को समझाते पूर्व केंद्रीय मंत्री.

राजद जिला सम्मेलन में भाग लेते नेता.

वहीं कांग्रेस में मची घमासान भी थमने का नाम नहीं ले रही है. बरबीघा से विधायक रहे अशोक चौधरी अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं. वहीं कांग्रेस के दिवंगत सांसद राजो सिंह की हत्या में उन्हें अभियुक्त बनाए जाने को लेकर राजो सिंह के पौत्र सुदर्शन कुमार द्वारा न्यायालय में आवेदन दिया गया. दरअसल, 2005 में राजो सिंह की हत्या में अशोक चौधरी एवं वर्तमान शेखपुरा विधायक रणधीर कुमार सोनी नामजद अभियुक्त थे. बाद में तत्कालीन एसपी अमीत लोढ़ के द्वारा अनुसंधान के बाद दोनों को हत्याकांड में लिप्त होने से बरी कर दिया गया. इसी के आलोक में न्यायालय में अभियुक्त बनाने का आवेदन दिया गया. हालांकि इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय में आवेदन को खारिज कर दिया, जबकि सुदर्शन कुमार इसे लेकर उच्च न्यायालय जाने की बात कहते हैं. वहीं इसे प्रदेश अध्यक्ष प्रतिद्वंद्विता का परिणाम बताते हुए कहते हैं कि पार्टी के विकास को लेकर वे ज्यादा गंभीर हैं. बहरहाल, पार्टियों के इस सिरफुटौवल की वजह से सभी पार्टियों की आंतरकि स्थिति खराब है और कार्यकर्ता चुपचाप तमाशा देख रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

सरकार की सुस्ती से

बढ़ रही है बाल तस्करी

इंतेज़ारूल हक़

समय-समय पर बाल तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं, उसके बावजूद प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाता. सवाल यह है कि आखिर मानव तस्करी पर सरकार और उसके नुमाइंदे मेहरबान क्यों हैं? आखिर उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने से यहां की सरकारी एजेंसियां व पुलिस परहेज क्यों करती है? चंपारण के इलाकों में आए दिन इन मुद्दों पर बहस छिड़ी रहती है. स्थानीय लोग यह स्वीकारते हैं कि पुलिस प्रशासन विभिन्न वजहों से मानव तस्करों को पकड़ने में खास दिलचस्पी नहीं दिखाती है. बिहार के सीमावर्ती जिला समेत करीब 15 जिला तस्करों व अवैध कारोबारियों के लिए इन दिनों सुरक्षित क्षेत्र बन गया है. मानव तस्कर व अवैध कारोबारी ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से पहुंच रहे हैं और आर्थिक तंगी से जूझ रहे गरीबों को कुछ पैसे देकर उनके नाबालिग बच्चों व बच्चियों को महानगरों में ले जाकर बेच रहे हैं. करीब दो वर्षों में सैकड़ों की संख्या में बाल श्रमिकों की हुई बरामदगी, करीब आधा दर्जन दलालों की हुई गिरफ्तारी, अभियोजन निदेशालय, बिहार पटना के न्यायालय में दर्ज करीब पांच दर्जन से अधिक मुकदमें तथा ऑर्केस्ट्रा की आड़ में चल रहे देह व्यापार के हुए खुलासे ने यह साफ कर दिया है कि मानव तस्करों व बाल तस्करों का जाल काफी मजबूत है और उन पर शिकंजा कसने के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है.

रक्सौल स्टेशन पर बाल मजदूर व कार्यशाला में उपस्थित लोग

बीते दिनों बोधगया में जेनेवा ग्लोबल के सौजन्य से इंडिया नेपाल ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क द्वारा मानव व्यापार के रोकथाम के लिए आयोजित कार्यशाला में भी इस मुद्दे पर गहन चर्चा हुई और उक्त संस्था से जुड़े प्रतिनिधियों ने मानव व्यापार को रोकने में आ रही अड़चनों को विस्तार से रखा. यह बात भी खुलकर सामने आई कि मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, कानपुर व अमृतसर जाने वाली गाड़ियों में सब से अधिक बालश्रमिक, मानव तस्कर व उनके दलाल मिलते हैं. ये दलाल बच्चों को सीट पर बैठाने के बाद तब तक स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, जब तक गाड़ी खुल न जाए. गाड़ी खुलने के बाद एक-दो स्टेशन तक वे दूसरी बोगी में रहते हैं और बड़ी चालाकी से इन बच्चों की गतिविधि देखते रहते हैं. मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए काम कर रही स्वंयसेवी संस्थाएं व रेलवे पुलिस कभी कभार ट्रेनों में तलाशी कर बाल मजदूरों को पकड़ भी लेती हैं, लेकिन दलाल भागने में कामयाब हो जाते हैं. ये दलाल स्टेशनों पर काफी सर्तक होकर तस्करी को अंजाम देते हैं. वहां तैनात कार्यकर्ताओं व रेल पुलिस को भी चकमा देकर निकल जाते हैं. वहीं दूसरी ओर अभियोजन निदेशालय बिहार, पटना के न्यायालय में दायर वादों के अनुसार समस्तीपुर में 04, नवादा में 01, वैशाली में 06, शिकारगंज में 06, बक्सर में 04, सिवान में 07, गोपालगंज में 09, अररिया में 02, पटना में 04, मोतिहारी में 07, पूर्णिया में 01, कटिहार में 03, मुंगेर में 01, दरभांगा में 05 व सुपौल में 01. यानी कूल 61 इस तरह के मामले दर्ज किए गए हैं. बाल तस्करों की सक्रियता की शिकायतें भी पुलिस व विभाग को समय-समय पर मिलती रहती हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल कागजी खानापूर्ति की जाती है. सबसे ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य तो यह है कि श्रम विभाग और उसका धावा दल भी इन बाल तस्करों को पकड़ना मुनासिब नहीं समझते और केवल कागजी घोड़ा दौड़ाकर मामले को रफा-दफा कर देते हैं. यही स्थिति अवैध तरीके से चल रहे ऑर्केस्ट्रा पार्टियों की है. जानकार बताते हैं कि यहां ऑर्केस्ट्रा की आड़ में खुलेआम नाबालिग लड़कियों का मानसिक व शारीरिक शोषण किया जा रहा है और प्रशासनिक पदाधिकारी अन्जान बने हुए हैं. बीते दिनों पूर्वी चंपारण जिले के छौड़ादानो में वर्षों से संचालित ऑर्केस्ट्रा के संचालक जितेंद्र कुमार के प्रयास से यहां प्रयास संस्था की पहल पर हुई छापेमारी से कई नाबालिग लड़कियां बरामद हुईं. वहीं बंगाल से कल्पना नाम की 19 वर्षीय लड़की हिरोइन बनाने का सपना दिखाकर लड़कियों से देह व्यापार करा रही थी. हालांकि पूर्वी चंपारण के पुलिस कप्तान विनय कुमार व उनकी टीम ने इस गोरखधंधे का खुलासा कर अपनी उपस्थिति तो दर्ज करा दी है, लेकिन इससे कोई खास असर नही पड़ा है. जानकार बताते हैं कि पुलिस को अभियान चलाकर ऑर्केस्ट्रा संचालकों के यहां छापेमारी करने की जरूरत है. इस बीच जिला बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष संगीता चित्रांश ने बताया कि मानव तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए प्रयास जारी है और एक विशेष कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई की जा रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

गया महानगर जदयू

एक अनार सौ बीमार

सुनील सौरभ

feedback@chauthiduniya.com

विधानसभा चुनाव में अभी दो साल की देर है, लेकिन गया महानगर जदयू में लोकसभा चुनाव निकट होने के बावजूद किसी को चिंता नहीं है. नेता विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक जोड़-तोड़ करने में लगे हैं.

बिहार के गांव-देहात में एक कहावत है- तालाब में मछली और नौ-नौ कुटिया हिस्सा. यानी की मछली तालाब से निकली ही नहीं और इसके पहले ही खाने के लिए लोगों ने हिस्से का बंटवारा कर लिया. कुछ ऐसी ही स्थिति है, गया महानगर जदयू की. विधानसभा चुनाव में अभी दो साल की देर है, लेकिन गया महानगर जदयू में लोकसभा चुनाव निकट रहने के बावजूद इसकी कोई चिंता नहीं है. सभी नेता विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक जोड़-तोड़ करने में ही लगे हैं. पिछले 15 सितंबर को ज़िला स्कूल, गया के प्रांगण में गया शहरी विधानसभा क्षेत्र के जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में जदयू कार्यकर्ताओं की भागीदारी हुई. इसमें प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने गया महानगर जदयू के अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद उर्फ राजू बर्णवाल को गया शहर विधानसभा क्षेत्र से जदयू का संभावित प्रत्याशी घोषित कर देने के बाद यहां की राजनीति गर्म हो गई. पार्टी टिकट की चाहत रखने वाले कई जदयू नेताओं को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा नागवार गुजरी. जदयू नेता ने इस पर टिका-टिप्पणी भी करने लगे. यहां से जदयू की टिकट की चाहत रखने वाले आधा दर्जन नेताओं का एक दूसरे से आपस में मिलना-जुलना भी गर्मजोशी से होता है, लेकिन पीठ पीछे घटिया टिप्पणी करते हैं. कोई किसी का जातीय आधार मजबूत नहीं होने देता, जातीय वोट नहीं मिलने की बात कर गया शहरी विधानसभा क्षेत्र से एक दूसरे की काट टिकट नहीं मिलने के लिए कर रहे हैं. विधानसभा चुनाव में अभी दो साल शेष है. लोकसभा चुनाव सात-आठ महीने में होने वाले हैं, लेकिन गया शहर के जदयू नेताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारी की चिंता नहीं है, क्योंकि लोकसभा का सुरक्षित क्षेत्र होने के कारण सामान्य जाति के नेताओं का इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं है. सबकी यही सोच है कि जो पार्टी प्रत्याशी आएगा, देखा जाएगा. झगड़ा गया शहरी विधानसभा क्षेत्र को लेकर ही अधिक है. स्थिति एक अनार, सौ बीमार वाली हो गई है. जदयू के नेताओं में अंदरूनी द्वेष बढ़ने का कारण यह है कि गया शहरी विधानसभा क्षेत्र जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष द्वारा राजू बर्णवाल को संभावित प्रत्याशी की घोषणा करना समय से पूर्व अच्छा नहीं लगा. नतीजा है कि पहले से जदयू की टिकट की दावेदारी करने वाले नेताओं के राजनीति गड़बड़ हो गई. यह बात भी सच है कि ऐसे दावेदारी करने वाले नेताओं की सक्रियता इस सम्मेलन के प्रति नहीं रही. जिला जदयू अध्यक्ष अभय कुशवाहा तथा गया महानगर अध्यक्ष राजू बर्णवाल की इस सम्मेलन के प्रति सक्रियता तन-मन-धन से रही. यही कारण है कि राजू बर्णवान को गया शहर विधानसभा क्षेत्र से इसने समर्थक संभावित प्रत्याशी मान रहे हैं, जबकि पूर्व से गया नगर निगम के वार्ड पार्षद लालजी प्रसाद, जदयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ तथा सेंट्रल बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव राजेश प्रसाद भी विधानसभा चुनाव के लिए गया शहर से दावेदार हैं. इन तीन के अलावा विनोद कुमार, राम लखन स्वर्णकार, विजय मेहता आदि अन्य भी अपनी दोवेदारी कर रहे हैं. इनमें अधिकांश प्रत्याशी व्यवसायी वर्ग से आते हैं, जिनमें दो राजू बर्णवाल तथा राजेश प्रसाद माहूरी जाति से आते हैं. इनकी गया में अच्छी खासी संख्या है. हाल के दिनों में जातीय आधार पर माहूरी समाज राजू बर्णवाल को मजबूत प्रत्याशी मान रहा है. वहीं दूसरी ओर राजेश प्रसाद इस बात से इनकार कर खुद को भी कमजोर नहीं मान रहे हैं. जदयू के एक व्यवसायी नेता से जब पूछा गया कि प्रदेश अध्यक्ष ने गया शहर विधानसभा क्षेत्र से जदयू का संभावित प्रत्याशी राजू बर्णवाल को घोषित किया है तो उक्त व्यवसायी नेता ने कहा कि वशिष्ठ नारायण सिंह का ही अपना ठिकाना नहीं है, तो वह दूसरों को क्या टिकट दिला पाएंगे? जदयू के इस व्यवसायी नेता का प्रदेश जदयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ की एक नेत्री से अच्छा संबंध है. 1990 से गया शहर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे भाजपा के प्रेम कुमार को लोग लाचारी में वोट देने की बात करते हैं. लोग कहते हैं कि किसी दल से अच्छा तथा मजबूत प्रत्याशी नहीं रहने के कारण प्रेम कुमार को लाभ मिल जाता है, लेकिन इस बार गया शहर की जनता भी चाहती है कि कोई बदलाव हो, कोई वजनदार प्रत्याशी किसी भी दल से आए. लोगों की आम धारणा है कि प्रेम कुमार कुछ सीमित लोगों के बीच ही सिमट गए हैं. ऐसे में गया शहर के लोग बदलाव चाहते हैं. बशर्ते की कोई मजबूत और साफ छवि का प्रत्याशी आये, दल चाहे कोई भी हो. जदयू के कई प्रदेश स्तर के नेताओं तथा गया शहर के प्रतिष्ठित लोगों की एक राय यह भी है कि सेंट्रल बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के कई बार अध्यक्ष रह चुके डॉ. कौशलेंद्र प्रताप को गया शहर विधानसभा क्षेत्र से जदयू का प्रत्याशी बनाया जाए तो प्रेम कुमार को बड़ी चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि सेंट्रल बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आकर नीतीश कुमार उनके कार्यों को देख-सुन कर प्रभावित हुए थे, लेकिन कौशलेंद्र प्रताप किसी दल में नहीं हैं और दलीय राजनीति भी नहीं करते हैं, लेकिन शहर की समस्याओं के लिए हमेशा मुखर रहने वालों में उनका नाम आता है. प्रेम कुमार से भी उनके अच्छे संबंध हैं, लेकिन सच तो यह है कि गया शहर के लोग प्रेम कुमार के कार्यकलाप से संतुष्ट नहीं हैं. उनके द्वारा शहर में लगाए गए चापाकलों, पार्कों के जीर्णोद्धार, तालाबों के जीर्णोद्धार, मोड़-मोड़ पर लगाये गये फव्वारे आदि का कार्य देखने पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने की बात शहर के लोग कहते हैं. लोगों का कहना है कि विधायक द्वारा कराए गए कार्यों की जांच हो तो हकीकत सामने आ जाएगा. यही कारण हैं कि जदयू के नेता गया शहरवासियों के मनोभाव से परिचित होकर जदयू का टिकट लेकर आने से जीत की उम्मीद पाल बैठे हैं. ■

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

21 अक्टूबर–27 अक्टूबर 2013

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

उत्तर प्रदेश में राहुल को घेरने की रणनीति

अजय कुमार

दिल्ली की सत्ता की लड़ाई उत्तर प्रदेश की जमीं पर लड़ी जा रही है. मंच सजा कर जनता का विश्वास जीता जा रहा है तो पर्दे के पीछे से चुनाव बाद के संभावित समीकरणों को मजबूत किया जा रहा है. राजनेताओं ने दोस्ती और दुश्मनी की परिभाषा ही बदल दी है. यह महज इत्तेफाक नहीं है कि एक तरफ तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और बसपा प्रमुख मायावती पर कई गंभीर आरोप लगा कर जनता को भरमा रहे हैं, वहीं केंद्र में उनका समर्थन भी लिए हुए हैं. बात यहीं खत्म नहीं होती. उससे भी दो कदम आगे बढ़कर केंद्र सरकार बैंक डोर से आय से अधिक संपत्ति मामले में माया–मुलायम को बरी करके यूपीए सरकार को समर्थन का ईनाम और 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद साथ खड़े रखने के लिए डोरे भी डाल रही है. जहां तक उत्तर प्रदेश में चुनाव की बात है तो यहां किसी तरह का कोई गठबंधन देखने को नहीं मिलेगा. भले ही सपा और बसपा केंद्र में कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रही हो, लेकिन यूपी में उनकी राहें जुदा हैं. समाजवादी पार्टी तो विधानसभा चुनाव में राहुल को धूल चटा ही चुकी है, इसलिए इसके हौसले बुलंद हैं, वहीं भाजपा भी इस बार नये जोश के साथ ताल ठोंक रही है. उसके निशाने पर भी मुलायम और माया से अधिक राहुल गांधी ही हैं. राहुल के साथ प्लस प्वांइट यह है कि भले ही विधानसभा चुनाव में उनका सिक्का नहीं चला था, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी को अच्छी खासी सीटें दिलाईं थीं. मरणासन्न पड़ी कांग्रेस ने यहां राहुल के चमत्कार से 22 सीटें जीती थीं.

उत्तर प्रदेश में सबका अपना वोट बैंक है. इसके अलावा एक खास बात और है. यूपी देश को कई प्रधानमंत्री दे चुका है. अटल के बाद यहां जो प्रधानमंत्री को लेकर सूखा पड़ा है, वह 2014 में खत्म होने की कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं. इसके अलावा एक बात और है कि हो सकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में अच्छी खासी दखल रखने वाली कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव, भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह आदि तमाम नेताओं का यह आखिरी आम चुनाव हो. इन नेताओं पर उम्र का प्रभाव दिखने लगा है. नहीं लगता है कि 2019 तक उक्त नेता सक्रिय राजनीति में अपने पैर जमाए रखने की स्थिति में रहेंगे. वैसे भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने पुत्र राहुल गांधी के ऊपर राजनीतिक जिम्मेदारियों का बोझ धीरे–धीरे डालती जा रही हैं. सोनिया पर लिखी किताब '24 अकबर रोड' के लेखक राशिद किदवई ने तो यहां तक कहा है कि 2016 में 70 वर्ष की होने के बाद सोनिया गांधी पूरी तरह से राजनीति से संन्यास ले लेंगी. कहा तो यहां तक जा रहा है कि पिछले जन्मदिन (09 दिसबंर, 2012) पर इस बात की जानकारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दे भी दी थी. यही हाल सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव का है. उन्होंने भी यूपी की सत्ता अखिलेश यादव को सौंप कर प्रदेश से तो किनारा कर लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का मोह जरूर पाले हुए हैं. बहरहाल, भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सभी पांच राज्यों के चुनाव की परवाह न करते हुए उत्तर प्रदेश में ज्यादा समय बिताना चाहते हैं. सपा और बसपा का तो यूपी गढ़ ही है. उन्हें यहां से सबसे अधिक उम्मीद रहती है. राहुल गांधी ने अलीगढ़ और रामपुर में सभाएं करके चुनावी बिगुल बजा दिया है. उनके निशाने पर दलित और मुस्लिम वोटर हैं. कांग्रेस की मंशा उत्तर प्रदेश में चल रही तमाम केंद्रीय योजनाओं को लेकर अखिलेश सरकार को कटघरे में खड़ा करने की है. मनरेगा में धांधली, स्वास्थ्य सेवाओं में गड़बड़ी, कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालत और खाद्य सुरक्षा बिल नहीं लागू करने का कसूरवार ठहरा कर अखिलेश सरकार को घेरने का खाका कांग्रेस ने तैयार कर दिया है. दंगों को लेकर कांग्रेस फूंक–फूंक कर कदम रखेगी. उसे पता है कि यह मुद्दा इसका घर भी जला सकता है.

कांग्रेस को राहुल पर भरोसा है तो उनके विरोधियों को यह विश्वास है कि राहुल गांधी राजनीति के पक्के खिलाड़ी नहीं बन पाए हैं, जिसका फायदा वह उठा सकते हैं. वैसे विरोधियों की सोच गलत भी नहीं है. राहुल गांधी के साथ समस्या यह है कि वह दो टूक बात कह देते हैं. दूरदर्शिता का अभाव उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है तो उनके विरोधियों के लिए उनको घेरना आसान हो जाता है. दागी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लाए गए अध्यादेश का विरोध करके राहुल ने जितनी सुर्खियां नहीं बटोरीं, उससे ज्यादा उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा. यही हाल यूपी में भी दिखाई दे रहा है. उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती पर आरोप लगाया कि उन्होंने दलित वर्ग के किसी नेता को उभरने नहीं दिया, तो लोग उनकी ही पार्टी पर उंगली उठाने लगे. राहुल से सवाल किया जा रहा है कि कांग्रेस ने 60 साल तक देश पर हुकूमत की. इससे दलितों का क्या भला हुआ. यह सही है कि बसपा सुप्रीमो मायावती अपने व्यवहार से वर्चस्ववादी नेता हैं, दलित हितों की वे बातें भले करें मगर व्यापक दलित नेतृत्व के उभार की उन्होंने भी कभी कोई चेष्टा नहीं की. अपनी पार्टी में अपने आगे किसी अन्य दलित नेता के व्यक्तित्व को उन्होंने उभरने नहीं दिया. वह स्वयं भी दलितों की इतनी बड़ी नेता नहीं बनती, अगर काशीराम का हाथ उनके सिर पर नहीं होता.

इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि बसपा और कांग्रेस की तरह दूसरी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने ही इस दिशा में कौन सा प्रयास किया था. आखिर किस पार्टी ने दलित नेतृत्व को शीर्ष पर जाने का मौका उपलब्ध कराया, जबकि कोई ऐसा दल नहीं है जो सैद्धांतिक रूप में खुद को दलित हितों का झंडाबरदार न बताता हो. जनशक्ति पार्टी के उदित राज ने तो कांग्रेस के युवराज राहुल पर व्यंग्य कसते हुए यहां तक कह दिया कि अगर राहुल को इस बात का गम है कि माया ने किसी दलित नेता को नहीं उभरने दिया तो वे दलित होने के नाते मुझे उभरने का मौका देकर अपने मन की टीस कम कर लें. वहीं बसपा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कैसा अपमान किया, किसी से छिपा नहीं है. कांग्रेस में ऐसे दलित नेताओं की अच्छी खासी संख्या रही है, जिनके सहारे कांग्रेस ने दलितों का वोट हासिल

(शेष पृष्ठ 18 पर)

समाजवादी मुलायम की जातिवादी सोच

न हम बदले हैं, न हमारी सोच बदली है. हमें तो जातिवाद का ही सहारा है. एम (मुस्लिम) वाई (यादव) फैक्टर के सहारे दिल्ली के तख्त-ओ-ताज पर कब्जा करने की हसरत पाले सपा प्रमुख की यही सोच उनके सामने चट्टान की तरह अवरोधक बन कर खड़ी हो गई है, लेकिन न तो मुलायम को कुछ दिखाई दे रहा है न कुछ सुनाई पड़ रहा है. किसी की सुनने को भी वह तैयार नहीं है. उनकी हठधर्मी से पार्टी के भीतर ही विरोध के सुर सनाई पड़ने लगे हैं. प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल मुलायम के पास राष्ट्रीय विजन का अभाव है. वह जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति में ही उलझे हुए हैं, जबकि अन्य दलों में बदलाव साफ देखने को मिल रहा है. 2014 के लिए प्रधानमंत्री पद के तीन प्रबल दावेदारों, भाजपा के नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के अघोषित राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के स्वयंभू उम्मीदवार मुलायम सिंह यादव की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है. आश्चर्यजनक है कि करीब-करीब सभी राजनीतिक दलों और उनके आकाओं ने समय के साथ अपने में बदलाव कर लिया है, लेकिन मुलायम हैं कि बदलने को तैयार ही नहीं हैं,

इतना ही नहीं सपा प्रमुख ने अपने पुत्र और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी अपने रंग में रंग कर उनके राजनीतिक जीवन पर ग्रहण लगा दिया है. दंगे के नामजद आरोपी और मदरसा संचालक मौलाना नजीर को अखिलेश सरकार ने जिस तरह से सरकारी मेहमान का दर्जा देते हुए उन्हें विषेश विमान से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लखनऊ बुलाकर मुलाकात की, इससे भाजपा तमतमा गई है. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय पाठक ने कहा कि अखिलेश सरकार ने सत्ता में रहने का अधिकार खो दिया है. जनता इसका जबाव चुनावी मैदान में देगी.

हालांकि, बात बदलाव की करें तो भारतीय जनता पार्टी अब राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे और जो हिंदू हित की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा जैसे नारे नहीं लगाती है. भाजपा सांप्रदायिकता का दाग धोने के लिए अपने पसंदीदा मुद्दे राम मंदिर से दूर चली गई है. उसके नेताओं ने अयोध्या की तरफ देखना ही बंद कर दिया है. भाजपाई सवा सौ करोड़ भारतीयों की बात करने लगे हैं. मोदी के सुर बदल गए हैं. बदली-बदली सी लग रही भाजपा के हौसले इतने बुलंद हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में वह बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाने का सपना देखने लगी है.

दूसरी ओर बसपा ने अपने उभार के समय, जब कांशीराम का बोलबाला था, तिलक-तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार का नारा खूब उछाला था, इस नारे ने चमत्कारी परिणाम दिए. दलित मायावती का मुरीद हो गया. इस नारे के बदौलत माया सीएम तक बनीं, लेकिन 2007 आते-आते माया और उनकी पार्टी बदल गई. वह सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात करने लगीं. बदला हुआ नारा बसपा के लिए इतना फायदेमंद साबित हुआ कि 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा को पूर्ण बहुमत मिल गया. ब्राहमण, क्षत्रिय आदि तमाम

(शेष पृष्ठ 18 पर)

हमारी विशेषताएं

-नगर सहकारी बैंक के एटीएम में सभी निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्ड स्वीकार्य हैं।
-नगर सहकारी बैंक के एटीएम कार्ड से सभी निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एटीएम से धन निकासी की सुविधा।
-चालू खाता, बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, सावधि खाता व लघु जमा योजना खाता संचालित।
-ड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध, बाहर के ड्राफ्टों का अतिशीघ्र कलेक्शन।
-आर.टी.जी.एस एवं एन.ई.एफ.टी की सुविधा उपलब्ध।
-भवन निर्माण ऋण, कैश क्रेडिट ऋण, कार्यशील पूंजी ऋण, वाहन ऋण, व्यक्तिगत ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड ऋण, किसान गोल्ड कार्ड योजना इत्यादि के लिए ऋण आसान शर्तों पर उपलब्ध।
-वरिष्ठ नागरिकों को एक प्रतिशत अधिक ब्याज।
-वेस्टर्न मनी ट्रांसफर सुविधा उपलब्ध।
-विशेष सावधि जमा योजना में जमा धन 83 माह में दोगुना से अधिक (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 75 माह में दोगुना)।
-एसएमएस अलर्ट की सुविधा।
-kiosk मशीन द्वारा नगद जमा, चेक जमा, बैलेंस जानने व पासबुक प्रिंट करने की सुविधा उपलब्ध।
-coin dispenser मशीन द्वारा सिक्के पाने की सुविधा उपलब्ध।
-ifsc code के माध्यम से देश के किसी कोने से पैसा मंगाने व भेजने की सुविधा।

• सौम्या अग्रवाल (आईएएस), जिलाधिकारी, महराजगंज • दिलीप कुमार (पुलिस अधीक्षक)

के कर कमलों से

स्थान–नगर सहकारी बैंक

सिविल लाइंस, फरेंदा रोड, महराजगंज

समय-12.30 दोपहर

विनय कुमार

सचिव/महाप्रबंधक

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन और प्रसार प्रतिनिधियों की. पारिश्रमिक योग्यता अनुसार. शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
ajaiup@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश–201301,
PH : 120-6450888, 6451999

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

गुजरात देगा यूपी को शेर

संदीप कश्यप

गुजरात और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच समझौता हो गया है. गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार और सपा प्रमुख मुलायम सिंह की अति महत्वाकांक्षी लायन सफारी योजना के लिए बिना राजनीतिक द्वेष के लायन उपलब्ध कराएगी. राजनीतिक विरोधों को दरकिनार करके मोदी सरकार ने यूपी की मांग पर इसे लायन सफारी देने को हामी भर दी है. अभी यह नहीं तय हो पाया है कि कितने लायन गुजरात से मिलेंगे, जिस तेजी के साथ गुजरात सरकार ने यह निर्णय लिया है, वह यह बताने के लिए काफी है कि इस योजना को लेकर यूपी सरकार कितनी गंभीर है. हाल में ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा प्रमुख मुलायम सिंह ने लायन सफारी क्षेत्र का भ्रमण किया था. इस मौके पर एक पुस्तिका फिशर वन इटावा का भी विमोचन किया गया. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मौके पर कहा भी था कि लायन सफारी इटावा बहुत अच्छे स्तर का पर्यटन स्थल साबित होगा. पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश को खुशहाली और विकास के रास्ते पर ले जाने का कार्य सपा सरकार तेजी से कर रही है. मुख्यमंत्री फिशर वन/लायन सफारी क्षेत्र इटावा के 1000 एकड़ क्षेत्र में परिस्थितिकीय पुनरुद्धार हेतु विशिष्ट वृक्षारोपण कार्यक्रम में पौधारोपण के उपरांत जनसभा को संबोधित कर रहे थे. उनका कहना था कि इस क्षेत्र में इस वर्ष 1.5 लाख से अधिक पौधों का पौधारोपण हुआ है. लायन सफारी का कार्य नेताजी (मुलायम सिंह यादव) ने शुरू किया था, जिसमें आई कई अड़चनों को दूर करके सफारी प्रोजेक्ट का कार्य निर्विघ्नता के साथ किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जल्द ही बब्बर शेर यहां दिखाई देंगे. बात खासियत करें तो दूसरे चिड़ियाघरों में जानवर/पंक्षी पिंजड़े में रहते हैं और देखने वाले खुले में घूमते हैं, लेकिन इटावा लायन सफारी की खास बात यह होगी कि यहां बब्बर शेर खुले में होंगे और देखने वाले पिंजड़े में. अंतरराष्ट्रीय मानकों से बनाई जा रही यह लायन सफारी देश की इकलौती सफारी होगी. एशियाई शेरों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्राकृतिक वातावरण में उनके वासस्थल को लायन सफारी परियोजना की स्थापना कर इटावा में विकसित किया जा रहा है. उसके बनने से आम जनता को बब्बर शेरों के जीवन को प्राकृतिक तौर पर नजदीक से देखने की सुविधा मिल सकेगी. लायन सफारी में एशियाई शेरों के प्रजनन हेतु लायन ब्रीडिंग सेंटर विकसित होगा. लायन सफारी परियोजना में 45 करोड़ रुपये से अधिक व्यय होंगे. इसमें से 30 करोड़ 50 लाख रुपशे शेरों की देखरेख के कार्यो जैसे-एनीमल हाउस का निर्माण, कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर का निर्माण, वेटनरी हॉस्पिटल आदि का निर्माण किया जा रहा है. सफारी क्षेत्र को पर्यटकों के लिए भी विकसित किया जा रहा है, ताकि देश-विदेश के पर्यटक एशियाई शेरों को नजदीक से देख सकें. पर्यटक सुविधाओं पर 9 करोड़ से अधिक व्यय होंगे, जिसके अंतर्गत इंटरप्रिटेशन सेंटर कम लाइब्रेरी, आंतरिक सड़कें, गार्डन, पार्किंग, वाच टॉवर, शौचालय आदि विकसित किया जा रहा है. सफारी क्षेत्र में 50 हेक्टेयर लायन सफारी कोर, 300 हेक्टेयर बफर जोन, 50 हेक्टेयर चैनलिंक फेंसिंग व 350 हेक्टेयर में हैबिटेट विकसित होगा. सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने फिशर वन क्षेत्र में 1,53,240वां पौधा रोप कर 1000 एकड़ के वृहद् वृक्षारोपण कार्यक्रम को पूर्ण करने के साथ लायन सफारी कार्य को तेजी से पूर्ण करने पर बल दिया. नेताजी ने लायन सफारी इटावा को विश्वस्तर पर प्रसिद्ध बनाए जाने पर बल दिया. अपने भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री व नेताजी ने लायन सफारी स्थित पर्यटन स्थल का भी निरीक्षण किया, जहां से पर्यटक लायन सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे. ■

छोटे दलों के खात्मे का संकेत

सुमन बी.आनन्द

दागी राजनीतिकों को लेकर खेले जा रहे शह-मात के खेल पर जनता की नजर राजनीतिक शुद्धिकरण, मूल्यों की स्थापना, अच्छे लोगों का राजनीति में प्रवेश एवं अपराधियों एवं जालसाजों को सत्ता से दूर रखने तक ही जाती है. परंतु इसका एक पक्ष यह भी है कि इस प्रकरण के निशाने पर क्षेत्रीय दलों को नेस्तनाबूद करना एवं क्षेत्रीय दलों के मुखियाओं की राजनीतिक हत्या करना भी है. बेशक इसमें राष्ट्रीय दलों के कुछ प्यादे भी शहीद होंगे, लेकिन इन प्यादों की कीमत पर यदि क्षेत्रीय दलों के बादशाह शहीद होते हैं तो राष्ट्रीय दलों के लिए यह कवायद महंगी नहीं है. इस राजनीतिक ड्रामे का कुछ-कुछ रूप सामने भी आने लगा है और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को अयोग्य घोषित कर दिया गया है. करुणानिधि की अजेय सत्ता भी इस चक्रव्यूह में बुरी तरह जकड़ गई है, जबकि मीडिया के प्रपंच से देश की जनता एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि राजनीति के स्वच्छता अभियान का जयगान करने एवं भाजपा एवं कांग्रेस को श्रेय देने में मशगूल हैं. कोई सारा श्रेय भाजपा को तो कोई कांग्रेस को दे रहा है, लेकिन शायद ही किसी की निगाह इस प्रकारण के निशाने पर जा रही है. मीडिया ने खुद को पूरी तरह राजनीति के शुद्धिकरण पर केंद्रित कर रखा है.

इस पूरे प्रकरण की शुरुआत 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें 2 साल या ज्यादा की सजा पाए जनप्रतिनिधियों को संसद अथवा विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने के साथ हुई. इसके विरोध में सभी दलों ने एक सुर में आवाज उठायी, जिसमें क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय दल दोनों के प्रतिनिधि शामिल थे. इसमें पक्ष-विपक्ष क्षेत्रीय-राष्ट्रीय सब एक सुर में विरोध कर रहे थे. सरकार ने इस विरोध के दबाव में सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुर्नविचार की मांग की, जिसपर 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में पुनर्विचार करने से मना कर दिया और कहा कि सरकार यदि चाहे तो ससंद में कानून पास करे. पुन: सभी दलों ने एकजुटता दिखाई और राज्यसभा में दागी नेताओं के बचाने का बिल पारित हो गया और लोकसभा में स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया. 24 सितंबर को लोकसभा में कुछ दलों के विरोध के चलते विल पास नहीं हो सका. इसके बाद यूपीए सरकार ने कैबिनेट में अध्यादेश पास करके दागी सांसदों एवं विधायकों को बचाने का प्रयास किया. इसके विरोध में राष्ट्रीय दलों की वकालत करने वाले लालकृष्ण अडवाणी 26 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति से मिले और अध्यादेश वापस करने का अनुरोध किया. आडवाणी पिछले लोकसभा चुनाव की चुनावी रैलियों में सार्वजनिक रूप से अपील करते थे कि यदि भाजपा को वोट नहीं देना चाहते तो कांग्रेस को दो, परंतु किसी भी सूरत में क्षेत्रीय दलों को वोट मत दो. इससे राष्ट्र का भला नहीं होने वाला. उनके राष्ट्रपति से मिलने के अगले दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेसवार्ता में विस्फोटक बयान जारी कर अध्यादेश को बकवास करार दिया. इसके बाद मात्र अध्यादेश वापसी की औपचारिकता करनी थी, जो प्रधानमंत्री जी के अमेरिका से वापसी के बाद पूरी कर दी गई.

अब एक नजर डालते हैं इस हाईटेक ड्रामे के निशाने पर आई क्षेत्रीय दलों की हस्तियों पर. अब तक बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के सर्वेसर्वा लालू प्रसाद यादव, तमिलनाडु के डीएमकेके करुणानिधि एवं इनके पुत्र, पुत्री एवं परिजन, डी राजा, कनिमोझी, स्तालिन, एवं मारन परिवार, एआईएडीएम के प्रमुख जयललिता पर केस विचाराधीन है. उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव एवं बसपा प्रमुख मायावती पर भी केस चल रहा है. बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री एवं जद (यू) के सर्वेसर्वा नीतीश कुमार पर भी केस विचाराधीन है. हरियाणा के धाकड़ नेता चौधरी देवीलाल के पुत्र ओम प्रकाश चौटाला और उनके परिजनों पर भी मामले दर्ज हैं. पंजाब के सुखवीर सिंह बादल एवं उनकी पार्टी का भविष्य भी इस अध्यादेश के तहत ही तय होना है. झारखंड के मधुकोड़ा पर तो गंभीर आरोप हैं. आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी, जो वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया एवं वर्तमान सांसद हैं, इस केस की जद में आ रहे हैं. कर्नाटक के बीएस येदियुरप्पा पर भी केस लंबित है जो कभी भी उनको अपनी चपेट में ले सकता है. इससे यह साफ है कि इस पूरे प्रकरण का लाभ राष्ट्रीय दलों को मिलता नजर आ रहा है और क्षेत्रीय दलों का भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है.

ज्ञातव्य है कि ज्यादातर क्षेत्रीय दलों का उदय जेपी आंदोलन एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्व विश्वनाथ प्रताप सिंह के उद्भव के साथ 90 के दशक में हुआ, जब पूरे देश में मंडल कमीशन एवं आरक्षण पर बवाल हुआ. आरक्षण एवं बीपी सिंह की ही देन थी कि इस देश में राष्ट्रीय दल हाशिये पर आते गए एवं क्षेत्रीय दलों का उद्भव शुरू हुआ जो थमने का नाम नहीं ले रहा था. स्व. वीपी सिंह ने ही एक राजनीकि फार्मूला दिया था कि राजनीति की सबसे सुरक्षित अवस्था यह है कि पक्ष और विपक्ष दोनों एक विचार पर काम करें, यानि सत्ताधारी दल का बाहर से समर्थन करने वाला दल ही संवैधानिक मुख्य विपक्षी दल हो. इस फार्मूले पर उन्होंने सत्ता भी चलाई. शायद ऐसी ही कुछ स्थिति आज भी दिख रही है, जब सत्ताधारी दल एवं मुख्य विपक्षी दल एक ही स्वर में अलाप कर रहे हैं. अगर ऐसा है तो यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि वीपी सिंह के द्वारा पैदा किए गए दलों को वीपी सिंह के फार्मूले से ही नेस्तानाबूद किया जा रहा है. वर्तमान में अडवाणी जी के ही फार्मूले से दोनों राष्ट्रीय दलों की गतिविधियां संचालित होती दिख रही हैं.

वैसे आम जनता ने इसे पूरे प्रकरण का तहे दिल से स्वागत किया है, करना भी चाहिए, क्योंकि नतीजा चाहे जो भी हो, हर हाल में साफ सुथरे लोगों को ही महिमामंडित किया जाना चाहिए एवं देश की जनता के भविष्य निर्धारित करने का अधिकार मिलना चाहिए. देश के विकास एवं राजनीतिक शुद्धता हेतु इस तरह के अध्यादेशों, फैसलों का खुले दिल से स्वागत होना चाहिए जैसा कि आम जनता की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आ भी रहा है. यह निश्चित रूप से स्वच्छ राजनीति एवं प्रजातंत्र के भविष्य का शुभ संकेत है. आम जनता ने जिस अंदाज में इस प्रकरण का स्वागत किया है वह स्पष्ट करता है कि आने वाला कल स्वर्णिम भारत की आधारशिला का निर्माण करेगा. ■

हुजूर मेरा कुसूर क्या है : कुशवाहा

दर्शन शर्मा

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य मंत्री का दर्जा पाए डॉ. राम आसरे कुशवाहा काफी व्यथित महसूस कर रहे हैं कि आखिर सपा हाईकमान ने उन्हें हटाने में इतनी जल्दी क्यों दिखाई? उन्हें सरकार और संगठन से अचानक हटाए जाने पर आश्चर्य है. उनका कहना है कि वह सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव से भेंटकर पूछना चाहते हैं कि आखिर उनका कसूर क्या है? वे तो नेताजी के वफादार सिपाही की तरह रहे हैं. विधानसभा चुनाव में पार्टी को कुशवाहा समाज का वोट दिलाने में पार्टी की काफी मदद भी की थी. उनकी बर्खास्तगी पर वही नहीं, बल्कि पूरा कुशवाहा समाज आहत है. हालांकि, उनकी बर्खास्तगी के पीछे सपा की ओर से ऐसे कोई खास कारण नहीं बताए गए हैं कि यह माना जा रहा है कि सपा हाईकमान ने राम आसरे कुशवाहा को उनके बड़बोलेपन के कारण सरकार और संगठन से बर्खास्त किया है. उनकी अनुशासनहीनता के पीछे का सबसे बड़ा आरोप यह है कि उन्होंने पिछले दिनों मुजफ्फरनगर दंगे पर पार्टी लाइन से हट कर बयानबाजी की थी. वे टीवी चैनलों पर विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय देते नजर आ रहे थे, जबकि इसके लिए वे पार्टी की ओर से अधिकृत नहीं किए गए थे. समाजवार्टी की ओर से मात्र दो प्रवक्ताओं को बोलने का अधिकार प्राप्त है, वे हैं राष्ट्रीय स्तर पर रामगोपाल यादव और प्रदेश स्तर पर राजेंद्र चौधरी. इन प्रवक्ताओं के अलावा किसी को भी मीडिया में पार्टी से जुड़े मामलों या अन्य विषयों पर बोलने की पाबंदी है. लेकिन कुशवाहा इसकी लगातार अनदेखी करते जा रहे थे. कुशवाहा की बर्खास्तगी के पीछे यह भी कारण गिनाए जा रहे हैं कि वह पिछले कई महीने से गाजियाबाद व नोएडा में पार्टी विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं, जो कि पार्टी हाईकमान के लिए नागवार था. कहते हैं कि कुशवाहा की इन गतिविधियों के चलते ही सपा हाईकमान ने गंभीरता से लिया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. विदित हो कि कुशवाहा ने 1990 से कांग्रेस कार्यकर्ता की हैसियत से अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया था. वे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में नौ प्रतिशत के करीब कुशवाहा समाज की आबादी है, जो यादव समाज से कहीं अधिक है और उनकी बर्खास्तगी से उनके समाज को काफी धक्का लगा है और समाज के लोग बुरी तरह से आहत हैं. कुल मिलाकर इन दिनों उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में लोकसभा चुनाव के चलते हवाएं काफी तेज चल रही हैं. राजनीति की मायावी दुनिया में कब कौन ,क्या कह दे, किधर चला जाए, इस आंधी में कौन कहां की सोच रहा है, किसको कौन पटकनी देना चाहता है, कुछ पता नहीं. लोकसभा के पूर्वाभ्यास के तौर पर प्रदेश की बड़ी पार्टियों में मंथन चल रहा है. अंदरखाने क्या हो रहा है, इसे परख पाना इतना सहज नहीं है, लेकिन हर दल मौके की तलाश में जरूर है. कौन बर्खास्त किया जा रहा है, कौन इस्तीफा दे रहा है. इस पर सभी दलों की निगाहें टिकी रहती हैं. अच्छे कंडीडेट की तलाश सभी को है. सपा के इस महासचिव की बर्खास्तगी पर भाजपा के मीडिया प्रभारी भारत सिंह मौर्य का कहना है कि मुलायम सिंह यादव पिछड़े वर्ग को वोटर के रूप में देखना पसंद करते हैं, नेता के रूप में नहीं. डॉ. कुशवाहा की बर्खास्तगी बानगी स्वरूप है. कुशवाहा के विरुद्ध कार्रवाई इसलिए की गई, क्योंकि उन्होंने 15 सितंबर को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह शासनकाल में बनी सामाजिक न्याय समिति की सिफारिशों का समर्थन किया था. ■

अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम निर्माण अधर में सियासत शुरू

राकेश कुमार यादव

फैजाबाद में 2006 से निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम एक बार फिर सियासी अखाड़ा बन गया है. डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम से बनने वाले इस स्टेडियम का निर्माण समय पर पूरा न हो पाने का ठीकरा सूबे के मंत्री जहां बहुजन समाज पार्टी पर फोड़ रहे हैं, वहीं स्टेडियम निर्माण की लागत अब दूनी हो जाने पर सूबे के खेल मंत्री नारद राय ने अनुपूरक बजट में 5 करोड़ रुपये स्वीकृत कराकर निर्माण को शीघ्र पूरा कराने का दावा किया है. जबकि स्टेडियम निर्माण के लिए लगभग 73 करोड़ रुपये की और जरूरत बताई जा रही है. स्टेडियम का निर्माण पूरा हो या न हो, परंतु सूबे की सरकार पांच करोड़ रुपये देने के बहाने इसका नाम बदलने का मन बना लिया है. स्थानीय सपा विधायक और सूबे के मनोरंजन कर राज्य मंत्री जहां इस स्टेडियम का नाम डॉ. भीमराव अंबेडकर के स्थान पर डॉ. राम मनोहर लोहिया करना चाह रहे हैं, वहीं खेल मंत्री नारद राय स्टेडियम का नाम छोटे लोहिया स्व. जनेश्वर मिश्र के नाम पर करने की बात कह रहे हैं.

फैजाबाद-इलाहाबाद मार्ग पर स्थित डाभासेमर में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के लिए 5 करोड़ रुपये की स्वीकृति दिलाने के बाद खेल मंत्री नारद राय स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंचे और निर्माणकार्य की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की. खेल मंत्री ने कार्यदायी संस्था को सबसे पहले बहुउद्देशीय हाल बनाने का निर्देष दिया और कहा कि जिससे स्टेडियम में खेल प्रतियोगिताएं शीघ्र शुरू कराई जा सकें, इसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बेहद चिंतित हैं. सपा की पिछली गठबंधन सरकार में स्टेडियम शिलान्यास के बाद 79 करोड़ रुपये की लागत के सापेक्ष 62 करोड़ रुपये शासन दे चुका है परंतु बसपा सरकार में काम की बजाय लूट खसोट की गई. बगैर स्वीकृति के मिट्टी के कार्यों पर ही दोगुना धन का खर्च दिखाया गया. इसलिए मामले की रिर्पोट पुलिस में दर्ज करा दी गई है. रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई, जो धन के बंदरबांट व अनियमितताओं की जांच करेगी.

गौरतलब है कि 2006 में समाजवादी पार्टी की तत्कालीन गठबंधन सरकार में खेल मंत्री रहे डीएस-4 के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरके चौधरी ने अपने गृह जनपद को अंतरराष्ट्रीय क्रीडा संकुल की सौगात देने की योजना स्वीकृत कराई थी. उनका मानना था कि फैजाबाद में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बन जाने के बाद स्थानीय खेल प्रतियोगिताएं निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगी. 2007 में विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें सपा को पराजय और बसपा को पूर्ण बहुमत मिलने पर तत्कालीन बसपा सरकार ने क्रीडा संकुल के निर्माण से मुंह मोड़ लिया. नतीजतन चल रहे निर्माण की गति रुक सी गई. बसपा सरकार के पांच साल बीत गए और स्टेडियम का निर्माण आधा-अधूरा ही रहा. विधानसभा चुनाव 2012 के पूर्व निर्माण कार्य पूरी तरह ठप हो गया और कार्यदायी संस्था ने फैजाबाद से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया. जिसको 2012 के चुनाव में सपा ने अपना चुनावी मुद्दा बनाया, परिणामस्वरूप सपा को इसका फायदा भी मिला. परंतु वह इस निर्माण के प्रति लगभग एक साल तक उदासीन बनी रही. अचानक लोकसभा चुनाव की आहट मिलते ही फिर समाजवादी पार्टी को अपना पुराना मुद्दा याद आया और बसपा पर प्रहार करते हुए निर्माणकार्य में तेजी लाने की कवायद और बयानबाजी शुरू कर दी. इस स्टेडियम को सपा मिशन 2014 तक भुनाने के मूड में है जिसके एवज में सूबे के खेल मंत्री नारद राय और मनोरंजन कर राज्य मंत्री तेजनारायण पांडेय पवन स्टेडियम का नाम डॉ. भीमराव अंबेडकर की जगह डॉ. राम मनोहर लोहिया या फिर छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र के नाम करने की बयानबाजी में जुट गए हैं. वहीं कार्यदायी संस्था सीएनडीएस ने संशोधित कार्ययोजना 1.40 अरब की शासन को भेज दी है.

फिलहाल सियासत में एक और मोड़ आ गया है. कभी समाजवादी पार्टी के साथ कदम दर कदम चलने वाले बीएस-4 के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरके चौधरी ने नाता ही नहीं तोड़ा है वरन बीएस-4 का बिलय बहुजन समाज पार्टी में कर दिया है. माना जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती फैजाबाद संसदीय क्षेत्र से आरके चौधरी को चुनावी समर में नये पैंतरे के तहत उतार सकती हैं. यदि आरके चौधरी चुनावी समर में कूदे तो निश्चित ही अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम उनका भी मुख्य चुनावी मुद्दा होगा. यह घबराहट सत्ता में बैठी समाजवादी पार्टी के नेताओं में साफ झलकने लगी है. यही वजह है कि स्टेडियम निर्माण पूरा हो या न हो, मात्र आडोटोरियम बनवाकर सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उसका उद्घाटन जल्दी से जल्दी करवा देने की कवायद तेज कर दी है. अब देखना है कि मिशन 2014 में फैजाबाद का यह स्टेडियम किसके पाले में गिरता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, महराजगंज

सावधान! खतरा! सावधान

चेतावनी

जहरीली शराब से बचें और मौत को दूर भगाएं:

1. मिथेनॉल\मिथाइल एल्कोहल का रंग, रूप व गंध शराब से मिलता जुलता होता है. यह जानलेवा जहर है. जिसके एक चम्मच पीने से आदमी अंधा हो सकता है. तथा दो चम्मच पीने से मौत हो सकती है.

2. अवैध श्रोत\अड्डों से खरीदी गई शराब जहरीली होती है और उसके पीने से मौत भी हो सकती है. गत दिनों में सहारनपुर, मेरठ गाजियाबाद, बुलंदशहर में अनेक लोगों की मृत्यु अवैध श्रोतों से खरीदी गई शराब के सेवन से हुई है.

3. सरकारी शराब की दुकानों से मानक के अनुसार शुद्ध एवं सुरक्षित शराब की बिक्री की जाती है.

अतः आपको सचेत किया जाता है कि सरकारी दुकानों के अतिरिक्त किसी भी अन्य श्रोत से शराब न खरीदें और न पिएं, अन्यथा मौत हो सकती है. यदि किसी व्यक्ति को अवैध शराब से संबंधित कोई सूचना देनी हो तो वह स्थानीय थानों पर सूचना दे सकता है. सूचना देने वाले का नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा.

बुंदेलखंड में शिक्षा की दशा सुधारने की कोशिश

सुरेंद्र अग्निहोत्री

वैसे तो उत्तर प्रदेश के हिस्से वाले समूचे बुंदेलखंड में अशिक्षा और गरीबी का आलम है, लेकिन कंकरीली-पथरीली जमीन के सहारे जीवन गुजार रहे ललितपुर तथा झांसी जिले के आदिवासी और दलितों को शिक्षित करना भी किसी संज्ञेय अपराध से कम नहीं है. यही वजह रही कि एक सामाजिक संगठन (एनजीओ) निरंतर ने सहजनी शिक्षा केंद्र संचालित कर प्रौढ़ महिलाओं को साक्षर करने का अभियान चलाया तो कुछ दबंग बाधक बनकर आ गए थे. इस क्षेत्र में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉ. पल्लम राजू के एक दिवसीय तथा प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी के तीन दिवसीय दौरे ने शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ जमीनी हकीकत को जानने का भरपूर प्रयास किया. इस अवसर पर विभिन्न शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों ने पुरानी पेंशन नीति बहाल करने व उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति, अध्यापकों को मिड डे मील, भवन निर्माण प्रभारी से मुक्त करने, शैक्षिक स्तर जांचने टास्क फोर्स का गठन झांसी मंडल में रिटायर हुए शिक्षकों को पेंशन दिलाने व वंचित शिक्षकों को अंतर्जनपदीय स्थानांतरण का लाभ देने की अपील की. इसके साथ संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों की दशा के लिए शिक्षक अकेले जिम्मेदार नहीं हैं. बच्चों की उपस्थिति बनाए रखने के लिए जनप्रतिनिधियों व अभिभावकों को भी जवाबदेह बनाया जाए. नगर क्षेत्र में शिक्षकों की कमी चल रही है. इस कमी को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों का स्थानांतरण नगर क्षेत्र में किया जाए. पदोन्नत शिक्षकों को 17,140 रुपये का लाभ देने, अनुदेशकों को बीटीसी कराकर नियमित करने, अप्रशिक्षित अनुदेशकों व शिक्षा मित्रों को दस हजार रुपये न्यूनतम मानदेय देने व अनुदेशकों को चिकित्सीय अवकाश देने की मांग की. शिक्षामित्रों का 3500 रुपये मानदेय से भरण-पोषण होना संभव न होने के कारण भुखमरी के कगार पर हैं और कई शिक्षामित्र आत्महत्या जैसा कदम उठाने विवश हुए हैं. बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी द्वारा शिक्षामित्रों की वकालत करते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. एमएम पल्लम राजू से अनुरोध किया गया कि राज्य सरकार द्वारा कई बार शिक्षामित्रों की मानदेय वृद्धि के संबंध में पत्र लिखा जा चुका है. जिस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया. इस पर केंद्रीय मंत्री डॉ. पल्लम राजू द्वारा तत्काल सचिव को तलबकर इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर तत्काल कार्यवाही करने को कहा.

केंद्रीय विद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम प्रशिक्षण कर रहे प्रथम बैच के शिक्षामित्रों को जनवरी, 2014 में तथा द्वितीय बैच के शिक्षामित्रों को दिसंबर 2014 में सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर देंगे. शेष इंटरमीडिएट शिक्षामित्रों की नियुक्ति के लिए केंद्र से स्वीकृति लेकर स्नातक होने तक उन्हें भी समायोजित कर दिया जाएगा. मंत्रियों द्वारा इन घोषणाओं से प्रतिनिधिमंडल में हर्ष की लहर दौड़ गई. बेसिक शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों से कर्तव्य पालन की अपील करते हुए कहा कि शिक्षकों की हर समस्या को हल करने के लिए प्रदेश सरकार पूरी बचनबद्धता के साथ कार्य कर रही है.

विकासखंड जखौरा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय नदनवारा में शैक्षिक माहौल में बच्चों की गुणवत्ता परखने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. एम.एम. पल्लम राजू, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री प्रदीप जैन आदित्य, बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया. पूर्व माध्यमिक विद्यालय नदनवारा का शैक्षिक माहौल देखकर सभी ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए बच्चों को इसी प्रकार शिक्षा ग्रहण करने की बात कही. तदोपरांत विद्यालय प्रांगण में चल रही मीना कक्षाओं को देखकर केंद्रीय मंत्री प्रफुल्लित हो उठे. इस दौरान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. एम.एम.पल्लम राजू ने विद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था को बारीकी से देखा. इसके बाद उन्होंने विद्यालय में बच्चों के लिए बनाए गए शौचालयों का भी निरीक्षण किया. इसके साथ ही मंत्रियों द्वारा प्रत्येक कक्षाओं में जाकर बच्चों द्वारा शिक्षाप्रद तरीके से किए जा रहे अन्य कार्यों को भी देखा. निरीक्षण के दौरान विद्यालय के बच्चों द्वारा मंत्री जी को लकड़ी की बैलगाड़ी व हल भेंट किया गया. इस दौरान बच्चों द्वारा विज्ञान से ओतप्रोत बनाए गए माडलों का भी निरीक्षण किया.

मंत्री का आगमन देख शिक्षा के मंदिर भले ही चकाचक हो गए हों, लेकिन विद्यालयों में शिक्षकों की कम संख्या के चलते शिक्षण कार्य सुचारु न होने का रंजोगम हर किसी ने बेसिक शिक्षा मंत्री के सामने रखा. बुंदेलखंड में स्कूल से वंचित बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान सहित अन्य योजनाओं में कई करोड़ रुपये खर्च देने के बाद नतीजे कुछ खास नही रहे. बेसिक शिक्षा मंत्री ने क्षेत्रीय अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुये बुंदेलखंड में शिक्षा का स्तर अच्छा करने के लिए कदम उठाने के साथ-साथ शिक्षकों को फंड के साथ पेंशन न उपलब्ध कराने पर असंतोष प्रकट किया. इस तीन दिवसीय दौरे ने प्राथमिक शिक्षा की कई खामियों को उजागर किया और चुस्त-दुरुस्त शिक्षकीय व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया.

रामगोविंद चौधरी ने सवालों के जवाब में कहा कि प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षित करने के लिए 55 लाख रुपये और दिए हैं. बुंदेलखंड में इस वर्ष चिन्हित किए गए 1833 आउट ऑफ स्कूल बच्चों पर सर्वशिक्षा अभियान में कुल 54.99 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इससे विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा. शासन ने 60 फीसदी यानि 32,99,400 रुपये बेसिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध भी करा दिया है. सरकार प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी तथा विज्ञान की शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है. शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शिक्षकों के स्थानांतरण और नियुक्ति में शिक्षक की मर्जी भी ली जा रही है. अब शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षा की तस्वीर बदलनी होगी. ■

नवरात्रि के पावन पर्व पर सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं!

बेटी को दहेज नहीं, शिक्षा दीजिए

दहेज रहित सामूहिक विवाह का आयोजन

दिनांक : 05 नवंबर 2013, दिन : मंगलवार
स्थान : अमृतपाली, बलिया

पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2013

इस शुभ अवसर पर वर-वधू को आशीर्वाद देने के लिए आप सभी सादर आमंत्रित है.

आयोजक : डॉ. हरेराम
प्रतिनिधि, सदस्य जिला पंचायत, बलिया
प्रबंधक, वल्लभ नीतीश सेवा संस्थान

संपर्क सूत्र : 05498-223769 मो. 9415254580

पृष्ठ 17 का शेष

यूपी में राहुल को घेरने की रणनीति

करने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन सम्मान और आगे बढ़ने का मौका किसी को नहीं दिया. अच्छा होता कि राहुल गांधी जैसे नेता इस बात के लिए सिर्फ दलित नेताओं को कोसने की जगह खुद की ही कोई मिसाल पेश करते. अपनी पार्टी के अहम पदों पर दलित चेहरों की जगह जनाधार वाले दलित नेताओं को अपने साथ काम करने का मौका देकर राहुल इतिहास रच सकते हैं पर क्या उनमें वह दृष्टि और साहस है?

राहुल दलितों के नाम पर खालिस राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने मायावती पर ऐसे ही नहीं उंगली उठाई है. उन्हें पता है कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद मायावती तो दूर उनकी पार्टी के अन्य नेताओं ने भी वहां के पीड़ित दलित वोटरों के घर जाना तो दूर संवेदना के दो शब्द भी नहीं कहे, जबकि मायावती की चुनावी राजनीति की शुरुआत मुजफ्फनगर से ही हुई थी. गौतमबुद्ध नगर का बादलपुर उनका गांव है. बसपा के एक सांसद और दो विधायकों के ऊपर दंगा भड़काने का आरोप लगा है. दंगों में दलित और मुसलमान आमने-सामने हो गए थे. दलितों को लग रहा है कि मायावती मुस्लिम वोटरों को नाराज नहीं करने के लिए ही दलितों से दूरी बनाकर चल रही हैं. इसका फायदा भाजपा उठाने की फिराक में है. वेस्ट यूपी में जाट-जाटव के बीच छत्तीस का आंकड़ा हुआ करता था, परंतु दंगों के बाद हालात बदल गए हैं. अब जाट-जाटव भाई-भाई का नारा सुनाई देने लगा है. ऐसा लगता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती दुविधा से बाहर नहीं निकल पा रही हैं. इससे नाराज पश्चिमी यूपी के कई मुस्लिम बसपा नेताओं और सांसद कादिर राणा, विधायक नूर सलीम और जीमल अहमद कासमी अपने खिलाफ लिखी एफआईआर की धार को कुंद करने के लिए सपा की तरफ देखने लगे हैं. हो सकता है देर-सबेर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका झेलना पड़ जाए. वैसे भी इन नेताओं की राजनीतिक पारी की शुरुआत सपा से ही हुई थी.

किसानों के दर्द को लेकर भी राहुल गांधी घिरते जा रहे हैं. सपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि जिन्होंने कभी खेत नहीं देखा, उसकी मेड़ों पर चले नहीं, उन्हें किसानों की चिंता होने लगी, यह किसी नये आश्चर्य से कम नहीं. अमेठी में कांग्रेस उपाध्यक्ष ने किसानों को फसल का उचित मूल्य न होने की बात कहीं और एक बड़े पूंजी घराने के मेगाफूड पार्क का शिलान्यास किया. चूंकि खेत और फसल की उनकी समझ सुनी सुनाई और किताबी है, इसलिए उन्होंने आलू के बाजार भाव और पैकिंग में आने वाले आलू चिप्स के दामों के अंतर पर दार्शनिक अंदाज में कुछ कह कर किसानों की हमदर्दी पाने की विफल चेष्टा की. कांग्रेस और इसके नेतृत्व की गलत नीतियों के चलते ही किसान बदहाल हुआ है और आत्महत्या करने तक को मजबूर रहा है. कांग्रेस-सपा और बसपा के बीच प्यार और तकरार का नजारा जनता देख रही है. जनता की मुट्ठी में भारत की तकदीर बंद है. इसीलिए नेताओं ने ड्रामेबाजी की दुकान सजा ली है.

भाजपा को लगता है कि अबकी तस्वीर बदलेगी. भाजपा लगातार यह कोशिश कर रही है कि कांग्रेस-सपा और बसपा को एक ही तराजू पर तौल दिया जाए. उसमें वह कामयाब भी होती दिख रही है. मोदी का जादू चलता दिख रहा है. यह वोट बैंक बन पाएगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी. आरएसएस और भाजपा ने मोदी को खुली छूट और खुला मैदान दे दिया है. वह ही यूपी में अमित शाह को लाकर नये-नये प्रयोग कर रहे हैं. सपा सरकार का तुष्टिकरण, केंद्र का भ्रष्टाचार, सपा-बसपा और कांग्रेस की दिखावी दुश्मनी पर से भाजपा नेता पर्दा हटा कर जनता को यह बताना चाहते हैं कि यह लोग सत्ता के लिए एक थे और चुनाव बाद भी एक ही रहेंगे. यह बात अगर भाजपा जनता को समझाने में सफल हो गई तो आधी लड़ाई तो वह वैसे ही जीत लेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

समाजवादी मुलायम की जातिवादी सोच

जातियां बसपा में अपना भविष्य तलाशने लगीं. 2012 में भी माया की सत्ता गई तो उसकी वजह यह नहीं थी कि किसी कौम का विश्वास उठ गया था, बल्कि पत्थरों पर बेतहाशा पैसा बहाना मतदाताओं को रास नहीं आया. समय की नजाकत और जनता की आवाज को भांपकर जो संभल जाए, उसे ही नेता कहते हैं. इसका अहसास कांग्रेस के अघोषित पीएम पद के दावेदार राहुल गांधी को भी होने लगा है. यूपी के 2012 के विधानसभा चुनाव में राहुल ने वन मैन आर्मी की तरह प्रचार किया था. दलितों के घर जाकर खाना खाया, सोए, चौपाल लगाई, मौलानाओं के दरवाजों पर दस्तक दी, लेकिन सब बेकार रहा. उनके सारे दांवपेच धरे रह गए. नतीजे आए तो राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया. उन्हें जमीनी हकीकत का अहसास हो गया. इसके बाद उनकी जुबान पर भूमि अधिग्रहण बिल को केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलना, दागी जनप्रतिनिधियों की सदस्यता बचाने के लिए लाए गए अध्यादेश का विरोध, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना खाद्य सुरक्षा बिल रहते हैं. राहुल आलोचनाओं से अधिक विकास की बात करते हैं. सपा की तो स्थिति यह है कि इसके सदस्य ही दो फाड़ हो गए हैं. अखिलेश सरकार की कार्यशैली पर उंगली उठ रही है. पार्टी के भीतर से ही आवाज आ रही है कि सरकार दंगा प्रभावित इलाकों में निष्पक्ष होकर कार्रवाई करे. मतलब, सपाई भी यह मान कर चल रहे हैं कि दंगा नियंत्रण में भेदभाव बरता जा रहा है. इसीलिए माहौल शांत नहीं हो रहा है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सपा नेताओं की तो स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि वह जनता से मुंह चुराते फिर रहे हैं.

उधर, मुलायम सिंह यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल शांत नहीं होने पर अपनी सरकार को दोष देने के बजाय आरएसएस और भाजपा राग अलाप कर और मौलानाओं के सामने नतमस्तक होकर काम चला रहे हैं. मौलानाओं को हवाई मार्ग से लखनऊ बुलाकर मुलायम से मिलाया जाता है. कहने को तो मुलायम जमीन से जुड़े नेता हैं, लेकिन आज तक उनके विवेक में यह बात नहीं आई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमन-चैन वापस आए, उसके लिए एक सर्वदलीय कमेटी बनाएं. मुलायम की सोच का दायरा संकुचित हो गया है. एक वर्ग विशेष के प्रति नरमी का ही नतीजा है कि सरकार के खिलाफ जनांदोलन का दायरा बढ़ता जा रहा है. सपा सरकार की कारगुजारी की तरफ से आंख मूंद लेने के कारण स्थितियों में सुधार नहीं हो रहा है. मुख्यमंत्री और उनके करीबी आज तक यह नहीं समझ पाए हैं कि अगर किसी जिले में लॉ एंड आर्डर की समस्या आती है तो स्थानीय प्रशासन को निष्पक्ष होकर कार्रवाई करने की छूट मिलना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होगा तो सपा के हाथ में नुकसान के अलावा कुछ नहीं लगेगा. वह भाजपा को कोसने में ध्यान लगाए हैं, जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी भाजपा इस दायरे से उठकर बात कर रही है. इसकी बानगी बार-बार देखने को मिल रही है. हाल में ही केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बयान आया. उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए कि जेलों में निर्दोष अल्पसंख्यक न बंद रहें. इस पर भाजपा का कहना था अल्पसंख्यक ही क्यों कोई भी निर्दोष जेल में न रहे.

समय तेजी से निकल रहा है और समाजवादी पार्टी संभल नहीं पा रही है. बदले हालात में मुसलमान भले ही उसके साथ खड़ा रहे, लेकिन पिछड़ा वर्ग और इसमें भी यादव बिरादरी, जिसपर मुलायम अपना हक समझते हैं, वह भी उनसे बिदकने लगा है. भले ही सरकार आज जितनी मनमानी कर ले, परंतु उसकी अंधेरगर्दी के खिलाफ हाईकोर्ट आंख मूंदकर बैठने के मूड में नजर नहीं आ रहा है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश से छांट-छांटकर जाट बिरादरी के पुलिसकर्मियों को दूरदराज के जिलों में तैनाती का मामला अदालत में पहुंच गया है. अदालत ने सरकार से जबाव-तलब किया है और सिपाहियों को उनकी पुरानी तैनाती पर ही बने रहने का फरमान जारी करने के साथ ही कई महत्वपूर्ण जानकारियां तो सरकार से मांगी ही हैं, इसके अलावा अदालत ने दंगों को लेकर विवादों में घिरे मंत्री आजम खान को भी नोटिस जारी किया है. ऐसा लगता है कि दंगों की जांच पर अदालत की भी नजरें लगी रहेंगी. ■

चौथी दुनिया साप्ताहिक अखबार के सफलतम प्रकाशन पर हार्दिक शुभकानाएं

- डी.पी. यादव, राष्ट्रीय महासचिव, हस्तक्षेप (मानवाधिकार जननिगरानी समिति)
- जे.पी. सिंह, राष्ट्रीय सचिव, हस्तक्षेप (मानवाधिकार जननिगरानी समिति)
- मूरत राम, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैंपेन फॉर मनरेगा
- डॉ राजेश कुमार यादव, प्रभारी, आरटीआई टास्कफोर्स उत्तर प्रदेश
- डॉ शैलजा राय, अध्यक्ष, डोमेस्टिक वायोलेंस एक्शन ग्रुप (डग) उ.प्र.
- संगीता जायसवाल, महासचिव, डोमेस्टिक वायोलेंस एक्शन ग्रुप (डग) उ.प्र.
- सरोज पांडेय, राष्ट्रीय महासचिव, डोमेस्टिक वायोलेंस एक्शन ग्रुप (डग)
- ओमकार नाथ मेहता, एडवोकेट
- हंसराज तिवारी एडवोकेट, कानूनी सलाहकार हस्तक्षेप (मानवाधिकार जन निगरानी समिति)

संस्था का सदस्य बनने अथवा संस्था के विषय में जानकारी के लिए संपर्क करें
Email : awsar3334@gmail.com
अथवा कॉल करें 09455209120, 09453517557,07668952813

अजय कुमार , लखनऊ ब्यूरो प्रमुख कार्यालय का पता : जे-3/2 डॉलीबाग़, हजरतगंज, लखनऊ-226001, फोन -(0522) 2204678/09415005111

समय–समय पर पार्टी लाइन से अलग बोल भी योगी को जहां सुर्खियों में लाती है, तो वहीं बीजेपी को मुश्किल में डालती है. पूर्वांचल के तीन दिग्गज भाजपा नेताओं सूर्य प्रताप शाही, चुनाव प्रबंध समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रमापति राम त्रिपाठी व प्रदेश उपाध्यक्ष शिव प्रताप शुक्ला से योगी की अनबन जगजाहिर है. ऐसे में यूपी को फतह करने की अमित शाह की उम्मीद कैसे परवान चढ़ती है, देखना दिलचस्प होगा.

राहुल पश्चिम, मुलायम पूरब से गरजे

रवि प्रकाश

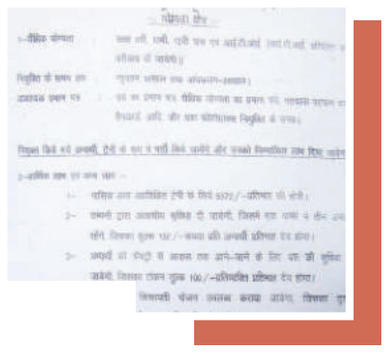

उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बज गया है. पीएम पद के तीन–तीन दावेदारों की बातें जनता सुन रही है. कांग्रेस के अघोषित प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने एक ही दिन में (10 अक्टूबर को) अलीगढ़ और रामपुर में दो जनसभाएं करके अपने राजनीतिक एजेंडे को धार दी. 19 अक्टूबर को भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और 29 अक्टूबर को गैर भाजपा, गैर कांग्रेस के तीसरे मोर्चे के सहारे पीएम बनने का सपना देख रहे सपा प्रमुख मुलायम सिंह अपनी–अपनी पार्टी (भाजपा–सपा) के चुनाव–प्रचार का श्रीगणेश कर अपनी बात जनता के सामने रखेंगे. तीनों ही उम्मीदवारों में अजब विरोधाभास देखा जा रहा है. राहुल गांधी ने अपनी रैलियों का आगाज जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किया, वहीं भाजपा के नरेंद्र मोदी मध्य यूपी से अपनी सभाओं का श्रीगणेश करेंगे, इधर पूर्वांचल में अपने आप को कमजोर समझ रही मुलायम सिंह यादव पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ में 29 अक्टूबर को अपने मुख्यमंत्री पुत्र अखिलेश यादव के साथ 2014 के चुनाव के लिए पहली बार ताल ठोंकते दिखेंगे. इसके बाद सपा की रैलियों का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा. सपा प्रमुख सभी 18 मंडलों में रैलियां करेंगे. अगले दो–तीन महीनों में भाजपा की करीब दर्जन भर रैलियों में मोदी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे. सबके अपने–अपने दावे हैं. चुनाव के मैदान में कोई किसी से कम नहीं रहना चाहता है. हवा में बातें हो रही हैं. आरोप–प्रत्यारोप की राजनीति में नेता एक–दूसरे की कलई खोलने में लगे हैं. शिगूफे भी छोड़े जा रहे हैं. सबसे ताजा शिगूफा भाजपा के प्रदेश प्रभारी अमित शाह से सुनने को मिला. उनका कहना था यदि केंद्र में मोदी की सरकार बनती है तो यूपी में मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे. कारण चुनाव के बाद सपा में भगदड़ मच जाएगी. कांग्रेस ने अमित शाह की यूपी में इंट्री पर बैन लगाने का शिगूफा सपा सरकार के सामने छोड़ रखा है. मायावती प्रदेश में राष्ट्रपति शासन का राग अलाप रही हैं. सपा ने अपना दामन पाक साफ बताते हुए दंगों के लिए भाजपा को कसूरवार ठहराने का शिगूफा छोड़ा है. राहुल की तो बात ही निराली है. वे आज भी वहीं खड़े नजर आ रहे हैं जहां 2012 के विधानसभा चुनाव के समय यूपी में खड़े थे.

जनता किसके पक्ष में मतदान करेगी, यह तो बाद की बात है, लेकिन जुबानी जंग में भाजपा अन्य दलों से काफी आगे दिख रही है. मोदी के राजनैतिक विरोधियों के समझ में ही नहीं आ रहा है कि वह मोदी के आभामंडल को किन तर्कों से फीका करें. फिलहाल मोदी के खिलाफ गुजरात दंगों के अलावा किसी के पास कुछ भी बोलने को नजर नहीं आ रहा है. स्थिति यह है राहुल गांधी यूपी में जनसभाएं करते हैं तो मुलायम और माया तक ही सिमट कर रह जाते हैं, लोग उनके मुंह से मोदी के बारे में सुनना चाहते हैं, लेकिन वह क्या बोलें, स्वयं ही नहीं समझ पाते हैं. लोग तो यहां तक क कह रहे हैं कि राहुल गांधी नये–नये राजनीति में आए युवा अखिलेश यादव को 2012 के विधानसभा चुनाव में नहीं पछाड़ पाए तो फिर मोदी तो राजनीति के काफी चतुर चालाक खिलाड़ी हैं. बहरहाल, मुलायम की रैली तो 29 अक्टूबर को होगी, परंतु उत्तर प्रदेश में मोदी के आगमन का समय हो गया है. उनकी पहली गर्जना 19 तारीख को कानपुर में सुनाई देगी. मोदी 19 को कानपुर में, 25 अक्टूबर को झांसी में, 08 नवंबर को बहराइच में रैली करेंगे. इन तीन रैलियों के बाद मुरादाबाद, मेरठ, गोरखपुर, आगरा, बरेली और वाराणसी में मोदी की जनसभाओं का कार्यक्रम रखा जाएगा. दसवीं और बड़ी रैली 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन कभी उनका संसदीय क्षेत्र रहे लखनऊ में होगी. मोदी मिशन 2014 में यूपी की अस्सी सीटों के बेहद महत्व दे रहे हैं. ■

उत्तर प्रदेश में समाजवादी सियासत

पुत्र ने दबंग को ठुकराया, पिता ने दागी को गले लगाया

संजय सक्सेना

समाजवादी पार्टी के संसदीय बोर्ड द्वारा दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव के हाथों में 2014 के लोकसभा चुनाव की कमान देने की घोषणा होते ही पार्टी का चेहरा बदलने लगा है. सपा में एक बार फिर चुनाव जिताऊ और वोट खिंचाऊ जातीय आधार वाले दागी–दबंगों की मांग बढ़ने लगी है. इसकी सबसे ताजा मिसाल हैं बाबू सिंह कुशवाहा की सपा में इंट्री, जिन्हें बसपा सुप्रीमो मायावती ने सत्ता में रहते भ्रष्टाचार के चलते बाहर का रास्ता दिखाया था. बसपा से भाजपा और भाजपा से सपा में आने का कुशवाहा का सफर काफी पेचीदगी भरा रहा. जेल में बंद बाबू से विधानसभा चुनाव के समय जब भाजपा ने नजदीकी बनाई तो इस समय भी सपा का रुख कड़ा था, लेकिन उसी दागी नेता, जिसकी सपा लगातार मुखालफत करती रही थी, की पत्नी शिवकन्या को हाल में ही सपा ने गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का टिकट थमा दिया. विधानसभा चुनाव के समय अखिलेश यादव ने बाहुबली डीपी यादव को पार्टी में न लेकर

जो साख बनाई थी, उसे लोकसभा चुनाव के लिए ताल ठोंक रहे सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने एक ही झटके में धो दिया.

सपा ने बाबू सिंह कुशवाहा से काफी सोच समझ कर नजदीकी बढ़ाई है. दोनों को सदस्यता दिलाते समय मुलायम सिंह यादव भी मौजूद थे. दोनों लोगों को सदस्यता दिलाने के बाद मुलायम ने मीडिया से बात करने का भी मन बनाया था, लेकिन बाद में फजीहत होने के बाद वह प्रेस कांफ्रेस करने से पीछे हट गए थे. तब सपा के प्रवक्ता और मंत्री राजेंद्र चौधरी बाबू सिंह कुशवाहा के भाई और पत्नी को लेकर उपस्थित हुए, लेकिन मीडिया के सवालों का जबाव देने में उन्हें छीकें आ गईं. उनसे मीडिया एक ही सवाल पूछ रहा था कि जब राजनीति से दागी–दबंगों को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अहम कदम उठा रहा है तो आप भ्रष्टाचारियों के परिवार वालों को क्यों राजनीतिक पनाह दे रहे हैं. इस बीच 11 अक्टूबर को डीएसपी हत्याकांड में मंत्रिमंडल से बाहर हुए राजा भैया को भी दोबारा सपा सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया. सपा की तरह की भाजपा ने भी संत ज्ञानेश्वर हत्याकांड के आरोपी सोनू और मोनू सिंह को पार्टी सदस्यता दिलाई थी. भाजपा के कुछ नेता नहीं चाहते थे कि सोनू–मोनू को पार्टी में लिया जाए, लेकिन वरुण गांधी के चलते उनकी एक नहीं चली. सोनू–मोनू को भाजपा की सदस्यता दिलाने के बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मुलायम सिंह यादव की तरह गैर–मौजूद रहे थे. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय पाठक ने ठीक वैसे ही दोनों को मीडिया के सामने पेश किया था, जैसे कि राजेंद्र चौधरी ने बाबू सिंह कुशवाहा के भाई और पत्नी को पेश किया था. फिलहाल, सोनू–मोनू और बाबू सिंह जेल की हवा खा रहे हैं. बाबू सिंह को समाजवादी सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों से राहत देने की पहल शुरू कर दी है. अब बसपा उस पर निशाना साध रही है. यहां यह बताते चलें कि विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने पिछड़े वर्ग की सशक्त जातियों काछी, शाक्य और कुशवाहा समाज का वोट हासिल करने के लिए कुशवाहा को पार्टी में शामिल करने की भूल करके उसका खामिजाया भुगता था. अब समाजवादी पार्टी की बारी है. ■

योगी आदित्यनाथ कहेंगे नमो–नमो!

पूजा श्रीवास्तव

भाजपा द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की घोषणा के साथ ही पूर्वांचल में भाजपा के सियासी समीकरण में बदलाव की उम्मीदें बढ़ गई हैं. वजह है पूर्वांचल में हिंदुत्व के उग्र पैरोकार योगी आदित्यनाथ. योगी को लाल कृष्ण आडवाणी के खेमे का माना जाता है. ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोर पकड़े हुए है कि क्या योगी पूर्वांचल में नमो–नमो बोलेंगे. सवाल यह भी है कि वे दिल से बोलेंगे या फिर सियासी दिमाग से. खैर, राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि योगी के पास मोदी मंत्र जपने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है.

योगी को लेकर बदले हालात में सवाल उठ रहे हैं. पहला, बदले हुए सियासी समीकरण में योगी मोदी के सुर में सुर मिलाते हैं या नहीं. दूसरा, विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका में रहे योगी को पार्टी कितना तवज्जो देती है. वैसे मोदी पूर्वांचल के करीब डेढ़ दर्जन सीटों पर योगी के प्रभाव व दखल को भलीभांति जानते हैं. तभी तो अमित शाह गोरखपुर के पहले ही दौरे में गोरक्षनाथ मंदिर जाना नहीं भूले. योगी की महत्वाकांक्षा ही है कि वह पूर्वांचल फतह कर अपना झंडा बुलंद करना चाहते हैं.

हालांकि, महत्वाकांक्षी योगी के बयानों से यह तय कर पाना मुश्किल है कि वे किस पाले में हैं. योगी बदले हालात में बदले–बदले से नजर आ रहे हैं. उनके सुर में सियासत की कलाबाजियों को सहज ही देखा जा सकता है. योगी बगैर लाग–लपेट के कहते हैं आज का जमीनी कार्यकर्ता मोदी की अगुवाई में खुद को उत्साहित पाता है. योगी के सुर यूं ही नहीं बदले हैं. समय की नब्ज पहचानने के मामले में वे बेहतर जौहरी भी हैं. यही वजह है कि मोदी के तर्ज पर ही योगी भी खुद की छवि को लेकर बेचैन हैं. आज योगी अपनी सभाओं में यह कहने का साहस नहीं जुटा सकने की स्थिति में हैं कि मुसलमान उनकी सभाओं से चले जाएं. योगी कहते हैं कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, हिंदुत्व व विकास मेरा एजेंडा है. मैं पार्टी में किसी पद का भी आकांक्षी नहीं हूं. जिस दिन मुझे लगेगा मेरे मिशन में राजनीति बाधक बन रही है, मैं सन्यास ले लूंगा.

बदले राजनीतिक परिवेश में योगी के प्रभाव वाली सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर भी कयासों का दौर शुरू हो गया है. महराजगंज लोकसभा सीट पर उम्मीदवारी को लेकर घमासान देखा जा रहा है. पांच बार लोकसभा में महराजगंज का प्रतिनिधित्व करने वाले पंकज चौधरी को लंगड़ी मारने वालों की संख्या काफी है. बीते विधानसभा चुनाव में सिसवा विधानसभा सीट से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी को चुनौती देने वाले इंजीनियर आरके मिश्रा खुद पर योगी का आशीर्वाद बताते हुए प्रचार युद्ध में जुट गए हैं. गोरखपुर की बांसगांव लोकसभा सीट पर योगी के आशीर्वाद से जीते कमलेश पासवान की गोरक्षपीठ से अनबन नये समीकरण की तरफ इशारा करती है.

समय–समय पर पार्टी लाइन से अलग बोल भी योगी को जहां सुर्खियों में लाती है, तो वहीं बीजेपी को मुश्किल में डालती है. पूर्वांचल के तीन दिग्गज भाजपा नेताओं पूर्व भाजपा अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही, चुनाव प्रबंध समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रमापति राम त्रिपाठी व प्रदेश उपाध्यक्ष शिव प्रताप शुक्ला से योगी की अनबन जगजाहिर है. ऐसे में यूपी को फतह करने की अमित शाह की उम्मीद कैसे परवान चढ़ती है, देखना दिलचस्प होगा. उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव अभियान के अध्यक्ष डॉ. रमापति राम त्रिपाठी ऐसी कयासबाजी को गैर–वाजिब मानते हैं. वह कहते हैं कि मोदी हो या योगी, सभी केंद्र के भ्रष्टाचार व तुष्टीकरण की हद करने वाली कांग्रेस सरकार को हटाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं. हम सब एक हैं. विरोधी मोदी की ताकत को देखकर ऐसी बातों को बेवजह तूल दे रहे हैं. वैसे समय की धारा पर पैनी नजर रखने वाले योगी न तो खुलकर कुछ बोल रहे हैं, न ही खामोश ही हैं. मोदी व उनके दूत अमित शाह योगी की ताकत पर पैनी नजर रखे हुए हैं. एक मूड व समान धारा के राजनीतिज्ञ मोदी व योगी का सियासी गठबंधन कैसे होता है, कैसा होता है, कब होता है. राजनीतिक पंडितों को इसका इंतजार है. ■

नौकरी के बहाने उल्लू सीधा कर रहा है वेलस्पन

शिवकुमार उपाध्याय

मिर्जापुर के ग्राम दादरी खुर्द गांव में प्रस्तावित वेलस्पन के निजी थर्मल पावर प्लांट को मंजूरी दिलवाने के लिए कंपनी अब इस हद तक गिर चुकी है कि इसने मड़िहान और आसपास के गांव में नौकरी देने का झांसा देकर कुछ स्थानीय दलालों से इस प्रोजेक्ट के समर्थन में हस्ताक्षर लेने की नई चाल चली है. ये बात तब सामने आई, जब विंध्य बचाओ संस्था बीएचयू बरकछा के दल ने यहां का दौरा किया और पाया कि वहां काफी संख्या में लोग आवेदन पत्र जमा करवा रहे हैं. बातचीत में पता चला कि स्थानीय दलालों ने गांव वालों को ये बताया है कि जो भी इस आवेदन पत्र को जमा कराएगा, उसे वेलस्पन की तरफ से नौकरी दी जाएगी. गरीबी की मार और कौड़ी के भाव अपनी जमीन खोने के बाद उन बेचारों के पास न अब खेत रहे और न ही कोई नौकरी. ऐसे में गांव वालों ने भी दलालों की बात मान कर आवेदन पत्र जमा करने पहुच गए. किस्सा समझ में तब आया, जब दल ने इसमें लिखित शब्दों को पढ़ा. आवेदन पत्र की आड़ में इस परियोजना के समर्थन में गांव वालों के हस्ताक्षर लेने की गंदी साजिश मालूम पड़ी. आवेदन पत्र का पहला पन्ना सिर्फ परियोजना के बारे में खुशी और समर्थन देने की बात कही गई है और इसी पन्ने में हस्ताक्षर भी लिए जा रहे है जिसके शब्द कुछ इस प्रकार हैं-हम सभी इस परियोजना के साथ हैं और इस परियोजना में बाधक बनने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध हम सभी सामूहिक रूप से परियोजना के साथ आवाज बुलंद करना चाहते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर वेलस्पन एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से स्थापित किए जाने वाले तापीय परियोजना के निर्माण में सहायक बनना चाहते हैं. विंध्य बचाओ टीम के सदस्य एवं पर्यावरणविद देवदित्यो सिन्हा ने बताया कि इस तापीय परियोजना की स्थापना के लिए गंगा से चार लाख लीटर पानी प्रति घंटा पंप करके अपर खजुरी बांध में जमा किया जाएगा और फिर इसका इस्तेमाल इस परियोजना में किया जाएगा. ये बात बहुत हास्यास्पद भी है क्योंकि जहां गरीब किसान खेती के लिए पानी के अभाव में जमीनें बेच चुके हैं, उनके लिए सरकार ने आज तक कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई, वहीं इस परियोजना के लिए पानी उपलब्ध करवाने में सरकार पूरी मदद कर रही है. इस परियोजना से गांव वालों को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि परियोजना के आते ही खजुरी बांध का पानी पीने और खेती के लायक नहीं रह जाएगा. हालत देख कर लग रहा है कि राज्य सरकार सिर्फ उद्योगपतिओं के विकास को ही विकास मानती है. अगर ऐसा न होता तो बेलहटा और मड़िहान के किसानों को खेती करने में कोई परेशानी नहीं आती और न ही इन्हें नौकरी करने के लिए किसी विदेशी कंपनी के आगे भीख मांगना पड़ता. विंध्य बचाओ सदस्य परियोजना स्थल के जांच के वक्त मौजूद थे. उन्होंने पाया कि कंपनी ने सरकार को जमा कराए दस्तावेज में जहां वन भूमि न होने की बात कही, वहीं जांच में सामने आया कि स्थान तक पहुंचने का रास्ता वन विभाग का है. यही नहीं, परियोजना स्थल के आसपास वन भूमि है. इस परिस्थिति में पर्यावरण मंजूरी के अलावा वन विभाग की मंजूरी की भी आवश्यकता है. एक ओर जहां इस फुटपाथ पर जाना मना है, वहीं इसकी चौड़ाई भी इतनी कम है कि एक छोटी गाड़ी भी नहीं निकल सकती. ऐसे में परियोजना के बनने के बाद वनों को नुकसान पहुंचेगा. बीएचयू बरकछा में पर्यावरण के शिक्षक डॉ. अनिल कुमार पांडेय के अनुसार इस परियोजना के मंजूरी से सबसे ज्यादा नुकसान बीएचयू परिसर को पड़ेगा. अपर खजुरी बांध का पानी ही लोअर खजुरी बाध में आता है, जिसे पूरा परिसर जल आपूर्ती के लिए इस्तेमाल करता है. इस परियोजना के आते ही स्थानीय जल स्रोतों पर भी प्रभाव पड़ेगा और इन्हें इस्तेमाल में लाना असंभव सा हो जाएगा. चिमनी से निकलने वाले धुएं का असर भी परिसर पर पड़ेगा और छात्रों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा. यही स्थिति आसपास के गावों में भी होगी. ■

जिन्हें लाभ मिल चुका है वे आरक्षण से बाहर होंगे

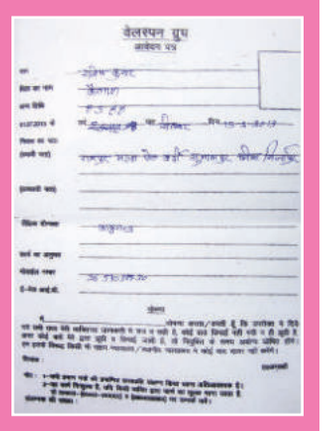

दर्शन शर्मा

हाईकोर्ट ने आरक्षण में पर्याप्त प्रतिनिधित्व पा चुकी जातियों को भविष्य में लाभ न दिए जाने का फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि जनसंख्या के अनुपात से जिन जातियों को नौकरियों में 50 फीसद आरक्षण का लाभ मिल चुका है, उसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व माना जाएगा. हाईकोर्ट ने सुमित कुमार शुक्ला व तीन अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को अपना जवाब लगाने के लिए एक महीने का समय दिया तथा याचिकाकर्ता को दो सप्ताह में उत्तर देने को कहा. कोर्ट ने माना कि सरकारी सेवाओं में कुछ विशेष जातियों के आरक्षित वर्ग को प्रतिनिधित्व पर्याप्त मात्रा में मिल चुका है. इसलिए प्रथम दृष्टया कोर्ट इस बात से सहमत है कि उनको आरक्षण देने का औचित्य नहीं है. राजनीतिक पंडितों का मानना है कि हाईकोर्ट के आदेश ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है. फैसले से जातिवादी राजनीति पर प्रभाव पड़ सकता है. इस आदेश का पालन करने से जहां सपा का वोट बैंक (यादव) आरक्षण के दायरे से बाहर निकल जाएगा, वहीं अनुसूचित जाति की चमार, धूसिया, जाटव आदि जातियां के भी आरक्षण के दायरे से बाहर निकलने की प्रबल संभावना है. कयास है कि यदि 2001 में राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में गठित सामाजिक न्याय समिति को आधार बनाएं तो आरक्षण की परिधि से पटेल और कुर्मी जातियां भी बाहर हो सकती हैं. क्योंकि इन जातियों पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल चुका है. यदि नये सिरे से उनके आंकड़े जुटाए गए तो कुछ और जातियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं. दूसरी ओर कई ऐसी भी जातियां भी हैं, जिनके लिए समाज की मुख्यधारा में आने की राह आसान हो जाएगी.केवट, मल्लाह, निषाद, मोमिन, कुम्हार, कश्यप, भर, राजभर आदि जातियां को भी इनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका है. यही स्थिति अनुसूचित जाति में भी देखने को मिल रही है, जिसमें पासी, तरमाली, धोबी, कोरी, वाल्मीकि, खटिक आदि जातियां हैं.

हालांकि, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में आरक्षण का लाभ देने के लिए मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र को इंगित किया गया था. समिति के अध्यक्ष तत्कालीन संसदीय कार्यमंत्री हुकुम सिंह थे और सदस्य तत्कालीन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री रमापति शास्त्री व विधान परिषद सदस्य दयाराम पाल सदस्य बनाए गए थे. समिति ने हर पांच साल में आरक्षण व इसके मूल्यांकन की सिफारिश भी की थी. लेकिन बसपा और सपा सरकारों ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था. हुकुम सिंह ने ताजा फैसले का स्वागत करते हुए प्रदेश सरकार को सलाह दी है कि वह इस फैसले की भावना का सम्मान करते हुए इसका विरोध करने का प्रयास न करे. भाजपा मछुआरा प्रकोष्ठ के संगठन मंत्री प्रकाश पाल का कहना है कि न्यायालय के इस निर्णय से वंचित जातियों में सामाजिक न्याय की आशा जगी है. प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक चौधरी लौटनराम निषाद का कहना है कि सरकार न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करे. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों की आरक्षण की समीक्षा के लिए 1962 में भारत सरकार द्वारा बनाए गई लूकर कमेटी ने एससी की सूची से चमार या जाटव को विलोपित किए जाने का सुझाव दिया था. ऐसी स्थिति में मल्लाह, केवट कहार, किसान, भर कुम्हार, बंजारा, नायक, अहेरिया, बिंद, बियार आदि जैसी जातियां अनुसूचित जाति में शामिल करने की पात्रता रखती हैं.

लब्बोलुआब यह है कि अदालत के इस फैसले से उन जातियों के युवकों में खुशी की लहर है, जिन्हें सियासत के चलते नौकरियों में आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला.वे कहते हैं उनके साथ अन्याय हुआ है. उन्हें भी सरकार समुचित प्रतिनिधित्व दे. उनके हिस्से का लाभ दूसरे लोगों ने भरपूर उठाया है. अब उन्हें आरक्षण में लाभ आगे न मिले. देखना यह है कि सरकार कोर्ट के इस आदेश को नौकरियों में लागू कर पाती है कि नहीं. ■

चौथी दुनिया
आवश्यकता है
संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि
चौथी दुनिया के लिए उत्तराखण्ड के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन, प्रसार प्रतिनिधियों एवं एजेंसियों के लिए शीघ्र आवेदन करें.
E-mail- konica@chauthiduniya.com
arifali@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
उत्तर प्रदेश–201301,
PH : 120-6450888, 6451999